

भारतीय रिज़र्व बैंक

# बुलेटिन



जून 2021

खंड 75 अंक 6

अध्यक्ष  
माइकल देबब्रत पात्र

संपादन समिति  
देबा प्रसाद रथ  
राजीव रंजन  
सितीकांत पट्टनाईक  
जी. पी. सामंता  
पल्लवी चव्हाण  
स्नेहल हेरवाडकर

संपादक  
शशीधर एम. लोकरे

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है। हस्ताक्षरित लेखों में व्यक्त विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2021

सर्वाधिकार सुरक्षित।  
सामग्री के पुनः प्रयोग की अनुमति है,  
बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन के सदस्यता शुल्क के लिए कृपया “भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन” खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से  
<https://bulletin.rbi.org.in> पर भी देखा जा सकता है।

# विषय-वस्तु

## गवर्नर का वक्तव्य

गवर्नर का वक्तव्य 1

## मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2021-22

मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य , 2021-22  
मौद्रिक नीति समिति(एमपीसी) का संकल्प  
02-04 जून, 2021 7

## विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य 11

## आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति 13

भारत के राष्ट्रक प्रतिफल वक्र के आकार का एक समष्टि-  
आर्थिक दृष्टिकोण 49

भारत में राजकोषीय फ्रेमवर्क और व्यय की गुणवत्ता 67

वर्तमान सांख्यिकी 91

हाल के प्रकाशन 137

## अनुपूरक

वार्षिक रिपोर्ट 2020-21



# गवर्नर का वक्तव्य

गवर्नर का वक्तव्य



## गवर्नर का वक्तव्य\*

### शक्तिकांत दास

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 2, 3 और 4 जून 2021 को बैठक की और उभरती समष्टिआर्थिक और वित्तीय स्थितियों के साथ-साथ महामारी की दूसरी लहर के प्रभाव का आकलन किया। अपने आकलन के आधार पर, एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखते हुए यथास्थिति बनाए रखने के लिए सर्वसम्मति से मत दिया। एमपीसी ने यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को बनाए रखने एवं अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने का भी निर्णय लिया। सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी हुई है। रिवर्स रेपो दर भी 3.35 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी हुई है।

एमपीसी की अप्रैल की बैठक के बाद से, कोविड-19 की दूसरी लहर कई राज्यों में बढ़ी है और छोटे शहरों और गांवों में फैल गई है, इसके कारण मानवीय दुख और त्रासदी बढ़ी है। फिर भी परीक्षणों और कष्टों के इन दिनों में, वायरस को हराने पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। विजयी होने के लिए कठिन समय कठिन विकल्पों और कठिन निर्णयों का आह्वान करता है। ऐसा कहा जाता है कि तूफान से पेड़ों की जड़ें और गहरी होती हैं। मुझे विश्वास है कि जैसे-जैसे हम वायरस को खत्म करने के लिए अपनी सहनशक्ति बढ़ाएंगे, यह मानव चरित्र और क्षमता के बेहतरीन पहलुओं को सामने लाएगा। मुझे यहां ग्रीक दार्शनिक एपिकटेटस का एक उद्धरण याद आ रहा है: "जितनी बड़ी कठिनाई होगी, उतना ही अधिक आनंद उसे पार करने में होगा..."<sup>1</sup>

मैं एमपीसी के निर्णय के अंतर्निहित तर्क के निर्धारण से शुरू करता हूँ। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 31 मई 2021 को जारी राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 के लिए भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) संकुचन को 7.3 प्रतिशत रहा, और जीडीपी की वृद्धि

चौथी तिमाही में 1.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) थी। सामान्य दक्षिण-पश्चिम मानसून का पूर्वानुमान, कृषि और कृषि अर्थव्यवस्था का लचीलापन, व्यवसायों द्वारा कोविड संगत परिचालन मॉडल को अपनाना, और वैश्विक सुधार की गति ऐसी ताकतें हैं जो दूसरी लहर थमने के बाद घरेलू आर्थिक गतिविधि के पुनरुद्धार के लिए अनुकूल गति प्रदान कर सकती हैं। दूसरी ओर, ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार और शहरी मांग की कमी ने नकारात्मक जोखिम पैदा किया है। टीकाकरण अभियान को तेज कर और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और महत्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति में कमी को कम करके इस महामारी के विनाश को कम किया जा सकता है।

अप्रैल के लिए मुद्रास्फीति प्रिंट 4.3 प्रतिशत पर अपने साथ कुछ राहत और नीति विस्तार लेकर आया है। एक सामान्य दक्षिण-पश्चिम मानसून के साथ आरामदायक बफर स्टॉक से अनाज की कीमतों के दबाव को नियंत्रण में रखने में मदद मिलेगी। दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय पण्य कीमतों और रसद लागतों में व्यापक उछाल के भीतर अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ते प्रक्षेपवक्र से लागत की स्थिति खराब हो रही है। ये घटनाक्रम कोर मूल्य दबावों को उंचा रख सकते हैं, हालांकि कमजोर मांग की स्थिति उपभोक्ता मुद्रास्फीति को प्रभावित कर सकती है।

एमपीसी का विचार था कि इस मोड़ पर, संवृद्धि की गति को फिर से हासिल करने के लिए सभी तरफ से नीतिगत समर्थन जो कि 2020-21 की दूसरी छमाही में स्पष्ट थी और इसके जड़ पकड़ने के बाद बहाली को पोषित करने की आवश्यकता है। तदनुसार, एमपीसी ने यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति आगे के समय में भी लक्ष्य के भीतर बनी रहे, नीतिगत दर को 4 प्रतिशत के अपने मौजूदा स्तर पर बनाए रखने और अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने और संवृद्धि को स्थायी आधार पर पुनर्जीवित और बनाए रखने के लिए जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख को जारी रखने का निर्णय लिया।

### संवृद्धि और मुद्रास्फीति का आकलन

#### संवृद्धि

कोविड-19 की दूसरी लहर पहली लहर की तुलना में अप्रत्याशित रूप से रुग्णता और मृत्यु दर की उच्च दर से जुड़ी है।

\* गवर्नर का वक्तव्य, 4 जून 2021

<sup>1</sup> एपिकटेटस: उद्धरण और तथ्य, ब्लागो किरोव (2016)

म्यूटेंट स्ट्रेन का फैलाव जिससे वायरस ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अत्यधिक संक्रमित किया और उसके कारण देश के एक बड़े हिस्से में गतिविधि पर नए प्रतिबंध लगाए गए। फिर भी पहली लहर के विपरीत, जब अर्थव्यवस्था एक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के तहत अचानक रुक गयी थी, गतिशीलता पर क्षेत्रीय आधार पर और सूक्ष्म अंतर से प्रतिबंध होने के कारण, दूसरी लहर में आर्थिक गतिविधि पर प्रभाव अपेक्षाकृत कम होने की उम्मीद है। इसके अलावा, लोग और व्यवसाय महामारी की कामकाजी परिस्थितियों के अनुकूल हो रहे हैं।

शहरी मांग, जो कुछ उच्च आवृत्ति संकेतकों में परिलक्षित होता है - बिजली की खपत; रेलवे माल ट्राफिक; बंदरगाह कार्गो; स्टील की खपत; सीमेंट उत्पादन; ई-वे बिल; और टोल संग्रह - में अप्रैल-मई 2021 के दौरान क्रमिक नरमी दर्ज की गई क्योंकि अधिकांश राज्यों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों / लॉकडाउन के कारण विनिर्माण और सेवा गतिविधि कमजोर हुई थी। अप्रैल-मई के दौरान गतिशीलता संकेतकों में गिरावट आई है, लेकिन वे पिछले वर्ष की पहली लहर के दौरान देखे गए स्तरों से ऊपर बने हुए हैं। घरेलू मौद्रिक और वित्तीय स्थितियां आर्थिक गतिविधियों के लिए अत्यधिक अनुकूल और सहायक बनी हुई हैं। इसके अलावा, आने वाले महीनों में टीकाकरण प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है और इससे आर्थिक गतिविधियों को सामान्य करने में मदद मिलेगी।

बाहरी मांग में मजबूती के साथ, वैश्विक व्यापार में एक पलटाव हो रहा है, जिससे भारत के निर्यात क्षेत्र को समर्थन मिलना चाहिए। राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में टीकाकरण की तेज प्रगति से वैश्विक मांग की स्थिति में और सुधार होने की उम्मीद है। भारत के निर्यात में मार्च, अप्रैल और मई 2021 में तेजी आई है। पूर्व-महामारी के स्तर से परे एक स्थायी बहाली के लिए अनुकूल बाहरी परिस्थितियां बन रही हैं। इस समय निर्यात के लिए संवर्धित और लक्षित नीतिगत समर्थन की मांग है। अब गुणवत्ता और मापनीयता पर ध्यान केंद्रित करके नीति को आगे बढ़ाने के लिए यह उपयुक्त है।

अप्रैल में ग्रामीण मांग के संकेतकों की क्रमिक गिरावट के बावजूद, ग्रामीण मांग के मजबूत रहने की उम्मीद है क्योंकि सामान्य मानसून के पूर्वानुमान के अनुसार आगे चलकर मानसून

के अपनी आधिक्य को बनाए रखने का अनुमान है। हालाँकि, ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 संक्रमणों का बढ़ता प्रसार नकारात्मक जोखिम पैदा करता है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अब 2021-22 में 9.5 प्रतिशत होने का अनुमान है, जिसमें 2021-22 की पहली तिमाही में 18.5 प्रतिशत; दूसरी तिमाही में 7.9 प्रतिशत; तीसरी तिमाही में 7.2 प्रतिशत; और चौथी तिमाही में 6.6 प्रतिशत शामिल है।

### मुद्रास्फीति

मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण की बात करें तो अप्रैल में हेडलाइन मुद्रास्फीति में 1.2 प्रतिशत अंक की कमी लाने वाले अनुकूल आधार प्रभाव, वर्ष की पहली छमाही तक जारी रह सकते हैं, जो मानसून की प्रगति और सरकार द्वारा प्रभावी आपूर्ति पक्ष हस्तक्षेपों के कारण प्रभावित हो सकता है। मुद्रास्फीति के लिए सकारात्मक जोखिम दूसरी लहर के बने रहने और वस्तुतः अखिल भारतीय आधार पर गतिविधि पर परिणामी प्रतिबंधों से उत्पन्न होता है। ऐसे परिदृश्य में, आपूर्ति पक्ष के व्यवधानों से आवश्यक खाद्य पदार्थों की रोधक कीमतों के लिए केंद्र और राज्यों दोनों द्वारा समन्वित, कैलिब्रेटेड और समय पर उपायों के लिए सक्रिय निगरानी और तैयारी की आवश्यकता होगी, ताकि आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं और खुदरा मार्जिन में वृद्धि को रोका जा सके।

इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, सीपीआई मुद्रास्फीति 2021-22 के दौरान 5.1 प्रतिशत: 2021-22 की पहली तिमाही में 5.2 प्रतिशत; दूसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत; तीसरी तिमाही में 4.7 प्रतिशत; और चौथी तिमाही में 5.3 प्रतिशत अनुमानित है, जिसमें जोखिम व्यापक रूप से संतुलित हैं।

### चलनिधि और वित्तीय बाजार मार्गदर्शन

इस महामारी के दौरान रिजर्व बैंक का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास अनुकूल वित्तीय स्थितियाँ बनाना रहा है ताकि वित्तीय बाजार और संस्थान सामान्य रूप से कार्य करते रहें। तदनुसार, पर्याप्त प्रणाली स्तर की चलनिधि सुनिश्चित की गई है और दबावग्रस्त संस्थानों और क्षेत्रों को लक्षित चलनिधि प्रदान की गई है। परिणामस्वरूप, उधार लेने की लागत और स्प्रेड ऐतिहासिक निम्न स्तर तक कम हो गए हैं। इससे वित्त वर्ष 2020-21 में



कॉर्पोरेट बॉण्ड और डिबेंचर के माध्यम से निजी उधारी की रिकॉर्ड राशि को प्रोत्साहन मिला है। 28 मई 2021 को आरक्षित मुद्रा में 12.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष)<sup>2</sup> की वृद्धि हुई, जबकि मुद्रा आपूर्ति (एम3) में 9.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) (21 मई को) और बैंक ऋण में 6.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) (21 मई को) की वृद्धि हुई। जी-एसएपी परिचालन और जी-सेक नीलामियों के रद्दीकरण, हस्तांतरण और ग्रीनशू विकल्पों के प्रयोग के कुछ उदाहरणों ने रिज़र्व बैंक के विचारों को बाजार तक पहुंचा दिया है। इस वित्तीय वर्ष में दूसरी लहर तेज होने के साथ, रिज़र्व बैंक का ध्यान तेजी से प्रणालीगत चलनिधि से अपने समान वितरण की ओर बढ़ रहा है। वास्तव में, भारतीय संदर्भ में महामारी के अनुभव से स्थायी सबक अपरंपरागत मौद्रिक नीति उपायों का नियोजन है जो सभी हितधारकों के बीच चलनिधि वितरित करते हैं। हम महामारी के प्रभाव को कम करने और अर्थव्यवस्था को उच्च और टिकाऊ विकास के पथ पर वापस लाने का प्रयास करते हुए हम संचरण के बाजार-आधारित चैनलों पर भरोसा करते हुए अपने सक्रिय और प्रथम दृष्टिकोण के साथ अग्रसर रहेंगे।

जी-एसएपी 1.0 के तहत नीलामियों ने अब तक की गई दो नीलामियों में क्रमशः 4.1 और 3.5 के बोली कवर अनुपात के साथ, बाजार सहभागियों से गहरी दिलचस्पी पैदा की है। दूसरी नीलामी का समय 22 मई 2021 से प्रभावी, निवल मांग और मियादी देयता (एनडीटीएल) के 4 प्रतिशत के अपने पूर्व-महामारी स्तर पर नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) की बहाली के कारण चलनिधि की निकासी को फिर से भरने के उद्देश्य से था। इसके अलावा, मई के अंतिम सप्ताह के दौरान लगभग ₹52,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों के मोचन ने सीआरआर बहाली को पूरी तरह से निष्प्रभावी कर दिया। जी-एसएपी 1.0 परिचालन से जुड़ी सकारात्मक बाह्यताएँ, अन्य वित्तीय बाजार खंडों, विशेष रूप से कॉर्पोरेट बॉन्ड और डिबेंचर में परिलक्षित होती हैं। वाणिज्यिक पत्र (सीपी), 91-दिवसीय खजाना बिल, और जमा प्रमाणपत्र (सीडी) पर ब्याज दरें भी कम और सीमाबद्ध रहीं।

7 अप्रैल 2021 के मेरे वक्तव्य में, मैंने संकेत दिया था कि जी-एसएपी के अलावा, रिज़र्व बैंक विशेष ओएमओ सहित

एलएएफ, दीर्घावधि रेपो/प्रतिवर्ती रेपो नीलामियों, विदेशी मुद्रा परिचालन और खुले बाजार परिचालन के तहत नियमित परिचालन को जारी रखेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चलनिधि की स्थिति मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप विकसित होती है और वित्तीय स्थिति सभी हितधारकों के लिए सहायक बनी रहती है। चालू वर्ष के दौरान अब तक, रिज़र्व बैंक ने अब तक नियमित ओएमओ किए हैं और जी-एसएपी 1.0 के तहत ₹60,000 करोड़ के अलावा ₹36,545 करोड़ (31 मई तक) की अतिरिक्त चलनिधि डाली है। प्रतिफल वक्र के सुचारु विकास की सुविधा के लिए 6 मई 2021 को ऑपरेशन ट्विस्ट के तहत एक खरीद और बिक्री नीलामी भी आयोजित की गई है। आगे चलकर, रिज़र्व बैंक चलनिधि प्रबंधन के लिए नियमित परिचालन करना जारी रखेगा।

इन गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, अब यह निर्णय लिया गया है कि ₹40,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के लिए जी-एसएपी 1.0 के तहत एक और परिचालन 17 जून 2021 को आयोजित किया जाएगा। इसमें से, ₹10,000 करोड़ में राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) की खरीद शामिल होंगे। बाजार को समर्थन देने के लिए 2021-22 की दूसरी तिमाही में जी-एसएपी 2.0 आरंभ करने और ₹1.20 लाख करोड़ का द्वितीयक बाजार खरीद परिचालन करने का भी निर्णय लिया गया है। जी-एसएपी 2.0 संचालन के तहत विशिष्ट तिथियों और प्रतिभूतियों को अलग से दर्शाया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि बाजार जी-एसएपी 2.0 की इस घोषणा पर उचित प्रतिक्रिया देगा।

अप्रैल-मई में छंटनी की जोखिम-मुक्त अवधि के बाद, भारत में पूंजी प्रवाह की संभावनाएं फिर से सुधर रही हैं। हालांकि ये प्रवाह बाहरी वित्तपोषण बाधाओं को कम करते हैं, चलनिधि में अवांछनीय और अनपेक्षित उतार-चढ़ाव पैदा करते हुए वे वित्तीय बाजारों और परिसंपत्ति की कीमतों में अस्थिरता भी प्रदान करते हैं, जो मौद्रिक नीति के रुख को बिगाड़ सकते हैं। इसने वित्तीय बाजार और चलनिधि स्थितियों को स्थिर करने के लिए हाजिर, वायदा और वायदा बाजारों में रिज़र्व बैंक द्वारा दो तरफा हस्तक्षेप की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है ताकि मौद्रिक नीति राष्ट्रीय उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपने घरेलू अभिविन्यास और स्वतंत्रता बनाए रखे। इस प्रकार, रिज़र्व बैंक सक्रिय रूप से

<sup>2</sup> आरक्षित नकदी निधि अनुपात में बदलाव के पहले दौर के प्रभाव के लिए समायोजित।

विदेशी मुद्रा बाजार और इसके विभिन्न खंडों में खरीद और बिक्री दोनों में शामिल है। इन प्रयासों की सफलता बाजार की स्थितियों में स्थिरता और व्यवस्था और बड़े वैश्विक स्पिलओवर के बावजूद विनिमय दर में परिलक्षित होती है। इस प्रक्रिया में, आरक्षित मुद्रा के संचय से देश के तुलन-पत्र को मजबूती मिलती है।

एक और मुद्दा जिसने अर्थशास्त्रियों, बाजार सहभागियों और विश्लेषकों के बीच व्यापक रुचि और चर्चा उत्पन्न की है, वह है हमारे आगामी मार्गदर्शन की भूमिका और प्रकृति। जैसा कि आपको विदित होगा, अप्रैल में एमपीसी ने समय-आधारित आगामी मार्गदर्शन के बजाय स्थिति-आधारित का निर्णय लिया था, यह मानते हुए कि महामारी के संदर्भ में यह पूर्णतः अनुमान लगाना मुश्किल है कि अर्थव्यवस्था कैसे विकसित होती है और कब आर्थिक सुधार मजबूती से जुड़ जाता है। इस तरह की व्यापक अनिश्चितता के बीच, रिज़र्व बैंक अपने नियंत्रण में सभी लिखतों का उपयोग करना जारी रखेगा और टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को पुनर्जीवित करने और बनाए रखने के लिए काम करेगा। यह बताने की जरूरत नहीं है, हमारे संचार की निरंतरता और विश्वसनीयता हमारे दृश्यमान कार्यों द्वारा प्रबलित होती है।

मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि महामारी से लड़ने की पूरी प्रक्रिया में, वित्तीय प्रणाली की ताकत बहुत महत्वपूर्ण है। वित्तीय संस्थाओं में ठोस कॉर्पोरेट प्रशासन के साथ पर्याप्त प्रावधानीकरण और पूंजी बफर का निर्माण, पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, इसलिए बैंकों और एनबीएफसी कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को कम करने के हमारे प्रयासों में सबसे आगे हैं। रिज़र्व बैंक एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है जिसमें वित्तीय स्थिरता को बनाए रखते हुए एक मजबूत और कुशल वित्तीय क्षेत्र फलता-फूलता है।

### अतिरिक्त उपाय

इस पृष्ठभूमि में और समष्टि आर्थिक स्थिति और वित्तीय बाजार की स्थितियों के हमारे निरंतर मूल्यांकन के आधार पर, कुछ अतिरिक्त उपायों की घोषणा की जा रही है। इन उपायों का विवरण मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य (भाग-बी) में उल्लिखित किया गया है। अतिरिक्त उपाय इस प्रकार हैं।

### संपर्क-गहन क्षेत्रों के लिए मांग पर चलनिधि विंडो

कुछ संपर्क-गहन क्षेत्रों पर महामारी की दूसरी लहर के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, रेपो दर पर तीन वर्ष तक की अवधि के साथ 31 मार्च 2022 तक ₹15,000 करोड़ की एक अलग चलनिधि विंडो खोली जा रही है। इस योजना के तहत बैंक, होटल और रेस्तरां; पर्यटन - ट्रेवल एजेंट, टूर ऑपरेटर और साहसिक कार्य/ विरासत सुविधाएं; विमानन सहायक सेवाएं - ग्राउंड हैंडलिंग और आपूर्ति श्रृंखला; और अन्य सेवाएं जिनमें निजी बस ऑपरेटर, कार मरम्मत सेवाएं, किराए पर कार सेवा प्रदाता, कार्यक्रम/सम्मेलन आयोजक, स्पा क्लीनिक और ब्यूटी पार्लर/सैलून शामिल हैं, को नए ऋण सहायता प्रदान कर सकते हैं। प्रोत्साहन के माध्यम से, बैंकों को अपनी अधिशेष चलनिधि को इस योजना के तहत बनाई गई ऋण पुस्तिका के आकार तक रिज़र्व बैंक के पास प्रतिवर्ती रेपो विंडो के तहत उस दर पर रखने की अनुमति दी जाएगी जो रेपो दर से 25 बीपीएस कम है या, एक अलग तरीके से कहा जाए तो, जो प्रतिवर्ती रेपो दर से 40 बीपीएस अधिक है।

### सिडबी को विशेष चलनिधि सुविधा

विकास आवेगों जो अभी नए हैं, को पोषित करने और वास्तविक अर्थव्यवस्था में ऋण के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 2021-22 में नए ऋण देने के लिए अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) को 7 अप्रैल 2021 को ₹50,000 करोड़ की नई सहायता दी थी। इसमें भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को ₹15,000 करोड़ शामिल हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), विशेष रूप से छोटे एमएसएमई और ऋण की कमी वाले और आकांक्षी जिलों सहित अन्य व्यवसायों की वित्त पोषण आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए नए मॉडल और संरचनाओं के माध्यम से उधार/ पुनर्वित्त के लिए सिडबी को ₹16,000 करोड़ की विशेष चलनिधि सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। यह सुविधा प्रचलित नीतिगत रेपो दर पर एक वर्ष तक की अवधि के लिए उपलब्ध होगी, जिसे इसके उपयोग के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है।

## रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत एक्सपोजर थ्रेसहोल्ड का संवर्धन

रिजर्व बैंक द्वारा 5 मई 2021 को घोषित रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 में एमएसएमई के साथ-साथ गैर-एमएसएमई छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित तनाव के समाधान और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने का प्रावधान है। रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए उधारकर्ताओं के एक बड़े समूह को सक्षम करने की दृष्टि से, एमएसएमई, गैर-एमएसएमई छोटे व्यवसाय और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को ऋण के लिए अधिकतम कुल एक्सपोजर थ्रेसहोल्ड ₹25 करोड़ से बढ़ाकर ₹50 करोड़ करके योजना के तहत उधारकर्ताओं के कवरेज का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है।

## एफपीआई की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेन के लिए मार्जिन का निर्धारण

रिजर्व बैंक भारतीय ऋण बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई उपाय कर रहा है। एफपीआई द्वारा सामना की जाने वाली परिचालन बाधाओं को कम करने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि अधिकृत डीलर बैंकों को अपने एफपीआई ग्राहकों की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों (राज्य विकास ऋण और खजाना बिल सहित) में उनके लेनदेन के लिए, बैंकों के ऋण जोखिम प्रबंधन ढांचे के भीतर मार्जिन रखने की अनुमति दी जाए।

## जमा प्रमाणपत्र जारी करने वालों द्वारा चलनिधि प्रबंधन में लचीलेपन को सुगम बनाना

दिसंबर 2020 में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को प्रतिस्पर्धी दरों पर आरआरबी द्वारा अधिक कुशल चलनिधि प्रबंधन की सुविधा के लिए रिजर्व बैंक की तरलता विंडो के साथ-साथ कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार तक पहुंचने की अनुमति दी गई थी। आरआरबी द्वारा अल्पावधि निधि जुटाने में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए, अब यह निर्णय लिया गया है कि आरआरबी को जमा प्रमाणपत्र (सीडी) जारी करने की अनुमति दी जाए। यह

भी निर्णय लिया गया है कि सीडी के सभी जारीकर्ताओं को कुछ शर्तों के अधीन परिपक्वता से पहले अपनी सीडी वापस खरीदने की अनुमति दी जाएगी। इससे चलनिधि प्रबंधन में अधिक लचीलेपन की सुविधा होगी।

## सप्ताह के सभी दिनों में राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) की उपलब्धता

एनएसीएच, एनपीसीआई द्वारा संचालित एक थोक भुगतान प्रणाली, एक-से-कई क्रेडिट ट्रांसफर जैसे लाभांश, ब्याज, वेतन, पेंशन, आदि के भुगतान के साथ-साथ बिजली, गैस, टेलीफोन, पानी, ऋण संबंधी आवधिक किश्तें, म्यूचुअल फंड में निवेश, बीमा प्रीमियम, आदि से संबंधित भुगतानों की सुविधा प्रदान करती है। एनएसीएच बड़ी संख्या में लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का एक लोकप्रिय और प्रमुख माध्यम के रूप में उभरा है। इससे वर्तमान कोविड-19 के दौरान समय पर और पारदर्शी तरीके से सरकारी सब्सिडी प्रदान करने में मदद मिली है। ग्राहक सुविधा को और बढ़ाने के लिए, और आरटीजीएस की 24x7 उपलब्धता का लाभ उठाने के लिए, एनएसीएच जो वर्तमान में बैंक के कार्य दिवसों पर उपलब्ध है, को 1 अगस्त 2021 से प्रभावी सप्ताह के सभी दिनों में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

इन सभी उपायों के लिए संबंधित निर्देश/परिपत्र अलग से जारी किए जाएंगे।

## समापन टिप्पणी

बीते वर्ष में, रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली को महामारी के कहर से बचाने में लगा हुआ है। हम निरंतर चौकसी पर रहे हैं - पहली लहर में ; लहरों के बीच की खामोशी; और अब दूसरी लहर। सभी हितधारकों के लिए वित्तीय स्थिरता और अनुकूल वित्तपोषण शर्तों को बनाए रखना एक प्रतिबद्धता है जिसका हमने दृढ़ता से पालन किया है। कोविड -19 संक्रमणों और घातक घटनाओं में अचानक वृद्धि ने नई बहाली को प्रभावित किया है, लेकिन इसे निकाल नहीं सका है। विकास के आवेग अभी भी जीवित हैं। दूसरी लहर के सामने समग्र आपूर्ति की स्थिति ने लचीलापन दिखाया है।

हम लीक से हटकर सोचना और कार्य करना जारी रखेंगे, सबसे बुरे समय के लिए योजना बना रहे हैं और सबसे अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं। आज घोषित किए गए उपायों, और अब तक उठाए गए अन्य कदमों के संयोजन के साथ, विकास प्रक्षेपवक्र को पुनः प्राप्त करने की उम्मीद है जिससे हम फिसल गए हैं। आगे देखते हुए, फार्मा उत्पादों के उत्पादन में नेतृत्व के साथ विश्व की वैक्सीन राजधानी के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए एक नीतिगत पैकेज कोविड कथा को बदल सकता है।

यह समय वर्तमान स्थिति से अभिभूत होने का नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से इससे उबरने की आवश्यकता है। अनिश्चितता और घोर निराशा के बीच दुर्लभ साहस और अदम्य भावना के कई उदाहरण हमारे देश के भविष्य में एक मजबूत विश्वास की जड़ें जमा चुके हैं। हमारे लचीलेपन, दृढ़ विश्वास और आशा को महात्मा गांधी के शब्दों में सर्वोत्तम रूप से अभिव्यक्त किया जा सकता है: "मैंने अपना आशावाद कभी नहीं खोया है। सबसे अँधेरे समय में मेरे भीतर आशा की किरण जल उठी है....."<sup>3</sup>।

धन्यवाद। सुरक्षित रहें। स्वस्थ रहें। नमस्कार।

---

<sup>3</sup> महात्मा गांधी के संकलित कार्य (सीडब्ल्यूएमजी), खंड 66, पृष्ठ 72

# मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2021-22

मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य, 2021-22  
मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प  
जून 2-4, 2021



## मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य, 2021-22 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प\*

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (4 जून 2021) को अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिआर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर यह निर्णय लिया है कि :

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाएगा।

परिणामस्वरूप, एलएएफ़ के तहत रिवर्स रेपो दर बिना किसी परिवर्तन के 3.35 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर एवं बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर बनी हुई हैं।

- यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को बनाए रखने एवं अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने का भी निर्णय लिया।

ये निर्णय संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को +/- 2 प्रतिशत के दायरे में रखते हुए 4 प्रतिशत का मध्यावधि लक्ष्य हासिल करने के अनुरूप है।

इस निर्णय के पीछे की मुख्य सोच नीचे दिए गए विवरण में व्यक्त की गई हैं।

### आकलन

वैश्विक अर्थव्यवस्था

2. अप्रैल में एमपीसी की बैठक के बाद से, वैश्विक आर्थिक सुधार गति प्राप्त कर रहा है, जो मुख्य रूप से प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) से प्रेरित और बड़े पैमाने पर टीकाकरण कार्यक्रमों और प्रोत्साहन पैकेजों द्वारा संचालित है। वायरस के

संक्रामक उत्परिवर्ती और टीकाकरण में अपेक्षाकृत धीमी प्रगति के कारण संक्रमण की नई लहरों से नकारात्मक जोखिम के कारण प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में गतिविधि असमान बनी हुई है। विश्व वाणिज्य व्यापार में सुधार जारी है क्योंकि बाहरी मांग फिर से शुरू हो गई है, हालांकि उच्च माल ढुलाई दरें और कंटेनर अव्यवस्थाएं बाधाओं के रूप में उभर रही हैं। अधिकांश ईई में सीपीआई मुद्रास्फीति मजबूत हो रही है, जो रुकी हुई मांग में सुधार होने, उच्च इनपुट कीमतों और प्रतिकूल आधार प्रभावों से प्रेरित है। प्रमुख ईएमई में मुद्रास्फीति हाल के महीनों में आम तौर पर आधिकारिक लक्ष्यों के करीब या उससे अधिक रही है, जो वैश्विक खाद्य और पण्य वस्तुओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि के कारण बढ़ी है। वैश्विक वित्तीय स्थिति सौम्य बनी हुई है।

घरेलू अर्थव्यवस्था

3. आर्थिक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हुए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 31 मई 2021 को जारी राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान में चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 1.6 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष (वर्ष-दर-वर्ष) के साथ 2020-21 के लिए भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को 7.3 प्रतिशत के संकुचन पर रखा है। 1 जून को, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सामान्य दक्षिण-पश्चिम मानसून की भविष्यवाणी की है, जिसमें दीर्घावधि औसत (एलपीए) के 101 प्रतिशत वर्षा होने की संभावना जताई गई है। यह कृषि के लिए शुभ संकेत है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण में वृद्धि के साथ, ग्रामीण मांग के संकेतक – ट्रैक्टर बिक्री और दोपहिया बिक्री – ने अप्रैल के दौरान क्रमिक गिरावट दर्ज की।

4. मार्च 2021 में औद्योगिक उत्पादन में व्यापक सुधार दर्ज किया गया। खनन और बिजली उत्पादन मार्च 2019 (महामारी से पहले) के स्तर को पार कर गया, लेकिन विनिर्माण में तेजी नहीं आई। कमजोर आधार के कारण अप्रैल 2021 में कोर उद्योगों के उत्पादन में वर्ष-दर-वर्ष दो अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि अप्रैल 2021 के दौरान जीएसटी संग्रह अपने उच्चतम स्तर पर था, मई में मॉडरेशन के संकेत हैं जैसा कि न्यून ई-वे बिल उत्पादन में परिलक्षित होता है। अन्य उच्च आवृत्ति संकेतक - बिजली

\* 04 जून 2021 को जारी किया गया।

उत्पादन; रेलवे माल यातायात; बंदरगाह कार्गो; स्टील की खपत; सीमेंट उत्पादन; और टोल संग्रह – में अप्रैल-मई 2021 के दौरान क्रमिक मॉडरेशन दर्ज किया गया, जो विशिष्ट गतिविधियों के लिए छूट के साथ राज्यों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और स्थानीयकृत लॉकडाउन के प्रभाव को दर्शाता है। उत्पादन और नए आदेशों में कमी के कारण अप्रैल में 55.5 से 50.8 तक मोडरेट होने के बावजूद विनिर्माण क्रय प्रबंधन सूचकांक (पीएमआई) मई में बढ़ी हुई रही। सेवा पीएमआई, जो अप्रैल में 54.0 था, सात महीनों के निरंतर बढ़ोत्तरी के बाद मई में संकुचित (46.4) हो गया।

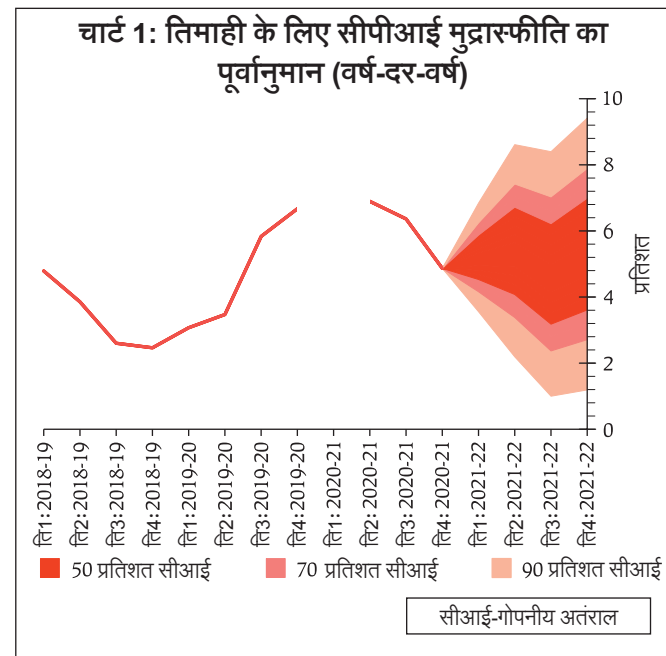
5. मुख्य रूप से अनुकूल आधार प्रभावों पर हेडलाइन मुद्रास्फीति मार्च में 5.5 प्रतिशत से कम होकर अप्रैल में 4.3 प्रतिशत दर्ज की गई। खाद्य मुद्रास्फीति अप्रैल में गिरकर 2.7 प्रतिशत पर आ गई, जो मार्च में 5.2 प्रतिशत थी, अनाज, सब्जियों और चीनी की कीमतों में वर्ष-दर-वर्ष गिरावट जारी रही। जबकि ईंधन मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई, कोर (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) मुद्रास्फीति मुख्य रूप से आधार प्रभावों के कारण, आवास और स्वास्थ्य को छोड़कर अधिकांश उप-समूहों में अप्रैल में मंद हुई। परिवहन और संचार में मुद्रास्फीति दोहरे अंकों में रही।

6. अप्रैल और मई 2021 में प्रणालीगत चलनिधि बड़े अधिशेष में रही, जिसमें चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत औसत दैनिक निवल अवशोषण ₹5.2 लाख करोड़ था। आरक्षित मुद्रा (नकदी आरक्षित अनुपात में बदलाव के पहले दौर के प्रभाव के लिए समायोजित) में 28 मई 2021 को मुद्रा की मांग के कारण 12.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) का विस्तार हुआ। 21 मई 2021 को मुद्रा आपूर्ति (एम3) और बैंक ऋण में क्रमशः 9.9 प्रतिशत और 6.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एक वर्ष पहले यह क्रमशः 11.7 प्रतिशत और 6.2 प्रतिशत थी। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2021-22 में (28 मई तक) 21.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 598.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

### संभावनाएं

7. आगे बढ़ते हुए, मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र के ऊपर और नीचे की ओर आने वाली अनिश्चितताओं से आकार लेने की संभावना है। अंतरराष्ट्रीय पण्यों की कीमतों में वृद्धि, विशेष रूप से कच्चा तेल,

रसद लागत के साथ, मुद्रास्फीति की संभावनाओं के लिए उल्टा जोखिम पैदा करती है। केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए उत्पाद शुल्क, उपकरण और करों को पेट्रोल और डीजल की कीमतों से उत्पन्न होने वाले इनपुट लागत दबावों को नियंत्रित करने के लिए समन्वित तरीके से समायोजित करने की आवश्यकता है। एक सामान्य दक्षिण-पश्चिम मानसून के साथ आरामदायक बफर स्टॉक से अनाज की कीमतों के दबाव को नियंत्रण में रखने में मदद मिलेगी। हाल ही में आपूर्ति पक्ष के हस्तक्षेप से दलहन बाजार में तंगी को कम करने की उम्मीद है। दालों और खाद्य तेल की कीमतों पर दबाव कम करने के लिए आपूर्ति पक्ष के और उपायों की जरूरत है। घटते संक्रमण के साथ, राज्यों में प्रतिबंध और स्थानीयकृत लॉकडाउन धीरे-धीरे कम हो सकते हैं और लागत दबाव को कम करते हुए आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान को कम कर सकते हैं। कमजोर मांग की स्थिति भी पास-श्रु कोर मुद्रास्फीति को प्रभावित कर सकती है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, व्यापक रूप से संतुलित जोखिमों के साथ, सीपीआई मुद्रास्फीति 2021-22 के दौरान 5.1 प्रतिशत: पहली तिमाही में 5.2 प्रतिशत; दूसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत; तीसरी तिमाही में 4.7 प्रतिशत; और चौथी तिमाही: 2021-22 में 5.3 प्रतिशत अनुमानित है (चार्ट 1)।

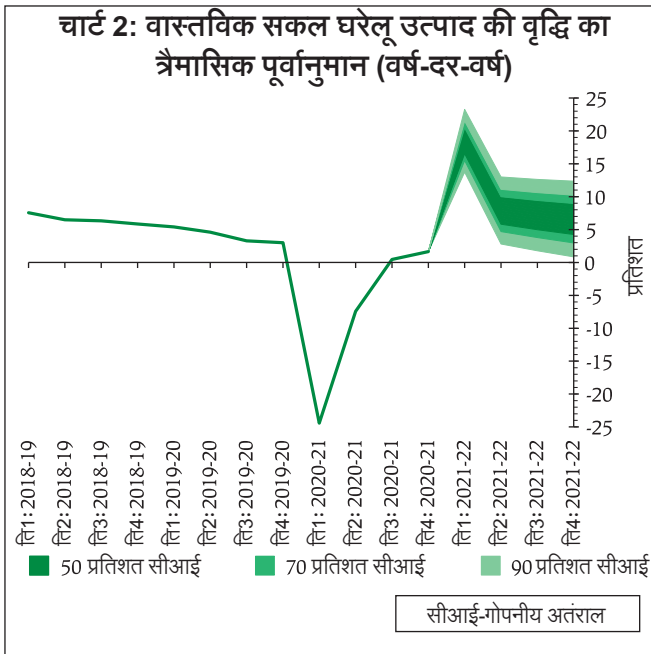




8. विकास की संभावनाओं की बात करें तो, ग्रामीण मांग मजबूत बनी हुई है और अपेक्षित सामान्य मानसून आगे चलकर अपनी उछाल को बनाए रखने के लिए सही है। हालाँकि, ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 संक्रमणों का बढ़ता प्रसार नकारात्मक जोखिम पैदा करता है। दूसरी लहर से शहरी मांग में कमी आई है, लेकिन एक उपयुक्त कार्य वातावरण के लिए व्यवसायों द्वारा नए कोविड-संगत व्यावसायिक मॉडल को अपनाने से आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ सकता है, विशेष रूप से विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में जो गहन संपर्क वाले नहीं हैं। दूसरी ओर, मजबूत वैश्विक सुधार को निर्यात क्षेत्र का समर्थन करना चाहिए। घरेलू मौद्रिक और वित्तीय स्थितियां आर्थिक गतिविधियों के लिए अत्यधिक अनुकूल और सहायक बनी हुई हैं। इसके अलावा, आने वाले महीनों में टीकाकरण प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है और इससे आर्थिक गतिविधियों को जल्दी से सामान्य करने में मदद मिलेगी। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अब 2021-22 में 9.5 प्रतिशत होने का अनुमान है, जिसमें पहली तिमाही में 18.5 प्रतिशत; दूसरी तिमाही में 7.9 प्रतिशत; तीसरी तिमाही में

7.2 प्रतिशत; और चौथी तिमाही: 2021-22 में 6.6 प्रतिशत शामिल है (चार्ट 2)।

9. एमपीसी नोट करता है कि कोविड-19 की दूसरी लहर ने निकट अवधि की संभावनाओं को बदल दिया है, जिससे तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप, सक्रिय निगरानी और समय पर उपाय करने की आवश्यकता है ताकि आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं के उभरने और खुदरा मार्जिन के निर्माण को रोका जा सके। टीकाकरण अभियान की तेज गति और शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में तेजी से सुधार जीवन और आजीविका को संरक्षित करने और संक्रमण की नई लहरों में पुनरुत्थान को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। इस समय, सभी ओर से नीतिगत समर्थन - वित्तीय, मौद्रिक और क्षेत्रीय - सुधार को बढ़ावा देने और सामान्य स्थिति में वापसी में तेजी लाने की आवश्यकता है। तदनुसार, एमपीसी ने मौजूदा रेपो दर को 4 प्रतिशत पर बनाए रखने और यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को बनाए रखने एवं अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने का निर्णय लिया।



10. एमपीसी के सभी सदस्य – डॉ. शंशाक भिडे, डॉ. आशिमा गोयल, प्रो. जयंत आर. वर्मा, डॉ. मृदुल के. सागर, डॉ. माइकल देबब्रत पात्र और श्री शक्तिकांत दास – ने नीति रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया। इसके अलावा, एमपीसी के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को बनाए रखने एवं अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने के लिए मतदान किया।

11. एमपीसी की बैठक का कार्यवृत्त 18 जून 2021 को प्रकाशित किया जाएगा।

12. एमपीसी की अगली बैठक 4 से 6 अगस्त 2021 के दौरान निर्धारित है।



# विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य



## विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य (i) चलनिधि प्रबंधन और लक्षित क्षेत्रों को समर्थन; (ii) विनियमन और पर्यवेक्षण; (iii) वित्तीय बाजार; और (iv) भुगतान प्रणाली पर विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपायों को निर्धारित करता है।

### I. चलनिधि उपाय

#### 1. संपर्क-गहन क्षेत्रों के लिए ऑन-टैप चलनिधि विंडो

5 मई 2021 को, देश में कोविड से संबंधित स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा और सेवाओं में सुधार के लिए तत्काल चलनिधि के प्रावधान को बढ़ावा देने के लिए 31 मार्च 2022 तक रेपो दर पर तीन वर्ष तक की अवधि के साथ ₹50,000 करोड़ की ऑन-टैप चलनिधि विंडो प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। अब 31 मार्च 2022 तक रेपो दर पर तीन वर्ष तक की अवधि के साथ ₹15,000 करोड़ की एक अलग चलनिधि विंडो, कुछ संपर्क-गहन क्षेत्रों अर्थात् होटल और रेस्तरां; पर्यटन - ट्रेवल एजेंट, टूर ऑपरेटर और साहसिक कार्य/ विरासत सुविधाएं; विमानन सहायक सेवाएं - ग्राउंड हैंडलिंग और आपूर्ति श्रृंखला; और अन्य सेवाएं जिनमें निजी बस ऑपरेटर, कार मरम्मत सेवाएं, किराए पर कार सेवा प्रदाता, कार्यक्रम/सम्मेलन आयोजक, स्पा क्लीनिक और ब्यूटी पार्लर/सैलून शामिल हैं, के लिए प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। बैंकों से योजना के तहत एक कोविड ऋण बही बनाने की उम्मीद की जाती है। प्रोत्साहन के माध्यम से, ऐसे बैंकों को अपनी अधिशेष चलनिधि को इस योजना के तहत बनाई गई ऋण पुस्तिका के आकार तक रिजर्व बैंक के पास प्रतिवर्ती रेपो विंडो के तहत उस दर पर रखने की अनुमति दी जाएगी जो रेपो दर से 25 बीपीएस कम है या, एक अलग तरीके से कहा जाए तो, जो प्रतिवर्ती रेपो दर से 40 बीपीएस अधिक है। इस योजना के तहत भारतीय रिजर्व बैंक से निधि प्राप्त किए बिना उपर्युक्त निर्दिष्ट क्षेत्रों को अपने स्वयं के संसाधनों से उधार देने के इच्छुक बैंक भी इस प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे।

#### 2. सिडबी को विशेष चलनिधि सुविधा

अर्थव्यवस्था के अपरिपक्व संवृद्धि आवेगों को पोषित करने के लिए, रिजर्व बैंक ने 7 अप्रैल 2021 को अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) को 2021-22 में नए ऋण देने के लिए ₹50,000 करोड़ का नया समर्थन दिया। इसमें, नाबार्ड को कृषि और संबद्ध गतिविधियों, ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों- सूक्ष्म वित्तीय फाइनेंस संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) को सहायता प्रदान करने के लिए ₹25,000 करोड़ की एक विशेष चलनिधि सुविधा (एसएलएफ), आवास क्षेत्र को संबल प्रदान करने के लिए एनएचबी को ₹10,000 करोड़ का एसएलएफ और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सिडबी को ₹15,000 करोड़ शामिल हैं। छोटे एमएसएमई और व्यवसायों जो ऋण की कमी और आकांक्षी जिलों में हैं, पर अतिरिक्त ध्यान देने के साथ एमएसएमई के लघु और मध्यम अवधि की ऋण जरूरतों के निवेश चक्र शुरू करने के लिए सिडबी को ₹16,000 करोड़ की एक और विशेष चलनिधि सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस सुविधा को डबल इंटरमीडिएशन, पूल्ड बॉन्ड/ऋण जारी करने इत्यादि सहित नए मॉडल और संरचनाओं के माध्यम से उधार / पुनर्वित्त के लिए बढ़ाया जाएगा। यह सुविधा प्रचलित पॉलिसी रेपो दर पर एक वर्ष तक की अवधि के लिए उपलब्ध होगी। रिजर्व बैंक इसके उपयोग के आधार पर सुविधा के और विस्तार पर विचार कर सकता है।

### II. विनियमन और पर्यवेक्षण

#### 3. समाधान ढांचा 2.0 के तहत एक्सपोजर सीमा का संवर्धन

5 मई 2021 को रिजर्व बैंक द्वारा घोषित समाधान ढांचा 2.0 में एमएसएमई के साथ-साथ गैर-एमएसएमई छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित तनाव और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को ऋण के समाधान पर विचार करने के लिए ₹25 करोड़ का अधिकतम कुल एक्सपोजर निर्धारित किया गया। समीक्षा के आधार पर, उपरोक्त एक्सपोजर सीमा को बढ़ाकर ₹50 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, उधारकर्ताओं की उपरोक्त श्रेणियां, जिनके लिए ऋण देने वाली संस्थाओं का 31

मार्च 2021 तक कुल ₹50 करोड़ से अधिक का एक्सपोजर नहीं है, और जिन्हें पहले किसी भी निर्दिष्ट पुनर्गठन ढांचे के तहत पुनर्गठित नहीं किया गया है, समाधान ढांचा 2.0 के तहत समाधान के लिए विचार करने हेतु पात्र होंगे। अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

### III. वित्तीय बाजार

#### 4. एफपीआई की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेन के लिए मार्जिन का निर्धारण

भारतीय ऋण बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए रिज़र्व बैंक कई उपाय कर रहा है जैसे कि निवेश के लिए नए चैनलों की शुरुआत, अनिवासियों द्वारा निवेश के लिए परिचालन ढांचे की आवधिक समीक्षा। एफपीआई द्वारा सामना की जाने वाली परिचालनगत बाधाओं को कम करने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि अधिकृत डीलर बैंकों को, बैंकों के ऋण जोखिम प्रबंधन ढांचे के भीतर अपने एफपीआई ग्राहकों की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों (राज्य विकास ऋण और खजाना बिल सहित) में उनके लेनदेन के लिए मार्जिन निर्धारित करने की अनुमति दी जाए।

#### 5. जमा प्रमाणपत्र जारी करने वालों द्वारा चलनिधि प्रबंधन में लचीलेपन को सुगम बनाना

दिसंबर 2020 में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को प्रतिस्पर्धी दरों पर आरआरबी द्वारा अधिक कुशल चलनिधि प्रबंधन की सुविधा के लिए रिज़र्व बैंक की चलनिधि विंडो के साथ-साथ मांग/सूचना मुद्रा बाजार तक पहुंचने की अनुमति दी

गई थी। आरआरबी द्वारा अल्पावधि निधि जुटाने में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए, अब यह निर्णय लिया गया है कि आरआरबी को पात्र निवेशकों को जमा प्रमाणपत्र (सीडी) जारी करने की अनुमति दी जाए। जारीकर्ताओं को चलनिधि प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से, यह भी निर्णय लिया गया है कि सीडी के सभी जारीकर्ताओं को कुछ शर्तों के अधीन परिपक्वता से पहले अपनी सीडी वापस खरीदने की अनुमति दी जाएगी।

### IV. भुगतान प्रणाली

#### 6. समाह के सभी दिनों में राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) की उपलब्धता

एनएसीएच, एनपीसीआई द्वारा संचालित एक थोक भुगतान प्रणाली, लाभांश, ब्याज, वेतन, पेंशन के भुगतान के साथ-साथ बिजली, गैस, टेलीफोन, पानी, ऋण के लिए आवधिक किस्तों से संबंधित भुगतानों, म्यूचुअल फंड में निवेश, बीमा प्रीमियम आदि के संग्रह जैसे एक-से-कई क्रेडिट अंतरण की सुविधा प्रदान करती है। एनएसीएच बड़ी संख्या में लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के एक लोकप्रिय और प्रमुख डिजिटल माध्यम के रूप में उभरा है। इससे वर्तमान कोविड-19 के दौरान समय पर और पारदर्शी तरीके से सरकारी सब्सिडी के अंतरण में मदद मिली है। एनएसीएच, वर्तमान में केवल उन दिनों में उपलब्ध है जब बैंक कार्य करते हैं। ग्राहक सुविधा के हित में, और वर्ष के सभी दिनों में आरटीजीएस की उपलब्धता का लाभ उठाने के लिए, 1 अगस्त 2021 से पूरे वर्ष के सभी दिनों में एनएसीएच उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

# आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति

भारत के राष्ट्रिक प्रतिफल वक्र के आकार का एक समष्टि-  
आर्थिक दृष्टिकोण

भारत में राजकोषीय फ्रेमवर्क और व्यय की गुणवत्ता





## अर्थव्यवस्था की स्थिति\*

महामारी की दूसरी लहर के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का संघर्ष जारी है, अपितु एक सतर्क आशावाद लौट रहा है। वर्तमान आकलन के अनुसार, दूसरी लहर का प्रहार मुख्यतः घरेलू मांग पर रहा है। इसके बेहतर पक्ष की बात करें तो, कुल आपूर्ति की स्थिति के कई पक्ष -कृषि और सपर्शरहित सेवाएं टिकी हुई हैं जबकि महामारी के इन्हीं प्रोटोकॉल के बीच औद्योगिक उत्पादन और निर्यात बढ़े हैं। आगे चलकर, स्थिति में सुधार टीकाकरण की गति और पैमाने पर निर्भर होगा। अर्थव्यवस्था में वह सुदृढ़ता और आधारभूत तत्व हैं जिससे महामारी से वापसी कर सकती है और पहले से मौजूद चक्रीय और संरचनात्मक बाधाओं की बेड़ियों से स्वयं को मुक्त कर सकती है।

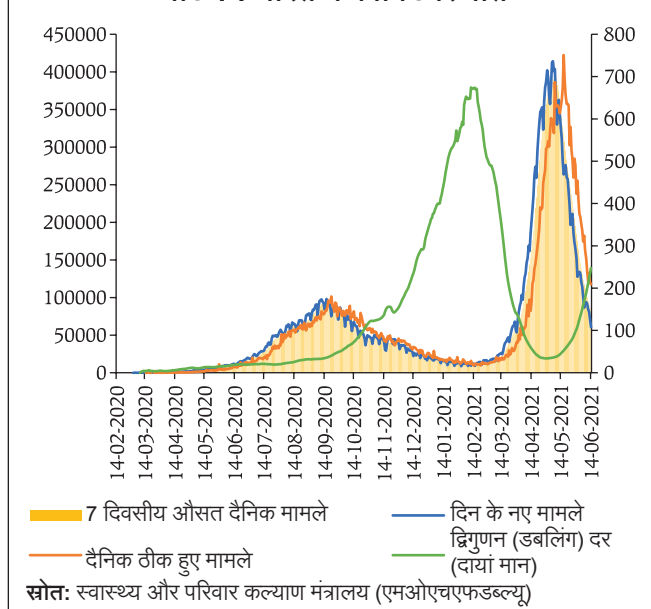
महामारी की दूसरी लहर के कम होने के संकेत तो साफ हैं पर इनको लेकर एक सावधानी भी बरती जा रही है। वास्तव में, आँकड़े बता रहे हैं कि दूसरी लहर लगभग उसी तेजी से वापस जा रही है जिस तेजी से आई थी। 14 जून, 2021 को भारत के दैनिक मामले एक महीने पहले (6 मई) के 4,14,188 के अपने शीर्ष (पीक) के सातवें हिस्से पर आ गए। दैनिक उतार-चढ़ाव को एक तल पर लाने वाला सात-दिवसीय औसत भी लगभग 4 लाख के अपने शीर्ष के पांचवें हिस्से तक घट गया। द्विगुणन दर<sup>1</sup> में भी यह दिखता है जो अप्रैल के अंत के 34 दिनों के अपने गर्त से बढ़कर 247 दिन हो गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट<sup>2</sup>, जो मई की शुरुआत में 22.7 प्रतिशत पर पहुँच गई थी, गिरकर 3.8 प्रतिशत हो गई और लगातार 14वें दिन 10 प्रतिशत से नीचे रही और अगस्त 2020 के अंत में पहली लहर के 11.7 प्रतिशत के पीक से भी कम रही। 36वें दिन ठीक होने वालों की संख्या नए मामलों से अधिक

\* यह लेख माइकल देब्रत पात्र, जीबिन जोस, कुणाल प्रियदर्शी, शशिधर एम. लोकेरे, राजीव जैन, विनीत कुमार श्रीवास्तव, अभिलाषा, कृष्ण मोहन कुशवाहा, मधुरेश कुमार, आनंद प्रकाश एक्का, अभिनंदन बोराड, जितेंद्र सोकल, मनु शर्मा, शोभित गोयल, ऋषभ कुमार, रिग्जेन यांगडोल, सक्षम सूद, राहुल अग्रवाल, अवनीश कुमार, राजस सरॉय, रमेश कुमार, आशीष थॉमस जॉर्ज, देबा प्रसाद रथ और समीर रंजन बेहरा। इस लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों।

<sup>1</sup> द्विगुणन दर को  $\ln 2/\ln(1+r)$  के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां  $r$  संचयी मामलों में पिछले सात दिनों की वृद्धि का औसत है। यह बताता है कि कितने दिनों में मामलों की संचयी संख्या दोगुनी हो जाती है।

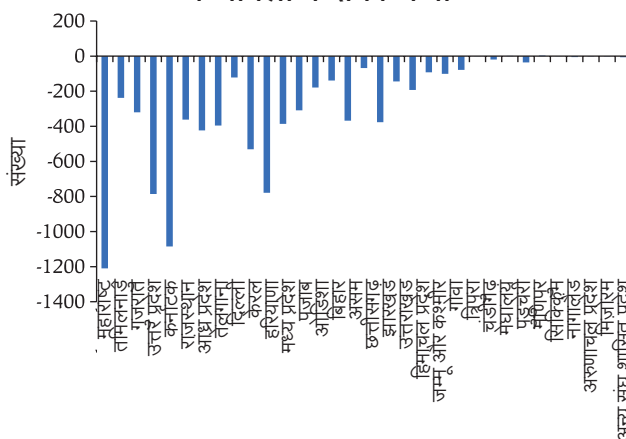
<sup>2</sup> परीक्षणों की कुल संख्या में से पॉजिटिव पाए जाने वाले मामलों की संख्या।

चार्ट 1 : भारत में कोविड स्थिति



रही और इस प्रकार ठीक होने वालों की कुल संख्या भारत में 2.8 करोड़ से अधिक हो गई। यह संयोगात्मक संरचना उन 12 में से 7 राज्यों भी है, जो दूसरी लहर के प्रकोप<sup>3</sup> में राष्ट्रीय संक्रमण सारणी में आगे थे (चार्ट 2)। राज्यों द्वारा अपनी रिपोर्टिंग में सुधार के साथ मृत्यु की संख्याओं में संशोधन हो रहा है, लेकिन संक्रमण की तुलना में इनकी कमी की धीमी गति राष्ट्र को चिंतित किए हुए हैं।

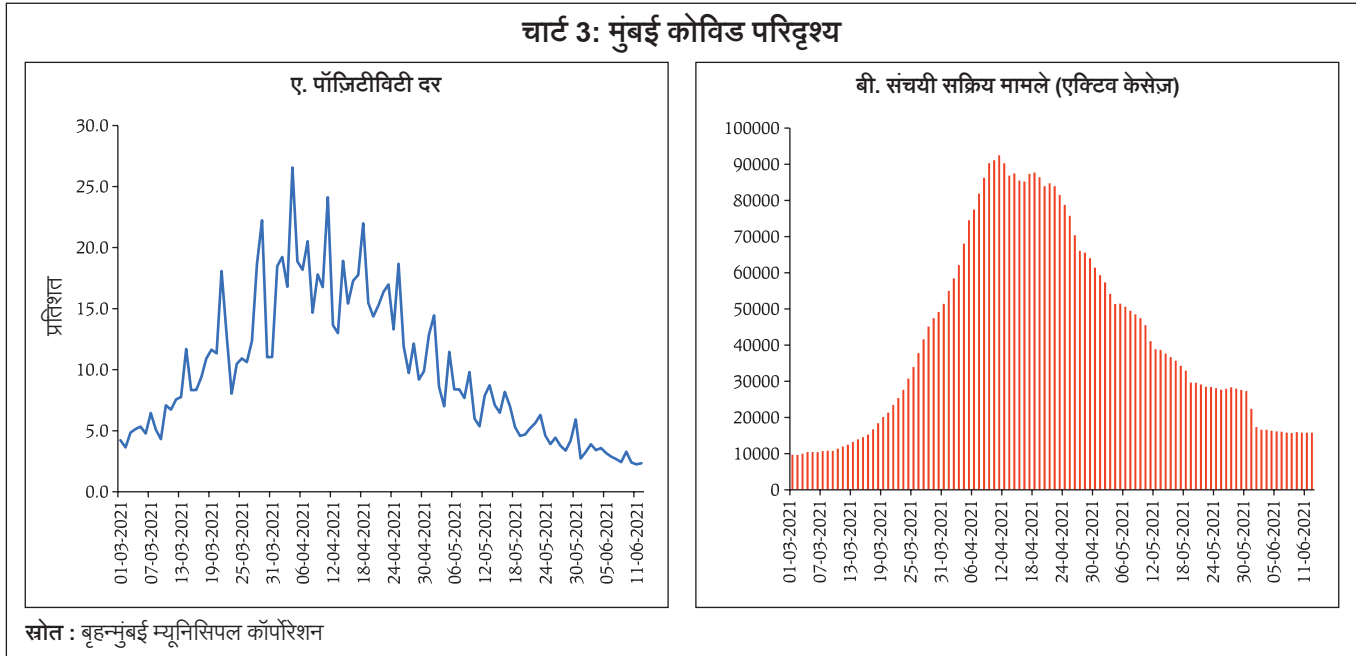
चार्ट 2: चरम (पीक) के बाद राज्यों में कोविड -19 के मामलों में दैनिक कमी



नोट: वाई-अक्ष पर की संख्या चरम (पीक) (6 मई 2021) के बाद से 13 जून, 2021 तक दैनिक औसत गिरावट बताती है। राज्यों को जीडीपी में उनके हिस्से के क्रम में रखा गया है।

स्रोत: सीडीआईसी; और लेखकों की गणनाएं।

<sup>3</sup> अधिक बोलने वाले राज्य जहाँ पीक के दौरान एक लाख से अधिक सक्रिय मामले रहे



भारत की वित्तीय राजधानी और सबसे घनी आबादी वाले शहर मुंबई, पर महामारी की दोनों लहरों की चोट पड़ी और वस्तुतः, हर लहर की शुरुआत यहीं से हुई है। लेकिन इस बार, इस शहर ने कुछ और किया और कोविड प्रबंधन<sup>4</sup> (चार्ट 3) के एक उदाहरण के रूप में सामने आया। यह पांच स्तंभों पर आधारित है: एम्बुलेंस, डॉक्टरों, टेलीफोन ऑपरेटरों और बुनियादी ढांचे से लैस वार्ड-स्तरीय कोविड कमांड पोस्ट - आपदा नियंत्रण कक्ष, पहली लहर में स्थापित एकमात्र यूनिट को इन 24 कमांड पोस्टों में विकेंद्रीकृत किया गया है; संपर्क पहचान (कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग) और घरों पर पहुँचाई गई चिकित्सा सहायता; अतिरिक्त चिकित्सा क्षमता बरकरार रखते हुए एकीकृत अस्पताल बिस्तर प्रबंधन; भंडारण आधार-संरचना के निर्माण, सिलेंडर रीफिलिंग और अस्पताल में ऑक्सीजन के उपयोग की निगरानी द्वारा ऑक्सीजन प्रबंधन; और डेटा आधारित निर्णय।

फिर भी, जो पहले सचेत वो पहले तैयार। गणितीय और महामारी विज्ञान मॉडल में ऐतिहासिक डेटा के आधार पर, वैज्ञानिक और विषाणु-विज्ञानी (वायरोलॉजिस्ट) तीसरी लहर की भविष्यवाणियों पर बहस कर रहे हैं, जिससे आकस्मिकता योजना में एक युद्ध-कक्ष की अत्यावश्यकता जुड़ जाती है। भारत में पाई गई एक किस्म जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा,

'डेल्टा' कहा गया है और जो वैज्ञानिक नाम बी.1.617.2 से जाना जाता है, को अत्यधिक तेजी से फैलने वाला माना जा रहा है और इसे चिंताजनक किस्म (वैरिएंट ऑफ़ कन्सर्न/वीओसी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए, सावधानी में कमी का कोई सवाल ही नहीं है। भारत को एक और लहर का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सामाजिक दूरी, मास्कंग, स्वास्थ्य की आधार-संरचना में सुधार और सबसे महत्वपूर्ण टीकाकरण के साथ इससे पार पाया जा सकता है। टीकाकरण के संदर्भ में, आगे की राह पर भविष्यदर्शी मार्गदर्शन घिरते अंधेरों के बीच रोशनी दिखाता है। वित्त मंत्रालय का अनुमान है कि सामूहिक रोग प्रतिरोधक शक्ति हासिल करने और आर्थिक सुधार की गति को फिर से हासिल करने के लिए सितंबर 2021 तक टीकाकरण की जाने वाली लक्ष्य जनसंख्या 70 करोड़ है और लगभग 113 करोड़ और खुराक की आवश्यकता है; तदनुसार, सामूहिक रोग प्रतिरोधक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रति दिन लगभग 93 लाख टीकाकरण की आवश्यकता है। जबकि अब तक की अधिकतम दैनिक टीकाकरण दर 42.65 लाख है, "शिफ्ट को डबल करना और संभवतः कुछ महीनों के लिए 24x7 टीकाकरण करना एक दिन में 1 करोड़ शॉट्स की महत्वाकांक्षी, मगर मुमकिन संख्या में सहायक हो सकता है। (भारत सरकार, मई 2021<sup>5</sup>)।" वैश्विक स्तर पर,

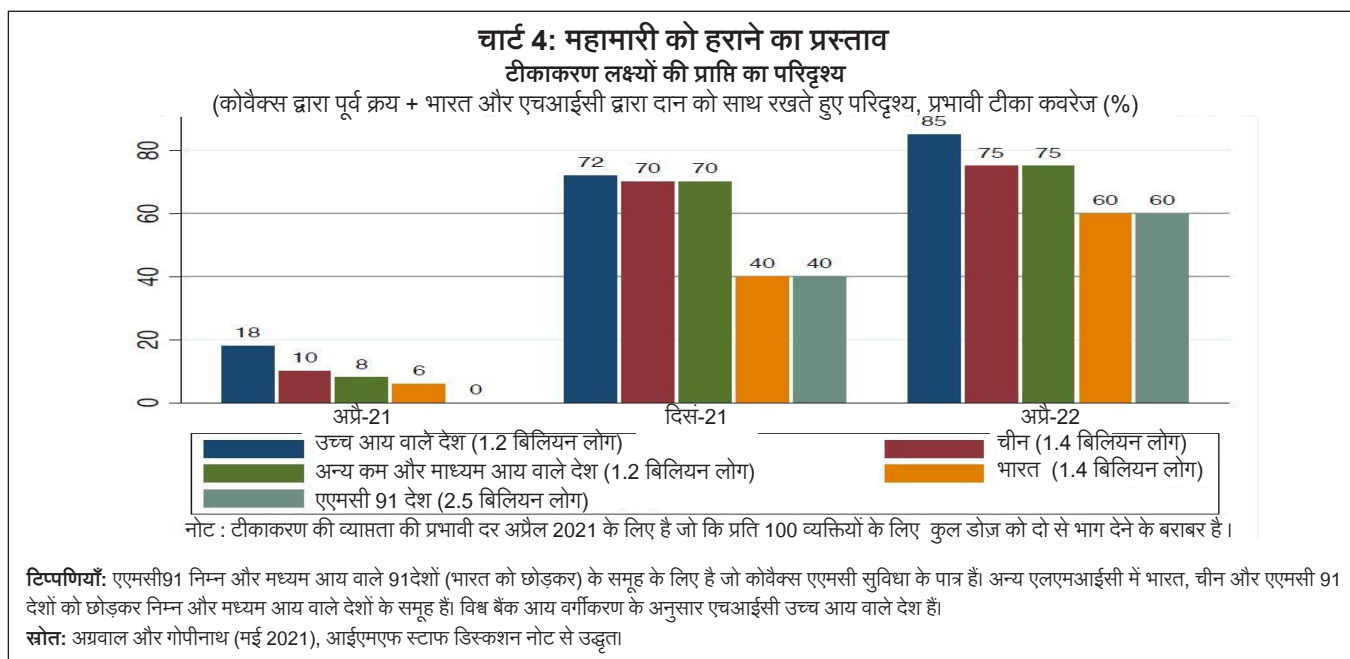
<sup>4</sup> 5 मई को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ और श्री एम.आर. शाह ने कहा, "बीएमसी [बृहन्मुंबई नगर निगम] कुछ अच्छे काम कर रहा है ... [अन्य नागरिक प्राधिकरण] उनसे सीख सकते हैं।"

<sup>5</sup> मासिक आर्थिक समीक्षा (मई 2020), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने महामारी को परास्त करने का एक प्रस्ताव तैयार किया है: (1) 2021 के अंत तक सभी देशों में कम से कम 40 प्रतिशत आबादी का टीकाकरण और 2022 की पहली छमाही तक कम से कम 60 प्रतिशत का; (2) अधोमुखी जोखिमों का पता लगाना और इनके परिणामों से सुरक्षा व्यवस्था; और (3) व्यापक परीक्षण और अनुरेखण सुनिश्चित करना, चिकित्सा व्यवस्थाओं का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखना और उन जगहों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को लागू करना जहाँ टीका कवरेज कम है (चार्ट 4)। इस तरह के उपायों से होने वाला लगभग 9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लाभ लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत से अधिक है - जिसमें से 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर तो दाताओं से अनुदान के तौर पर मिल जाना चाहिए और शेष द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों से संभावित रियायती वित्तपोषण की सहायता से राष्ट्रीय सरकारों द्वारा। इस रणनीति के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है ताकि विश्व हेतु अधोमुखी जोखिमों से सुरक्षा के लिए जोखिम पर निवेश, अग्रिम वित्तपोषण, और अग्रिम टीका दान सुनिश्चित किया जा सके (आईएमएफ, 2021<sup>6</sup>)। 'विश्व के टीकाकरण' का जी7 का संकल्प इन गणनाओं को बल प्रदान करता है।

31 मई को, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने 2020-21 के लिए भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को

संशोधित किया, जिससे पहले के अनुमान की तुलना में एक कम संकुचन (-7.3 प्रतिशत) सामने आया और चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2021) का बेहतर परिणाम परिवर्तन का निर्णायक कारक बना। पहली लहर के बाद उत्तरोत्तर अनलॉकिंग के साथ अवरुद्ध मांग के मुक्त होने से निजी उपभोग लगातार तीन तिमाहियों के संकुचन से उबरा। सरकारी व्यय ने लाज रख ली - बिना इसके, चौथी तिमाही में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि 1.1 प्रतिशत की गिरावट में पलट गई होती और पूरे वर्ष का संकुचन 8.5 प्रतिशत होता। सार्वजनिक व्यय का कुछ अंश स्थिर पूंजी निर्माण में भी दिखा। 2021-22 के लिए, रिज़र्व बैंक ने इस अनुमान पर 9.5 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है कि दूसरी लहर का प्रभाव उस वर्ष की पहली तिमाही में समाहित होगा जिसमें पिछले वर्ष के तीव्र संकुचन से मजबूत आधार प्रभाव सामने आएंगे। इस प्रकार वास्तविक जीडीपी पहली तिमाही में 18.5 प्रतिशत तक बढ़ सकती है और जब आधार प्रभाव धीरे-धीरे कम होने लगेंगे तो दूसरी तिमाही में धीमा पड़कर 7.9 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 7.2 प्रतिशत और वर्ष की अंतिम तिमाही में 6.6 प्रतिशत हो सकता है क्योंकि (चार्ट 5 ए)। इस प्रकार दूसरी लहर के प्रभाव से 2021-22 के उत्पादन में लगभग ₹2 लाख करोड़ के नुकसान का अनुमान है। वर्तमान आकलन के अनुसार, दूसरी लहर की मार मुख्य रूप से देशव्यापी तालाबंदी के



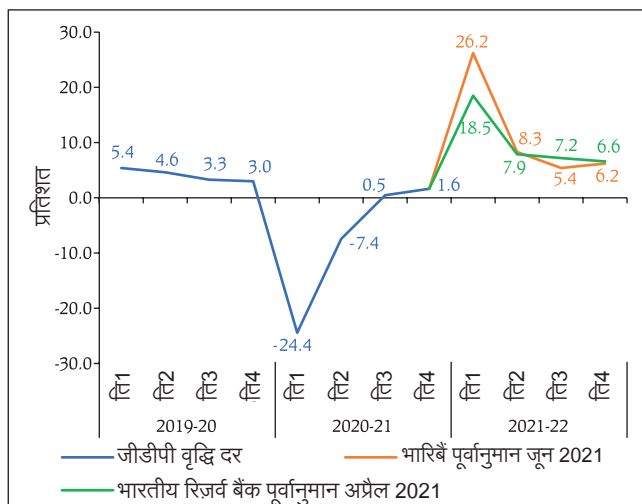
<sup>6</sup> अग्रवाल और गोपीनाथ (मई 2021), "ए प्रोजेक्ट टू एंड द कोविड-19 पैडेमिक" आईएमएफ स्टाफ डिस्कशन नोट

बजाय क्षेत्रीय और विशिष्ट क्षेत्रों में नियंत्रण के कारण घरेलू मांग को प्रभावित करने के रूप में है। इसके अलावा, छोटे शहरों और गांवों में फैलकर इस लहर ने ग्रामीण मांग को बहुत कमजोर कर दिया है। सरकारी व्यय से मिलने वाला समर्थन भी पिछले साल के असाधारण विस्तार से कम हो सकता है। उज्ज्वल पक्ष यह है कि, महामारी आचार नियमों (प्रोटोकॉल्स) के बीच समग्र आपूर्ति स्थिति के कई पहलू जैसे कृषि और स्पर्शरहित सेवाएं टिकी हुई हैं। औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में मजबूत आधार प्रभावों के कारण वृद्धि हुई है, परंतु सकारात्मक गति के साक्ष्य भी हैं। एक बार फिर दोहरा दिया जाए कि समुत्थान को आकार टीकाकारण ही देगा। अर्थव्यवस्था में वह सुदृढ़ता और आधारभूत तत्व हैं जिससे महामारी से वापसी कर सकती है और पहले से मौजूद चक्रीय और संरचनात्मक बाधाओं की बेड़ियों से स्वयं को मुक्त कर सकती है जिसके कारण उत्पादन का मार्ग 2019-20ति4 के बाद संभावित से से विचलित होकर ऋणात्मक उत्पादन अंतराल की ओर चला गया है (चार्ट 5 बी)।

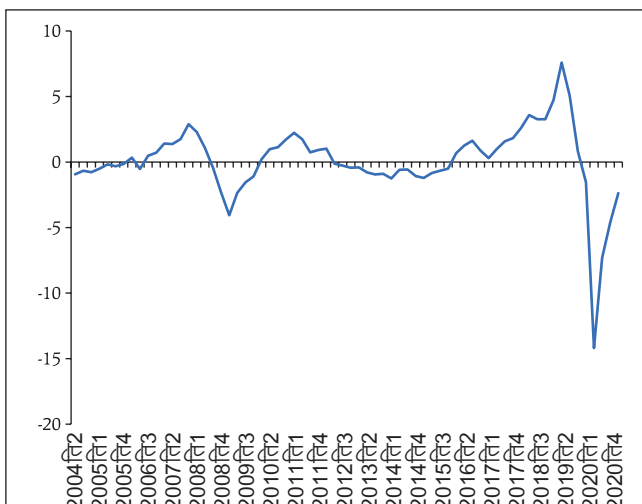
इस बीच, रिज़र्व बैंक अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय सुरक्षा जाल, जिसका उल्लेख पिछले महीने के आलेख में हुआ था, के ताने-बाने बुनने में लग गया, तथा वित्तीय स्थितियों को और सुगम बनाने के लिए विभिन्न माध्यमों से वित्त प्रवाहित करने की अपनी प्रतिबद्धता का पालन करने में जुट गया। जैसा कि गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने कहा,

“इस वित्तीय वर्ष में दूसरी लहर के तेज होने के साथ, रिज़र्व बैंक का ध्यान तेजी से प्रणालीगत चलनिधि से इसके समान वितरण की ओर बढ़ रहा है। वास्तव में, भारतीय संदर्भ में महामारी के अनुभव से स्थायी सबक अपरंपरागत मौद्रिक नीति उपायों के प्रयोग का है जो सभी हितधारकों के बीच चलनिधि वितरित करते हैं। हम महामारी के प्रभाव को कम करने और अर्थव्यवस्था को उच्च और टिकाऊ विकास के पथ पर वापस लाने के प्रयास में हम संचरण के बाजार-आधारित चैनलों पर भरोसा करते हुए अपने अग्रसक्रिय और पूर्वकृत दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। हम लीक से

चार्ट 5ए: भारतीय रिज़र्व बैंक तिमाही वृद्धि पूर्वानुमान



चार्ट 5बी: उत्पादन अंतराल (आउटपुट गैप)



नोट: उत्पादन अंतराल वास्तविक उत्पादन का अपनी दीर्घवधि प्रवृत्ति से प्रतिशत में विचलन है और इसकी गणना चार फिल्टरों (होड्रिक-प्रेसकोट, क्रिस्टियानो-फिट्जगेराल्ड, बैंड-पास और कलमैन) के औसत के रूप में की जाती है। चार्ट 5बी में एक्स (x)-अक्ष कैलेंडर वर्ष के अनुसार है।

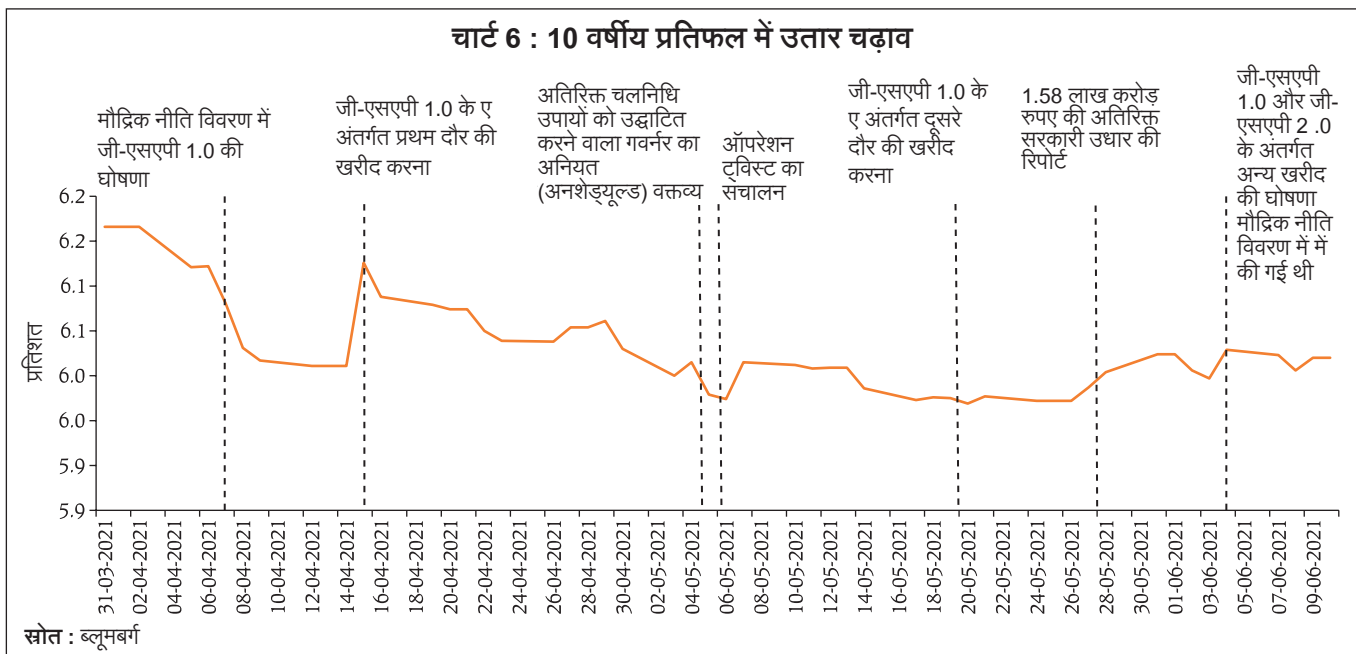
स्रोत: एनएसओ; और भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ अनुमान।

हटकर सोचना और कार्य करना, बुरे से बुरे के लिए तैयारी और अच्छे से अच्छे की उम्मीद जारी रखेंगे..... इस समय आवश्यक है कि वर्तमान स्थिति से विचलित न हो, बल्कि मिलकर इसे परास्त करें।“

नीतिगत दर को 4 प्रतिशत (मई 2020 से अपरिवर्तित) के सर्वकालिक निम्न स्तर पर बनाए रखने और जब तक आवश्यक हो तब तक एक निभावी रुख जारी रखने के मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के निर्णय के अनुसार, 4 जून को रिज़र्व बैंक ने अपने आस्ति क्रय पहल जी-एसएपी 1.0 को पूरा करने के लिए जून में एक और बड़े क्रय परिचालन की घोषणा की। ₹ 40,000 करोड़ की घोषित मात्रा में से, ₹ 10,000 करोड़ राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के लिए आरक्षित थे, ताकि तत्संबंधी केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की तुलना में उनके स्प्रेड को कम किया जा सके। बदले में यह, एसडीएल की तुलना में अत्यंत-दीर्घ (अल्ट्रा-लॉन्ग) केंद्र सरकार प्रतिभूतियों के लिए क्षुधा को बढ़ाने की दिशा में काम करेगा, और इन दीर्घ प्रतिभूतियों के प्रतिफल (यील्ड) बाइ-टू-होल्ड निवेशकों के लिए अपेक्षाकृत आकर्षक बनेंगे। 2021-22 की दूसरी तिमाही के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपये के जी-एसएपी 2.0 की भी घोषणा की गई थी, जिसका समय वर्ष के लिए नियोजित निर्गमों की मात्रा के शीर्ष पर आने के साथ था। इस पर भी जोर दिया गया था कि जी-एसएपी के अलावा अन्य खुला बाजार और

विदेशी मुद्रा परिचालन जारी रहेंगे तथा चालू वित्त वर्ष में पहले से ही 4 जून तक 37,955 करोड़ रुपये के ऐसे संचालन किए जा चुके हैं। इन कार्रवाइयों से बाजार दबावों से राहत मिलेगी, निवेशक मांग में सुधार होगा और सरकार की उधारी को न्यूनतम लागत और रोलओवर जोखिम पर बाजार में रखने में मदद मिलेगी (चार्ट 6)।

वित्तीय सुरक्षा के दायरे का और विस्तार करते हुए, रिज़र्व बैंक ने ₹15,000 करोड़ की एक लिक्विडिटी विंडो की भी घोषणा की, जो कि महामारी से प्रतिकूल रूप से प्रभावित सेवाओं जैसे कि होटल और रेस्तरां, पर्यटन, विमानन सहायक सेवाओं और अन्य संपर्क-गहन सेवाओं के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए रेपो दर पर बैंक लेंडिंग के लिए टाइप पर उपलब्ध रहेगी। प्रोत्साहन के रूप में, बैंक अपनी ऋण पुस्तिका के बराबर राशि को रिज़र्व बैंक के पास फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो के रूप में विंडो के अंतर्गत पार्क कर सकते हैं और चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत दी जाने वाली 3.35 प्रतिशत की दर के मुकाबले 3.75 प्रतिशत कमा सकते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), विशेष रूप से छोटे एमएसएमई और अन्य व्यवसायों को ऋण देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई) को पॉलिसी रेपो दर पर ₹ 16,000 करोड़ की विशेष चलनिधि सुविधा प्रदान की गई और इसमें ऋण की कमी और जरूरतमन्द जिले शामिल हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के साथ-साथ



गैर- एमएसएमई छोटे व्यवसायों और व्यक्तियों (व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए) के बीच कोविड -19 संबंधित तनाव के समाधान के लिए 5 मई, 2021 को घोषित रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के कवरेज का विस्तार करके अधिकतम कुल एक्सपोजर सीमा ₹25 करोड़ से ₹50 करोड़ तक विस्तार किया गया। इसके साथ-साथ, व्यवसाय करना और भी आसान हो गया (i) अधिकृत डीलर बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिए अपने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक ग्राहकों की ओर से मार्जिन रखने की अनुमति देना; (ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और सभी सीडी जारीकर्ता को परिपक्वता से पहले उन्हें वापस खरीदने की अनुमति देना; और (iii) नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) को सक्षम करना, एक थोक भुगतान प्रणाली जो एक-से-कई और कई-से-एक क्रेडिट हस्तांतरण और संग्रह के साथ-साथ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है, जिसे सप्ताह के सभी दिनों में उपलब्ध कराया जाना है। इस प्रकार, रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था और उसकी वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा करने, वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और सभी हितधारकों के लिए अनुकूल वित्तपोषण शर्तों (सारणी 1ए और 1बी) में लगा हुआ है।

रिजर्व बैंक ने 27 मई को वर्ष 2020-21 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की। इसके स्पष्ट और गंभीर संदेश निष्पक्ष और पेशेवर <sup>7</sup> के रूप में नीचे गए। रिजर्व बैंक के आकलन में, महामारी ने एक व्यापक-आधारित समग्र मांग आघात और एक लॉकडाउन-प्रेरित आपूर्ति आघात का एक संलयन उत्पन्न किया और कई सबक दिए। इसने हमें दिखाया कि हम कितने वैश्वीकृत हैं, न केवल वायरल संक्रमणों के प्रति अपनी भेद्यता में बल्कि टीकों के उत्पादन और साझा करने के तरीके में भी। सार्वजनिक और निजी निवेश का एक अच्छा संयोजन निवेश की ओर एक बदलाव को प्रज्वलित कर सकता है और इस तरह निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर हो सकता है। महामारी से लड़ने के लिए एक सामूहिक वैश्विक प्रयास निश्चित रूप से अलग-अलग देशों की तुलना में बेहतर परिणाम लाएगा जो अपने दम पर लड़ रहे हैं। मजबूत, सतत और समावेशी विकास का जी-20 लक्ष्य अभी भी दृष्टि में और पहुंच के भीतर हो सकता है।

<sup>7</sup> पुलाप्रे बालकृष्णन, "द इकोनॉमिक टूलकिट रिवील्ड", द हिंदू, 2 जून 2021

## सारणी 1ए: 6 फरवरी 2020 से चलनिधि उपाय (31 मार्च 2021 तक)

(₹ करोड़)

उपायों की घोषणा	घोषित राशि	प्राप्त राशि
एलटीआरओ	2,00,000	1,25,117
परिवर्तनीय दर रेपो	2,25,000	90,017
पीडी के लिए एसएलएफ	7,200	6,000*
सीआरआर कट	1,37,000	1,37,000
एमएसएफ (एसएलआर में अतिरिक्त 1% की गिरावट)	1,37,000	शून्य#
टीएलटीआरओ	1,00,000	1,00,050
टीएलटीआरओ (2.0)	50,000	12,850
शुद्ध ओएमओ खरीद	1,50,000	3,56,265
म्युचुअल फंड के लिए विशेष चलनिधि सुविधा	50,000	2,430
एआईएफआई (नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी और एकिजम बैंक) को पुनर्वित्त	75,000	48,514*
एनबीएफसी के लिए विशेष चलनिधि योजना	30,000	7,126
56-दिवसीय टर्म रेपो	1,00,000	1,000
टैप टीएलटीआरओ . पर	1,00,000	5,000
संपूर्ण	<b>13,61,200</b>	<b>8,91,369</b>
2020-21 के लिए नॉमिनल जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार	<b>6.9</b>	<b>4.5</b>

नोट: #: एमएसएफ छूट की घोषणा 27 मार्च, 2020 को की गई थी। हालाँकि, बैंकों ने इस अवधि के दौरान एमएसएफ विंडो के तहत उधार लेने के लिए एनडीटीएल के मूल रूप से अनुमत 2% से नीचे अपनी एसएलआर होल्डिंग में डिप नहीं किया है।

\*: अवधि के दौरान अधिकतम।

स्रोत: आरबीआई

वार्षिक रिपोर्ट का एक पहलू जिसपर मीडिया में काफी चर्चा की गई, वह है सरकार को हस्तांतरित अधिशेष है। मुख्य रूप से बैलेंस शीट प्रावधानों और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और अन्य निधियों पर बचत से उपजी, अधिशेष सकल घरेलू उत्पाद का

## सारणी 1बी: 2021-22 के दौरान अब तक (7 जून तक) चलनिधि उपाय

(₹ करोड़)

उपायों की घोषणा	घोषित राशि	प्राप्त राशि
जी-एसएपी+ एनडीएस-ओएम के माध्यम से नियमित ओएमओ	2,20,000	97,955*
एआईएफआई के लिए चलनिधि सुविधा	66,000	Nil
लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए विशेष दीर्घकालिक रेपो परिचालन (एसएलटीआरओ)	10,000	400
आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच के लिए टर्म लिक्विडिटी सुविधा	50,000	Nil
संपर्क-गहन क्षेत्रों के लिए ऑन-टैप चलनिधि विंडो	15,000	Nil
संपूर्ण	<b>3,61,000</b>	<b>98,355</b>
2020-21 के लिए नॉमिनल जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार	<b>1.8</b>	<b>0.5</b>

नोट: \*: 4 जून 2021 तक

स्रोत: आरबीआई

सिर्फ 0.44 प्रतिशत है (जिसे वरिष्ठता<sup>8</sup> के उपाय के रूप में लिया जाता है)। इस संदर्भ में, विकासशील देशों (फ्राई, गुडहार्ट और अल्मेडा, 1996) में केंद्रीय बैंकिंग पर व्यापक शोध के निष्कर्षों को नोट करना सार्थक है : "प्रवाह के संदर्भ में, हम केंद्रीय बैंक को सरकार के सुनहरे हंस के रूप में समझ सकते हैं। एक असम्बद्ध बैलेंस शीट के साथ:

- स्वतंत्रता की एक उचित डिग्री के साथ रूढ़िवादी मौद्रिक नीति का संचालन करने वाली फ्री-रेंज गूज , सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 से 1 प्रतिशत के मूल्य के सिग्नियोरिज के रूप में सुनहरे अंडे का उत्पादन करती है;
- बैटरी फार्म गूज जिसे विशेष रूप से अधिक अंडे देने के लिए पैदा किया गया है, मुद्रास्फीति कर के रूप में सोने के अंडे का उत्पादन कर सकता है जो सकल घरेलू उत्पाद का 5 से 10 प्रतिशत उपज देता है;
- ऐसा गूज जिसे बलपूर्वक खाना खिलाया गया हो वह सीमित अवधि के लिए अपनी अपरिहार्य मृत्यु और अर्थव्यवस्था के पतन से पहले सकल घरेलू उत्पाद के 25 प्रतिशत तक का राजस्व उत्पन्न कर सकता है।

हाल के वर्षों में केंद्रीय बैंक के सभी तीन रूपों को देखा गया है।"

केवल अधिशेष हस्तांतरण के बिंदु से, रिजर्व बैंक को 'मुक्त-रेंज' और स्वतंत्र मौद्रिक नीति का संचालन करने के रूप में वर्णित किया जा सकता है, अर्थात्, राजकोषीय प्रभुत्व से स्वतंत्र (सारणी 2)।

एक और महत्वपूर्ण मुकाम जिससे जून की शुरुआत में चुपचाप पा लिया गया था, वह था विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करना। इस विकास के साथ, भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रिजर्व होल्डिंग देश<sup>9</sup> वां, यूएस ट्रेजरी सिक्वोरिटीज का 12वां सबसे बड़ा विदेशी धारक<sup>10</sup>

<sup>8</sup> "वैध मुद्रा जारी करने वाले को होने वाला लाभ, मुख्य रूप से मुद्रा के उत्पादन की भौतिक लागत और उसके अंकित मूल्य के बीच अंतर के परिणामस्वरूप" (ए डिक्शनरी ऑफ फाइनेंस एंड बैंकिंग, ऑक्सफोर्ड रेफरेंस के अनुसार)। मौजूदा बाजार मूल्यों पर जीडीपी का अनुमान मौद्रिक नीति समिति के 2021-22 के लिए वास्तविक जीडीपी के अनुमानों के आधार पर लगाया जाता है।

<sup>9</sup> चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और रूस के बाद।

<sup>10</sup> <https://home.treasury.gov/data/treasury-international-capital-tic-system-home-page/tic-forms-instructions/securities-b-portfolio-holdings-of-us-and-foreign-securities>

## सारणी 2: केंद्रीय बैंकों से सरकारों को अधिशेष का अंतरण\*\*

(जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

देश	2020
सिंगापुर	1.13
रूस	1.00
तुर्की	0.78
इंडिया	0.29
यूएस	0.26
मलेशिया	0.25
जापान	0.23
इंडोनेशिया	0.22
कोरिया	0.19
जर्मनी	0.18
फ्रांस	0.15
ऑस्ट्रेलिया	0.13
स्वीडन	0.11
केन्या	0.07
दक्षिण अफ्रीका	0.01
यूके	0.00
मेक्सिको	0.00
देश	2021
तुर्की	0.50
इंडिया	0.44
मलेशिया	0.26
स्वीडन	0.13
केन्या	0.04
जर्मनी	0.00
मेक्सिको	0.00
चेक रिपब्लिक	0.00

\*: वार्षिक रिपोर्ट के प्रकाशन के वर्ष के आधार पर हस्तांतरित अधिशेष के अनंतिम आंकड़े चूंकि विभिन्न केंद्रीय बैंक अपने वित्तीय विवरणों के लिए अलग-अलग लेखा वर्षों का पालन करते हैं, अनुमान विश्व आर्थिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) जीडीपी संख्या पर आधारित हैं

#: रूस की सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनी स्बरबैंक के साधारण शेयरों की बिक्री से रूसी संघ के सेंट्रल बैंक द्वारा प्राप्त आय के हिस्से का स्थानांतरण।  
 स्रोत: सेंट्रल बैंक की वार्षिक रिपोर्ट; अखबार की रिपोर्ट; और डब्ल्यूईओ डेटाबेस।

वां और सोने के भंडार के मामले में 10वां सबसे बड़ा देश है। जबकि विदेशी मुद्रा भंडार अप्रत्याशित बाहरी झटकों के खिलाफ कुशन प्रदान करते हैं, स्तर अक्सर भ्रामक होते हैं, और बाहरी भेद्यता का एक बेहतर गेज विशिष्ट संकेतकों का आकलन है। 2021-22 के लिए अनुमानित आयात के संदर्भ में, भंडार का वर्तमान स्तर 15 महीने से कम समय के लिए कवर प्रदान करता है, जो कि अन्य प्रमुख आरक्षित धारकों की तुलना में कम है -

## सारणी 3: भारत के लिए बाहरी भेद्यता संकेतक

सूचक	बाहरी ऋण (अरब अमेरिकी डॉलर)	जीडीपी अनुपात के लिए बाहरी ऋण (%)	कुल ऋण के लिए आरक्षित (%)	अल्पावधि ऋण (आरएम) से कुल ऋण (%)	अल्पकालिक ऋण (आरएम) से भंडार (%)	अल्पकालिक ऋण (आरएम) के लिए आरक्षित (%)	आयात का आरक्षित कवर (महीनों में)	ऋण सेवा अनुपात (%)	शुद्ध आईआईपी/ जीडीपी अनुपात (%)
अंत-दिसंबर 2020*	563.5	21.4	104.0 (107.4)	44.8	43.1 (41.7)	232.0 (239.6)	18.6 (19.3)	9.0	-12.9

नोट: \* कोष्ठक में आंकड़े 4 जून, 2021 को विदेशी मुद्रा भंडार पर आधारित हैं।

आरएम: अवशिष्ट परिपक्वता। आईआईपी: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति।

स्रोत: आरबीआई।

स्विट्जरलैंड (39 महीने); जापान (22 महीने); रूस (20 महीने); और चीन (16 महीने) <sup>11</sup>. इसके अलावा, भारत का भंडार सकल घरेलू उत्पाद के (-) 12.9 प्रतिशत (सारणी 3) की शुद्ध अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति के साथ सह-अस्तित्व में है। ये कारक विदेशी मुद्रा भंडार पर आरक्षित पर्याप्तता के व्यावहारिक मूल्यांकन की गारंटी देते हैं, जिसमें वैश्विक अनिश्चितता की दुनिया में मूल्यांकन परिवर्तन और बाजार जोखिम के जोखिम शामिल हैं।

शेष लेख चार खंडों में संरचित है। खंड II विश्व स्तर पर वर्तमान आर्थिक विकास को संक्षेप में बताता है। घरेलू अर्थव्यवस्था में हाल ही में हुई घटनाओं को खंड III में संक्षेपित किया गया है। खंड IV वित्तीय स्थितियों की जांच करता है और अंतिम खंड लेख का समापन करता है।

## II. वैश्विक पृष्ठभूमि







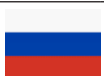



वैश्विक आर्थिक समुत्थान गति प्राप्त कर रहा है, हालांकि साथ ही साथ सुधार की बहु-गति विशेषता तीव्र होती जा रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति मिश्रित है, हम एक साल पहले की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में हैं (कार्टून, 2021), लेकिन समुत्थान असमान और अधूरा है और वास्तव में, तीन अलग-अलग समुत्थान चल रहा है - महामारी के तेजी से घटते प्रभावों के साथ अमेरिका और चीन; कुछ शुरुआती अड़चनों के बावजूद विकास की संभावनाओं वाले यूरोपीय देश 2021 के लिए अनुकूल बने हुए हैं; और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं (ईएमई) विभिन्न विकास संभावनाओं के साथ लेकिन संक्रमण में पुनरुत्थान और टीकाकरण पर धीमी प्रगति के कारण अपेक्षाकृत कम सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ।

<sup>11</sup> सीईआईसी डेटाबेस में डेटा के आधार पर तुलना।

31 मई, 2021 को जारी अपने नवीनतम आर्थिक आउटलुक में आर्थिक सहयोग संगठन और विकास (ओईसीडी) ने 2021 के लिए वैश्विक पूर्वानुमान को 5.8 प्रतिशत संशोधित किया (सारणी 4)। यह चेतावनी दी है कि विकास काफी हद तक नीति समर्थन और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों पर निर्भर करेगा। यह

## सारणी 4: 2021 के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान- ई और ईएमई का चयन

(प्रतिशत)

देश	ओईसीडी		विश्व बैंक	
	मार्च 2021	मई 2021	जन 2021	जून 2021
 विश्व*	5.6	5.8	4.3	5.7
<b>अग्रिम अर्थव्यवस्था</b>				
 यूएस	6.5	6.9	3.5	6.8
 यूके	5.1	7.2		
 यूरो क्षेत्र	3.9	4.3	3.6	4.2
 जापान	2.7	2.6	2.5	2.9
<b>उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्था</b>				
 ब्राजील	3.7	3.7	3.0	4.5
 रूस	2.7	3.5	2.6	3.2
 भारत	12.6	9.9	5.4	8.3
 चीन	7.8	8.5	7.9	8.5
 दक्षिण अफ्रीका	3.0	3.8	3.3	3.5

\*: भारत पीपीपी

स्रोत: ओईसीडी; विश्व बैंक।

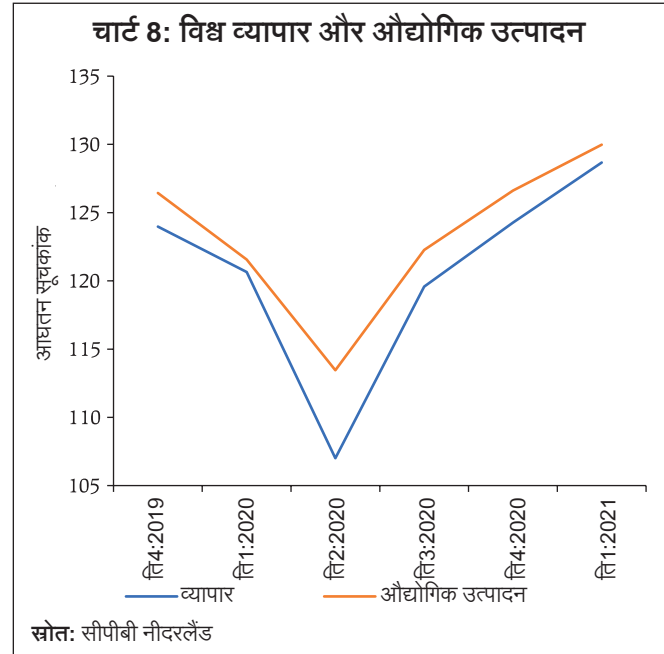


अनुमान है कि 2022 के अंत तक विश्व की आय वास्तविक रूप से लगभग 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर कम होगी, जो राष्ट्रों के बीच बढ़ती असमानता के साथ एक महामारी रहित परिवृश्य की तुलना में कम होगी।

जून 2021 की वैश्विक आर्थिक संभावनाओं में, विश्व बैंक ने भी इस वर्ष वैश्विक विकास के अपने पूर्वानुमान को संशोधित कर 5.7 प्रतिशत कर दिया है। यह नोट करता है कि बहाली कुछ प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) के नेतृत्व में है, जबकि अधिकांश ईएमई बहुत पीछे हैं। 2022 तक, वैश्विक जीडीपी पूर्व-महामारी अनुमानों की तुलना में 1.8 प्रतिशत कम होगी।

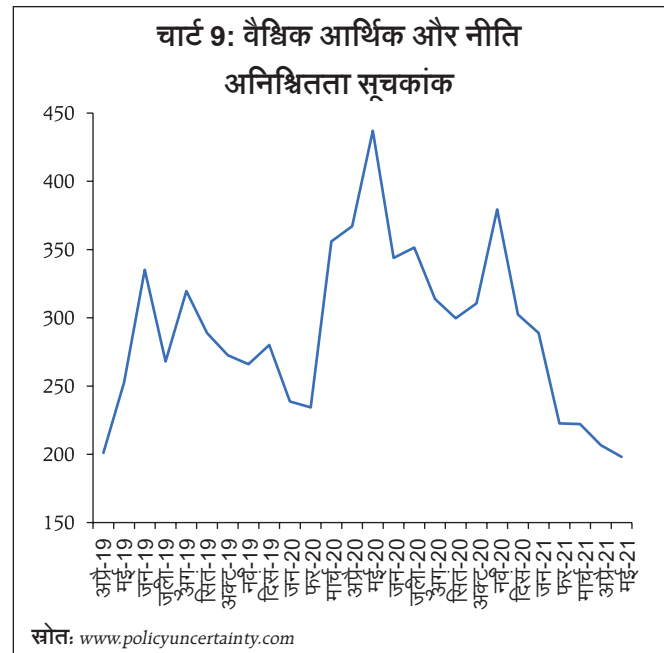
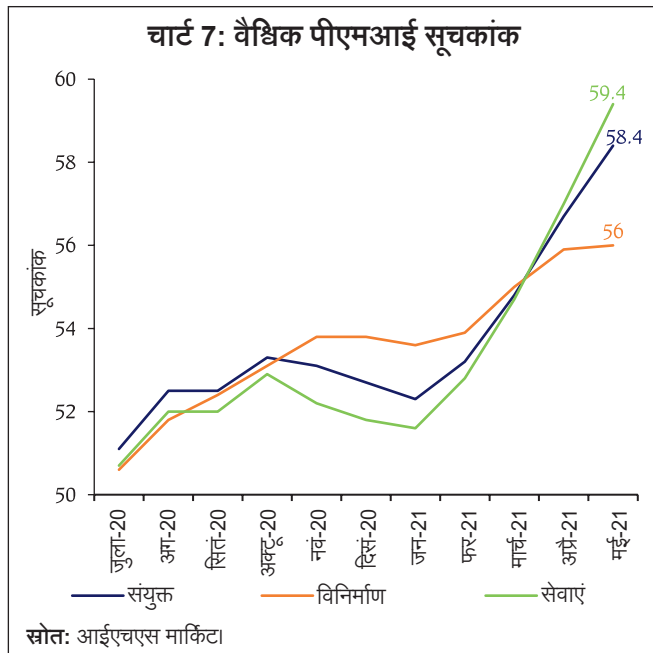
वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) मई 2021 में पंद्रह वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। सेवाओं के लिए पीएमआई 181 महीने के उच्च स्तर पर था और लगातार दूसरे महीने विनिर्माण पीएमआई से अधिक था (चार्ट 7)।

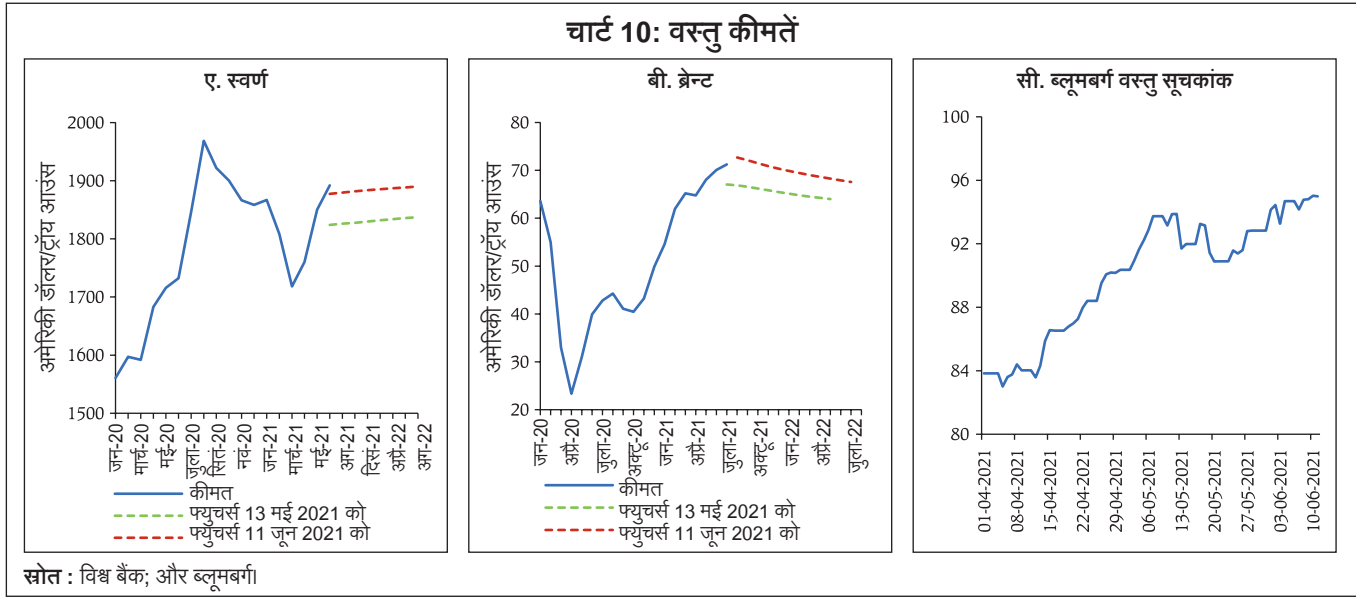
विश्व व्यापार और मजबूत हो रहा है: विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) द्वारा 109.7 पर संकलित ग्लोबल ट्रेड बैरोमीटर की मई 2021 तक की नवीनतम रीडिंग 100 के आधार अंकों की रेखा से लगभग 10 अंक अधिक और एक साल पहले की तुलना में लगभग 22 अंक अधिक है। 2020 के अंत तक पूर्व-महामारी के स्तर पर पहुंचने के बाद, विश्व व्यापार और औद्योगिक उत्पादन में (तिमाही-दर-तिमाही) क्रमशः 2021 की पहली तिमाही में 3.5



प्रतिशत और 2.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट 8)। शिपिंग लागत लगातार बढ़ रही है, बाल्टिक ड्राइ सूचकांक एक दशक से अधिक समय में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है क्योंकि आपूर्ति में रुकावट मांग में उछाल के साथ-साथ मौजूद है।

वैक्सीन रोलआउट और अर्थव्यवस्थाओं के धीरे-धीरे फिर से खुलने के कारण वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता कम हो रही है। यह वैश्विक आर्थिक वातावरण के लिए शुभ संकेत है (चार्ट 9)।





यूएस ट्रेजरी यील्ड में नरमी के कारण, सोने की मांग में नए सिरे से वृद्धि हुई है, मुद्रास्फीति के लिए बचाव के रूप में इसकी अपील से भी बढ़ावा मिला है। मई में लाभ पिछले जुलाई के बाद से सबसे अधिक मासिक वृद्धि थी। जून (11 जून तक) में समेकन के साथ, पीली धातु साल-से-आज तक आधार पर फिर से गिरावट में है। (चार्ट 10 ए)। पिछले दो महीनों में कच्चे तेल की कीमतों में एक सीमित दायरे में कारोबार हुआ है, हालांकि मांग में पुनरुत्थान और यात्रा प्रतिबंधों को धीरे-धीरे उठाने के साथ एक मजबूत पूर्वाग्रह के साथ (चार्ट 10 बी)। ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स, जो 23 कच्चे माल की कीमतों को ट्रैक करता है, पिछले दो महीनों में कई मौकों पर दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जिसमें नवीनतम 10 जून (चार्ट 10सी) है।

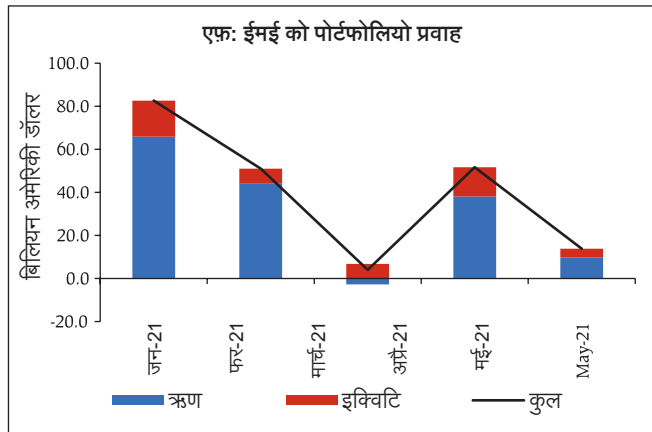
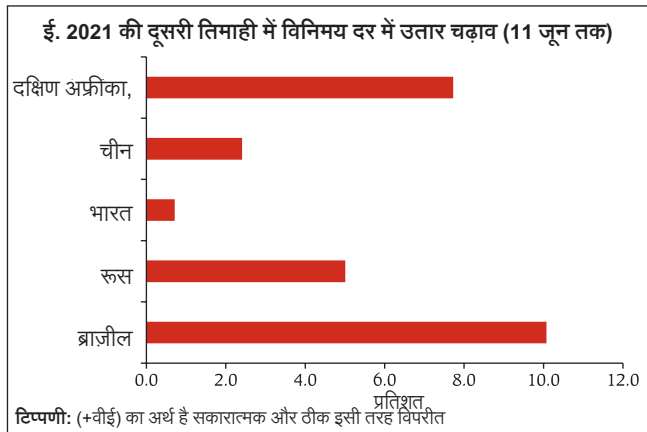
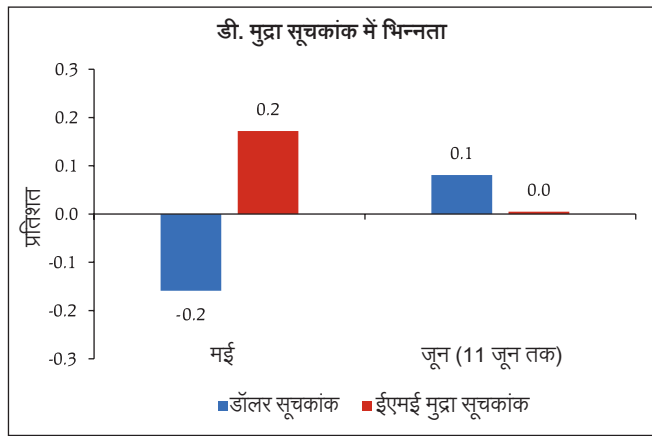
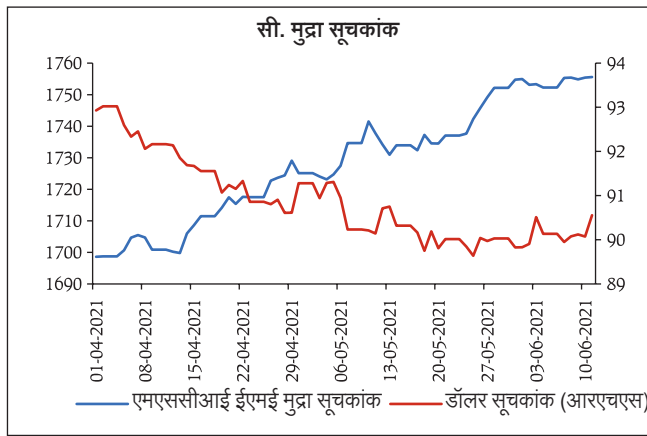
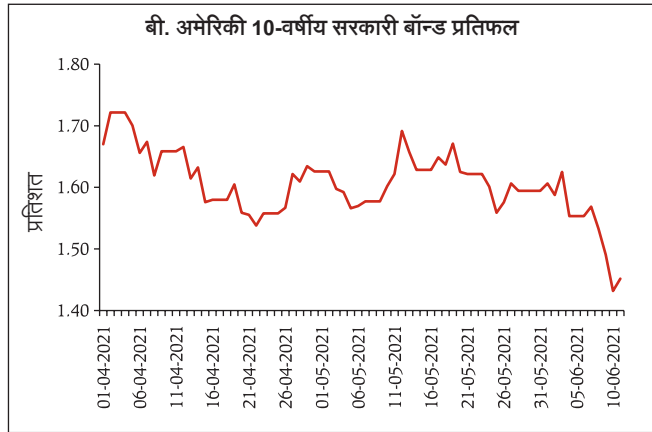
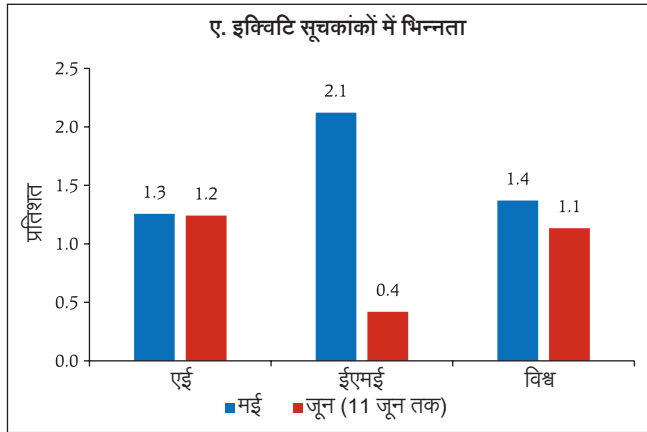
वित्तीय बाजारों में शेयर बाजार में अफरातफरी का माहौल रहा। मई की पहली छमाही में अधिकांश शेयर बाजारों में गिरावट आई क्योंकि एशिया और अन्य देशों के बड़े हिस्से में संक्रमण और मृत्यु दर बढ़ गई। इसके बाद, बेहतर आर्थिक परिणामों और टीकाकरण की एकत्रित गति के साथ, बाजार बढ़ रहे हैं (चार्ट 11ए)। यूएस एस एंड पी इंडेक्स 11 जून को एक नए शिखर पर पहुंच गया। मौद्रिक नीति के रुख के आसपास अनिश्चितता और परिसंपत्ति खरीद के टेपिंग पर कभी-कभार बिल्प्स के साथ दीर्घकालिक यूएस ट्रेजरी यील्ड में नरमी जारी रही है (चार्ट 11

बी)। कुछ उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं सहित अन्य देशों में प्रतिफल समवर्ती रूप से नरम हुए हैं।

मुद्रा बाजारों में, अमेरिकी डॉलर में गिरावट रही क्योंकि खज़ाना प्रतिफल में नरमी आई। 2021 की पहली तिमाही में अर्जित सभी लाभों को मई के अंत तक मिटा दिया गया था, जून में अब तक (11 जून तक) कुछ निशान के साथ। मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) उभरते बाजारों के मुद्रा सूचकांक मई के दूसरे सप्ताह में अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया और 25 मई, 2021 से दस कारोबारी दिनों में और अधिक शिखर पर पहुंच गया, 11 जून, 2021 को 1755.59 के उच्च स्तर पर बंद हुआ (चार्ट 11सी और 11डी)। 2021 की दूसरी तिमाही में अब तक (11 जून तक), ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में सबसे तेज़ अधिमूल्यन देखा गया, जो कमोडिटी निर्यातक हैं। भावनाओं और उच्च कमोडिटी कीमतों पर जोखिम के माहौल में, इन ईएमई मुद्राओं में देशों में संक्रमण के हालिया पुनरुत्थान के बावजूद मजबूती आयी है (चार्ट 11ई)।

इंस्टिट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस (आईआईएफ) के अनुसार, मई में ईएमई में पोर्टफोलियो प्रवाह अप्रैल (चार्ट 11 एफ) का केवल एक-चौथाई था। मई में कुल ईएमई पोर्टफोलियो प्रवाह 13.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें ऋण प्रवाह अप्रैल की तरह ही बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार था। चीन को छोड़कर, मई में अधिकांश अन्य ईएमई में इक्विटी से शुद्ध बहिर्वाह हुआ।

**चार्ट 11: वित्तीय बाज़ार**



स्रोत: ब्लूमबर्ग; एफबीआईएल; और आईआईएफ।

जबकि कई ईएमई लक्ष्य पर या उससे अधिक मुद्रास्फीति का अनुभव कर रहे हैं, हाल के महीनों में एई में भी मुद्रास्फीति में तेजी से वृद्धि हुई है। मई में अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति लगभग 13 साल के उच्च स्तर 5.0

प्रतिशत पर थी। मई में यूरो क्षेत्र में 2 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर्ज की गई, जो इसके मुद्रास्फीति लक्ष्य की ऊपरी सीमा थी। इसी तरह, मुद्रास्फीति अब जापान को छोड़कर अधिकांश अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में लक्ष्य से काफी दूर है।

महामारी फैलने के बाद से दरें बढ़ाने वाला आइसलैंड पहला आई केंद्रीय बैंक बन गया। आइसलैंड के केंद्रीय बैंक ने मुद्रास्फीति की चिंताओं पर मई में अपनी नीतिगत दर में 25 आधार अंकों (बीपीएस) की वृद्धि की। जून में, बैंक ऑफ रशिया ने मार्च के बाद से 125 आधार अंकों की कुल बढ़ोतरी के साथ लगातार तीसरी बार अपनी प्रमुख दर 50 आधार अंकों की वृद्धि की।

वैश्विक कर प्रणाली में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, देशों के जी 7 समूह ने कम से कम 15 प्रतिशत की बड़ी फर्मों पर वैश्विक न्यूनतम निगम कर के सिद्धांत पर 5 जून को सहमति व्यक्त की; जुलाई में जी-20 के बीच व्यापक समझौते का मार्ग प्रशस्त किया। यह सुनिश्चित करके कि बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों वास्तविक संचालन वाले देश में कर का भुगतान करती हैं, यह समझौता बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कम कर क्षेत्राधिकार में लाभ स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता है। हालांकि, सौदे की सफलता व्यापक स्वीकृति पर निर्भर करती है।

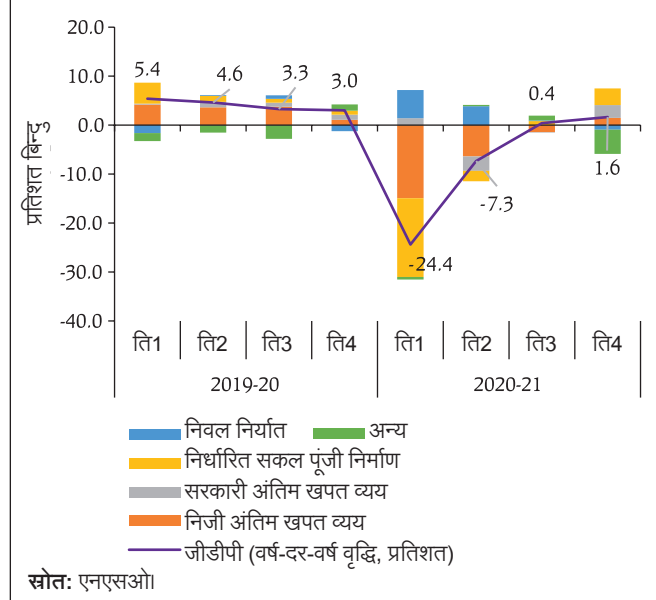
आगे देखते हुए, भले ही विकास निरंतर नीति समर्थन और तेजी से और व्यापक टीकाकरण पर आकस्मिकता को पुनर्जीवित करने के लिए तैयार है, मुद्रास्फीति पर करीब से नजर रखने की जरूरत है। कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि के साथ, मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण के आसपास की अनिश्चितता, वित्तीय बाजारों, विशेष रूप से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए वसूली और स्पिलओवर जोखिम के लिए जोखिम पैदा करती है।

### III. घरेलू विकास

भारतीय अर्थव्यवस्था महामारी की दूसरी लहर से जूझ रही है, हालांकि सतर्क आशावाद लौट रहा है, जुलाई की शुरुआत में अधिक सुधार की उम्मीद है, जैसा कि सांख्यिकीय/गणितीय मॉडल द्वारा भविष्यवाणी की गई है।<sup>12</sup> शिखर का पहला संकेत, जैसा कि मई के मध्य में आया था, इन पूर्वानुमानों के अनुरूप है।

<sup>12</sup> कानपुर और हैदराबाद के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) (सूत्र मॉडल) फैंकल्टी द्वारा विकसित एक मॉडल दिखाता है कि दैनिक केसलोड 2 जून तक 100,000 से नीचे और 7 जुलाई तक 10,000 से नीचे गिर सकता है,। भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरु के प्रोफेसरों द्वारा निर्मित एक अन्य गणितीय मॉडल से बताया है कि 26 मई तक दैनिक गणना 100,000 से नीचे गिर सकती है।

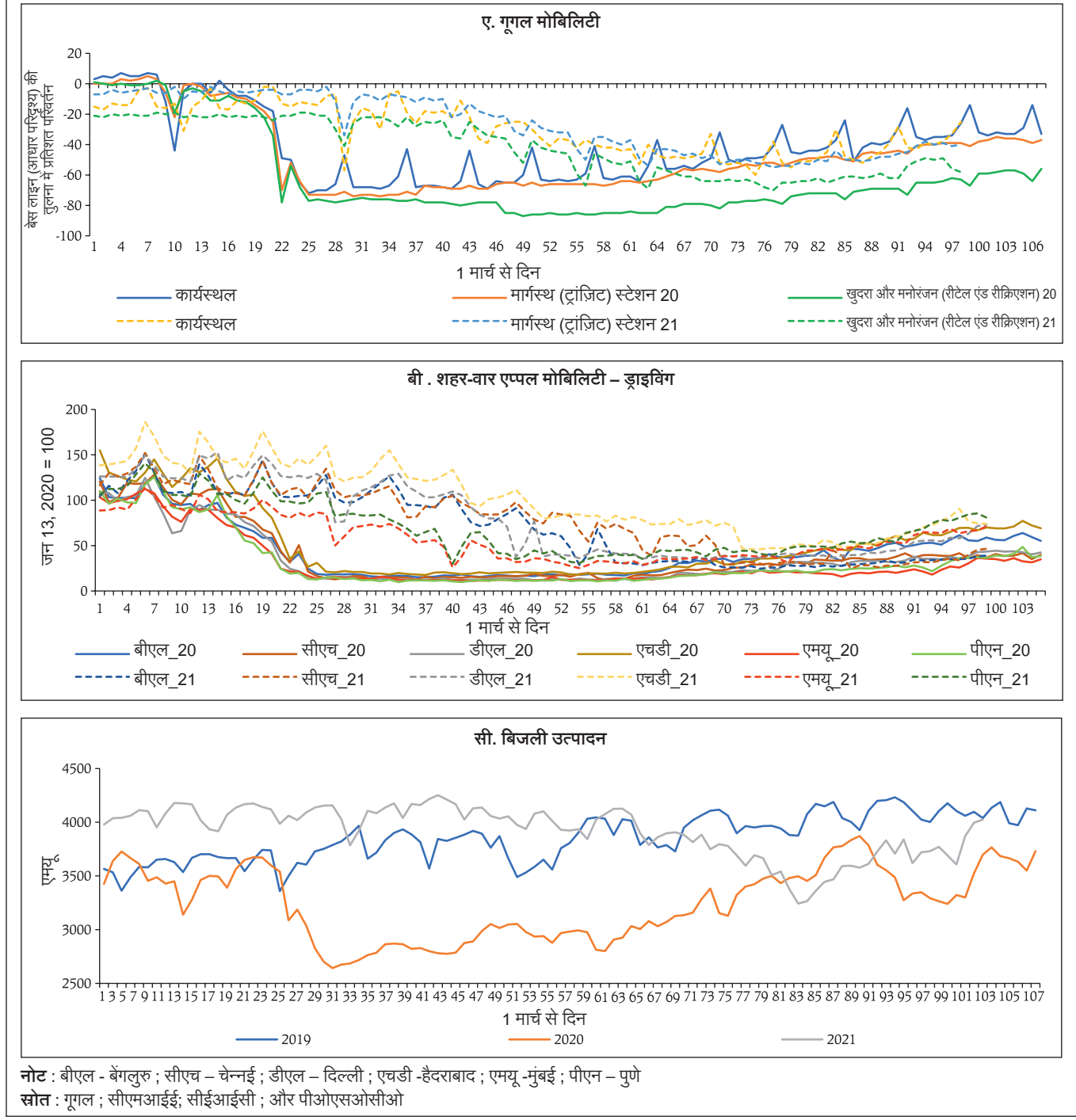
चार्ट 12: जीडीपी वृद्धि में भारत योगदान



राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 31 मई को वार्षिक राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान (पीई) ने भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि को दूसरे अग्रिम अनुमान से 0.7 प्रतिशत अंक बढ़ाकर 2020-21 में 7.3 प्रतिशत के निचले संकुचन में संशोधित किया। सबसे आशाजनक प्रिंट सकल अचल पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) में दर्ज दो अंकों की वृद्धि थी, जो सरकार द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर को दी हुई सहायता थी (चार्ट 12)। इसके अलावा, दूसरी लहर के दौरान परिवारों का बचत व्यवहार आगे चलकर खपत के सामान्यीकरण पर कुछ प्रकाश डाल सकता है (अनुबंध बॉक्स 1)।

अर्थव्यवस्था पर दूसरी लहर का प्रभाव मई 2021 में और बढ़ गया था, जब कई राज्यों ने स्थानीय तालाबंदी का विकल्प चुना था। इन प्रतिबंधों ने सार्वजनिक गतिशीलता को चारों ओर से बाधित कर दिया जैसा कि गूगल और एप्पल गतिशीलता संकेतकों में दिखाया गया है, हालांकि आंदोलन में गिरावट ने मई के अंतिम सप्ताह में नीचे गिरने के संकेत दिखाए (चार्ट 13ए और 13बी)। गतिशीलता संकेतकों की तरह, बिजली उत्पादन रीडिंग भी कम हो गई, मई के अंतिम सप्ताह में आपूर्ति में सुधार हुआ (चार्ट 13सी)।

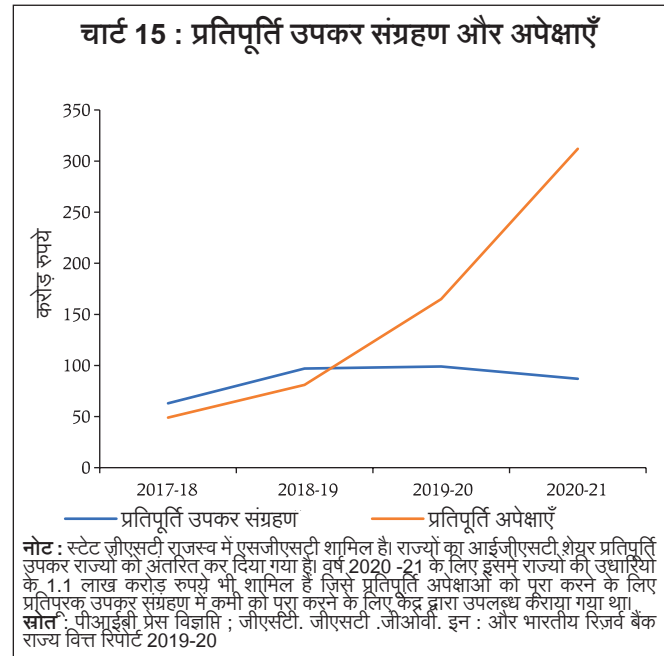
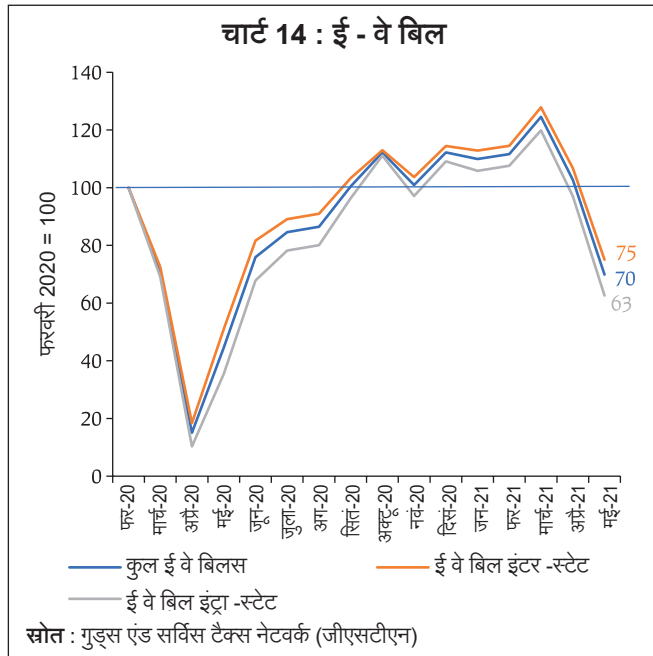
**चार्ट 13 : आर्थिक गतिविधि पर कोविड 19 की दूसरी लहर का प्रभाव**



**कुल मांग**

कुल मांग की स्थिति देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों से जूझ रही है। मई 2021 में लगातार दूसरे महीने जीएसटी ई-वे बिल में नरमी आई, जो एक साल के निचले स्तर पर

पहुंच गया। पूर्व-महामारी फरवरी 2020 के स्तर के लिए सामान्यीकृत, ई-वे बिल जून 2020 से पहले देखे गए स्तरों तक गिर गए। अंतर-राज्यीय ई-वे बिलों ने अंतर-राज्यीय ई-वे बिलों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया, संभवतः अंतर-राज्य प्रतिबंधों के



कारण (चार्ट 14)। क्रमिक रूप से, ई-वे बिल में 32.0 प्रतिशत की गिरावट आई और मई 2019 की तुलना में उनमें 26.3 प्रतिशत की कमी आई। यह आगे चलकर जीएसटी संग्रह में और नरमी का संकेत दे सकता है।

जीएसटी कानून ने पांच साल (2017-18 से 2021-22) की संक्रमण अवधि के दौरान 2015-16 के राजस्व आधार पर 14 प्रतिशत प्रति वर्ष की वार्षिक वृद्धि के साथ राज्यों के राजस्व की रक्षा की। किसी भी कमी को पाप/विलासिता वस्तुओं पर अतिरिक्त कर (क्षतिपूर्ति उपकर) के माध्यम से वित्त पोषित किया जाना था। जीएसटी लागू होने के बाद के चार वर्षों में, केंद्र के लिए 2017-18 और 2018-19 में राज्य सरकारों के जीएसटी संग्रह में कमी को पूरा करने के लिए मुआवजा उपकर संग्रह पर्याप्त था; हालांकि, 2019-20 और 2020-21 में एक अंतर था (चार्ट 15) <sup>13</sup>।

आगे बढ़ते हुए, दूसरी लहर के बावजूद, 2021-22 (अब तक) में जीएसटी संग्रह ने 2020-21 की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है, इस आशावाद को बढ़ावा देते हुए कि राज्यों के राजस्व

<sup>13</sup> जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक 12 जून, 2021 को कोविड -19 संबंधी आवश्यक वस्तुओं (एसेंशियल्स) पर दरों की समीक्षा की एकल बिंदु एजेंडा के साथ बुलाई गई थी। इसने टीकों के लिए जीएसटी दर को 5 प्रतिशत पर बरकरार रखा और कोविड -19 एसेंशियल्स (मास्क, सैनिटाइजर, दवाएं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन उत्पादन किट, परीक्षण और नैदानिक किट) पर दरों को 30 सितंबर, 2021 तक 12/18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया। एंजुलेंस पर जीएसटी की दर भी 28 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दी गई।

आधार को 7 प्रतिशत <sup>14</sup> की वृद्धि दर के साथ संरक्षित किया जाएगा , और यह पिछले वर्ष में कमी की भरपाई के लिए कुछ अधिशेष हो सकता है। मई 2021 में सकल जीएसटी राजस्व ₹1,02,709 करोड़ था, जो पिछले वर्ष के इसी महीने में जीएसटी राजस्व से 65 प्रतिशत अधिक है।

2020-21 के लिए केंद्र सरकार के अनंतिम खाते (पीए) 9.5 प्रतिशत (सारणी 5) के संशोधित अनुमान (आरई) के मुकाबले

**सारणी 5: प्रमुख वित्तीय संकेतक (जीडीपी का प्रतिशत)**

	2019-20	2020-21			2021-22
	वास्तविक	बीई	आरई	पीए	बीई
1	2	3	4	5	6
1. राजकोषीय घाटा	4.6	3.5	9.5	9.2	6.8
2. राजस्व घाटा	3.3	2.7	7.5	7.4	5.1
3. प्राथमिक घाटा	1.6	0.4	5.9	5.8	3.1
4. सकल कर राजस्व	9.9	10.8	9.8	10.3	9.9
5. गैर-कर राजस्व	1.6	1.7	1.1	1.1	1.1
6. राजस्व व्यय	11.6	11.7	15.5	15.6	13.1
7. पूंजीगत व्यय	1.6	1.8	2.3	2.2	2.5

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज; और लेखा महानियंत्रक (सीजीए)

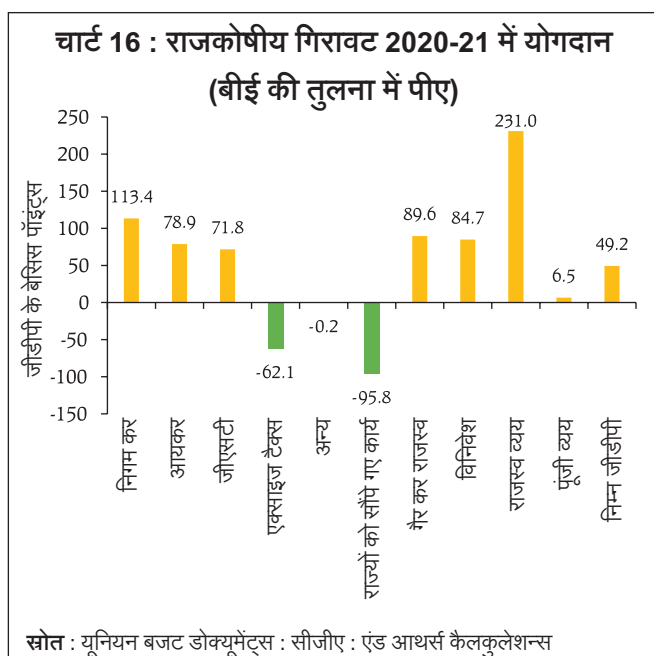
<sup>14</sup> 28 मई 2021 को जीएसटी परिषद की 43 वीं बैठक में बहुमत से निर्णय लिया कि राज्यों के लिए आधार राजस्व (कमी की गणना के लिए जिसका केंद्र द्वारा मुआवजा दिया जाएगा) की गणना वर्ष 2019-20 के स्तर से प्रतिवर्ष 7 फीसदी की राजस्व वृद्धि मानते की जाए जिसमें केंद्र द्वारा महामारी के कारण फोर्स मेज्योर का प्रयोग किया जा रहा है।

जीएफडी को सकल घरेलू उत्पाद के 9.2 प्रतिशत पर रखते हैं। यह सुधार उच्च प्राप्तियों से उत्पन्न हुआ, जिसका सकल कर राजस्व ₹ 20.2 लाख करोड़ था, आंशिक रूप से उच्च राजस्व व्यय से ऑफसेट, मुख्य रूप से सब्सिडी के ऑन-बजटिंग के कारण। एक सक्रिय कदम के रूप में, कुछ वर्षों में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) के ऋण को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की मूल योजना के बजाय, मार्च 2021 में सभी बकाया राशि को एक झटके में साफ कर दिया गया।

बजट अनुमान (बीई) से पीए तक वर्ष के दौरान कुल वित्तीय गिरावट 568 आधार अंक (बीपीएस) है, जिसमें से 280 बीपीएस प्राप्तियों में कमी, 238 बीपीएस अधिक व्यय के कारण है (उच्च खाद्य सब्सिडी के कारण 208 बीपीएस सहित) और बीई (चार्ट 16) की तुलना में कम जीडीपी के हर प्रभाव के कारण 49 बीपीएस

आगे बढ़ते हुए, 2020-21 में एनएसएसएफ को सभी एफसीआई बकाया का निपटान और रिजर्व बैंक द्वारा उच्च अधिशेष हस्तांतरण 2021-22 में लगभग 45-50 बीपीएस का अतिरिक्त वित्तीय स्थान खोलेगा।

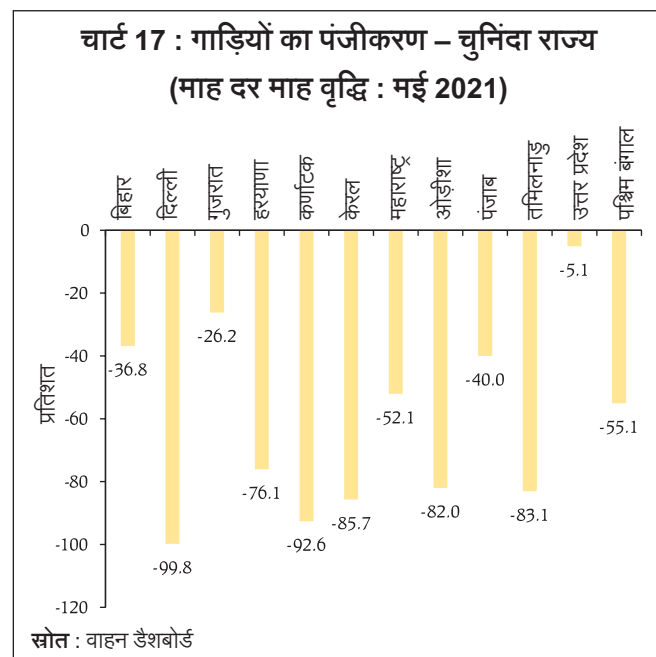
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के त्रैमासिक सर्वेक्षण के हालिया दौर के अनुसार,



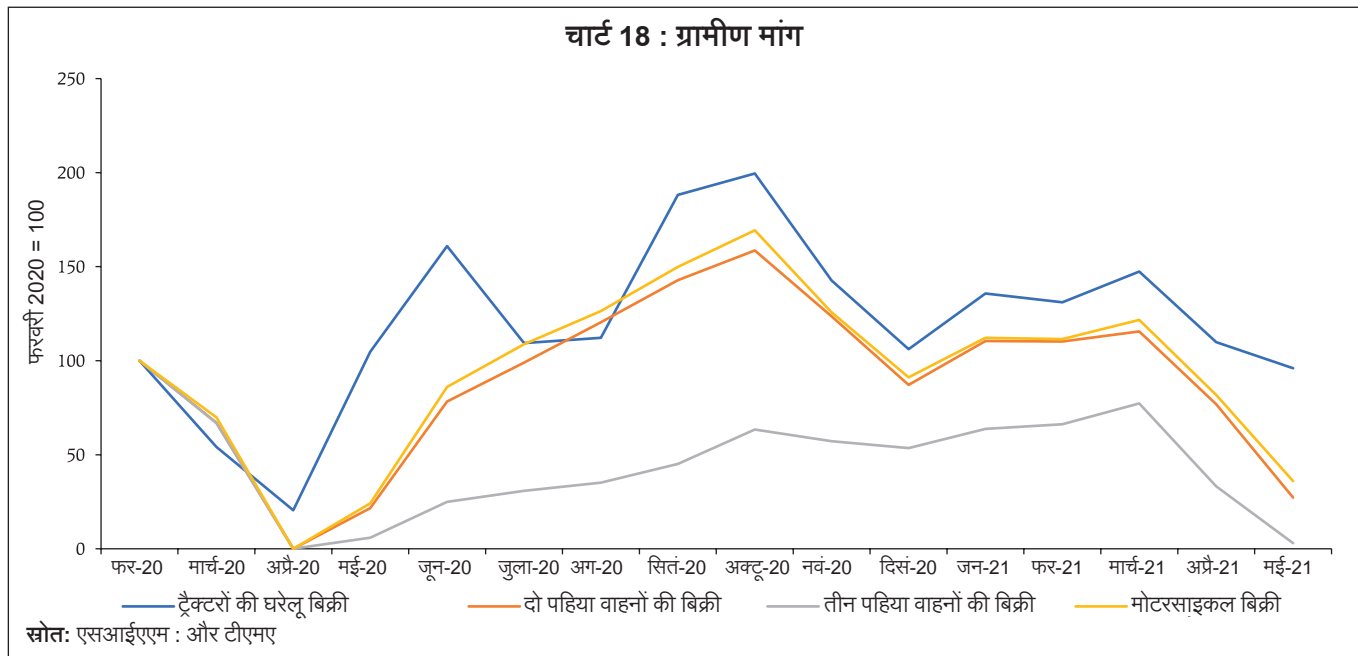
भारतीय कंपनियों का कारोबारी विश्वास मई के दौरान पिछले तीन तिमाहियों में अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले दौर में एक दशक के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। सर्वेक्षण (टकसाल, 1 जून)। जून तिमाही (मिंट, 18 मई) में बड़े उपकरण, परिधान और सौंदर्य उत्पादों जैसे विवेकाधीन खरीद में उपभोक्ता सामान कंपनियों में मंदी देखी जा रही है।

वाहन डैशबोर्ड के अनुसार, मोटर वाहनों की खुदरा बिक्री मई 2021 में अप्रैल 2021 की तुलना में 55.0 प्रतिशत गिर गई, परिवहन वाहनों में 68.1 प्रतिशत और गैर-परिवहन वाहनों में 54.0 प्रतिशत की गिरावट आई। सभी प्रमुख राज्यों में पंजीकरण में संकुचन दर्ज किया गया (चार्ट 17)। गांवों और छोटे शहरों में दूसरी लहर बनाने के साथ, ग्रामीण मांग में भी कमी आई है, जैसा कि ट्रैक्टर, दोपहिया, मोटरसाइकिल और तिपहिया वाहनों (चार्ट 18) की बिक्री में कमी का संकेत मिलता है।

एक उम्मीद की किरण यह है कि भारतीय रेलवे ने मई में 11.4 करोड़ टन माल लदान किया, जो इस महीने में अब तक का सबसे अधिक और एक महीने पहले <sup>15</sup> की तुलना में 2 प्रतिशत अधिक है। रेलवे माल ढुलाई राजस्व 2.9 प्रतिशत की क्रमिक वृद्धि दर्ज करते हुए मजबूत रहा, साथ ही मई 2019 में पूर्व-



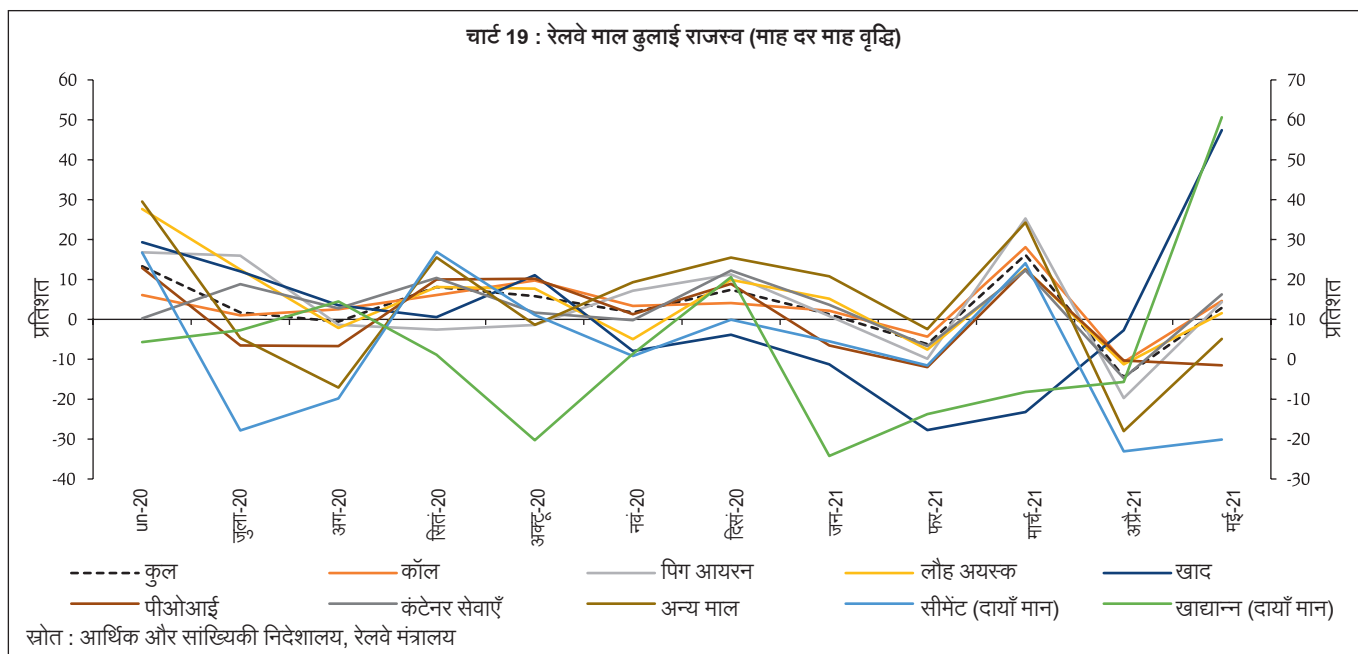
<sup>15</sup> बिजनेस लाइन, 3 जून, 2021।



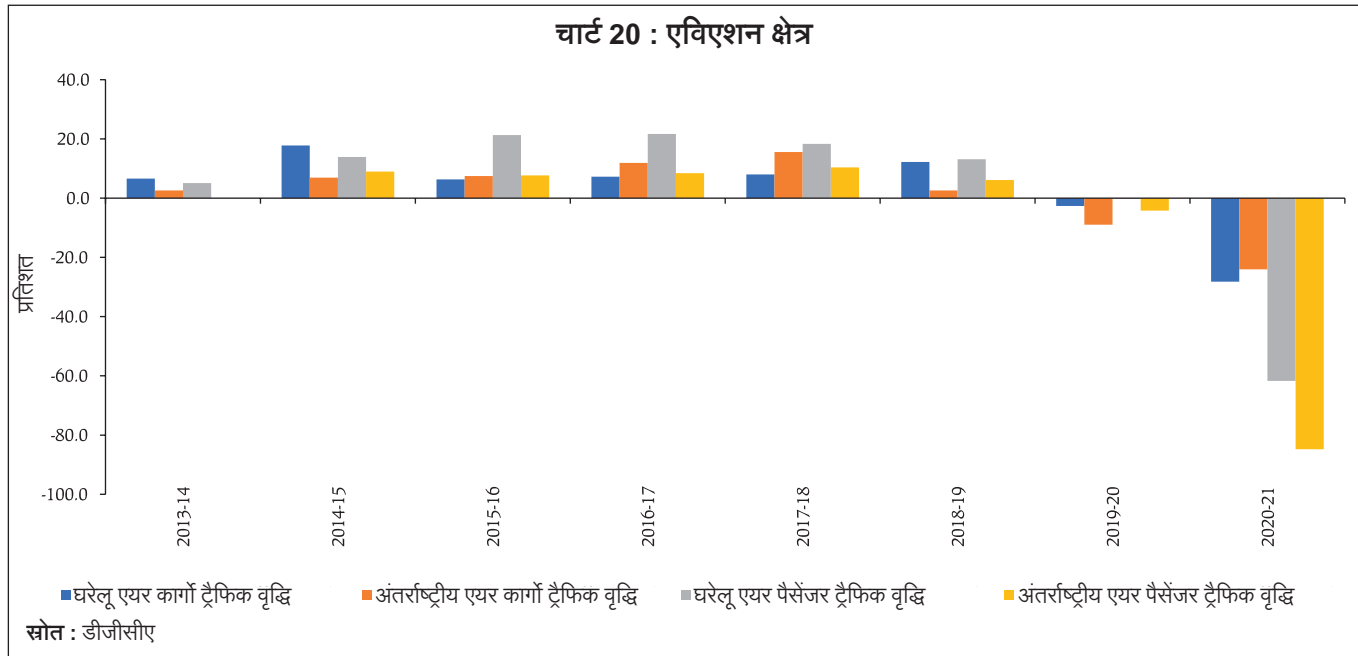
महामारी से 9.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। उर्वरकों और खाद्यान्नों के नेतृत्व में यातायात की सभी श्रेणियों में क्रमिक सुधार दर्ज किया गया, जो क्रमशः 47.4 प्रतिशत और 60.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट 19)।

दूसरी लहर के भार से कमजोर पड़े नागरिक उड्डयन क्षेत्र को वित्त वर्ष 2020:21 में महत्वपूर्ण संकुचन का सामना करना

पड़ा, जिसमें यात्री खंड में 66.2 प्रतिशत (घरेलू यात्री खंड में -61.7 प्रतिशत और अंतर्राष्ट्रीय यात्री खंड में -84.8 प्रतिशत की गिरावट आई); हालांकि कार्गो खंड में गिरावट अपेक्षाकृत कम स्पष्ट थी, अर्थात 25.7 प्रतिशत (घरेलू कार्गो खंड - 28.2 प्रतिशत और अंतर्राष्ट्रीय कार्गो खंड -24.1 प्रतिशत) (चार्ट 20)। इसे महामारी से सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में से एक माना जाता





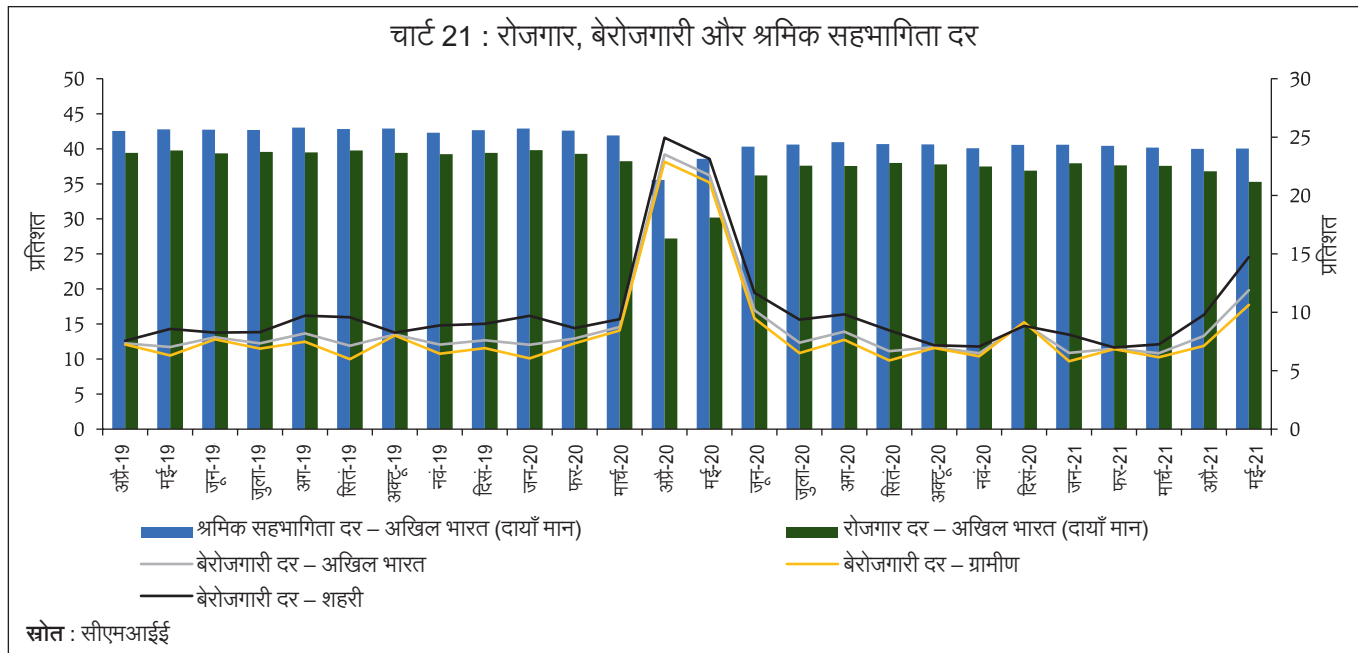


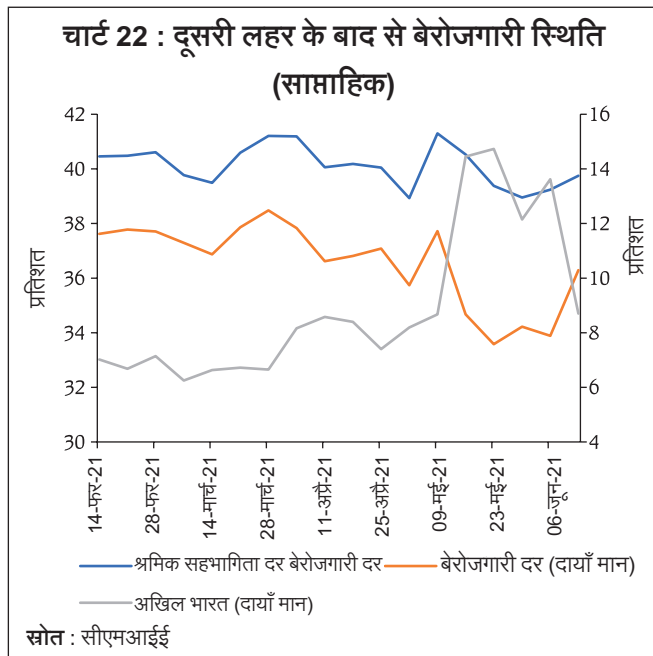
है, सरकार ने कठिनाइयों को कम करने में मदद के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को इस क्षेत्र में विस्तारित किया।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के घरेलू सर्वेक्षण के अनुसार, मई 2021 में बेरोजगारी दर बढ़कर 11.9 प्रतिशत हो गई, जो मई 2020 के बाद सबसे अधिक है।

हालांकि, श्रम भागीदारी दर मई 2021 में अप्रैल 2021 के बराबर 40 प्रतिशत रही (चार्ट 21)।

अप्रैल 2021 के पहले सप्ताह से घटने लगे श्रम बाजार साप्ताहिक संकेतक जून 2021 के दूसरे सप्ताह में ठीक होने लगे हैं। 13 जून, 2021 को समाप्त सप्ताह में बेरोजगारी दर पिछले सप्ताह के 13.6 प्रतिशत से 8.7 प्रतिशत कम थी। 6 जून 2021 को





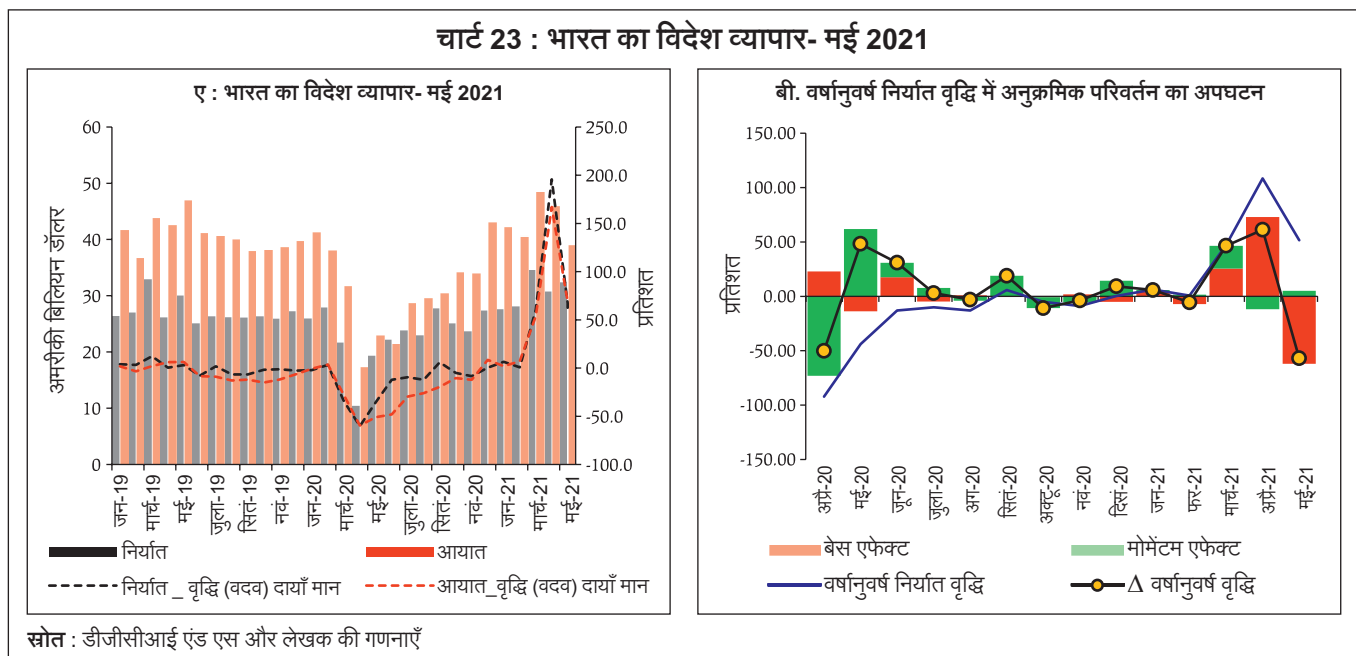
भारत का व्यापारिक निर्यात मई 2021<sup>16</sup> में मजबूत विकास पथ पर जारी रहा, जो आंशिक रूप से कम आधार (चार्ट 23ए और 23बी) को दर्शाते हुए 50 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) से अधिक बढ़ रहा है। गैर-तेल निर्यात ने लगातार नौवें महीने सकारात्मक गति प्रदर्शित की।

मई 2019 की तुलना में भी, मई 2021 में निर्यात बढ़ा है। मई 2019 की तुलना में जिन प्रमुख क्षेत्रों में वृद्धि हुई है, उनमें इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, लौह अयस्क, सूती वस्त्र और दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स (चार्ट 24) शामिल हैं।

इंजीनियरिंग सामान, भारत के कुल निर्यात का लगभग एक-चौथाई हिस्सा, महामारी के कारण हुई मांग / आपूर्ति में व्यवधान के कारण व्यापक रूप से प्रभावित हुआ। इस खंड ने पूर्व-महामारी के स्तर (चार्ट 25) को पार करते हुए, हाल के महीनों में एक स्मार्ट रिकवरी दर्शाते हुए वापस उछाल दिया है।

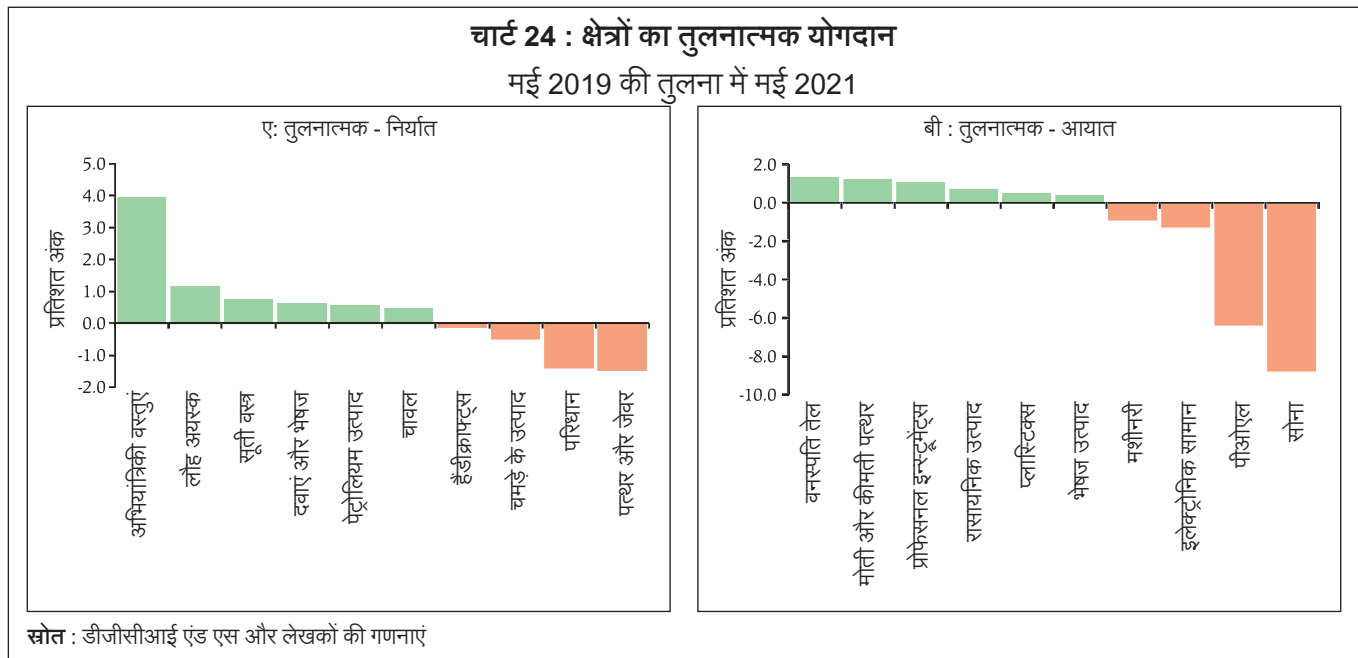
समाप्त सप्ताह में रोजगार दर (कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात) गिरकर 33.9 प्रतिशत हो गया, जो 13 जून, 2021 (चार्ट 22) को समाप्त सप्ताह में 36.3 प्रतिशत तक है।

जून 2020 से, कृषि निर्यात ने महामारी को सहन किया है और मासिक आधार पर लगातार 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (चार्ट 26ए और 26बी) से ऊपर रहकर लचीलापन दर्शाया है।



<sup>16</sup> वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 15 जून, 2021 को जारी आंकड़ों के आधार पर।

<sup>17</sup> वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि में एक क्रमिक परिवर्तन वर्तमान माह में माह-दर-माह दर और बारह महीने पहले की माह-दर-माह दर के बीच के अंतर के लगभग समान है (यूरोपीय सेंट्रल बैंक, 2005)।



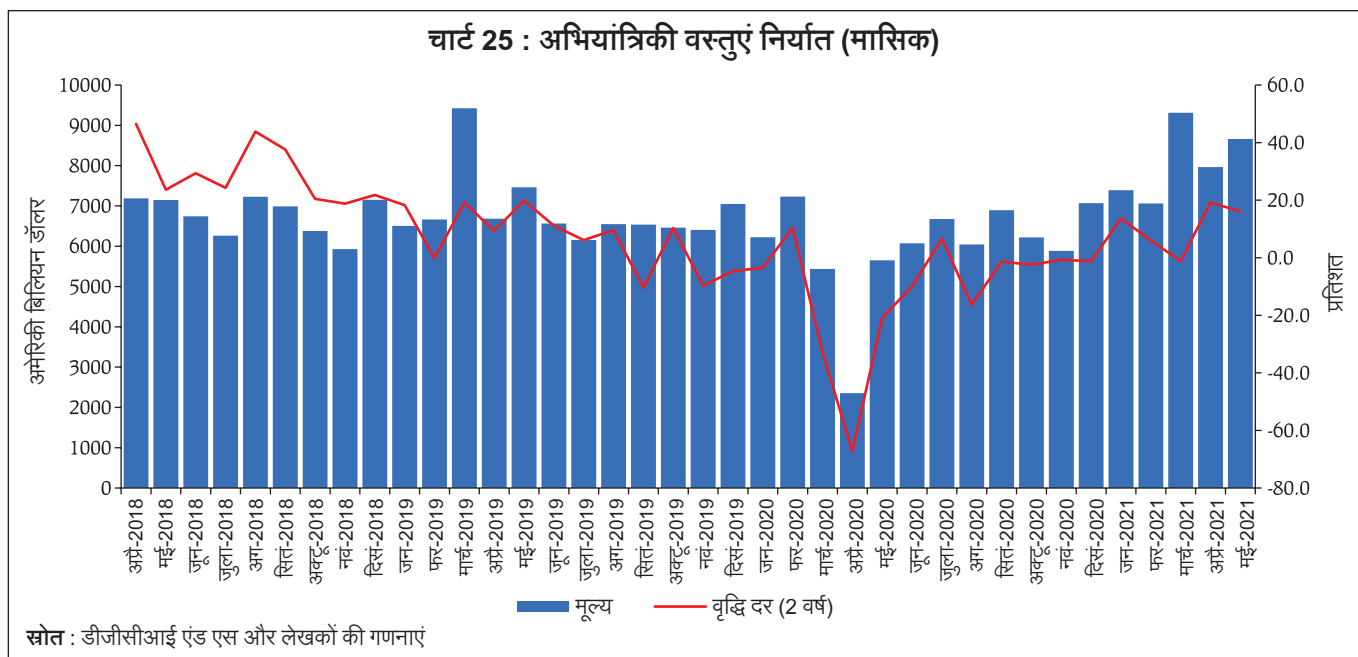
उच्च वैश्विक मांग, कमजोर वैश्विक गेहूं और चावल उत्पादन की उम्मीद के साथ निकट भविष्य में इन भारतीय निर्यातों की मांग को बनाए रखने में मदद करनी चाहिए।

एक साल पहले कम आधार के कारण मई 2021 में भारत के व्यापारिक आयात में भी 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की

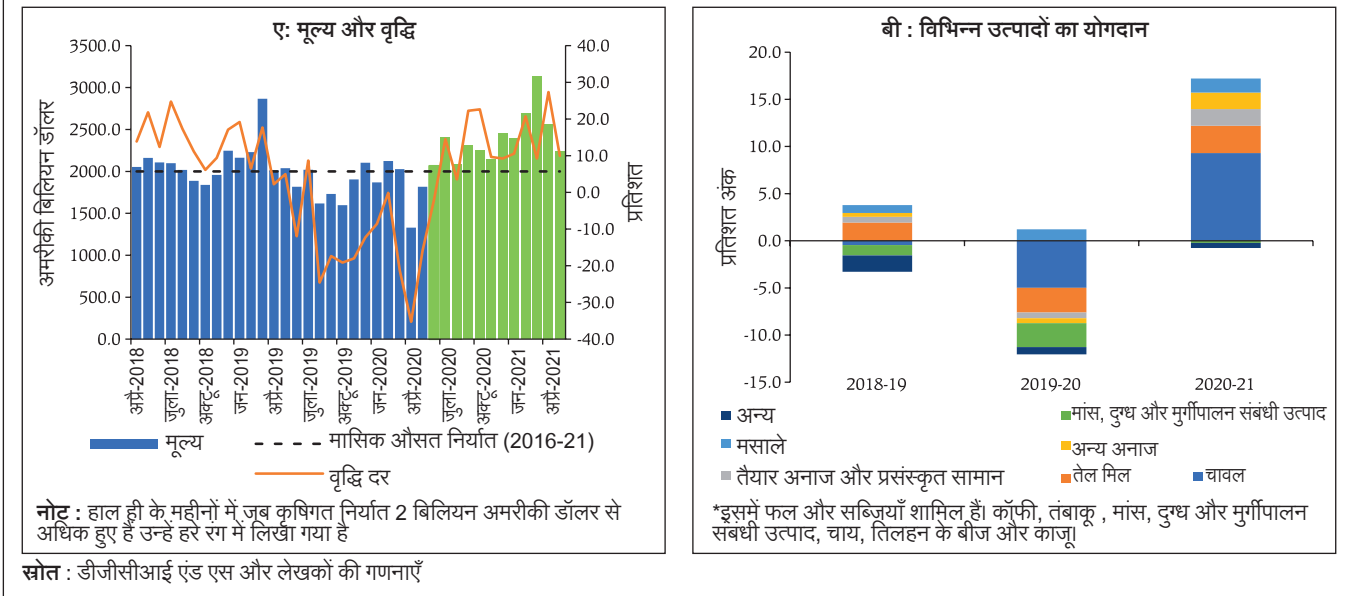
गई (चार्ट 23ए)। एक साल पहले के लॉकडाउन की तुलना में हाल के प्रतिबंधों का आयात मांग पर सीमित प्रभाव पड़ा है।

#### सकल आपूर्ति

भारत में कृषि समग्र आपूर्ति की स्थिति का मुख्य आधार बनी हुई है। 25 मई 2021 को जारी 2020-21 के लिए तीसरे



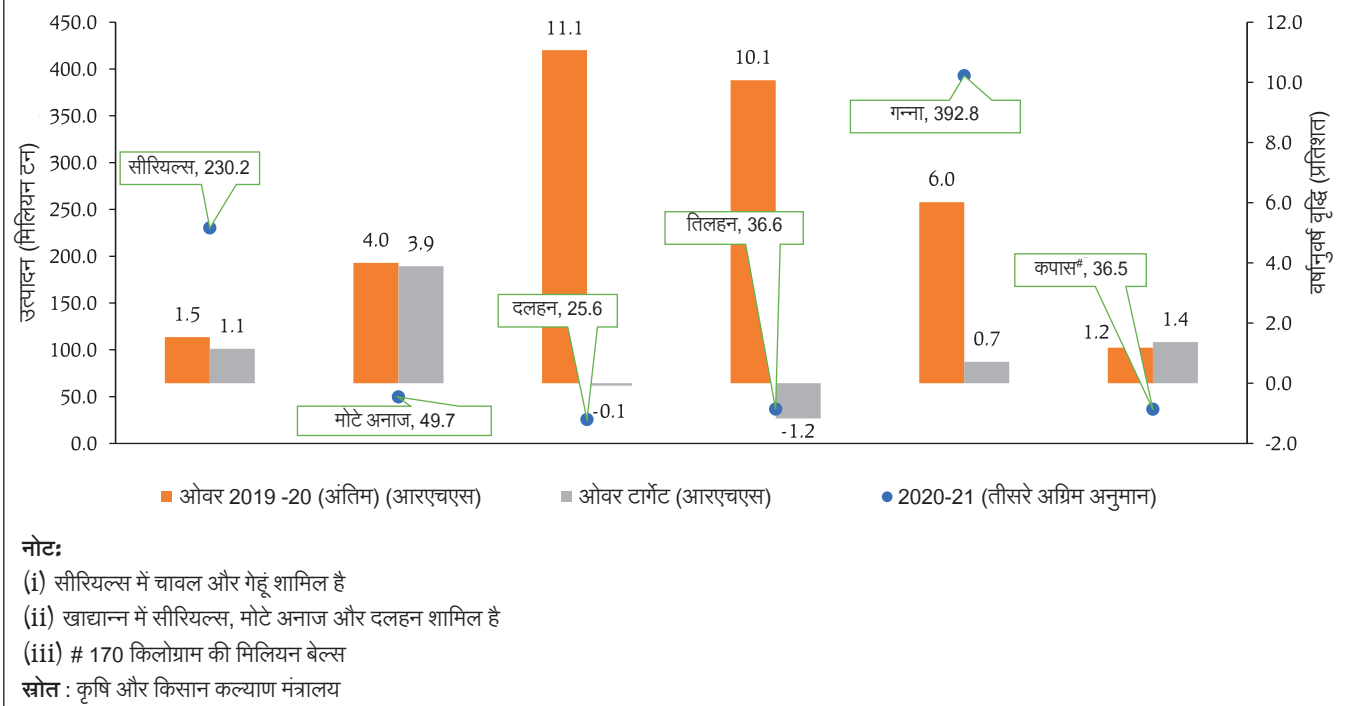
**चार्ट 26 : कृषिगत निर्यात प्रदर्शन**



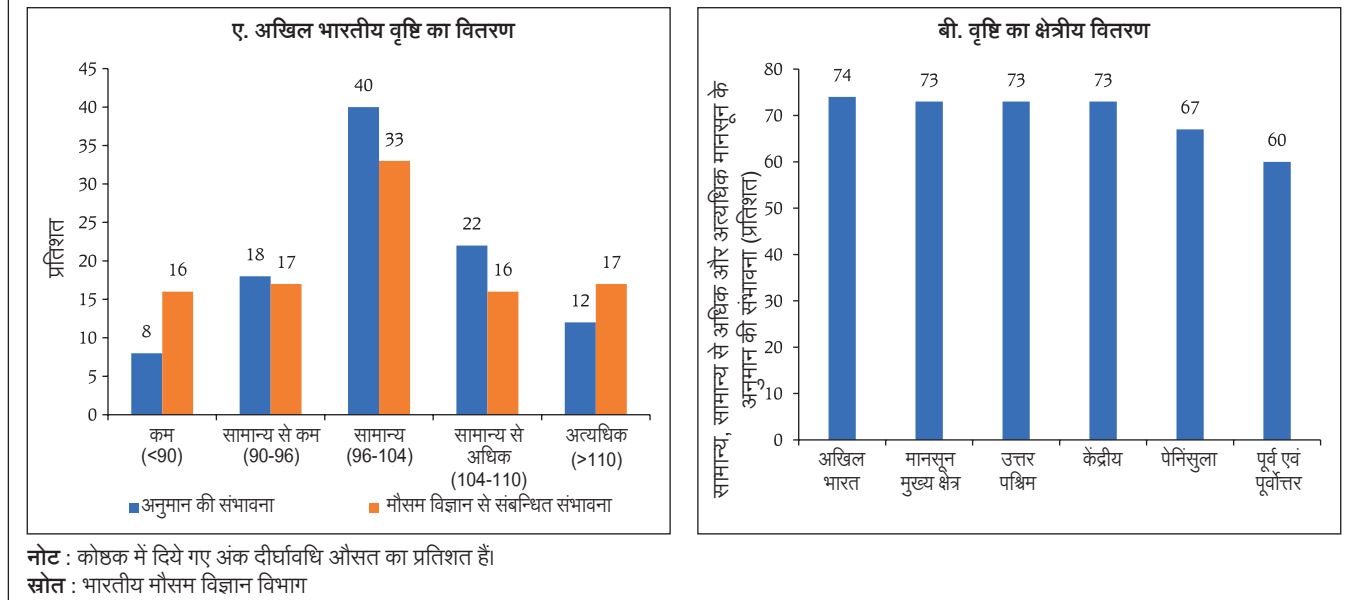
अग्रिम अनुमान (एई) ने कृषि उत्पादन को 305.4 मिलियन टन रखा, जो एक साल पहले की तुलना में 2.7 प्रतिशत और लक्ष्य से 1.5 प्रतिशत अधिक है (चार्ट 27)। खाद्यान्न, मोटे अनाज, दलहन, तिलहन और कपास ने रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया है। गेहूं

की खरीद ने लगातार दूसरे वर्ष रिकॉर्ड स्तर को छुआ है, जो एक साल पहले (10 जून, 2021) की तुलना में 12.2 प्रतिशत अधिक है। गेहूं और चावल दोनों की खरीद पहले ही पिछले साल के स्तर को क्रमशः 4.2 प्रतिशत और 12.1 प्रतिशत से पार कर चुकी है।

**चार्ट 27 : फसल उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान 2020-21**



**चार्ट 28 : दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए दूसरा लंबी दूरी का अनुमान (2021)**

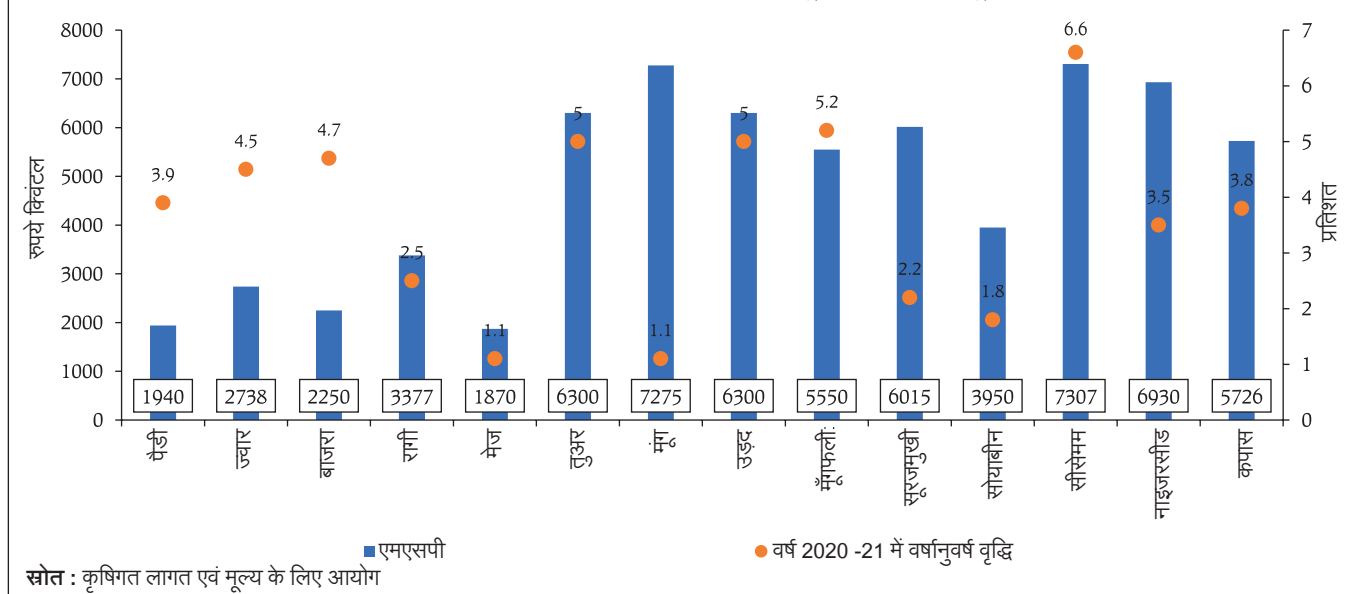


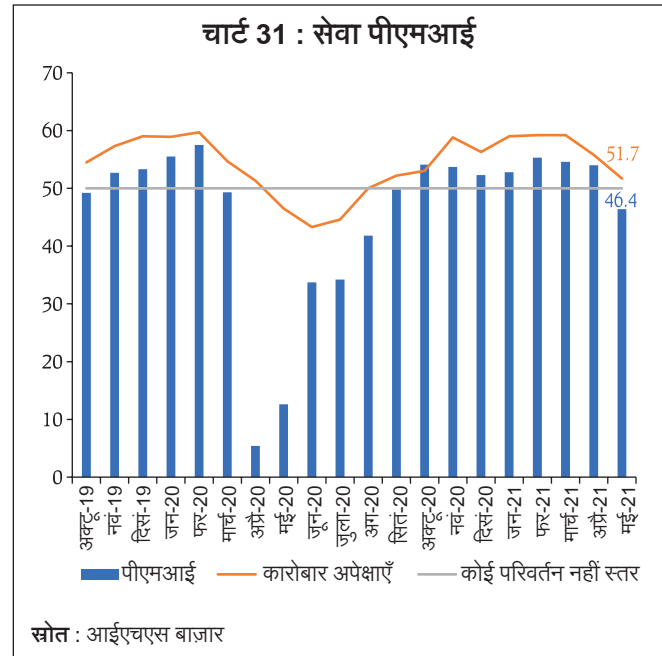
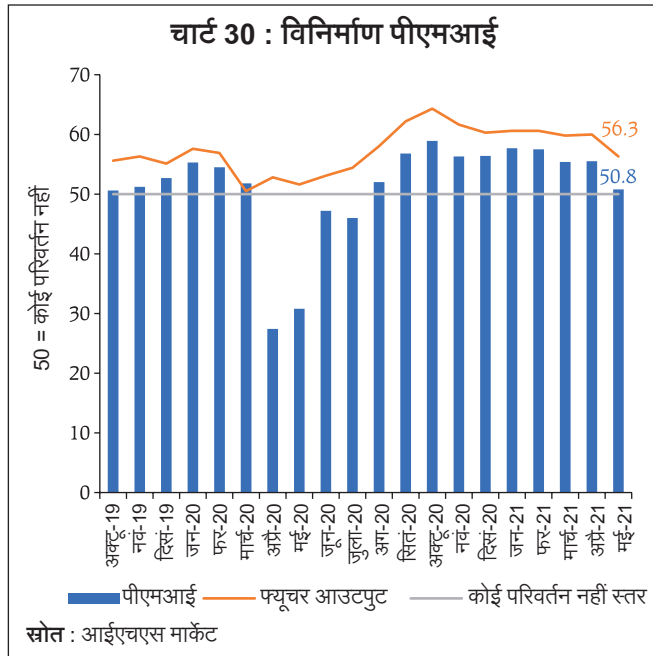
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा 01 जून, 2021 को जारी किए गए पूर्वानुमान से संकेत मिलता है कि देश के 74 प्रतिशत हिस्से में सामान्य से अधिक या अधिक बारिश होने की संभावना है (चार्ट 28ए)। 10 जून 2021 तक कुल वर्षा इसकी लंबी अवधि के औसत (एलपीए) की तुलना में 23 प्रतिशत अधिक थी और जलाशय का स्तर 21 प्रतिशत के दशक के औसत के

मुकाबले पूरी क्षमता के 27 प्रतिशत पर था, जो कृषि उत्पादन के लिए अच्छा संकेत है।

जहां तक नीति समर्थन का संबंध है, खरीफ सीजन 2021-22 के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि ने सभी फसलों के लिए उत्पादन लागत पर कम से कम 50

**चार्ट 29 : खरीफ मौसमी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य**



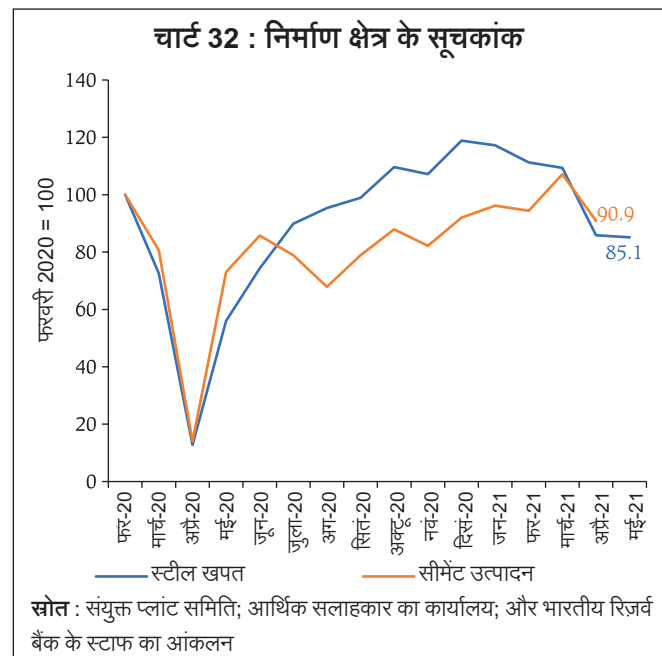


प्रतिशत की वापसी सुनिश्चित की है (चार्ट 29)। वर्ष 2021-22 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 307 मिलियन टन (पिछले वर्ष के तीसरे एई से 0.5 प्रतिशत अधिक) निर्धारित किया गया है। इस साल खरीफ दलहन और तिलहन की बुवाई बढ़ने की उम्मीद है, इसके बाद उच्च एमएसपी की घोषणा और सरकारी खरीद योजनाओं (पीएम-आशा) के माध्यम से उच्च खरीद की उम्मीद है।

मई 2021 में हेडलाइन पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग दस महीने के निचले स्तर पर आ गया। 50.8 की रीडिंग के साथ, यह एक महीने पहले 55.5 से भारी गिरावट के बाद भी विस्तार क्षेत्र में बना रहा। संकुचन मुख्य रूप से नए ऑर्डर और आउटपुट के उप-सूचकांकों से उपजा, क्योंकि दूसरी लहर की हेडविंड मांग को एक आभासी ठहराव (चार्ट 30) में ले आई। मई 2021 में सेवाओं के पीएमआई ने आठ महीनों में पहली बार 46.4 का मान दर्ज किया। निर्यात और नए व्यवसायों में संकुचन, सेवाओं में गिरावट के प्रमुख कारण थे, मुख्य रूप से कोविड संबंधित प्रतिबंधों (चार्ट 31) के कारण।

निर्माण क्षेत्र में भी अप्रैल-मई 2021 में गिरावट दर्ज की गई क्योंकि स्थानीय प्रतिबंधों ने निर्माण गतिविधि में गिरावट को

प्रेरित किया। हालांकि, अप्रैल और मई 2021 में सीमेंट उत्पादन और स्टील की खपत के लिए साल-दर-साल मजबूत वृद्धि दर दर्ज की गई, लेकिन कम आधार पर, क्षेत्रों ने पूर्व-महामारी 2019 (चार्ट 32) में समान महीनों की तुलना में भारी गिरावट दर्ज की।



कोविड -19 प्रेरित लॉकडाउन की दूसरी लहर के बावजूद, राजमार्ग निर्माण, जिसने 2020-21 (36.4 किमी / दिन) (फाइनेंशियल एक्सप्रेस, 10 जून) में 13,298 किमी के अब तक के उच्चतम स्तर को छू लिया, में अप्रैल-मई 2021 लो बेस पर वर्ष-दर-वर्ष 73.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2019 (28.2 किमी / दिन) से अधिक, 2021 में प्रदर्शन (24.1 किमी / दिन) विश्वसनीय बना हुआ है। क्रिसिल रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र जिसने उच्च परियोजना पुरस्कार, रिकॉर्ड निर्माण, और यातायात के संबंध में पिछले वित्त वर्ष में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और जिसकी गति को संक्रमण की दूसरी लहर से घटा हो सकता है, लेकिन चालू वित्त वर्ष के लिए इसमें कोई खास असर नहीं होगा।

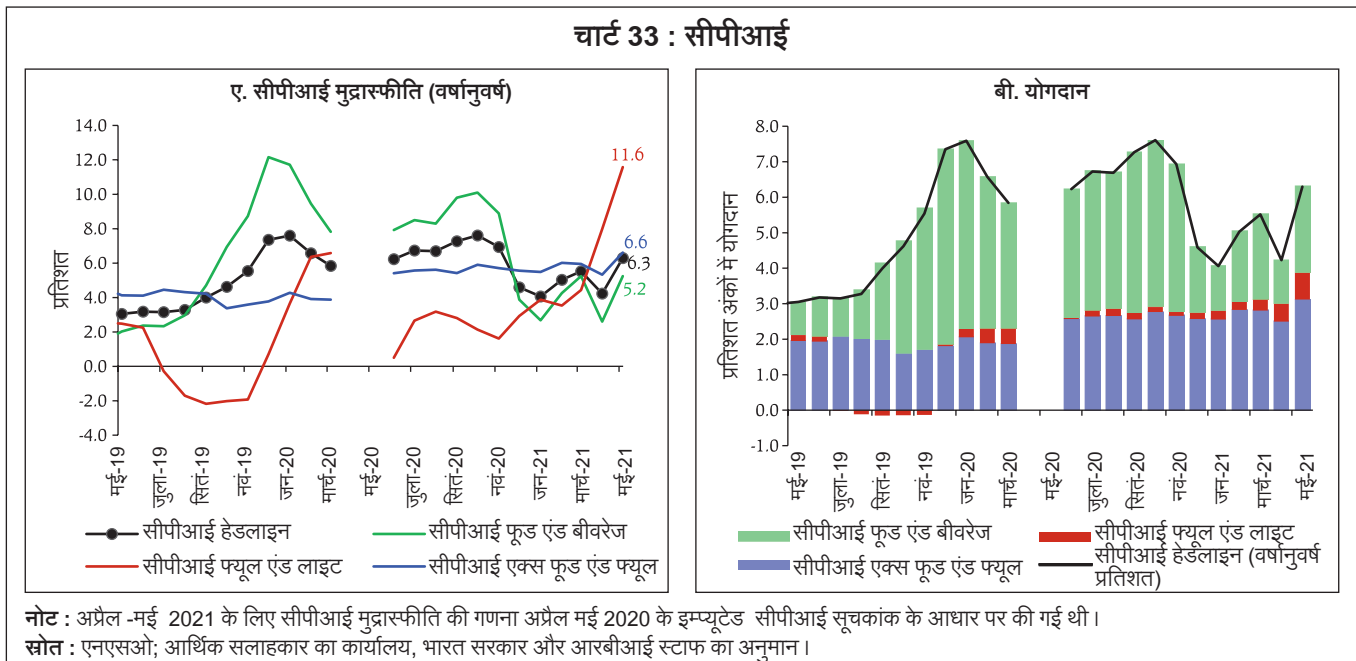
### मुद्रास्फीति

मई 2021<sup>18</sup> में सीपीआई मुद्रास्फीति 6.3 प्रतिशत पर रही अप्रैल 2021 में 4.2 प्रतिशत की तुलना में 2.1 प्रतिशत अंक की वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट 33ए)। एक प्रतिकूल आधार प्रभाव (एक साल पहले कीमतों में महीने-दर-महीने परिवर्तन) के साथ-साथ खाद्य, ईंधन और मुख्य श्रेणियों में कटौती करने वाले एक बड़े

सकारात्मक मूल्य गति (चालू महीने में कीमतों में महीने-दर-महीने परिवर्तन) के कारण हेडलाइन मुद्रास्फीति में उछाल लाया।

सीपीआई समूहों में, सीपीआई खाद्य और पेय पदार्थ मुद्रास्फीति मई में बढ़कर 5.2 प्रतिशत हो गई, जो अप्रैल की तुलना में 2.6 प्रतिशत अधिक है। अंडे, दूध, तेल और वसा, फल, दालें, मसाले और तैयार भोजन में मुद्रास्फीति मई में बढ़ी जबकि सब्जियों, अनाज और चीनी में अपस्फीति में कमी आई। खाद्य उप-समूहों में, केवल मांस और मछली ने मुद्रास्फीति में नरमी दर्ज की। समग्र मुद्रास्फीति में भोजन का योगदान (सीपीआई में 45.9 प्रतिशत के भार के साथ) मई में बढ़कर 39 प्रतिशत हो गया, जो अप्रैल में 29 प्रतिशत था (चार्ट 33 बी)। मई में ईंधन मुद्रास्फीति तेजी से दोहरे अंकों में - 3.6 प्रतिशत अंक - बढ़कर 11.6 प्रतिशत हो गई। खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति को छोड़कर सीपीआई मई में बढ़कर 6.6 प्रतिशत हो गया, जो मई 2014 के बाद का उच्चतम प्रिंट है। सभी मुख्य उप-समूहों ने कपड़ों और जूते, घरेलू सामान और सेवाओं, परिवहन और संचार, मनोरंजन और मनोरंजन, और व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव में पर्याप्त वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति में तेजी दर्ज की।

चार्ट 33 : सीपीआई



<sup>18</sup> एनएसओ ने मई 2021 के मुद्रास्फीति प्रिंट के आधार के रूप में मई 2020 के इम्प्यूटेड इंडिसेस का इस्तेमाल किया था। मई 2021 में, ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार-वार मूल्य रिपोर्टिंग गिरकर 68.1 प्रतिशत (अप्रैल 2021 में 84.6 प्रतिशत से) और शहरी क्षेत्रों में 67.5 प्रतिशत (अप्रैल 2021 में 87.4 प्रतिशत से) हो गई।

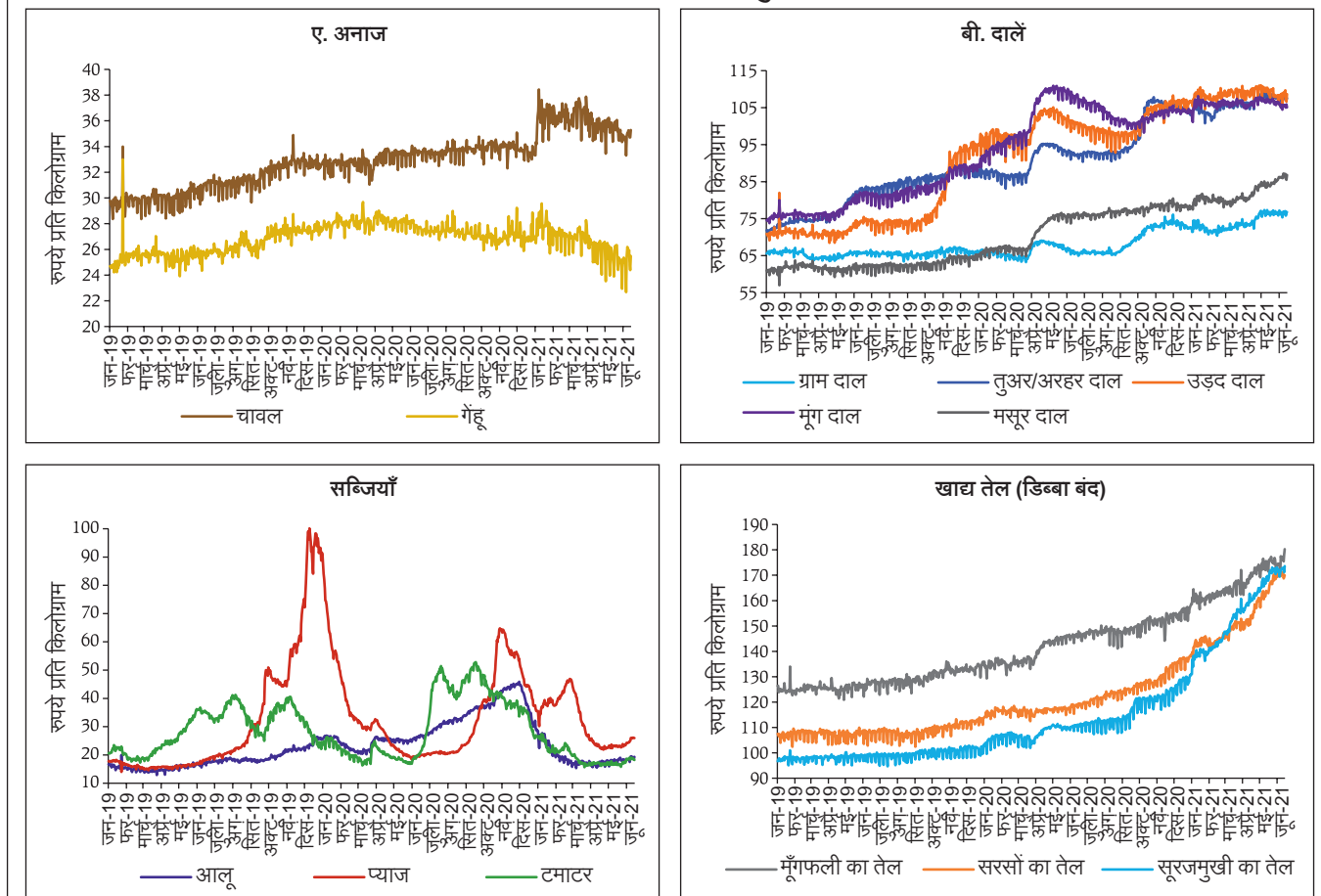
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) के उच्च आवृत्ति वाले खाद्य मूल्य डेटा जून की पहली छमाही में अनाज की कीमतों में और नरमी का संकेत देते हैं। दालों के तहत, अरहर, उड़द और मूंग की कीमतों में भी जून में अब तक कुछ नरमी दर्ज की गई है, हालांकि कीमतें एक साल पहले की तुलना में अधिक बनी हुई हैं। जून में खाद्य तेलों की कीमतों में और तेजी आई है। प्रमुख सब्जियों में, आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में तेजी आई है, हालांकि आलू और टमाटर की कीमतें अभी भी पिछले साल की तुलना में कम हैं (चार्ट 34)।

मई 2021 की शुरुआत से पेट्रोल और डीजल की घरेलू पंप कीमतों में वृद्धि जून में अब तक (जून 1-14, 2021) बेरोकटोक

जारी रही, जो नई ऐतिहासिक ऊंचाईयों को छू रही है। 31 मई, 2021 और 14 जून, 2021 के बीच पेट्रोल और डीजल पंप की कीमतें (चार प्रमुख महानगरों में कीमतों का औसत) क्रमशः ₹2.08 प्रति लीटर और ₹2.13 प्रति लीटर बढ़कर ₹98.26 प्रति लीटर और ₹91.01 प्रति लीटर हो गईं। जून में अब तक घरेलू मिट्टी के तेल की कीमतों में तेज वृद्धि दर्ज की गई जबकि एलपीजी की कीमतें स्थिर रहीं (सारणी 6)।

जैसा कि पीएमआई में परिलक्षित होता है, विनिर्माण और सेवाओं में इनपुट लागत मई 2021 में और बढ़ गई, हालांकि वृद्धि की दर पिछले चार महीनों में सबसे कम थी। सेवाओं के लिए बिक्री मूल्य मई 2021 में बड़े पैमाने पर स्थिर रहे, विनिर्माण में लागत के अपेक्षाकृत अधिक पास-थ्रू के प्रमाण के साथ।

चार्ट 34 : डीसीए आवश्यक वस्तुओं की कीमतें



स्रोत : उपभोक्ता मामलों का विभाग, भारत सरकार; और भारतीय रिजर्व बाइंक स्टॉफ आंकलन उपभोक्ता मामलों का विभाग



## सारणी 6: पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतें

मद	इकाई	घरेलू कीमतें			महीने दर महीने (प्रतिशत)	
		जून-20	मई-21	जून-21 ^	मई-21	जून-21
पेट्रोल	₹/लीटर	79.22	94.37	97.20	1.9	3.0
डीजल	₹/लीटर	72.98	86.68	89.93	2.5	3.7
मिट्टी का तेल (सब्सिडी)	₹/लीटर	15.45	30.38	32.13	0.2	5.7
एलपीजी (गैर-सब्सिडी)	₹/सिलेंडर	601.50	819.63	819.63	0.0	0.0

^: 1 जून -14, 2021 की अवधि के लिए।

नोट: मिट्टी के तेल के अलावा, कीमतें चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) में औसत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की कीमतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मिट्टी के तेल के लिए, कीमतें कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में रियायती कीमतों के औसत को दर्शाती हैं।

स्रोत: आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी); और भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ का अनुमान है।

## हाल की अवधि में सीपीआई-डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति विचलन

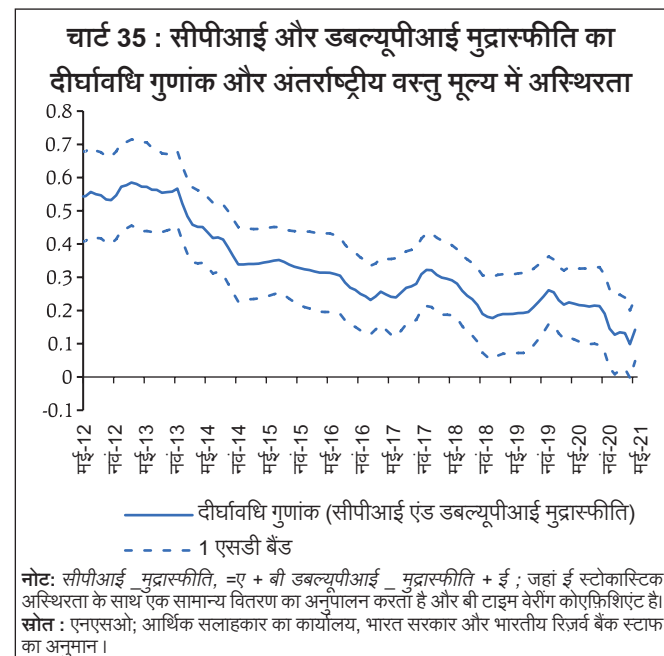
लॉकडाउन के बाद की अवधि में, सीपीआई और थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति दर काफी विचलन प्रदर्शित कर रही है। मई 2021 तक, डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति 12.9 प्रतिशत थी, जो सीपीआई मुद्रास्फीति 6.6 प्रतिशत अंक से अधिक थी। इसने खुदरा मुद्रास्फीति, विशेष रूप से मूल रूप से संभावित फैलाव के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस तरह के बड़े विचलन के एपिसोड अक्सर बुनियादी और मध्यवर्ती वस्तुओं और औद्योगिक उत्पादों की कीमतों के कारण होते हैं, जो सीपीआई में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन डब्ल्यूपीआई (दास और जॉर्ज, 2017<sup>19</sup>) का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। इनका बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार होता है, घरेलू कीमतें वैश्विक कमोडिटी मूल्य चक्रों से निकटता से जुड़ी होती हैं। अप्रैल-जुलाई 2020 के दौरान, अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी कीमतों में गिरावट के कारण डब्ल्यूपीआई ने निरंतर अपस्फीति दर्ज की; बाद में, एच 2: 2020-21 के बाद से कमोडिटी की कीमतों में तेज उछाल के साथ, डब्ल्यूपीआई ने अप्रैल-मई 2021 तक दोहरे अंकों में मुद्रास्फीति दर्ज की।

समय-भिन्न पैरामीटर प्रतिगमन का उपयोग करते हुए, अप्रैल 2012 से मई 2021 की अवधि के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) पर डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) का गुणांक नवंबर 2013 में 0.57 से घटकर मई 2021 में 0.14 हो जाने का अनुमान है (चार्ट 35)।

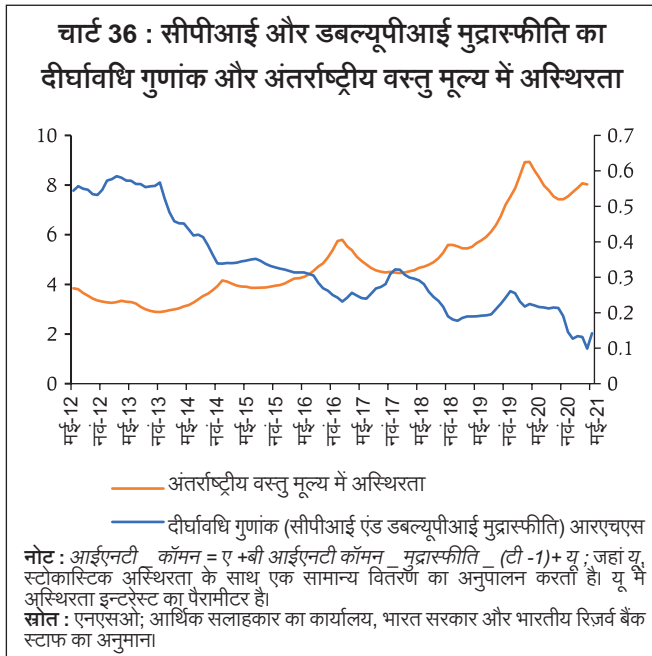
<sup>19</sup> दास, पी., एंड जॉर्ज, एटी (2017), "कम्पैरिजन ऑफ कन्ज्यूमर एंड होलसेल प्राइस इंडिसेस इन इंडिया : एन एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टीज एंड सोर्सिस ऑफ डाइवर्जेंस ", आरबीआई वर्किंग पेपर सीरीज, डब्ल्यूपीएस (डीईपीआर): 05/2017।

अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी कीमतों में समय-भिन्न अस्थिरता का अनुमान जब सीपीआई-डब्ल्यूपीआई गुणांक के साथ जोड़ा जाता है, तो दो के बीच एक मजबूत व्युत्क्रम संबंध (-) 0.79<sup>20</sup> (चार्ट 36) के सहसंबंध गुणांक के साथ दिखाई देता है।

यह इंगित करता है कि पिछले एक दशक में अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी की कीमतों में बढ़ती अस्थिरता के परिणामस्वरूप सीपीआई और डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति के बीच लंबे समय तक चलने वाले संबंध कमजोर हुए हैं।



<sup>20</sup> आरबीआई स्टाफ अनुमान।



**IV. वित्तीय स्थितियां**

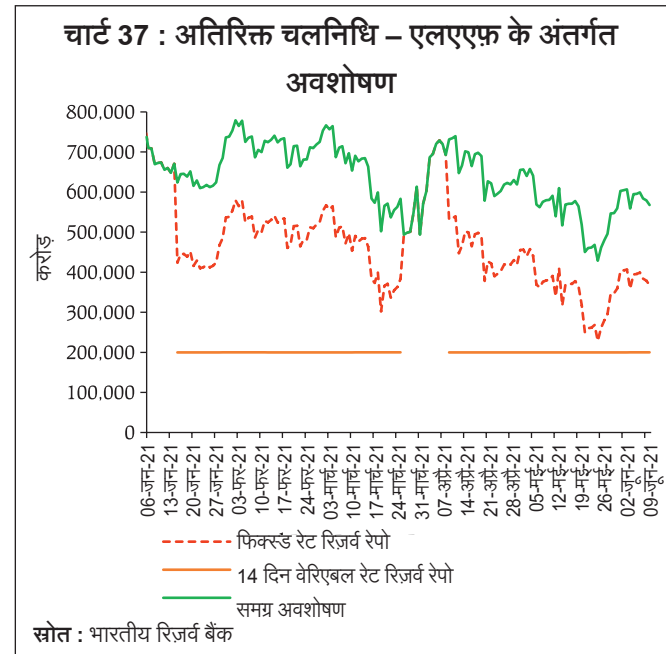
रिजर्व बैंक ने यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रणालीगत चलनिधि बहुतायत में बनी रहे, प्रणाली में अनुकूल वित्तीय स्थितियों को संचालित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया। गवर्नमेंट सिक्वोरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम (जी-एसएपी) 1.0 के तहत दूसरे दौर की खरीदारी 20 मई, 2021 को की गई थी, जिसकी राशि ₹35,000 करोड़ थी। इसे 3.5 के बिड-कवर अनुपात में यथा प्रतिबिंबित के रूप में एक सुखद प्रतिक्रिया मिली। जी-एसएपी 1.0 के तहत ₹40,000 करोड़ की खरीद का एक और दौर 17 जून को आयोजित किया जाएगा, जिसमें से ₹10,000 करोड़ राज्य विकास ऋण (एसडीएल) का गठन करेंगे। रिजर्व बैंक ने 4 जून, 2021 को जी -एसएपी 2.0 की भी घोषणा की - 2021-22 की दूसरी तिमाही के दौरान द्वितीयक बाजार से ₹1.2 लाख करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद।

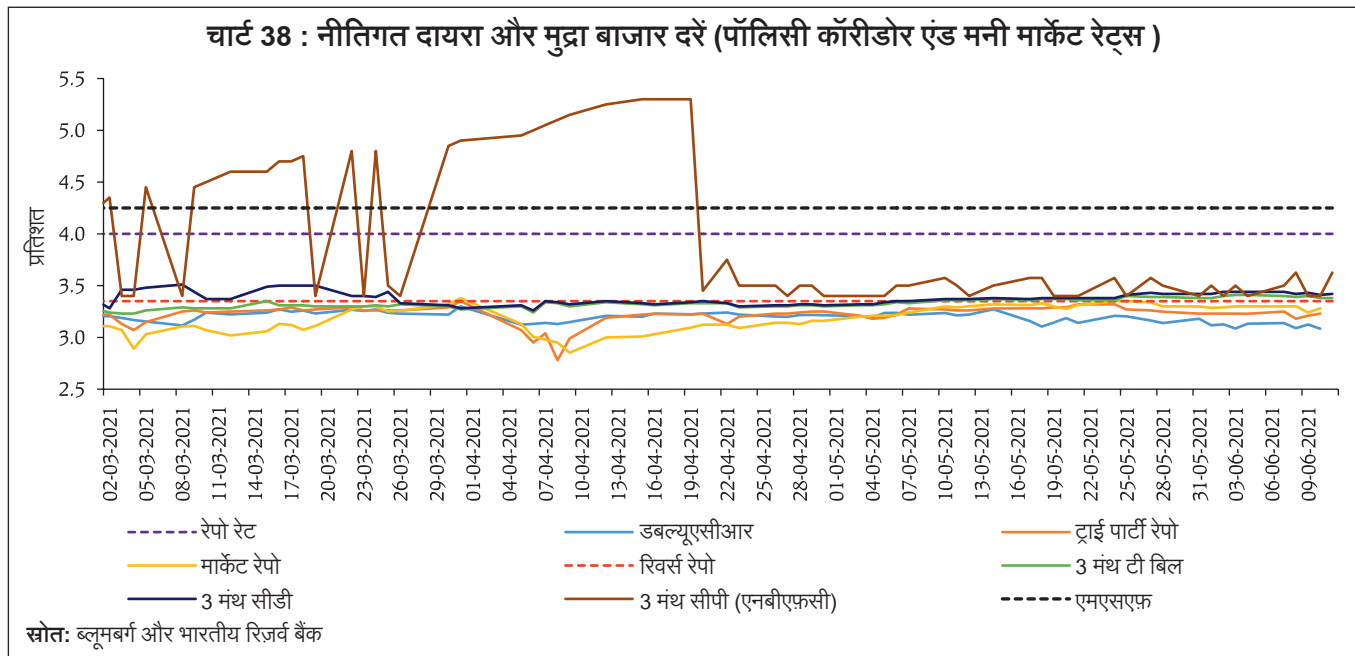
जून 2021 (14 जून तक) के दौरान औसत दैनिक शुद्ध अवशोषण फिर से बढ़कर ₹5.0 लाख करोड़ हो गया, जो पूंजी प्रवाह से सहायता प्राप्त है। चलनिधि के अन्य स्वायत्त चालकों के बीच, महामारी की दूसरी लहर के बीच नकदी की बढ़ी हुई एहतियाती मांग के साथ, 2021-22 में अब तक (4 जून तक) प्रचलन में मुद्रा का 1.2 लाख करोड़ रुपये तक विस्तार हुआ,

जिसने बैंकिंग प्रणाली से चलनिधि को भी समाप्त कर दिया। हालांकि, संचयी रूप से, स्वायत्त ड्राइवर्स के माध्यम से रिसाव ओएमओ के माध्यम से चलनिधि के संचालन और रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित विदेशी मुद्रा खरीद द्वारा ऑफसेट से अधिक था। परिणामस्वरूप, रिवर्स रेपो (फिक्स्ड और वेरिएबल रेट दोनों) परिचालनों के माध्यम से अवशोषित चलनिधि मई 2021 के दौरान औसतन ₹5.5 लाख करोड़ और जून में ₹5.8 लाख करोड़ थी (14 जून तक)(चार्ट 37)।

मई 2021 के दौरान गैर-संपार्श्विक खंड में रातोंरात दरें रिवर्स रेपो दर की ओर बढ़ गईं। मई 2021 में बीपीएस और 6 बीपीएस भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर), ट्राई-पार्टी रेपो और बाजार रेपो दर उप-रिवर्स रेपो दर स्तरों पर बनी रही, जो 16 बीपीएस, 9 से पीछे है (चार्ट 38)। जून में (14 जून तक) प्रणालीगत चलनिधि के विस्तार के रूप में, इन दरों में क्रमशः 24 बीपीएस, 12 बीपीएस और 6 बीपीएस की गिरावट आई। जून 2021 में (14 जून तक) टर्म मनी मार्केट रेट्स, यानी, 3 महीने की टी-बिल दर और 3 महीने की जमा प्रमाणपत्र (सीडी) दरें मई 2021 के दौरान क्रमशः अप्रैल-अप्रैल के स्तर से 9 बीपीएस और 11 बीपीएस तक बढ़ीं और समान स्तरों के आसपास कारोबार किया।

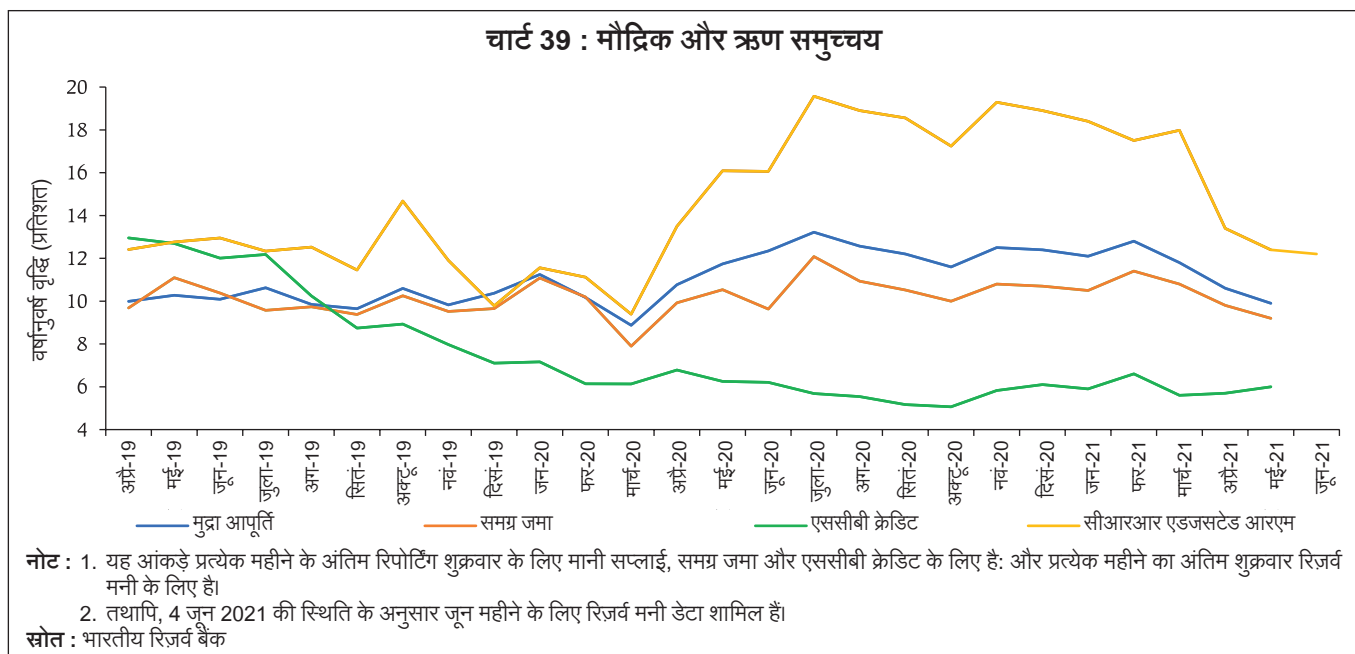
आर्थिक सुधार के समर्थन में कुल मिलाकर मौद्रिक/ऋण की स्थिति अनुकूल रही। वाणिज्यिक क्षेत्र में अनुसूचित वाणिज्यिक





बैंकों (एससीबी) के ऋण में 6.0 प्रतिशत (एक वर्ष पहले 6.2 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट 39)। इसके अलावा, वैधानिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियों और गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में एससीबी के निवेश के साथ-साथ क्रेडिट ऑफ़टेक को ध्यान में रखते हुए, अर्थव्यवस्था में उनके धन के प्रवाह में 7.0 प्रतिशत (एक साल पहले 8.8 प्रतिशत) का विस्तार हुआ।

मार्च 2020 से मई 2021 के दौरान, एससीबी की 1 साल की औसत सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) में कुल मिलाकर 95 बीपीएस की कमी आई, जो फंड की कुल लागत में कमी का संकेत है। इसी अवधि के दौरान, मध्यकालीन सावधि जमा दर (एमटीडीआर)-सभी अवधियों में ताजा जमा राशियों पर औसत कार्ड दरों का प्रतिनिधित्व करते हुए -144 आधार अंकों की गिरावट के साथ, एक वर्ष तक की परिपक्वता की छोटी अवधि



## सारणी 7: रेपो दर से बैंकों की जमा और उधार दरों में अंतरण

(आधार अंक)

अवधि	रेपो दर	सावधि जमा दरें		उधार दरें		
		माध्य सावधि जमा दर	डबल्यूएडीटीआर	1 - वर्ष मेडियन एमसीएलआर	डबल्यूएएलआर - बकाया रूपया ऋण	डबल्यूएएलआर - ताजा रूपया ऋण
फरवरी 2019 - सितंबर 2019	-110	-9	-7	-30	2	-40
अक्टूबर 2019 - मई 2021*	-140	-174	-148	-122	-109	-147
<b>मार्च 2020 - मई 2021*</b>	<b>-115</b>	<b>-144</b>	<b>-109</b>	<b>-95</b>	<b>-91</b>	<b>-116</b>
फरवरी 2019 - मई 2021*	-250	-210	-155	-154	-107	-187

\*: डबल्यूएएलआर और डबल्यूएडीटीडीआर पर नवीनतम डेटा अप्रैल 2021 से संबंधित है।

डबल्यूएएलआर : भारित औसत उधार दर।

डबल्यूएडीटीआर: भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर;

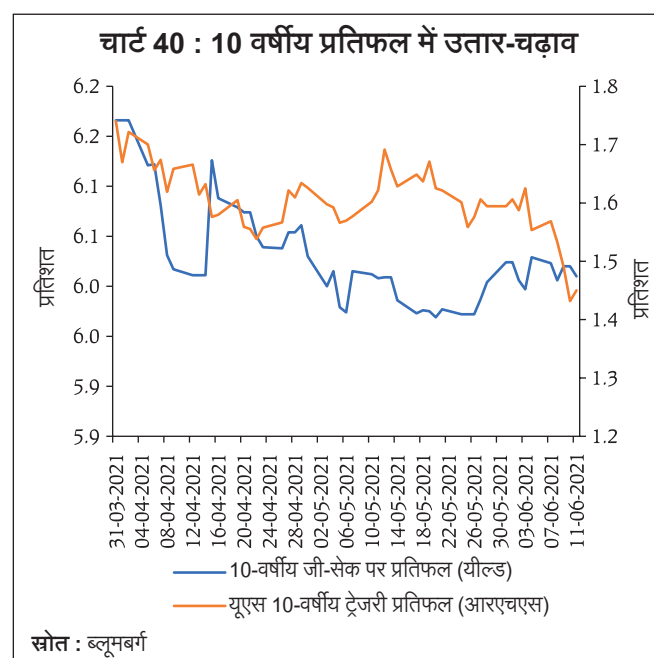
एमसीएलआर: फंड की सीमांत लागत आधारित उधार दर।

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

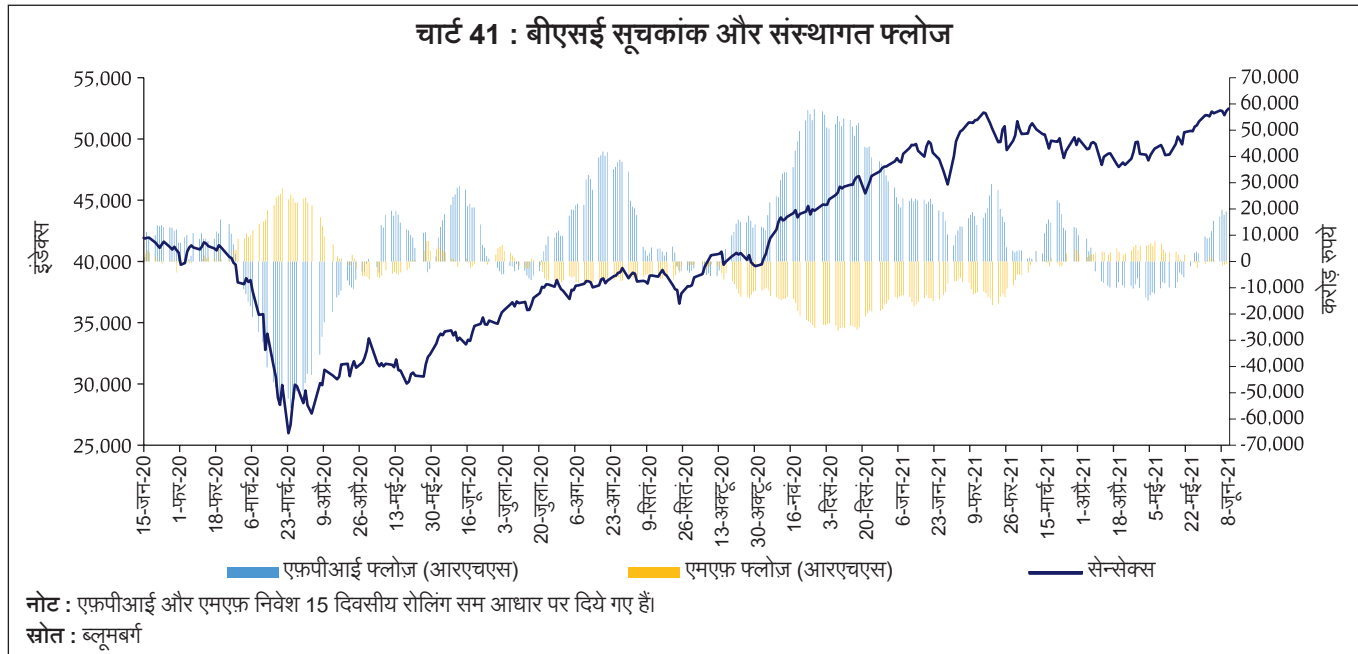
की जमा राशियों (156 बीपीएस) से ध्यान देने योग्य कमी आई। सभी बैंक समूहों में, सावधि जमा दरों में अधिकतम कटौती विदेशी बैंकों के संबंध में हुई, इसके बाद निजी बैंकों का स्थान रहा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जो छोटी बचत जैसे वैकल्पिक बचत साधनों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करते हैं, ने सावधि जमा दरों में अधिक मध्यम संचरण की अनुमति दी (सारणी 7)। स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स (एसएसआई) पर ब्याज दरें, जो अपेक्षित फॉर्मूला-आधारित दरों,<sup>21</sup> से अधिक हैं, की समीक्षा 30 जून, 2021 को की जाएगी।

निश्चित आय खंड में, मई 2021 के दूसरे पखवाड़े और जून 2021 की शुरुआत (चार्ट 40) में 10-वर्षीय जी-सेक पर यील्ड ने 6 प्रतिशत के स्तर के करीब कारोबार किया। अप्रैल 2021 के लिए अनुकूल सीपीआई मुद्रास्फीति प्रिंट, जी-एसएपी 1.0 नीलामियों के विश्वास-प्रेरक प्रभाव और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में नरमी ने प्रतिफल में गिरावट को जन्म दिया। तथापि, मई के अंत में अतिरिक्त आपूर्ति पर चिंताओं के बाद सरकार द्वारा ₹ 1.58 लाख करोड़ की अतिरिक्त उधारी की रिपोर्ट के बाद बाजार में गिरावट आई, जिससे 10 साल की जी-सेक यील्ड 6 प्रतिशत से ऊपर हो गई।

इसके बाद, यूएस ट्रेजरी यील्ड में नरम पड़ती गति के बीच, ति. 2:2021-22 के लिए जी-एसएपी 1.0 के तहत जी-एसएपी 2.0 के साथ युग्मित खरीद के एक और दौर की घोषणा के संकेतों द्वारा निर्देशित, बाजार एक संकीर्ण दायरे में रहा। प्राथमिक बाजार में, मई के दूसरे अर्ध भाग में और जून के पहले पखवाड़े में चार नीलामियां आयोजित की गईं, जिससे केंद्र सरकार द्वारा सकल उधारी ₹2.71 लाख करोड़ हो गई, इस प्रकार एच1: 2021-22 के लिए निर्धारित ₹7.24 लाख करोड़ में से लगभग 37 प्रतिशत को पूरा किया गया।



<sup>21</sup> लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें भारत सरकार द्वारा नियंत्रित और निर्धारित की जाती हैं। ये नियंत्रित ब्याज दरें एक अंतराल के साथ सरकारी प्रतिभूतियों पर बाजार प्रतिफल से जुड़ी होती हैं और तुलनीय परिपक्वता वाले जी-सेक प्रतिफल के ऊपर 0-100 बीपीएस के दायरे के स्प्रेड पर तिमाही आधार पर तय की जाती हैं।



मुख्य रूप से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और कॉर्पोरेट्स (अनुलग्नक सारणी ए1) के नेतृत्व में रेटिंग और जारीकर्ता कैटेगरी में मई 2021 के दौरान कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड में और कमी आई। हालांकि नीतिगत रेपो दर अपरिवर्तित बनी हुई है, कई पारंपरिक और अपरंपरागत नीतिगत उपायों ने अनुकूल वित्तीय स्थितियों को बढ़ावा दिया और कॉर्पोरेट बॉन्ड पर जोखिम प्रीमियम को कम किया।

भारतीय इक्विटी बाजारों ने मई 2021 की शुरुआत मंदी के साथ की, लेकिन रिजर्व बैंक द्वारा घोषित चलनिधि बढ़ाने के उपायों और पोर्टफोलियो प्रवाह को फिर से शुरू करने (चार्ट 41) के कारण मजबूती मिली। कोविड -19 केसलोड्स में लगातार गिरावट, रिकवरी और टीकाकरण में निरंतर वृद्धि से भारतीय इक्विटी को और बढ़ावा मिला। इन सकारात्मक घटनाक्रमों को दर्शाते हुए, मई 2021 के दौरान बीएसई सेन्सेक्स 6.5 प्रतिशत बढ़कर 51,937 पर बंद हुआ।

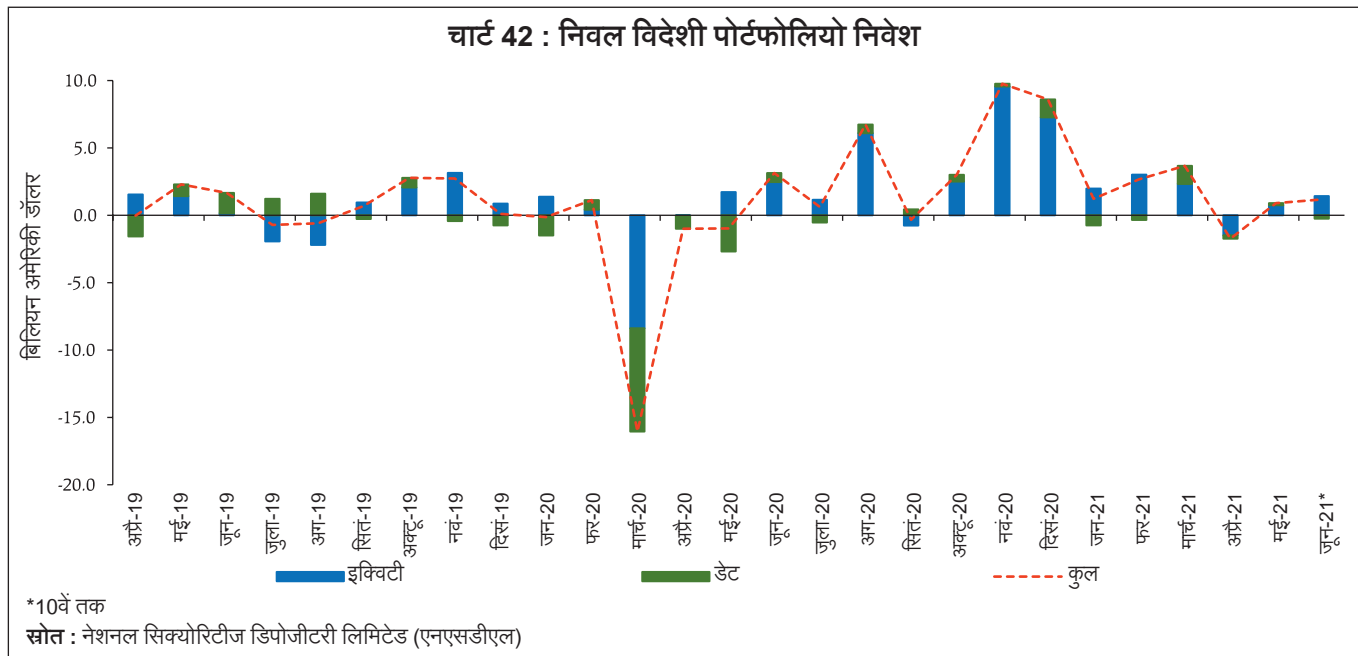
रोकथाम के उपायों में ढील की संभावनाओं से उत्साहित, घरेलू इक्विटी बाजारों ने जून 2021 में अपनी बढ़त को बढ़ाया, बीएसई सेन्सेक्स 1.2 प्रतिशत बढ़कर 14 जून, 2021 को 52,552 पर बंद हुआ। रिस्क-ऑन सेंटिमेंट के बीच, बीएसई मिडकैप और बीएसई स्मॉलकैप सूचकांकों में लाभ दर्ज किया गया, जिसमें जून

2021 में अब तक क्रमशः 4.7 प्रतिशत और 6.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

विदेशी प्रतिभूतियों को रखने के लिए प्राथमिकताओं में वृद्धि को दर्शाते हुए, विदेशों में निवेश करने वाले फंड ऑफ फंड्स (एफओएफ) द्वारा शुद्ध संसाधन जुटाना - विदेशी फंड में निवेश की गई कुल संपत्ति के न्यूनतम 95 प्रतिशत के साथ एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड योजना - मई 2020 को समाप्त 12 महीनों में ₹1,006 करोड़ से, मई 2021 को समाप्त 12 महीने में बढ़कर ₹10,850 करोड़ हो गई।

मई 2021 में, शुद्ध विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) का प्रवाह 0.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। एफपीआई ने 18 मई से 10 जून, 2021 के बीच इक्विटी सेगमेंट में 3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की शुद्ध खरीदारी की, जो भारत में कोविड -19 मामलों की संख्या में गिरावट के साथ मेल खाता है। इक्विटी बाजार में उच्च एफपीआई गतिविधि, अर्थव्यवस्था में एक आसन्न सुधार के बारे में उनके बढ़ते आत्मविश्वास को दर्शाती है, जो कॉर्पोरेट आय पर निवेशकों की पहले की चिंताओं को दूर करती है (चार्ट 42)।

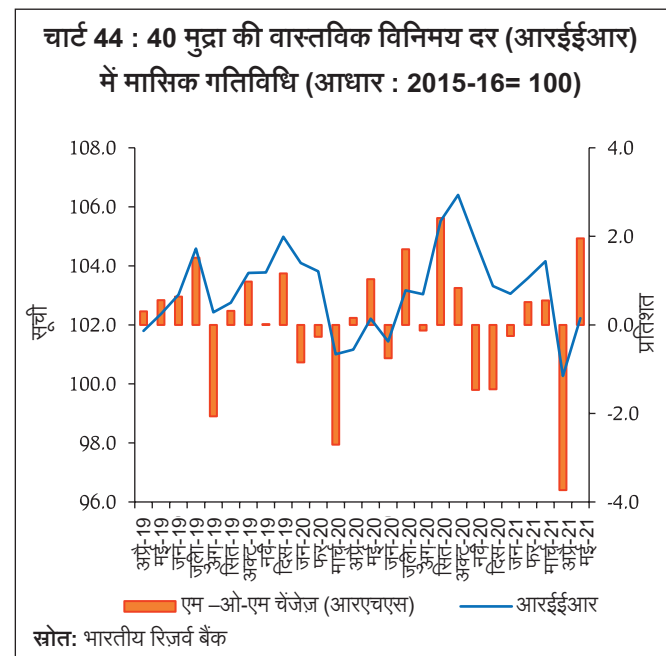
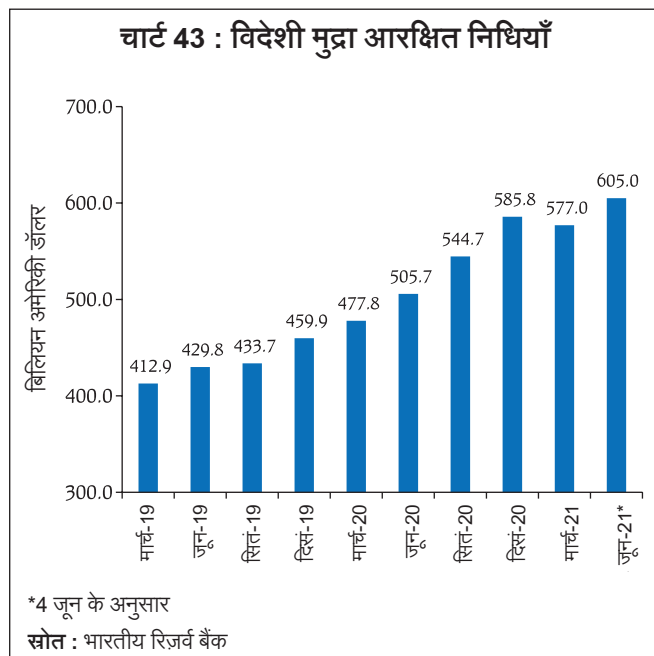
4 जून 2021 को विदेशी मुद्रा भंडार 605.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया (चार्ट 43)।



विदेशी मुद्रा बाजार में, भारतीय रुपया (आईएनआर) मई 2021 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ और जून में (11 तारीख तक) और बढ़ गया। 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक के संदर्भ में, आईएनआर एक महीने पहले के स्तर (चार्ट 44) की तुलना में मई 2021 में 2.0 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की।

#### भुगतान प्रणाली

डिजिटल स्पेस में, बोर्ड में भुगतान चैनलों ने मई 2021 (सारणी 8) में विकास (वर्ष-दर-वर्ष) का अनुभव किया, हालांकि यह आंशिक रूप से असामान्य रूप से उच्च आधार प्रभावों के कारण एक महीने पहले की तुलना में कम हुआ। मई 2021 में वास्तविक



**सारणी 8 : चुनिन्दा भुगतान प्रणालियों में वृद्धि दर**

भुगतान प्रणाली	लेनदेन की मात्रा में वृद्धि (वर्षानुवर्ष प्रतिशत)				लेनदेन के मूल्य में वृद्धि (वर्षानुवर्ष प्रतिशत)			
	अप्रै-2020	अप्रै-2021	मई-2020	मई-2021	अप्रै-2020	अप्रै-2021	मई-2020	मई-2021
आरटीजीएस	-52.6	178.8	-27.9	37.0	-42.7	36.6	-43.2	18.8
एनईएफटी	-13.5	62.7	-11.4	33.0	-36.4	56.6	-30.4	22.8
यूपीआई	27.9	164.2	68.3	105.6	6.4	226.6	43.3	124.5
आईएमपीएस	-33.8	163.7	-9.1	67.9	-28.4	147.3	-6.1	57.2
एनएसीएच	64.4	-48.6	-1.2	53.6	6.3	14.9	14.2	1.8
एनईटीसी	-60.5	1500.8	100.5	111.1	-57.7	1021.6	85.3	86.0
बीबीपीएस	44.6	175.2	68.4	137.1	29.9	279.4	57.2	187.8

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

समय सकल निपटान (आरटीजीएस), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी), एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई), तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) जैसी प्रमुख भुगतान प्रणालियों में लेनदेन की मात्रा और मूल्यों दोनों में पूर्ण रूप से कटौती की गई है। फिर भी, जून 2021 की शुरुआत के डेटा अधिकांश प्लेटफार्मों में फिर से शुरू होने वाले विकास की ओर इशारा करते हैं।

**V. निष्कर्ष**

हाल के इतिहास में शायद सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियां होने के बावजूद, टीके अपने आप महामारी को समाप्त नहीं करेंगे। हमें स्वास्थ्य देखभाल, रसद और अनुसंधान में निवेश बढ़ाने के साथ टीकों को पूरक करते हुए वायरस के साथ जीना सीखना होगा। वास्तविक परिणामों के साथ महामारी एक वास्तविक सदमा है। इसलिए, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वसूली व्यापार निवेश और उत्पादकता वृद्धि की ठोस नींव पर बनी है। जीवन और कार्य-शैली में परिवर्तन जैसे कि दूरस्थ कार्य और ऑनलाइन खरीदारी में वृद्धि की संभावना हो सकती है। जब मांग का पैटर्न बदलता है, तो कुछ फर्मों को बंद होने का सामना करना पड़ सकता है। कुछ उद्योग स्थायी रूप से छोटे हो सकते हैं। इसी समय, उद्योगों में मौजूदा फर्मों की बढ़ती मांग का विस्तार हो सकता है और नए उभरेंगे। जो मायने रखता है वह यह है कि संसाधनों को उनके सर्वोत्तम उपयोग में लाया जाता है और यह कि पुनः आवंटन सुचारू रूप से और यथासंभव कम लागत के साथ हो (कास्टर्न, 2021) <sup>22</sup>। एक प्रभावशाली नजरिया उन तीन

<sup>22</sup> बीएनपी परिबास 2021 ग्लोबल ऑफिशियल इन्सटीट्यूट्स कॉन्फरेंस, बासल, 9 जून 2021 में "द स्टेट ऑफ ग्लोबल इकॉनॉमी" पर भाषण।

क्षेत्रों की पहचान करता है जिनमें रिकवरी के बाद के दशक में सबसे ज्यादा विकास की संभावना है (स्पेंस, 2021) <sup>23</sup> : डिजिटल प्रौद्योगिकियां; जैव चिकित्सा विज्ञान (स्वास्थ्य देखभाल में इसकी एप्लीकेशन्स के साथ); और प्रौद्योगिकियां जो स्थिरता के लिए विभिन्न चुनौतियों का समाधान करती हैं, खासकर जलवायु परिवर्तन से संबंधित। जैसा कि विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की, एक निराशावादी हर अवसर में कठिनाई देखता है; और आशावादी व्यक्ति को हर कठिनाई में अवसर दिखाई देता है। <sup>24</sup>

वैश्विक मैक्रोइकॉनॉमिक आउटलुक पर विकसित हो रहे विमर्श के माध्यम से मुद्रास्फीति की बात तनाव को बढ़ा रही है। बाजार और विश्लेषकों का मानना है कि मुद्रास्फीति लंबी अवधि में बढ़ रही है और मौद्रिक प्राधिकारियों के हाथ को अल्ट्रा-एकोमोडेशन छोड़ने के लिए मजबूर कर देगी। केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति में वृद्धि को क्षणभंगुर के रूप में देखते हैं और अपने आसान नीतिगत रुख को वापस डायल करने के बारे में अटकलों पर बात करते हैं। आने वाले हर डेटा के साथ संघर्ष भड़क उठता है। नवीनतम घटनाक्रम में, हालांकि, यूएस सीपीआई मुद्रास्फीति मई में 5 प्रतिशत बढ़ी, जो लगभग 13 वर्षों में सबसे अधिक है। विरोधाभासी रूप से, यह बांड की कीमतों में एक वैश्विक रैली से मिला, जिसने अमेरिकी बेंचमार्क 10-वर्षीय प्रतिफल को 1.48 प्रतिशत तक ले लिया, मार्च 2021 के बाद से इसका सबसे निचला स्तर, और दुनिया भर के अन्य सरकारी बॉन्ड बाजारों को अपने ज्वार में उठा लिया। क्या मुद्रास्फीति को लेकर बाजार की चिंता कम होने लगी है, और क्या यह बहस के दूसरे पक्ष की ओर मुड़ रही है? बाजार आधारित मुद्रास्फीति की उम्मीदें - 10 साल की ब्रेक-ईवन - गिरावट पर हैं।

विश्लेषकों का तर्क है कि मुद्रास्फीति में वृद्धि मामूली और अस्थायी दोनों हो सकती है, लेकिन उनके विचार में, कई केंद्रीय बैंकों ने खुद को बहुत धीमी प्रतिक्रिया में बंद कर दिया है - "परिणाम-आधारित" "पूर्वानुमान-आधारित" नीति के विपरीत अनिवार्य रूप से एक अतिवादी प्रतिक्रिया होगी, नीति और

<sup>23</sup> ए माइकल स्पेंस, हाइ ग्रोथ सेक्टर्स इन पोस्ट-रिकवरी डिकेड, प्रोजेक्ट सिंडिकेट, 29 अप्रैल 2021।

<sup>24</sup> विंस्टन चर्चिल की उक्तियां (रा)। BrainyQuote.com. Retrieved June 4, 2021, from BrainyQuote.com वेब साइट: [https://www.brainyquote.com/quotes/winston\\_churchill\\_103739](https://www.brainyquote.com/quotes/winston_churchill_103739) से 4 जून, 2021 को लिया गया।

परिणामों के बीच अंतराल को देखते हुए, जैसा कि 1970 के दशक में ब्रूटल वोलकर अवस्फीति के साथ देखा गया था। एक गंभीर मौद्रिक तंगी अब विनाशकारी होगी (वुल्फ, 2021<sup>25</sup>)। इस गतिरोध के तहत, विश्लेषकों को बड़े मौद्रिक और राजकोषीय प्रोत्साहन को कुल मांग और संभावित आपूर्ति के बीच के अंतर के अनुपात के रूप में देखते हैं। वे इस तथ्य की ओर भी इशारा करते हैं कि जलवायु परिवर्तन (राजा, 2021)<sup>26</sup> जैसे बदलावों से उनके मुद्रास्फीति मैनेजेंट्स कमजोर हो रहे हैं। यह इंगित किया गया है कि मार्केट फ्रॉथ के संकेत कई गुना बढ़ रहे हैं और बढ़ती वस्तुओं की कीमतों पर इनपुट लागत दबाव के बारे में पहले की तुलना में अधिक चेतावनी दी जा रही है। जबकि मुद्रास्फीति में वृद्धि का महामारी के आधार प्रभावों से बहुत कुछ लेना-देना हो सकता है, यह वर्षों के कम निवेश से भी प्रेरित होता है, जिससे आपूर्ति प्रतिक्रिया कम गतिशील हो जाती है और यह आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं से बढ़ जाती है। इस स्थिति में, मौद्रिक नीति अपने स्वयं के रुख के लिए बंधक है और इससे उत्पन्न होने वाली मंद वित्तीय स्थितियां बाजारों में अत्यधिक जोखिम लेने का कारण बनती हैं, भले ही मुद्रास्फीति ऊपर की ओर बढ़ती है। अंततः, मौद्रिक ब्रेक को वक्र के पीछे से लाना होगा और जो एक लंबी, समावेशी वसूली हो सकती थी, उसे कम कर दिया जाएगा (एल एरियन, 2021)<sup>27</sup>।

इसके विपरीत, केंद्रीय बैंकों ने बार-बार दोहराया है कि कीमतों में बढ़ोतरी का मौजूदा दौर अस्थायी है, और यह उन्हें मौद्रिक प्रोत्साहन को जल्दी खोलने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। वे तब तक नीति को अति-समायोज्य बनाए रखने की प्रतिज्ञा करते हैं, जब तक कि एक टिकाऊ पुनर्प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है, जिसमें सभी को शामिल किया गया है। ईसीबी का मानना है कि कुछ अड़चनें जिनके कारण उच्च मुद्रास्फीति हुई है, वे धीरे-धीरे दूर हो जाएंगी क्योंकि यह आपूर्ति प्रतिक्रिया (लगार्ड, 2021)<sup>28</sup> का मामला है। यह बताया गया है कि अभी भी महत्वपूर्ण आर्थिक मंदी है, और इसे केवल धीरे-धीरे ही अवशोषित किया जाएगा।

मध्यम अवधि की चिंताओं को पूरा करने वाली मौद्रिक नीति रणनीति के साथ, इसका मतलब है कि अल्पकालिक उतार-चढ़ाव को देखा जाना चाहिए (श्राबेल, 2021)<sup>29</sup>। अमेरिका में, बाजार में निहित मुद्रास्फीति की उम्मीदें केवल उन स्तरों तक बढ़ी हैं जो 2010 की शुरुआत में प्रचलित थीं, जिसके बाद मुद्रास्फीति कभी भी 2 प्रतिशत से ऊपर नहीं चली, और अधिकांश सर्वेक्षण उपाय समान संकेत भेज रहे हैं (क्वार्ल्स, 2021)<sup>30</sup>। इसके अलावा, प्रोत्साहन का नवीनतम दौर ब्याज दरों या मुद्रास्फीति की उम्मीदों में अत्यधिक वृद्धि के बिना खर्च और विकास का समर्थन करता प्रतीत होता है।

भारत में, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने हाल ही में बहस किया है। अपने 4 जून के प्रस्ताव में, इसने भारत में मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र को ऊपर और नीचे दोनों जोखिमों से आकार लेते देखा। इसके विचार में, विशेष रूप से कच्चे तेल, रसद लागत, उत्पाद शुल्क, उपकरण और करों की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी की कीमतें मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण के लिए ऊपर की ओर जोखिम पैदा करती हैं। दूसरी ओर, सामान्य दक्षिण-पश्चिम मानसून की उम्मीदें, दालों के बाजार में हाल ही में आपूर्ति पक्ष के हस्तक्षेप और दालों और खाद्य तेल की कीमतों को ठंडा करने के लिए आपूर्ति पक्ष के उपायों, और घटते संक्रमण के साथ रोकथाम के उपायों को कम करने वाली ताकतों के रूप में देखा जाता है। लागत दबाव और मुद्रास्फीति आगे बढ़ रही है। कमजोर मांग की स्थिति भी पास-श्रु कोर मुद्रास्फीति को प्रभावित कर सकती है। तदनुसार, एमपीसी ने 2021-22 में ऊपरी पहुंच में सीपीआई मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया लेकिन टोलरेंट बैंड के भीतर 5 प्रतिशत से थोड़ा अधिक जोखिम के साथ व्यापक रूप से संतुलित है (चार्ट 45)।

अंत में, अर्थव्यवस्था की स्थिति पर लेख विविध विचारों को उद्घाटित करता है। कुछ लोगों ने कहा है कि इसने बुलेटिन को पठनीय बना दिया है, कि यह आशा का एक बयान है, और

<sup>25</sup> <https://www.ft.com/content/9f1fcd5-7cd6-4a28-bc6b-fe867622e111>

<sup>26</sup> <https://www.ft.com/content/6f23cf87-0e66-4b6b-bf36-8c73f1bfbd9d>

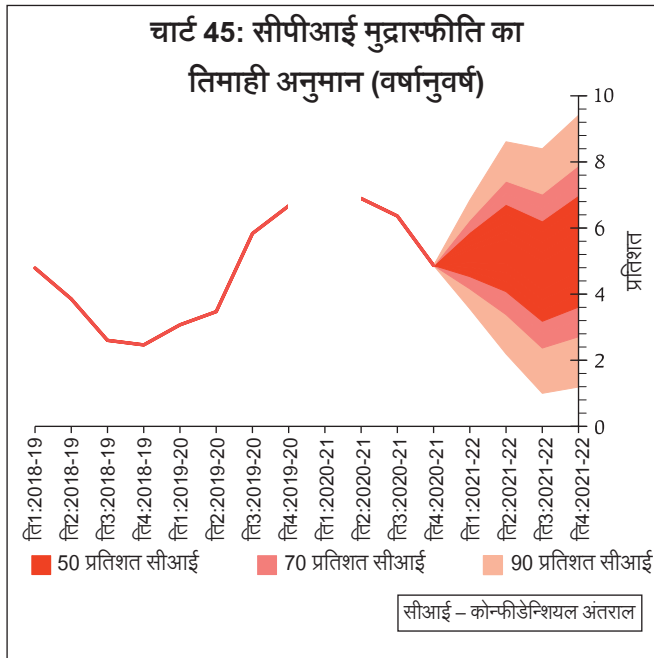
<sup>27</sup> <https://www.ft.com/content/46450be2-99dd-43ec-a9f3-9cf3c60d72e1>

<sup>28</sup> ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, 10 जून, 2021

<sup>29</sup> <https://www.ft.com/content/507d159a-9ae3-4f57-8427-434e950f7f8b>

<sup>30</sup> हचिन्स सेंटर ऑन फिस्कल एंड मॉनिटरी पॉलिसी में रेंडल के. क्वार्ल्स द्वारा मई 26, 2021 को आर्थिक और मौद्रिक नीति पर भाषण।





हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। अन्य कम दयालु रहे हैं, लेकिन वे पदार्थ के बजाय रूप के मुद्दों की ओर झुक गए हैं। उन्होंने हमसे बोरिंग होने की गृहार लगाई है। वे हमें ब्रोमाइड की पेशकश में शीर्ष पर जाने और ल्यूमिनरीज़ और उधार दर्शन को सूचीबद्ध करके उद्धरणों में शामिल होने के रूप में देखते हैं। हाँ, हम अपने पूर्वजों और अपने समकालीनों के ज्ञान पर भरोसा करते हैं, जिनके शब्द प्रकाश की तरह चमकते हैं, जिन्हें छिपाया नहीं जा सकता। आखिर ज्ञान एक जंजीर है, जिसका न आदि है और न अंत। कोई भी अपने आप में एक संपूर्ण द्वीप नहीं है; हर कोई महाद्वीप का एक टुकड़ा है, मुख्य<sup>31</sup> का एक हिस्सा है। इसलिए, हम 1675<sup>32</sup> में सर आइज़ैक न्यूटन के शब्दों को याद करने से बेहतर कुछ नहीं कर सकते :

"अगर मैंने आगे देखा है, तो यह जायंट्स के कंधों पर खड़ा है।"

<sup>31</sup> जॉन डन की पुस्तक "नो मैन इज एन आइलैंड" के अंश

<sup>32</sup> सर आइज़ैक न्यूटन ने 1675 में रॉबर्ट हुक को लिखे एक पत्र में यह टिप्पणी की थी

## सारणी ए 1 : कारपोरेट बॉन्ड प्रतिफल एंड स्प्रेड (3 -वर्ष)

जारीकर्ता	रेटिंग	यील्ड					स्प्रेड				
		मई-20	अप्रै-20	मई-21	भिन्नता	भिन्नता	मई-20	अप्रै-20	मई-21	भिन्नता	भिन्नता
					मई 2020 की तुलना में मई 2021	अप्रैल 2021 की तुलना में मई 2021				मई 2020 की तुलना में मई 2021	अप्रैल 2021 की तुलना में मई 2021
		प्रतिशत			(बीपीएस)		(बीपीएस)			(बीपीएस)	
पीएसयू, बैंक्स और एफआई	एएए	5.59	5.58	5.43	-16	-15	78	41	51	-27	10
	एए	6.34	6.27	6.20	-13	-7	153	110	129	-24	19
	बीबीबी	9.22	9.47	9.41	19	-7	441	430	449	8	19
कार्पोरेट्स	एएए	6.85	5.38	5.16	-170	-22	205	19	24	-180	5
	एए	7.61	6.08	5.94	-167	-14	281	94	103	-178	8
	बीबीबी	10.79	10.05	9.91	-88	-14	598	486	499	-99	13
एनबीएफसी	एएए	6.94	5.52	5.32	-163	-21	214	34	40	-173	7
	एए	7.81	6.78	6.50	-131	-28	301	160	158	-142	-1
	बीबीबी	11.26	11.04	10.76	-51	-29	645	586	584	-61	-2

नोट : प्रतिफल और स्प्रेड्स मासिक औसत हैं

स्रोत : एफआईएमएडीए

**अनुबंध बॉक्स 1: कोविड -19 और घरेलू वित्तीय बचत**

ऐसी धारणा है कि कोविड -19 महामारी ने आय धाराओं पर बढ़ती अनिश्चितता के बीच उपभोक्ता / परिवार की खपत और बचत व्यवहार को बदल दिया है। स्थायी आय परिकल्पना (पीआईएच) और जीवन चक्र मॉडल (एलसीएम) दोनों ही समय की अवधि में घरों की खपत को सुचारु बनाने पर जोर देते हैं। जबकि एलसीएम दिखाता है कि जीवन के एक चरण से दूसरे चरण में क्रय शक्ति को स्थानांतरित करने के लिए बचत का उपयोग कैसे किया जा सकता है, खपत आय और धन दोनों पर निर्भर करती है। आय में उतार-चढ़ाव पर परिवार/उपभोक्ता दो तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। अस्थायी आय के झटके के मामले में, उधार के माध्यम से परिवार सुचारु उपभोग करते हैं, वे स्थायी आय के झटके के मामले में अपने धन की रक्षा करते हैं। फ्रीडमैन का पीआईएच भी स्थायी आय और झटके की भूमिका को नकारात्मक/सकारात्मक अस्थायी आय के रूप में पहचानता है।

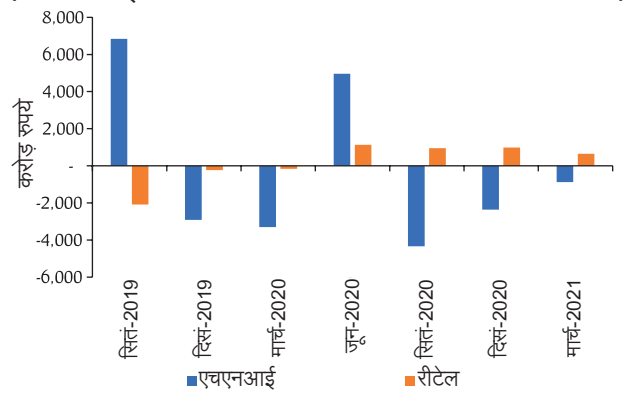
आय की उच्च अनिश्चितता के बीच, विवेकाधीन खर्च में गिरावट के साथ एहतियाती बचत में वृद्धि होती है, जैसा कि महामारी की अवधि के दौरान भारत पर निजी अंतिम उपभोग व्यय डेटा में परिलक्षित होता है। रिज़र्व बैंक के प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, 2020-21 की तीसरी तिमाही में घरेलू वित्तीय बचत पिछली दो तिमाहियों में 21 प्रतिशत और 10.4 प्रतिशत से घटकर जीडीपी के 8.2<sup>33</sup> प्रतिशत पर आ गई है।

**लिक्विड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ईटीएफ में परिवारों की बचत**

लिक्विड फंडस में उच्च निवल मूल्य व्यक्तियों (एचएनआई) और खुदरा व्यक्तियों की बचत<sup>34</sup> ति 1 में तेजी से बढ़ी जो 2020-21 में कोविड -19 प्रेरित लॉकडाउन से उत्पन्न अनिश्चितता के प्रभाव को प्रतिबिंबित करती है (चार्ट 1 ए और 1 बी)। परिवारों ने भी अपना पैसा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में लगाया। तब से, लिक्विड फंडों में एचएनआई का निवेश नकारात्मक रहा है (जिसका मतलब है कि गिरावट), लेकिन खुदरा व्यक्ति अपनी बचत को लिक्विड फंड में रखना जारी रखते हैं। गोल्ड ईटीएफ में एचएनआई और खुदरा व्यक्तियों का निवेश जून 2020 से सकारात्मक रहा है। लिक्विड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ईटीएफ में परिवारों की बचत 2020-21 की पहली तिमाही में बढ़ी, इसके बाद अगली दो तिमाहियों में गिरावट आई, इससे पहले इसमें फिर से तेजी आई। ति.4: 2020-21।

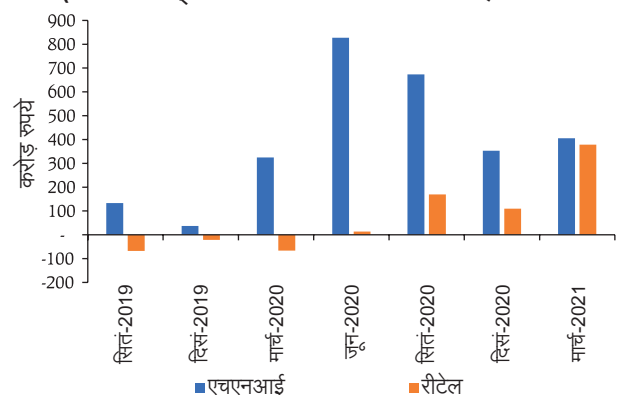
बैंक जमा<sup>35</sup> - परिवारों की कुल संपत्ति में लगभग 55 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ - अप्रैल 2020 में 1.1 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले अप्रैल 2021 के अंत में 0.1 प्रतिशत की कमी आई; जबकि बैंक अग्रिम - कुल देनदारियों में 79 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ - पिछले वर्ष के (-) 0.9 प्रतिशत की तुलना में 0.8 प्रतिशत अनुबंधिता बैंक जमा की तुलना में बैंक जमा में गिरावट की दर भी अधिक रही है, यह दर्शाता है कि इस बार घरेलू बचत के बैंकिंग क्षेत्र के घटक में पहली लहर के दौरान

**चार्ट 1 ए : चलनिधि निधियों में घरेलू बचत का विनियोजन (हाउसहोल्ड्स डिप्लॉयमेंट ऑफ सेविंग्स इन लिक्विड फंडस)**



स्रोत: भारिबैं स्टॉफ आकलन; और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंडस इन इंडिया (एएमएफआई)

**चार्ट 1 बी : गोल्ड ईटीएफ में घरेलू बचत का विनियोजन (हाउसहोल्ड्स डिप्लॉयमेंट ऑफ सेविंग्स इन गोल्ड)**



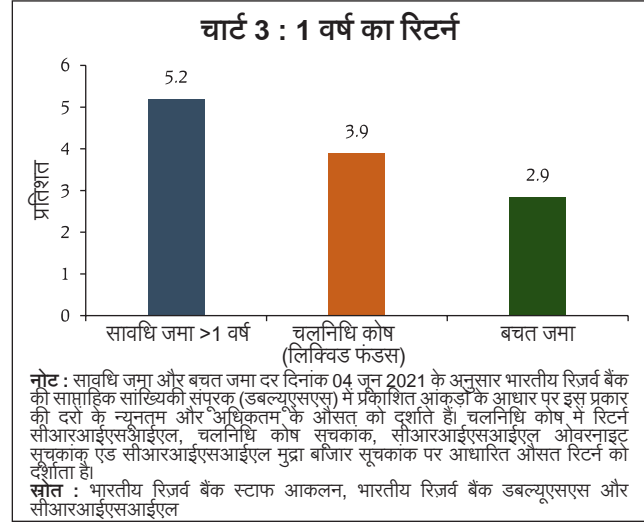
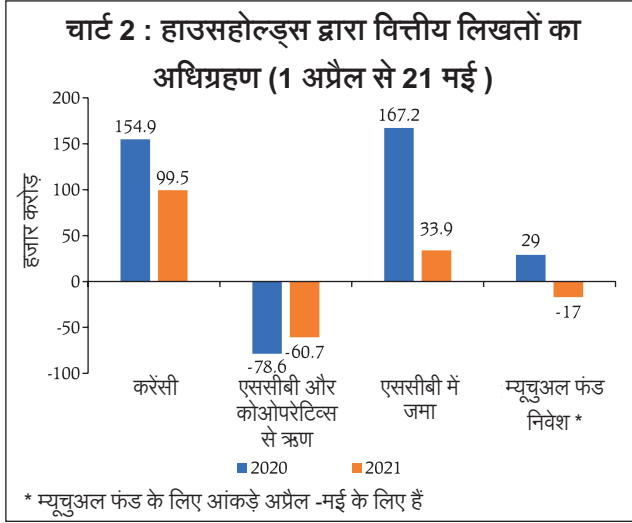
स्रोत: भारिबैं स्टॉफ आकलन; और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंडस इन इंडिया (एएमएफआई)

(Contd.)

<sup>33</sup> ति3: 2020-21 के लिए घरेलू वित्तीय बचत दर 31 मई, 2021 को जारी सकल घरेलू उत्पाद के अनंतिम अनुमान के कारण 8.1 प्रतिशत से संशोधित होकर 8.2 प्रतिशत हो गई है।

<sup>34</sup> में लिक्विड/ओवरनाइट/मनी मार्केट फंड शामिल हैं।

<sup>35</sup> अनुसूचित वाणिज्यिक और सहकारी बैंक।



देखी गई बचत में स्पाइक के विपरीत गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, जनता के पास मुद्रा धारण भी एक साल पहले के 3.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में अप्रैल 2021 के दौरान 1.7 प्रतिशत तक काफी कम हो गया है, जिसका अर्थ है कि कोविड प्रेरित चिकित्सा व्यय (चार्ट 2) के लिए भारी व्यय।

अप्रैल 2021 को समाप्त अवधि के लिए लिक्विड फंडों पर औसत 1 साल का कर-पूर्व रिटर्न 04 जून 2021 (चार्ट 3) की बचत

जमा दर से अधिक है। इसके अलावा, लिक्विड फंड (तीन साल से अधिक) के दीर्घकालिक धारकों द्वारा अर्जित रिटर्न पर कर देनदारियां बैंक जमा धारकों की तुलना में व्यक्तियों, विशेष रूप से उच्च आय वाले स्लैब वाले व्यक्तियों के लिए कम हो जाती हैं। इसलिए, कम ब्याज दरों के परिदृश्य में, विभिन्न उपकरणों पर रिटर्न की अलग-अलग उम्मीदें कुछ परिवारों की बचत प्राथमिकताओं को बदल सकती हैं।

## भारत के राष्ट्रिक प्रतिफल वक्र के आकार का एक समष्टि-आर्थिक दृष्टिकोण\*

अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रभावित करने में मौद्रिक नीति के लिए राष्ट्रिक प्रतिफल वक्र का विशेष महत्व है। एक गतिशील उपादान मॉडल में प्रतिफल वक्र के अंतर्निहित कारकों के साथ समष्टि-आर्थिक चरों को स्पष्ट रूप से एकीकृत करते हुए, परिणाम बताते हैं कि प्रतिफल वक्र के स्तर में 2019 की दूसरी तिमाही से गिरावट आई है, जो मौद्रिक नीति के अत्यधिक समायोजनकारी रुख को दर्शाता है। प्रचुर मात्रा में चलनिधि के कारण अल्पकालिक ब्याज दरों में आनुपातिक रूप से अधिक कमी आ रही है और प्रतिफल वक्र में गिरावट आती जा रही है, जबकि अत्यधिक दीर्घावधि वाणिज्यिक पत्र (अल्ट्रा-लॉन्ग डेटेड पेपर) जारी करने में बढ़त हुई है। वैश्विक नीति की अनिश्चितता प्रतिफल वक्र के स्लोप और कर्वेचर को प्रभावित करती है, जो भारत में बॉन्ड बाजारों के बढ़ते एक्स्पोजर को वैश्विक प्रभाव-विस्तार में द्योतित करता है। आउट ऑफ सैंपल पूर्वानुमानों से अधिक लंबी अवधि के प्रतिफल के मौजूदा स्तरों से मॉडरेशन के लिए गुंजाइश का संकेत मिलता है।

"वित्तीय बाजार स्थिरता और प्रतिफल वक्र का क्रमिक विकास सार्वजनिक मर्दे हैं और इस संबंध में यह बाजार सहभागियों और आरबीआई दोनों की साझा जिम्मेदारी है।"

श्री शक्तिकांत दास, अक्टूबर 2020<sup>1</sup>

फरवरी के अंत और मार्च 2021 की शुरुआत में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में फ्लैश बॉन्ड की बिकवाली हुई और भारत में भी यही स्थिति देखी गई, जिससे हर जगह राष्ट्रिक प्रतिफल वक्र में गिरावट आती गई। हालांकि यह उथल-पुथल अल्पकालिक थी, लेकिन इसने उस असहज शांति को दूर कर दिया जो उस समय तक बनी हुई थी। बॉन्ड बाजारों और मौद्रिक नीति प्राधिकारियों का आमना-सामना हुआ, दोनों ने पहले झुकने से अनिच्छा जताई।

\* यह आलेख भारतीय रिजर्व बैंक के श्री माइकल देब्रत पात्र, श्री हरेन्द्र बेहरा और जॉइस जॉन द्वारा तैयार किया गया है। लेखक श्री सीतीकंठ पट्टनायक, श्री समीर रंजन बेहरा और श्री ए. एम. कुशवाहा को उनकी टिप्पणियों, सारगर्भित चर्चा और आंकड़ों में सहायता के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

<sup>1</sup> गवर्नर महोदय का वक्तव्य, 9 अक्टूबर, 2020

बाजारों के लिए, राजकोषीय प्रोत्साहन, मौद्रिक निभाव, वैकसीन रोलआउट और रुकी हुई मांग (पेंट-अप डिमांड) के निर्माण का संयोजन से वृद्धि पूर्वानुमानों में ऊर्ध्वगामी संशोधन हुआ और इस दिशा में, बॉन्डों के नेमेसिस- मुद्रास्फीति जो मौद्रिक प्राधिकारियों के हाथ को अत्यधिक समायोजनकारी रुख को छोड़ने और जल्द-से-जल्द कसने के लिए मजबूर करेगी। दूसरी ओर, दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने इस बात पर जोर दिया है कि वे समायोजन पर टिके रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनके अनुसार, बॉन्ड व्यापारियों की उम्मीदों को परिणामों से अधिक होने और अभी भी नाजुक और मुश्किल से किए गए आर्थिक सुधार को कमजोर करने के लिए जोखिम की संभावना बहुत अधिक है।

भारत में, बेंचमार्क 10-वर्षीय प्रतिफल, जो अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 के दौरान औसतन 5.93 प्रतिशत था, केंद्र सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम की घोषणा पर 2 फरवरी को बढ़कर 6.13 प्रतिशत हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 5 फरवरी को कई उपायों की घोषणा के बाद, बेंचमार्क प्रतिफल 11 फरवरी तक 5.96 प्रतिशत तक सामान्य हो गया। इसके बाद पूर्व में संदर्भित वैश्विक प्रभाव-विस्तार से हलचल मच गई; 5 मार्च तक भारत में बेंचमार्क प्रतिफल 6.23 फीसदी पर पहुंच गया था, लेकिन आरबीआई की बड़े आकार के ऑपरेशन ट्विस्ट्स की घोषणाओं ने चिंताओं को समाप्त किया और 9 मार्च को इसे लगभग 6.21 प्रतिशत पर ला दिया। तब से इसमें काफी ढील दी गई है और इस आलेख के मुद्रण होने के समय तक ट्रेडिंग रेंज लगभग 6 प्रतिशत तक सीमित थी।

मौद्रिक नीति के लिए राष्ट्रिक प्रतिफल वक्र का विशेष महत्व है। वास्तव में, अपरंपरागत मौद्रिक नीति कार्रवाइयों और रुखों की विशेषता वाले असाधारण समय में, यह नीति निर्धारण का केंद्र-बिंदु है। पहला, नीतिगत दरों के जीरो बाउंड पर होने के कारण, मौद्रिक नीति संचरण का सामान्य माध्यम निष्क्रिय है। तदनुसार, नीति निर्माताओं ने वित्तीय स्थितियों को अधिक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने के लिए ब्याज दर संरचना के अंत में छलांग लगाने का प्रयास किया है दूसरा, राष्ट्रिक प्रतिफल वक्र वह बेंचमार्क है जिससे अन्य वित्तीय लिखतों की कीमत तय की जाती है (दास, 2020ए)। प्रतिफल वक्र को प्रभावित करके, केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रभावित कर सकते हैं और इस तरह समग्र लागत की स्थिति को प्रभावित

कर सकते हैं। तीसरा, प्रतिफल वक्र जोखिम प्रीमियम की प्रवृत्ति में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो इस बात का सुराग प्रदान करती है कि मौद्रिक नीति को इन बहिर्जात कारकों पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। चौथा, जब जोखिम प्रीमियम को अलग कर दिया जाता है, प्रतिफल वक्र भविष्य की वृद्धि और मुद्रास्फीति के बारे में अपेक्षाओं को शामिल करता है और यह भविष्योन्मुखी मौद्रिक नीति के संचालन के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शिका है। पांचवां, केंद्रीय बैंकों के लिए, जो अधिदेश द्वारा सार्वजनिक ऋण के जारीकर्ता भी हैं, प्रतिफल वक्र गतिकी की एक अच्छी समझ बाजार में ऋण को न्यूनतम लागत और रोलओवर जोखिम पर रखने में मदद करती है। अंत में, नीति निर्माता बाजार की मौद्रिक नीति की अपेक्षाओं के बारे में जानने के लिए प्रतिफल की मीयादी संरचना से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

प्रतिफल आम तौर पर केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित अल्पकालिक ब्याज दर का एक संयोजन है, भविष्य की अपेक्षित अल्पकालिक ब्याज दर आमतौर पर मौद्रिक नीति की अवस्थिति और अवधि प्रीमियम में सन्निहित है। चूंकि प्रीमियम शब्द प्रत्यक्ष रूप से काबिल-ए-गौर नहीं है, इसलिए इसे कुछ मान्यताओं के तहत तैयार किया जाना है। प्रारंभिक मॉडल ब्याज दरों की अवधि की संरचना की अपेक्षाओं की परिकल्पना पर आधारित थे, जिसने बॉन्ड की परिपक्वता अवधि पर प्रतिफल को अल्पकालिक ब्याज दरों का औसत अपेक्षित स्तर माना (फिशर, 1896; फ्रूट, 1989)। हालाँकि, प्रत्याशा की परिकल्पना के लिए अनुभवजन्य समर्थन कमजोर है (गुर्कानक और राइट, 2012)। एक अन्य दृष्टिकोण, बाजार विभाजन परिकल्पना है जिसमें कहा गया है कि दीर्घावधि और अल्पकालिक ब्याज दरें एक-दूसरे से संबंधित नहीं हैं और उन्हें अलग-अलग बाजारों में अलग-अलग मर्दों की तरह देखा जाना चाहिए (कैंपबेल, 1980)। प्रतिफल वक्र प्रत्येक बाजार/ऋण सुरक्षा की श्रेणी के भीतर आपूर्ति और मांग बलों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, और परिपक्वता की एक श्रेणी के लिए प्रतिफल का उपयोग परिपक्वता की एक अलग श्रेणी के लिए प्रतिफल का पूर्वानुमान लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है। अवधि, बॉन्ड विशेषताओं और निवेश की आदतों के संदर्भ में प्रत्येक खंड के लिए बाजार विशिष्ट निवेशक प्राथमिकताओं से प्राप्त होता है (आंग और पियाज़ेसी, 2003)। खंडित बाजार परिकल्पना का प्रतिफल वक्र के किसी विशेष आकार को समझाने

के लिए सबसे अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है, हालांकि यह सकारात्मक स्लोपिंग वक्रों हेतु सबसे सुयोग्य है। हालाँकि इसका उपयोग संपूर्ण प्रतिफल वक्र की व्याख्या करने के लिए नहीं किया जा सकता है, चाहे वह किसी भी आकार में हो, और इसलिए विश्लेषण के दौरान कोई सूचना सामग्री प्रदान नहीं करता है, अर्थात् अपने आप में यह पर्याप्त नहीं है (टेलर एंड मैसन, 1991; गुर्कानक और राइट, 2012)। वित्त साहित्य में, उपादान मॉडल लोकप्रिय हैं और आम तौर पर बिना किसी अंतरपणन (आर्बिट्रेज) प्रतिबंध को लागू करते हैं- समान जोखिम विशेषताओं वाली प्रतिभूतियों की कीमत समान होती है। इन मॉडलों में, अव्यक्त या अप्रकट कारक प्रतिफल संरचना की व्याख्या करते हैं और उन्हें आम तौर पर स्तर, स्लोप और कर्वचर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि, वे समष्टि-आर्थिक स्थितियों के बारे में प्रतिफल का निर्माण से जुड़ी किसी भी जानकारी से अछूते हैं। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर ऐसे मॉडल हैं, जो प्रतिफल वक्र के समष्टि-आर्थिक निर्धारक तत्वों पर निर्भर होते हैं (डाइबॉल्ड और अन्य, 2006)।

यह आलेख साहित्य में हालिया और तेजी से बढ़ते हुए स्टैंड में एक आधारभूत अप्रकट उपादान मॉडल में समष्टि-आर्थिक निर्धारक-तत्वों को स्पष्ट रूप से एकीकृत करने में शामिल होता है। इस क्षेत्र में मौलिक कार्य ने एक ऐसे मॉडल को प्राथमिकता दी जिसमें समष्टि-आर्थिक और वित्तीय चरों को एकीकृत किया जाता है ताकि दो-तरफा आकस्मिक घटना पर विचार करके प्रतिफल वक्र का अनुमान लगाया जा सके। समष्टि-आर्थिक चर के लिए प्रतिफल वक्र के घटक, और इसके विपरीत- ताकि संभावित द्वि-दिशात्मक प्रतिक्रिया से प्रतिफल वक्र से अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था से प्रतिफल वक्र मॉडल में निहित रहें (डाइबॉल्ड और अन्य, 2006)। इस आलेख में, हम खुली अर्थव्यवस्था की गतिकी के साथ-साथ आरबीआई की चलनिधि और बाजार उधार लेने की कार्यनीतियों का एक खांका खींचने के लिए अतिरिक्त समष्टि चरों को शामिल करके इसका विस्तार करते हैं। मॉडल पैरामीटर का अनुमान लगाने के लिए बायेसियन विधियों को लागू किया जाता है क्योंकि असंप्रेक्षित चर से निपटने में कुशल हैं। परिणाम इंगित करते हैं कि हमारा हाइब्रिड मॉडल संप्रेक्षित प्रतिफल का भली-भांति पूर्वानुमान लगाता है। वे यह भी बताते हैं कि 2019 की दूसरी तिमाही से प्रतिफल वक्र के स्तर में गिरावट आई है, जो दीर्घावधि प्रतिफल पर अत्यधिक समायोजनकारी

मौद्रिक नीति के प्रभाव को दर्शाता है; हालांकि अल्पकालिक ब्याज दरों को कम करने वाली प्रचुर मात्रा में चलनिधि और अत्यधिक दीर्घावधि वाणिज्यिक पत्रों को जारी करने में तेजी के कारण प्रतिफल वक्र में गिरावट दर्ज की गई है। अन्य समष्टि-आर्थिक निर्धारक-तत्वों के बीच, वैश्विक नीति की अनिश्चितता प्रतिफल वक्र के स्लोप और कर्वेचर को प्रभावित करती है, जो भारत में बॉन्ड बाजारों के बढ़ते एक्सपोजर को वैश्विक प्रभाव-विस्तार में द्योतित करता है।

शेष आलेख को चार खंडों में व्यवस्थित किया गया है: खंड II में हालिया प्रतिफल वक्र गतिकी और भारत में सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) बाजार को प्रभावित करने वाले कारकों पर कुछ शोधपरक तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, खंड III प्रतिफल वक्र के निर्धारक तत्वों का पता लगाने के लिए एक पद्धतिगत ढांचे पर चर्चा करता है और उसके परिणाम खंड IV में प्रस्तुत किए गए हैं। खंड V में कुछ नीतिगत दृष्टिकोणों के साथ आलेख का समापन होता है।

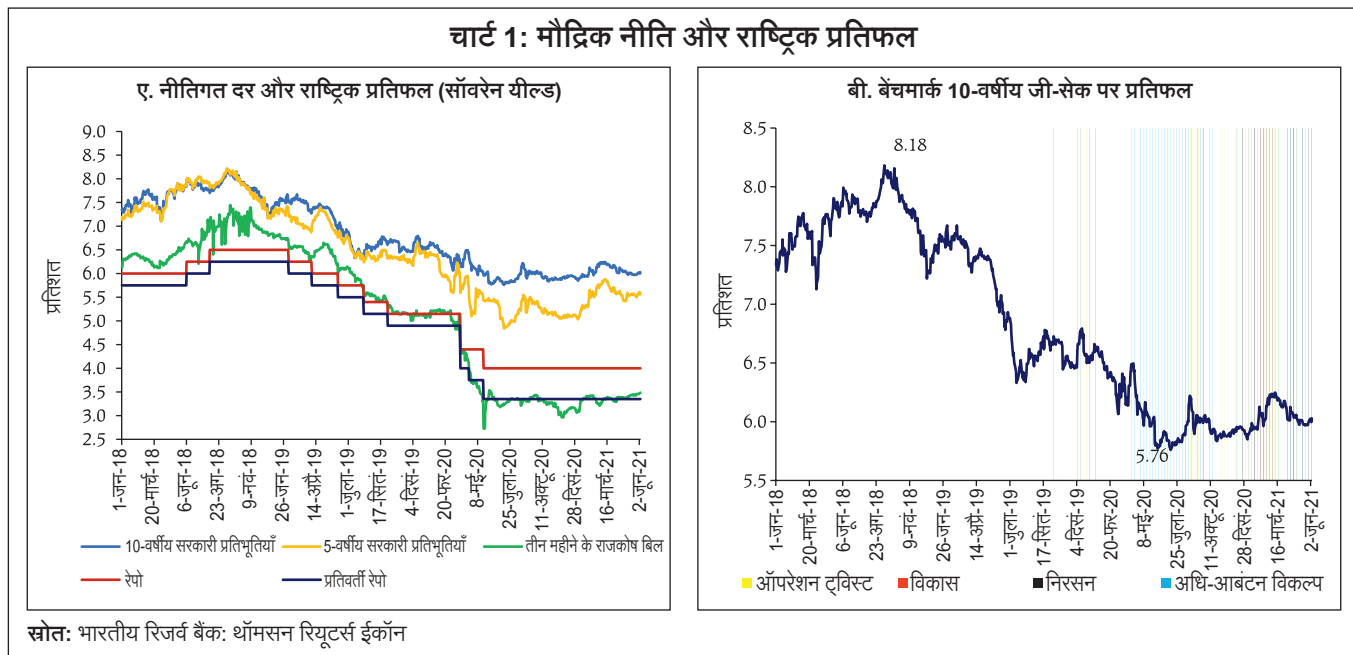
## II. बॉन्ड मार्केट के हालिया घटनाक्रम

दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों ने कोविड-19 महामारी के प्रकोप से निपटने हेतु बॉन्ड खरीद और तुलन-पत्र की नीतियों द्वारा प्रचुर मात्रा में चलनिधि के प्रावधान के माध्यम से आसान वित्तीय

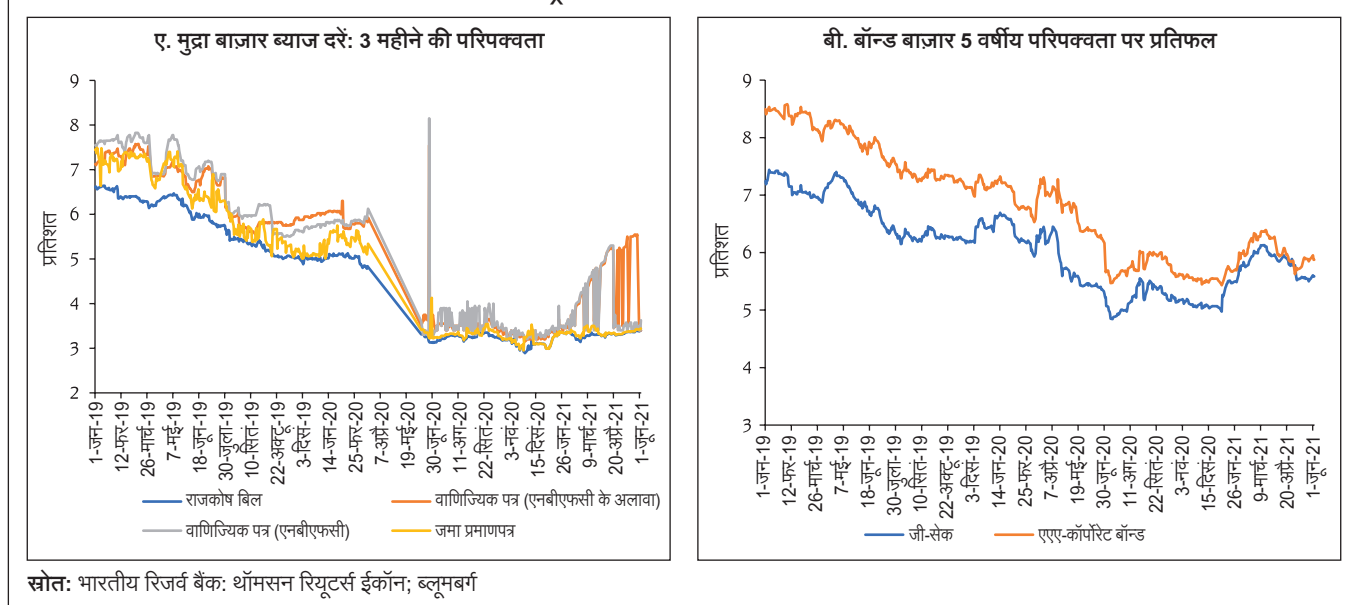
स्थितियों को जोखिम में डाल दिया। इसके परिणामस्वरूप, बॉन्ड प्रतिफल 2020 में अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गए हैं और रिकॉर्ड कॉर्पोरेट निर्गम करने के साथ-साथ इक्विटी में मजबूत स्थिति के लिए मंच तैयार किया। भारत में बाजारों और मौद्रिक प्राधिकरण के इंटरफेस के बीच एक समान अनुक्रम देखने को मिला, जिसका प्रमुख उद्देश्य वित्तीय बाजारों को रुकाव से बचाने और वित्तीय मध्यस्थों के सामान्य कामकाज सुनिश्चित करना था; परिवारों और व्यवसायों द्वारा झेले जाने वाले तनाव को कम करने हेतु ताकि वित्त की अपरिहार्य जीवन-रेखा बनी रहे (दास, 2020बी)। तदनुसार, आरबीआई ने प्रतिफल वक्र के एक व्यवस्थित विकास पर जोर देते हुए सावधानीपूर्वक प्रतिफल में वृद्धि लायी (दास, 2021ए)। इस संचालन को प्राथमिक और द्वितीयक बाजार संचालन दोनों में नीलामी कट-ऑफ, न्यागमन, निरसन और अधि-आबंटन के विकल्प के माध्यम से समर्थित किया गया था (चार्ट 1)।

नीतिगत दरों में कटौती और प्रचुर मात्रा में चलनिधि के कारण वित्तीय बाजारों में उधार-संबंधी लागत एक दशक में अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई। अल्पावधि राजकोष बिल, वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और जमा प्रमाणपत्र (सीडी) पर ब्याज दरों ने पूरी तरह से नीतिगत दर में कमी लायी और वास्तव में,

चार्ट 1: मौद्रिक नीति और राष्ट्रक प्रतिफल



**चार्ट 2: अन्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय प्रतिफलों और और ब्याज दरों का सह-संचलन**



इससे नीचे रहीं (चार्ट 2ए)। गिल्ट बाजार में उधार की भारित औसत लागत 16 वर्षों में अपने सबसे निचले स्तर पर गिर गई (दास, 2020)। कॉरपोरेट और सरकारी प्रतिभूतियों की दरों के बीच स्प्रेड को कॉरपोरेट बॉन्ड की सभी परिपक्वताओं और रेटिंग श्रेणियों में संकुचित किया गया था (चार्ट 2बी)।

### 11.1 वैश्विक संदर्भ

जैसे-जैसे 2020 के अंत में कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में टीकाकरण अभियान ने गति और पैमाना बढ़ाया, दुनिया भर के वित्तीय बाजारों ने पुनर्मूद्रास्फीति व्यापार को तेजी से वैश्विक सुधार की उम्मीद के रूप में माना। इक्विटी और ऋण बाजारों ने बढ़े हुए मूल्यांकन के बावजूद लाभ बढ़ाया, और जनवरी 2021 में अमेरिकी डॉलर की कमजोर स्थिति के कारण पूंजी प्रवाह उभरते बाजारों में बढ़ जाने से जोखिम होने के रुख की वापसी ने प्रतिफल को टटोलना शुरू किया। बाजार आधारित मुद्रास्फीति की प्रत्याशा में तेजी आयी और बॉन्ड बाजार यह मानने लगे कि केंद्रीय बैंकों को स्थिति के सामान्यीकरण के लिए मजबूर हो जाएंगे क्योंकि वसूली में तेजी आने से मुद्रास्फीति के लक्ष्य से अधिक होने की संभावना है। वैश्विक स्तर पर उच्च अनिश्चितता ने मौद्रिक नीति के लिए दृष्टिकोण को धूमिल कर दिया और निरंतर कटौती पर चर्चा

और अतीत के विफल सामान्यीकरण हावी हो गए। इसके बाद, यू.एस. का राजकोषीय प्रतिफल बढ़ने लगा और 31 मार्च, 2021 को एक वर्ष में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इस वृद्धि में कमी आई और इसके कारण उन्नत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में मीयादी प्रीमियम में वृद्धि हुई (चार्ट 3)। ईएमई में मीयादी प्रीमियम दक्षिण अफ्रीका में 500 आधार अंक (बीपीएस), लैटिन अमेरिका में लगभग 400 बीपीएस और एशिया में 65-300 बीपीएस (भारत में 225 बीपीएस) तक बढ़ गया। जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जहां प्रतिफल नियंत्रण मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य है, मीयादी प्रीमियम कम और स्थिर रहा है या उसमें गिरावट आई है।

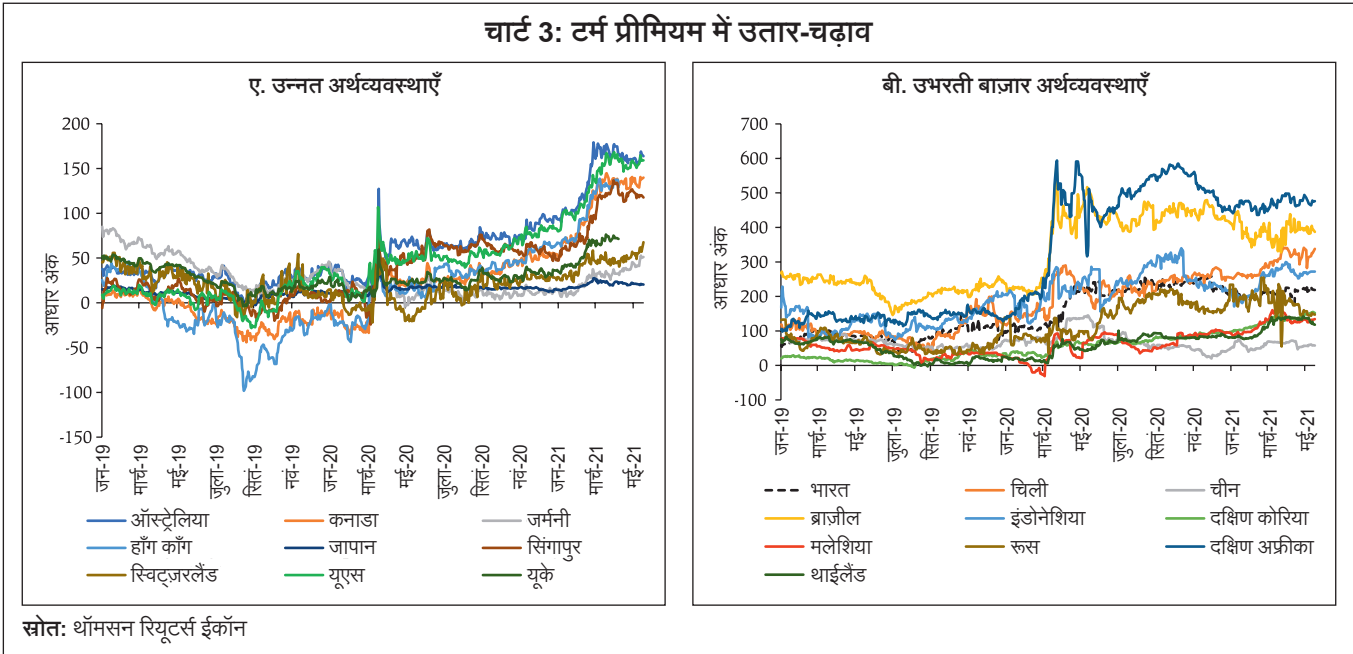
### 11.2 भारत में बॉन्ड बाजार की गतिकी

भारत में, फरवरी में सरकार के उधार कार्यक्रम की घोषणा ने ट्रिगर का काम किया, लेकिन पश्च दृष्टि में हुए, यह स्पष्ट है कि 2021 की शुरुआत में वृद्धिशील वैश्विक आर्थिक नीति की अनिश्चितता (चार्ट 4) के तारतम्य में वैश्विक प्रभाव-विस्तार में

<sup>2</sup> मीयादी प्रीमियम की गणना 10 वर्षों और 1 वर्ष के जी-सेक पर प्रतिफल के बीच के अंतर को लेकर की जाती है।



**चार्ट 3: टर्म प्रीमियम में उतार-चढ़ाव**



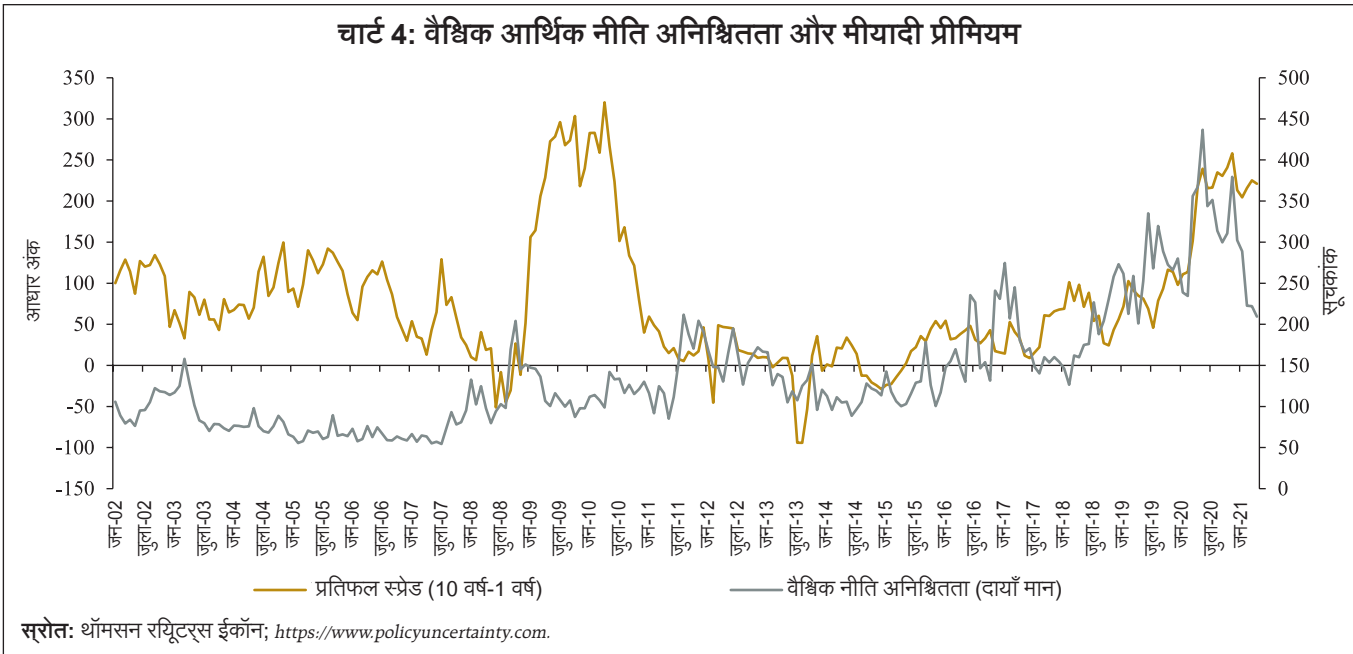
मीयादी प्रीमियम की बढ़ती संवेदनशीलता की ओर इंगित करते हुए मीयादी प्रीमियम में तेजी आई थी (पात्र और अन्य, 2020)।

**11.3 एक क्रॉस-सेक्शनल दृष्टिकोण**

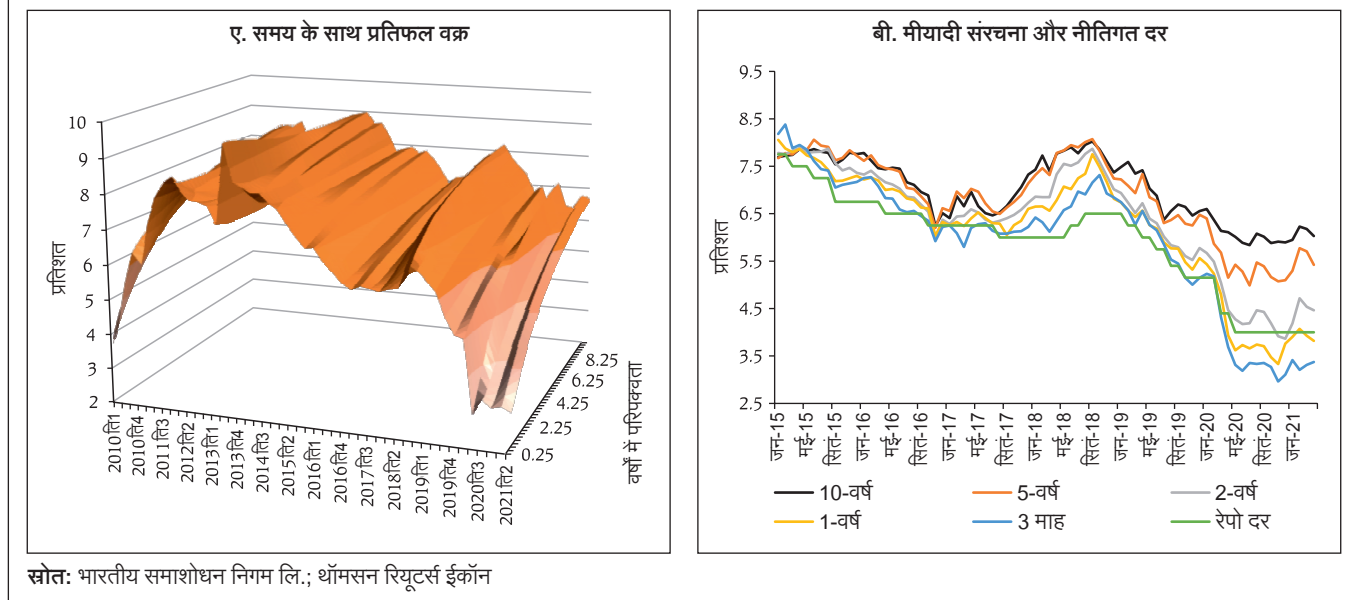
प्रतिनिध्यात्मक रूप से और समय के साथ भारत की प्रतिफल वक्र में गिरावट की जांच करते हुए (चार्ट 5ए), यह देखा

गया है कि परिपक्वता की विस्तार-सीमा के दौरान प्रतिफल में गिरावट आई है, लेकिन शुरुआती क्षणों की तुलना में अंतिम क्षणों में अधिक कमी देखी गई है (चार्ट 5बी)। इस प्रकार, मौद्रिक नीति अल्पावधि ब्याज दरों को कम करने और स्थिर करने में प्रभावी रही है, जिसने बदले में दो साल तक की परिपक्वता के लिए नीति दर से भी नीचे दरों को कम करने में मदद की।

**चार्ट 4: वैश्विक आर्थिक नीति अनिश्चितता और मीयादी प्रीमियम**



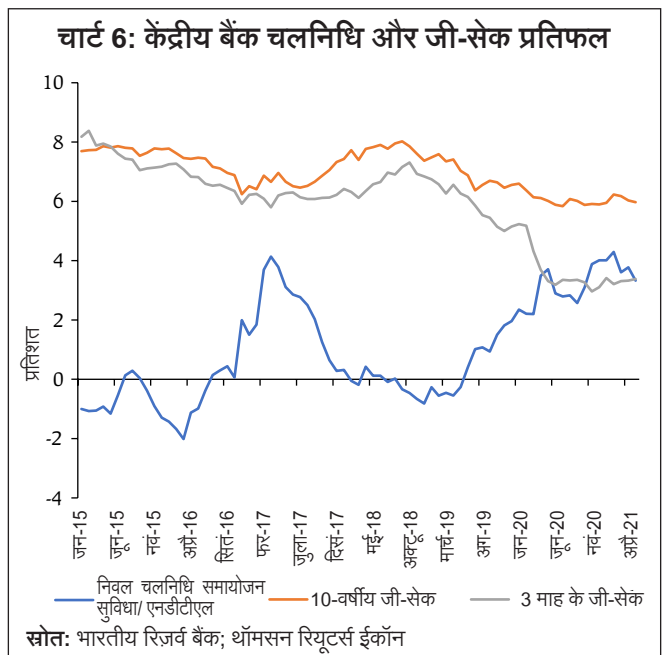
**चार्ट 5: राष्ट्रिक बॉन्डों पर ब्याज दरों की मीयादी संरचना**



दूसरी ओर, लंबी दरों पर संचरण पिछड़ गया और कम हो गया, जिससे मीयादी प्रीमियम में वृद्धि हुई और प्रतिफल वक्र में कमी आई। जबकि केंद्रीय बैंक की चलनिधि और अल्पावधि प्रतिफल के बीच प्रतिलोम संबंध दिखाई देता है, यह सह-आंदोलन लंबी अवधि के प्रतिफल के मामले में इतना स्पष्ट नहीं है (चार्ट 6)।

**11.4 समष्टि-आर्थिक कारकों की भूमिका**

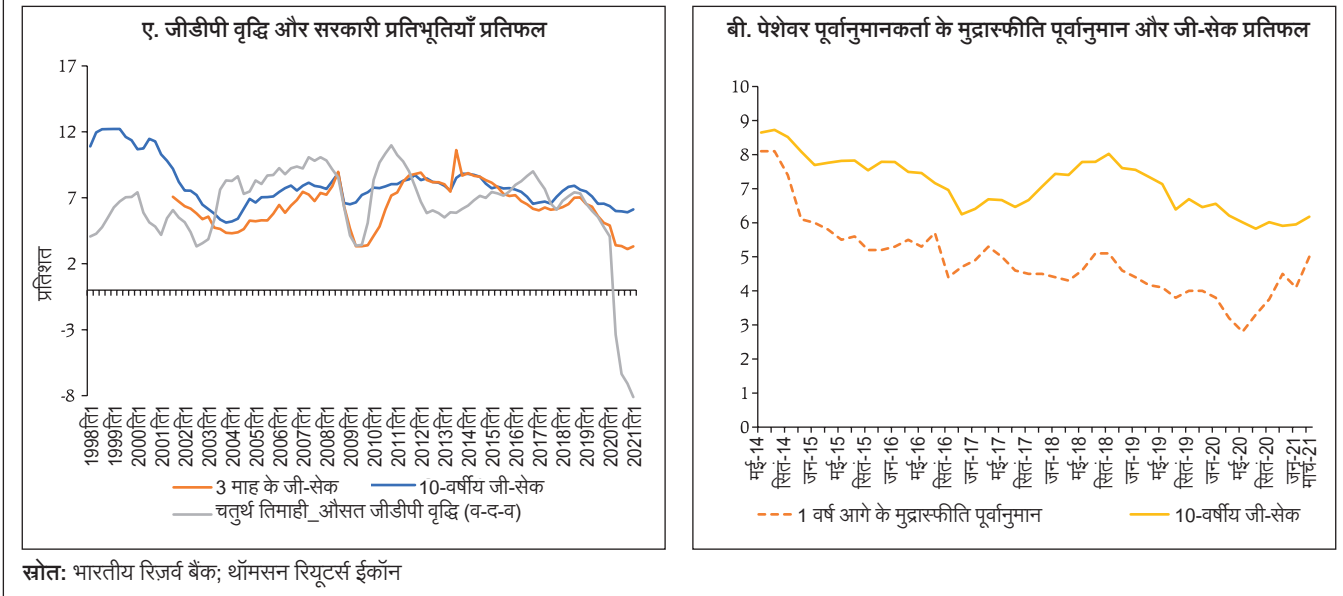
समष्टि-आर्थिक प्रभावों में, प्रतिफल वक्र मुद्रास्फीति और वृद्धि अपेक्षाओं, दोनों के साथ सह-गति की एक उचित डिग्री को दर्शाता है। सितंबर 2020 और मार्च 2021 के बीच संक्रमण के मामलों में कमी ने मजबूत और निरंतर विकास की बहाली की उम्मीदों को हवा दी, पूर्वानुमानों के लिए कई दौर में ऊर्ध्वगामी संशोधन के साथ, जो आधारभूत प्रभावों से प्रभावित थे। ऐसा प्रतीत होता है कि मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं ने भी प्रतिफल के विकास के लिए एक मंजिल निर्धारित की है (चार्ट 7)।



**11.5 नीतिगत हस्तक्षेप और बॉन्ड बाजार**

बाधित संचरण का सामना करते हुए, आरबीआई द्वारा द्वितीयक बाजार में सरकारी बॉन्डों की बड़े पैमाने पर खुले बाजार में खरीद हुई, जिससे सरकार द्वारा अपने तुलन-पत्र पर महामारी से संबंधित प्रतिभूतियों के निर्गम के अधिभार को प्रभावी ढंग से कम किया गया (चार्ट 8)। मीयादी प्रीमियम के आरबीआई द्वारा अस्वीकार्य स्तरों पर बने रहने से, जैसा कि बार-बार निरसन, न्यागमन, बड़े द्वितीयक बाजार परिचालनों और आगे के मार्गदर्शन में परिलक्षित होता है - यह स्पष्ट है कि मौद्रिक नीति के अलावा बॉन्ड विजिलांटी जैसी अन्य शक्तियाँ इसकी पृष्ठभूमि में प्रतिध्वनित होती हैं (पात्र और अन्य, 2021)।

**चाट 7: अपेक्षाएँ और सरकारी प्रतिभूति का प्रतिफल**

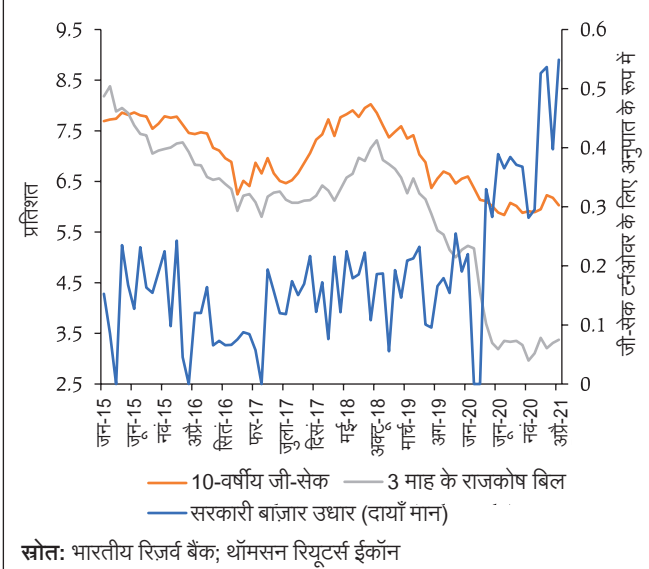


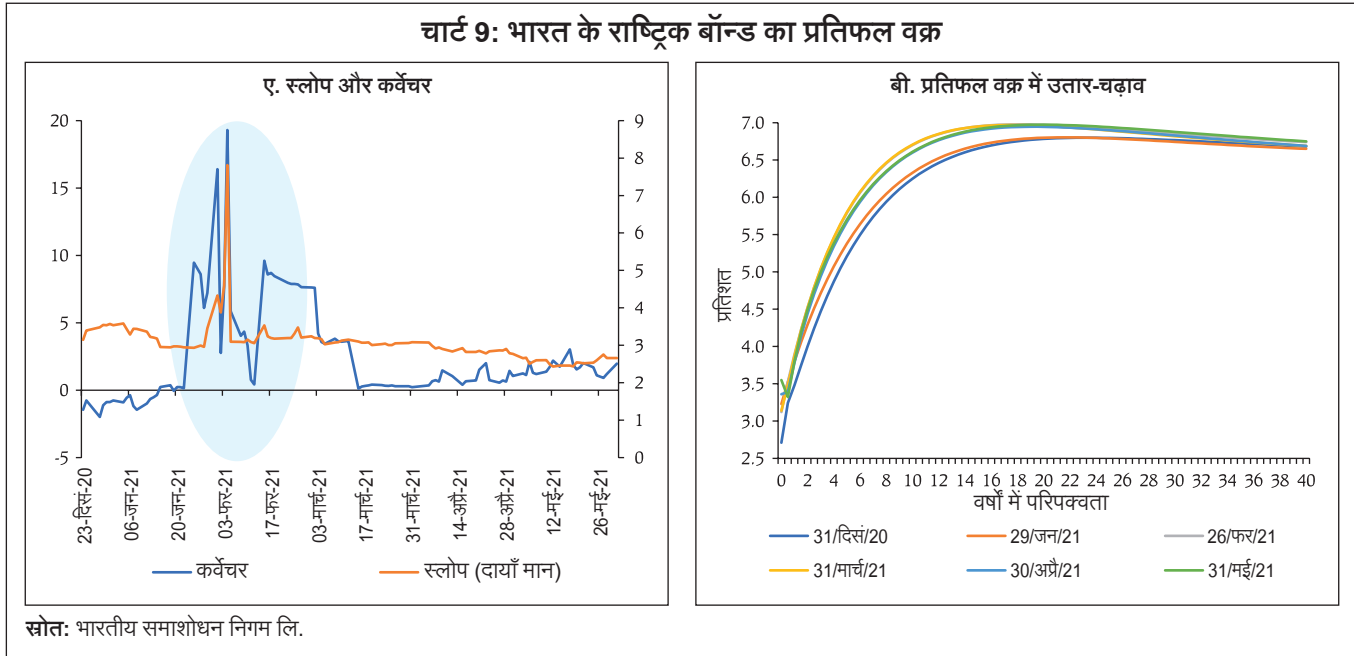
**II.6 अप्रकट कारकों की जांच**

भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) द्वारा प्रतिफल वक्र, यानी स्तर, स्लोप और कर्वेचर के अंतर्निहित अप्रकट कारकों पर दैनिक डेटा प्रकाशित किया जाता है, जो कि मॉडल के प्रमुख अंतरपणन-मुक्त वर्ग पर आधारित है (नेल्सन और सीगल, 1987; स्वेन्सन, 1994)। इन आंकड़ों से पता चलता है कि प्रतिफल वक्र का स्तर, जो मोटे तौर पर पूरे 2020 में स्थिर

था, उसमें फरवरी 2021 के पहले सप्ताह के दौरान वृद्धि हुई है, जो आने वाले वर्ष के लिए सरकारी बाजार उधारियों के बारे में बॉन्ड व्यापारियों की प्रतिकूल धारणा और उसके परिणामस्वरूप बाजार में वाणिज्यिक पत्रों की अतिरिक्त आपूर्ति के प्रवाह को दर्शाता है। यह प्रतिफल वक्र की संयोगवश गिरावट के रूप में भी परिलक्षित हुआ, जो सांयोगिक था और आगामी अवधि में कायम नहीं रह सका। खुदरा निवेशकों को सीधे जी-सेक बाजार में ऑनलाइन पहुंच प्रदान करने के रूप में कुछ अतिरिक्त उपायों की घोषणा के माध्यम से सिस्टम में पर्याप्त चलनिधि की उपलब्धता के लिए आरबीआई द्वारा गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए मांग पर लक्षित दीर्घकालिक रेपो संचालन (टीएलटीआरओ) चलनिधि, बैंकों के लिए सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत सुलभ चलनिधि की सीमा बढ़ाना, खुले बाजार संचालन, ऑपरेशन ट्विस्ट और बड़े पैमाने पर द्वितीयक बाजार सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (जीएसएपी) के माध्यम से आश्वासन दिया गया। और मार्गदर्शन के आश्वासन ने बाजार के रुख को शांत किया और वक्र में चलनिधि को कम किया, जिसके परिणामस्वरूप स्लोप में कमी आई। उसी कड़ी में मध्यावधि प्रतिफल में अस्थायी रूप से वृद्धि होने से आँकड़े कर्वेचर में भी वृद्धि का संकेत देते हैं। आगामी महीनों में पुनः सामान्यीकरण हुआ। इस प्रकार तीनों अप्रकट तत्वों में अल्पकालिक वृद्धि हुई और आरबीआई के उपायों ने प्रतिफल को नीचे लाने में मदद की, जैसा कि 4 और 5

**चाट 8: केंद्रीय सरकार की बाजार उधारियाँ और जी-सेक प्रतिफल**





फरवरी के दौरान स्तर, स्लोप और कर्वेचर में क्रमशः 483 बीपीएस, 472 बीपीएस और 232 बीपीएस की गिरावट के रूप में देखी गई (चार्ट 9)।

### III. मॉडल संरचना

हमारा अनुमान संबंधी फ्रेमवर्क अनिवार्य रूप से डाइनेमिक लॉट फैक्टर दृष्टिकोण की परंपरा का पालन करता है जो वास्तविक गतिविधि, मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति रुख को दर्शाने वाले मैक्रोइकॉनॉमिक चर के साथ संवर्धित होता है (डाइबॉल्ड एवं अन्य, 2006)। इसके अलावा, हम संवर्धित मॉडल में वैश्विक कारक, चलनिधि की स्थिति और सरकारी बाजार उधार कार्यक्रम को शामिल करते हैं। हम अव्यक्त चर - स्तर<sup>3</sup>, ढलान<sup>4</sup>, और वक्रता<sup>5</sup> - को एक ऑटोरेग्रेसिव प्रक्रिया का पालन करने की अनुमति देकर एक समय-भिन्न संरचना पेश करते हैं, जिसे साहित्य में यादृच्छिक चलने की प्रक्रिया की तुलना में ज्यादा तवज्जो दी जाती क्योंकि बाद वाला एक गैर-स्थिर प्रगति है।

<sup>3</sup> स्तर, परिपक्वता अवधियों के दौरान प्रतिफलों का औसत है।

<sup>4</sup> स्लोप दीर्घावधि और अल्पावधि दरों के बीच का अंतर है।

<sup>5</sup> कर्वेचर लघु, मध्यम और लंबी परिपक्वता पर प्रतिफल के बीच का संबंध है - यह मध्यम अवधि की दर के दोगुने और अल्पकालिक दर और लंबी अवधि की दर के योग के बीच का अंतर होता है। उच्च कर्वेचर इंगित करता है कि मध्यम अवधि की दर अल्पकालिक दर और लंबी अवधि की दर से अधिक है, जो प्रतिफल वक्र में एक उभार के रूप में दिखाई देती है।

किसी भी परिपक्वता पर प्रतिफल ( $\tau$ ) को इस प्रकार विघटित किया जाता है:

$$y_t(\tau) = L_t + S_t \left( \frac{1 - e^{-\lambda_t \tau}}{e^{-\lambda_t \tau}} \right) + C_t \left( \frac{1 - e^{-\lambda_t \tau}}{e^{-\lambda_t \tau}} - e^{-\lambda_t \tau} \right) \dots (1)$$

जहां  $L_t$ ,  $S_t$  और  $C_t$  क्रमशः स्तर, ढलान और वक्रता हैं, और अप्रत्यक्ष एवं समय-परिवर्तनीय हैं। पैरामीटर  $\lambda_t$  घातीय क्षय दर<sup>6</sup>, भी समय-परिवर्तनीय है।

प्रतिफल वक्र की संरचना का आकलन और समष्टि-आर्थिक और वैश्विक चर के साथ इसकी गतिक अन्योन्यक्रिया एक अवस्था-समष्टि निरूपण तैयार करके की जाती है जो वर्णन करती है कि कैसे प्रेक्षित चर अव्यक्त चर से संबंधित हैं और वे समय के साथ कैसे विकसित होते हैं। मापन समीकरण एक मैट्रिक्स निरूपण में प्रेक्षित प्रतिफल को अप्रत्यक्ष कारकों, यानी, स्तर, ढलान और वक्रता को मिलाकर करके तैयार किया जाता है:

$$y_t = A f_t + \varepsilon_t \dots (2)$$

$$(f_t - \mu) = A(f_{t-1} - \mu) + \eta_t$$

$$\text{जहां } f_t = [L_t, S_t, C_t] \dots (3)$$

<sup>6</sup> घातीय क्षय (एक्सपोनेन्शियल डिके) किसी समयावधि में सुसंगत प्रतिशत दर से स्लोप और वक्रता में कमी की प्रक्रिया का वर्णन करता है।

यह प्रतिफल-मात्र मॉडल है, जिसका उपयोग हम पूर्व में वर्णित प्रतिफल-मैक्रो मॉडल (डाइबॉल्ड एवं अन्य, 2006) में समष्टि-आर्थिक चर के साथ संवर्धित करते समय सटीक लाभ का मूल्यांकन करने के लिए बेंचमार्क के रूप में करते हैं। हमारा मॉडल फीडबैक के साथ प्रतिफल वक्र की संरचना के साथ समष्टि चर के गतिक दो-तरफा अन्योन्यक्रिया की अनुमति देता है।

इस प्रकार, भारत में प्रतिफल वक्र के अनुमान के लिए हमारा डाइनेमिक लटेंट फैक्टर यील्ड-मैक्रो मॉडल माप और संक्रमण समीकरणों के निम्नलिखित सेट पर आधारित है:

$$y_t = \Lambda f_t + \varepsilon_t$$

जहां  $\Lambda$  समीकरण (1) द्वारा निर्देशित है ... (4)

$$(f_t - \mu) = C(f_{t-1} - \mu) + \eta_t$$

जहां

$$f_t = [L_t, S_t, C_t, OG_t, WACR_t, INF_t, GEPU_t, LIQU_t, GMB_t]$$

और

$$C = \begin{bmatrix} C6 & c(. ,7) & c(. ,8) & c(. ,9) \\ 0 & c77 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c88 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c99 \end{bmatrix}$$

जहां

$$C6 = \begin{bmatrix} c11 & \dots & c16 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c61 & \dots & c66 \end{bmatrix}$$

$$c(. ,7) = \begin{bmatrix} c17 \\ c27 \\ c37 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, c(. ,8) = \begin{bmatrix} c18 \\ c28 \\ c38 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, c(. ,9) = \begin{bmatrix} c19 \\ c29 \\ c39 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \dots (5)$$

वास्तविक गतिविधि को आउटपुट गैप (ओजी) द्वारा दर्शाया जाता है, मुद्रास्फीति के साथ मुद्रास्फीति अंतर (आईएनएफ) को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में तिमाही परिवर्तनों पर मौसमी रूप से समायोजित तिमाही के रूप में मापा जाता है और मौद्रिक नीति जो भारत और अंतर्राष्ट्रीय मांग मुद्रा दर (डबल्यूएसीआर) द्वारा अनुमानित होती है –इसका परिचालन लक्ष्य है। चलनिधि

की स्थिति या एलआईक्यूयू, बैंकों की निवल मांग और सावधि देनदारियों के अनुपात के रूप में आरबीआई की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत बकाया अवशोषण/अंतर्वेशन द्वारा निकाला जाता है। सरकारी बाजार उधार कार्यक्रम बाजार के कारोबार अनुपात (जीएमबी) के लिए बाजार से उधार लेता है और वैश्विक अनिश्चितता वैश्विक आर्थिक नीति अनिश्चितता सूचकांक (जीईपीयू)<sup>7</sup> द्वारा दर्शाया जाता है। एलआईक्यूयू, जीएमबी और जीईपीयू को बहिर्जात चर के रूप में माना जाता है और माना जाता है कि यह प्रतिफल वक्र कारकों और अन्य समष्टि वृद्धि से स्वतंत्र रूप से विकसित होता है - उन्हें केवल प्रतिफल वक्र कारकों को प्रभावित करने की अनुमति है, न कि सीधे अन्य मैक्रो चर को।

मॉडल का अनुमान बायेसियन तरीकों का उपयोग करके किया जाता है जो अपेक्षाकृत कम समय अवधि में बड़ी संख्या में मापदंडों पर कार्य करने के लिए अन्य समय श्रृंखला की तुलना में सफल हैं। एक बहुचर कालमैन फ़िल्टर का उपयोग करके अप्रकट (अप्रकट चर) फ़िल्टर किए जाते हैं।<sup>8</sup>

#### IV. परिणाम

मॉडल का अनुमान 2010 की पहली तिमाही से 2021 की तदनुसूची तिमाही तक 2 से 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि की भारत सरकार की प्रतिभूति प्रतिफल पर तिमाही आंकड़ों के आधार पर लगाया गया है। जीईपीयू के अलावा सभी डेटा आरबीआई के भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस (डीबीआई) से लिया गया है, जीईपीयू डेटा फुटनोट 7 में दिए गए अनुसार लिया गया है।

<sup>7</sup> जीईपीयू सूचकांक 21 देशों के लिए राष्ट्रीय ईपीयू सूचकांकों का जीडीपी – भारत और अंतर्राष्ट्रीय प्रत्येक सूचकांक अपने देश के समाचार पत्रों में अर्थव्यवस्था (ई), नीति(पी) तथा अनिश्चितता(यू) से संबंधित इन तीन शब्दों वाले लेखों की सापेक्ष बारंबारता को प्रतिबिंबित करता है। यह आँकड़े [https://www.policyuncertainty.com/global\\_monthly.html](https://www.policyuncertainty.com/global_monthly.html) पर उपलब्ध हैं।

<sup>8</sup> कालमैन फ़िल्टर समय के साथ देखे गए चर के एक सेट से अदृश्य चर का अनुमान लगाने के लिए एक एल्गोरिदम है। जब एक से अधिक देखने योग्य चर शामिल होते हैं, तो प्रक्रिया को बहुभिन्नरूपी (मल्टिवेरीयेट) कहा जाता है। ये अनुमान अकेले देखने योग्य चर पर आधारित अनुमानों की तुलना में अधिक सही होते हैं। इसके अतिरिक्त कालमैन फ़िल्टर अन्य अनुमान पद्धतियों की तुलना में अधिक परिशुद्ध अनुमान देता है।

## IV.1 बेंचमार्क अनुमान

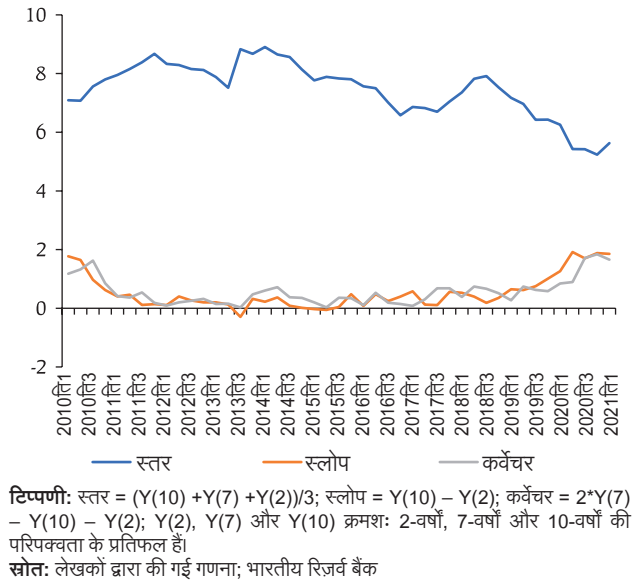
वित्तीय साहित्य को ध्यान में रखते हुए, हम प्रतिफल वक्र संवितरण-माध्य; विचलन - इसके अप्रकट कारकों के मूल्यों का पता लगाने की घटनाओं का उपयोग करके प्रतिफल वक्र की संरचना का अनुमान लगाते हैं। हम इस लेवल के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले अनुभवजन्य प्रॉक्सी पर निर्भर है, जो अल्प (2 वर्ष की परिपक्वता), मध्यम (7 वर्ष) और दीर्घ (10 वर्ष) अवधि का प्रतिफल (डाइबॉलड और अन्य, 2006) का औसत है। स्लोप स्प्रेड से जुड़ा हुआ है और 10-वर्ष और 2-वर्ष की प्रतिफल के बीच के अंतर के रूप में प्राप्त किया जाता है। वक्रता को मध्यम अवधि के दोगुने प्रतिफल और अल्प और दीर्घ अवधि के प्रतिफल योग के बीच के अंतर से मापा जा सकता है, अर्थात्,  $2Y(7) - \{Y(2) + Y(10)\}$ <sup>9</sup>

ये अनुमान 2018 की चौथी तिमाही के बाद से प्रतिफल वक्र के लेवल में लगातार गिरावट की ओर इशारा करते हैं, जो यह दर्शाता है कि मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव के अनुरूप प्रतिफल वक्र नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है<sup>10</sup> (चार्ट 10)। हालांकि, 2019-20 की पहली तिमाही से, प्रतिफल वक्र का स्लोप बढ़ना शुरू हो गया, जो नीतिगत दर में एक तटस्थ नीति रुख के बावजूद क्रमिक कटौती दर्शाता है, जिससे अल्पावधि प्रतिफल को अनुपात से अधिक कम कर दिया। वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही से, आरबीआई द्वारा अपरंपरागत मौद्रिक नीति लिखतों के नियोजन के कारण प्रतिफल वक्र का स्लोप कम होना शुरू हो गया, जो प्रणालीगत केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाई गई तुलन पत्र नीतियों के समान था। समकालिक रूप से, अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों प्रकार के प्रतिफल में गिरावट के साथ, वक्रता में वृद्धि हुई है, जो प्रतिफल वक्र के मध्यवर्ती खंड की सापेक्ष अनम्यता को दर्शाती है, जहां अनिवार्य रूप से ऑफ द रन प्रतिभूतियों की भरमार है।

<sup>9</sup> डाइबॉलड एट अल देखें। (2006)

<sup>10</sup> फरवरी 2019 को एक व्यापक महत्वपूर्ण मोड के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसके बाद भारत में मौद्रिक नीति का रुख नीति दर को 25 आधार अंक से कम करते हुए समझित रूप से सख्त होने के बजाय तटस्थ की ओर अंतरित हुआ। "मौद्रिक नीति के रुख का समझित रूप से सख्त होने के बजाय तटस्थ की ओर अंतरण .. जब तक मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण सौम्य रहता है, तब तक आने वाले महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था के निरंतर विकास के लिए चुनौतियों का समाधान करने के लिए लचीलापन और अवसर प्रदान करता है। इस संबंध में एमपीसी के निर्णय डेटा से संचालित होंगे और विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए मौद्रिक नीति के प्राथमिक उद्देश्य के अनुरूप होंगे।" (दस, 2019)

चार्ट 10: प्रतिफल वक्र कारकों के अनुभवजन्य प्रॉक्सीस



## IV.2 प्रतिफल-समष्टि मॉडल

अंतर्निहित समष्टि आर्थिक स्थितियों द्वारा अवगत शुद्ध 'तकनीकी' से हटकर प्रतिफल वक्र के अधिक मौलिक दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हुए, हम बायेसियन फ्रेमवर्क में (4 और 5) समीकरणों की प्रणाली का अनुमान लगाते हैं। इससे जुड़ी स्थितियों के पिछले अनुभव के आधार पर किसी संभावित घटना को शामिल कर सकते हैं। हम अपेक्षाकृत कमजोर प्रायोरस के साथ काम करना चुनते हैं – हम कल्पना करते हैं कि एक विस्तृत श्रृंखला में पैरामीटर भिन्न होते हैं क्योंकि हम पैरामीटर के मूल्य प्रायोरी के बारे में कम आश्वस्त होते हैं। हम मानते हैं कि सभी पैरामीटर सामान्य संवितरण का अनुपालन करते और आघात के मानक विचलन विपरित गामा संवितरण का अनुपालन करते हैं जो आमतौर पर साहित्य में अपनाया जाता है। न्यूटन-प्रकार के एल्गोरिथम को हल करके चर के लंबे समय तक चलने वाले या स्थिर अवस्था मान्यताएं प्राप्त की जाती हैं<sup>11</sup> लेवल, स्लोप, कर्वेचर और एकस्पोजिशन डिफे पैरामीटर सहित अप्रकट, एक बहुचर कलमैन फ़िल्टर का उपयोग करके निकाले जाते हैं, जो अज्ञात

<sup>11</sup> इष्टतम मापदंडों को प्राप्त करने के लिए सामान्य नॉन-लिनीअर समीकरणों को हल करने के लिए यह एक पुनरावर्ती पद्धति है। यह एक प्रारंभिक अनुमान से शुरू होता है, शेष त्रुटि के संदर्भ में मूल समीकरणों को फिर से लिखने के लिए त्रुटि सुधार का एक क्रम निकालता है और जब तक सटीकता के वांछित स्तर प्राप्त नहीं किया जाता फिर एक नए सुधार के लिए हल निकालता है।

**सारणी 1: प्रतिफल-समष्टि मॉडल कार्य-निष्पादन**

परिपक्वता (वर्षों में)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	औसत
औसत त्रुटि (आधार अंकों में)	-1.86	-5.54	-3.09	-0.36	1.60	2.00	1.44	-8.42	-9.15	-2.60
त्रुटि की एसडी (आधार अंकों में)	9.91	6.39	5.97	6.99	10.78	11.79	13.73	11.98	12.63	10.02
आरएमएसई (आधार अंकों में)	9.97	8.40	6.67	6.92	10.78	11.83	13.65	14.53	15.49	10.92
पीआरएमएसई (प्रतिशत)	1.39	1.15	0.90	0.92	1.41	1.54	1.77	1.90	2.02	1.44

**टिप्पणी:** विभिन्न परिपक्वताओं के प्रतिफल को वर्षों में मापा गया है, इसलिए माप त्रुटि और आरएमएसई के साधन और मानक विचलन आधार अंकों के रूप में दर्शाये गए हैं।

चर के अनुमान निकालता है जो अविभाज्य फ़िल्टर के सापेक्ष अधिक सटीक होते हैं, विशेषतः जब कई अप्रकट कारक और समष्टि आर्थिक निर्धारक दोनों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। यह आकलन मैटलैब सॉफ्टवेयर के आईआरआईएस टूलबॉक्स में किया जाता है।

अनुमानित मॉडल की इन-सैंपल प्रेडिक्टिव पावर अत्यधिक है, जो त्रुटियों के निम्न औसत मानक विचलन (विभिन्न परिपक्वताओं में 6 बीपीएस और 14 बीपीएस के बीच), 11 बीपीएस की कम औसत वर्ग मूल माध्य त्रुटि (आरएमएसई), केवल 1.44 प्रतिशत औसत प्रतिशत आरएमएसई (पीआरएमएसई) और प्रत्येक परिपक्वता (2-10 वर्ष) में (-) 9 बीपीएस और 2 बीपीएस के बीच औसत त्रुटियों से पता चलता है। अतः यह मॉडल प्रतिफल का सटिक पूर्वानुमान देने में सक्षम है (सारणी 1)।

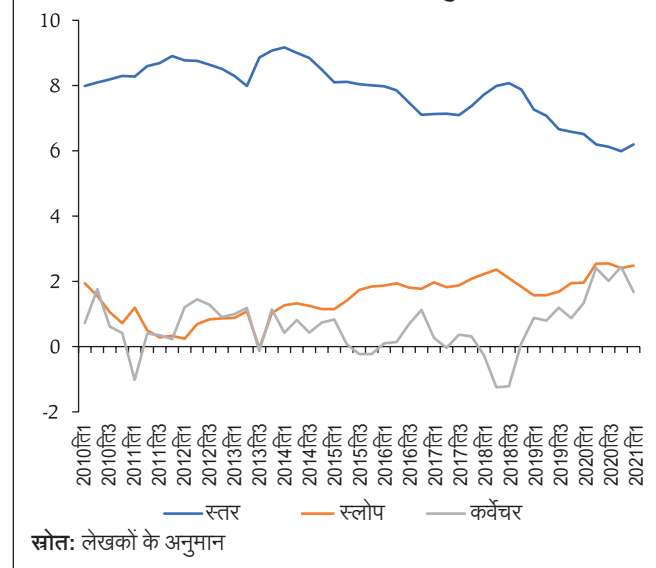
यील्ड-मैक्रो मॉडल से अनुमानित स्तर, ढलान और वक्रता इस खंड की शुरुआत में परिभाषित अनुभवजन्य परदे के पीछे की पुष्टि करते हैं (चार्ट 11)। यील्ड कर्व का स्तर 2018 में लगभग 8 प्रतिशत से धीरे-धीरे घटकर 2020 में लगभग 6 प्रतिशत हो गया है, जो मुद्रास्फीति लक्ष्य को बनाए रखने और मुद्रास्फीति की उम्मीदों को बनाए रखने और निरंतर आवास पर स्पष्ट आगे के मार्गदर्शन से आरबीआई को अर्जित विश्वसनीयता बोनस को दर्शाता है। दूसरी ओर, ढलान और वक्रता दोनों में वृद्धि हुई है, मुख्य रूप से अल्पकालिक ब्याज दरों में गिरावट के कारण आरबीआई द्वारा नीतिगत दर में आक्रामक कटौती के कारण लंबी अवधि की दरों में गिरावट से बड़ी है, शुरु में झुकाव हवा के खिलाफ प्रति-चक्रीय रूप से और उसके बाद महामारी की प्रतिक्रिया। यील्ड-मैक्रो मॉडल से प्राप्त अव्यक्त कारकों और

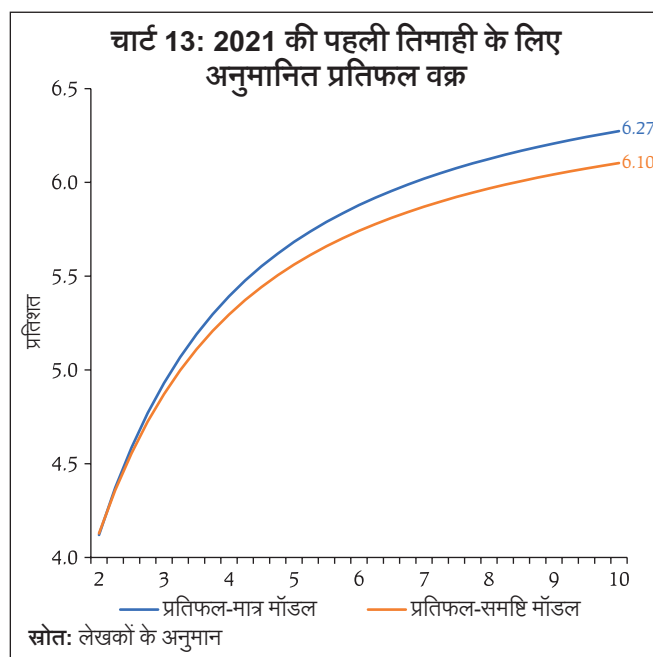
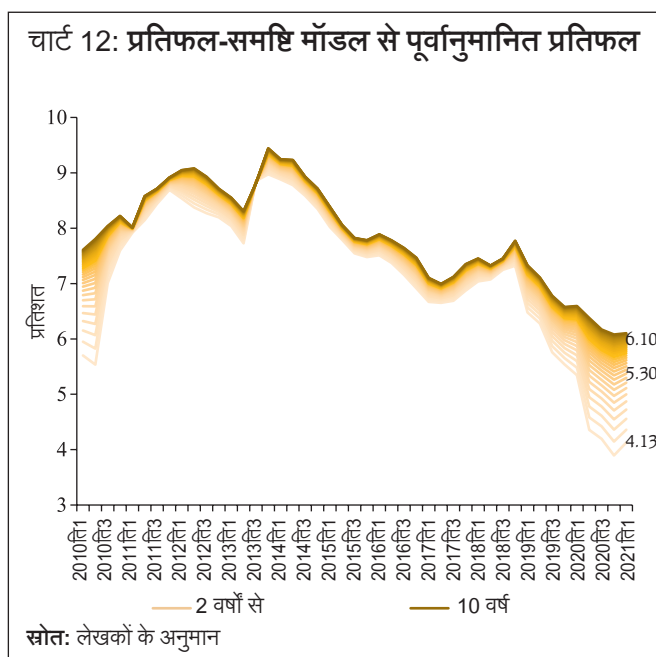
अनुभवजन्य परदे के बीच सहसंबंध सभी सांख्यिकीय रूप से 1 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण हैं - स्तर के लिए 0.98; ढलान के लिए 0.57; और 0.41 वक्रता के लिए - हमारे अनुमानों को मजबूती प्रदान करना।

अनुमानित मॉडल का उपयोग विभिन्न परिपक्वताओं के प्रतिफल को अनुकरण करने के लिए भी किया जा सकता है (चार्ट 12)। हाल के दिनों में स्प्रेड और दशकीय निम्न दीर्घकालिक दरों में वृद्धि की पहचान मॉडल द्वारा की जाती है।

प्रतिफल-समष्टि मॉडल से नमूने के भीतर अनुमानित प्रतिफल कर्व और प्रतिफल-मात्र मॉडल से प्राप्त तुलना से एक स्पष्ट और उल्लेखनीय अंतर्दृष्टि का पता चलता है कि वर्ष 2021 कि पहली तिमाही में प्रतिफल-मात्र मॉडल की तुलना में 10 साल

**चार्ट 11: प्रतिफल-समष्टि मॉडल पर आधारित स्तर, स्लोप और कर्वचर के अनुमान**





की परिपक्वता के लिए 17 बीपीएस तक प्रतिफल-समष्टि मॉडल से अनुमानित प्रतिफल कर्व को नीचे रखा गया है (चार्ट 13)। 2021 की दूसरी तिमाही के लिए प्रतिफल वक्र के आउट ऑफ सैंपल पूर्वानुमानों से मध्यम से लंबी परिपक्वता में प्रतिफल में एक और सामान्यीकरण की ओर संकेत करते हैं, बेंचमार्क 10-वर्षीय प्रतिफल 5.87 प्रतिशत पर अनुमानित हैं (सारणी 2) है। यह भारत में प्रतिफल वक्र के आकार के निष्पक्ष मूल्यांकन में समष्टि-आर्थिक निर्धारक- तत्वों पर विचार करने के महत्व को रेखांकित करता है।

जैसा कि सारणी 2 से पता चलता है, प्रतिफल-मात्र मॉडल से तैयार किए गए प्रतिफल वक्र के अनुमान डेटा को नमूने के

भीतर अच्छी तरह से फिट करते हैं, लेकिन अप्रकट कारकों के अंतर्निहित व्यवहार में कोई भी अंतर्दृष्टि प्रदान नहीं करते हैं। इसके अलावा, नमूना यथार्थ से परे हो जाता है क्योंकि ये अनुमान समष्टि-आर्थिक आधार से रहित हैं। महामारी जैसी असाधारण परिस्थितियों के सामने, विशिष्ट बाजार व्यवहार, प्रतिफल-मात्र मॉडल से आउट-सैंपल अनुमान परिणामों को असमान रूप से प्रभावित करता है।

समष्टि-आर्थिक चर के संबंध में एक यूनिट शॉक के लिए अप्रकट कारकों की आवेग प्रतिक्रियाएं उनकी अंतःक्रिया को दर्शाती हैं, जिससे साहित्य में उपलब्ध पूर्व के संदर्भों के अनुभवजन्य मूल्यांकन को बढ़ावा देता है (चार्ट 14)।

## सारणी 2: मॉडल आधारित प्रतिफल पूर्वानुमान

(प्रतिशत)

परिपक्वता (वर्षों में)	वास्तविक (ति1: 2021)	2021 की ति1 के लिए नमूना पूर्वानुमान		2021 की ति2 के आउट-ऑफ-सैंपल पूर्वानुमान		ति3: 2021
		प्रतिफल-मात्र मॉडल	प्रतिफल-समष्टि मॉडल	प्रतिफल-मात्र मॉडल	प्रतिफल-समष्टि मॉडल#	प्रतिफल-समष्टि मॉडल
2	4.41	4.12	4.13	4.95	4.46	4.86
3	4.91	4.93	4.87	5.47	4.99	5.26
4	5.31	5.39	5.30	5.76	5.29	5.49
5	5.73	5.68	5.56	5.95	5.48	5.64
6	6.01	5.88	5.74	6.07	5.61	5.73
7	6.21	6.02	5.87	6.16	5.70	5.80
8	6.31	6.13	5.97	6.23	5.77	5.86
9	6.22	6.21	6.04	6.28	5.82	5.90
10	6.26	6.27	6.10	6.32	5.87	5.93

#: 2021 की दूसरी और तीसरी तिमाही के लिए, जीडीपी वृद्धि और मुद्रास्फीति के लिए आरबीआई के पूर्वानुमानों का उपयोग करके और मई तक देखे गए एलएएफ, जीएमबी और जीईपीयू के औसत स्तर को मानते हुए आउट-ऑफ-सैंपल पूर्वानुमान प्राप्त किए जाते हैं।



**चार्ट 14: प्रतिफल वक्र कारकों पर मैक्रो-शॉक्स की प्रतिक्रिया**

प्रतिक्रिया	स्तर	स्लोप	कर्वेचर
शॉक्स			
ए. डबल्यूएसीआर (शॉक: 1 प्रतिशत अंक की कमी)			
बी. चलनिधि (एनडीटीएल प्रतिशत) (शॉक: 1 प्रतिशत अंक की बढ़त)			
सी. मुद्रास्फीति (शॉक: 1 प्रतिशत अंक की बढ़त)			
डी. उत्पादन-अंतराल (शॉक: 1 प्रतिशत अंक की कमी)			
ई. जीईपीयू (शॉक: 10 प्रतिशत अंक की बढ़त)			
एफ. जीएमबी कारोबार (शॉक: 0.1 प्रतिशत अंक की बढ़त)			

स्रोत: लेखकों के अनुमान

नीतिगत दर में गिरावट का प्रतिफल वक्र के स्लोप पर तत्काल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि नीतिगत दर में परिवर्तन का प्रभाव तेजी से और पूरी तरह से अल्पकालिक परिपक्वताओं की ओर संचारित होता है, जिससे प्रतिफल वक्र में अधिक गिरावट आती है (चार्ट 14ए)। यह बहु-राष्ट्रीय अनुभव के अनुरूप है (वर्गास, 2005; डाइबोल्ड और अन्य, 2006; फैन और जोहानसन, 2010)।

जब चलनिधि एक प्रतिशत अंक (पीपीटी)<sup>12</sup> से बढ़ जाती है, तो प्रतिफल वक्र का स्तर 5 बीपीएस कम हो जाता है और स्लोप में 16 बीपीएस की कमी आती है। चलनिधि वृद्धि का जोखिम प्रीमियम को कम करते हुए दीर्घकालिक दरों पर अपेक्षाकृत बड़ा प्रभाव और प्रतिफल स्पेक्ट्रम में मंद प्रभाव पड़ता है, चलनिधि का अंतर्वेशन प्रतिफल वक्र की तेजी में शिथिलता ला देता है। कर्वेचर पर चलनिधि का प्रभाव स्पष्ट है, जो कि ऑफ-द-रन प्रतिभूतियों के तेजी से अतरल होते ही मध्यम से लंबी अवधि के खंड में प्रतिफल वक्र में गिरावट ला देता है (चार्ट 14बी)।

लक्ष्य के सापेक्ष मुद्रास्फीति में एक प्रतिशत अंक का परिवर्तन, प्रतिफल वक्र के स्तर को 13 बीपीएस तक परिवर्तित कर देता है क्योंकि बाजार सहभागियों की भावी ब्याज दरों के बारे में प्रत्याशा इस प्रतिक्रिया के अनुकूल होती है। स्लोप को भी 28 बीपीएस द्वारा समायोजित किया गया, जो यह दर्शाता है कि मुद्रास्फीति में परिवर्तन होने से दीर्घावधि दरें अपेक्षाकृत अधिक आक्रामक रूप से प्रतिक्रिया करती हैं (चार्ट 14 सी)।

यदि उत्पादन अंतराल एक प्रतिशत अंक से कम हो जाता है और किसी झटके के प्रभाव में ऋणात्मक हो जाता है, तो यह स्तर और कर्वेचर को कम कर देता है और स्लोप को बढ़ाता है, और नीतिगत दर में कमी के कारण प्रतिफल वक्र की प्रतिक्रिया का अनुकरण करता है (चार्ट 14डी)।

जीईपीयू में 10 प्रतिशत अंकों की वृद्धि से स्लोप 12 बीपीएस बढ़ जाता है और वैश्विक नीति अनिश्चितता जोखिम प्रीमियम बढ़ाती है। स्लोप में वृद्धि को या तो एजेंटों की एक समायोजनकारी नीति की अपेक्षा की प्रतिक्रिया के रूप में (जैसा कि कोविड-19

महामारी के मामले में हुआ) या अत्यधिक अनिश्चितता के जवाब में दीर्घकालिक ब्याज दरों में वृद्धि के रूप में समझाया जा सकता है। बढ़ी हुई अनिश्चितता की प्रतिक्रिया में कर्वेचर भी बढ़ जाता है और यह लघु से मध्यम परिपक्वता खंड (चार्ट 14ई) पर प्रतिफल वक्र की कमी में परिलक्षित होता है।

सरकारी बाजार उधारी में वृद्धि (आवर्त अनुपात में 0.1 प्रतिशत अंकों की वृद्धि) का स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इसे 7 बीपीएस बढ़ा देता है, लेकिन इसका स्लोप और कर्वेचर पर न्यूनतम प्रभाव होता है क्योंकि उधार कार्यक्रम में विस्तार से स्पेक्ट्रम भर में प्रतिफलों में वृद्धि होती है (चार्ट 14एफ)।

## V. निष्कर्ष

इस असाधारण समय में, भारत के साथ-साथ दुनिया के बाकी हिस्सों में गिल्ट बाजारों में हालिया घटनाक्रम मीयादी प्रीमियम की समस्या पेश करते हैं। जब बड़े सरकारी उधार कार्यक्रमों की घोषणा की जाती है या जब मुद्रास्फीति उनकी अपेक्षाओं से अधिक बढ़ती है, तो बाजार सहभागियों को अप्रसन्नता होती है। केंद्रीय बैंक नीतिगत दरों को जीरो बाउंड और उससे नीचे तक, जितना हो सके, नीचे ले जाकर उन्हें इन समस्याओं से बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। वे चलनिधि के अंतर्वेशन के लिए खुले बाजार के परिचालन भी करते हैं और बाजार कारोबार से बॉन्ड का अंतरण करते हैं। वे अपने स्वयं के तुलन-पत्र की ब्लोटिंग की कीमत पर बाजार में आपूर्ति के दबाव को दूर करते हैं, बाजार जोखिम के लिए अतिरिक्त प्रावधान करते हैं। केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करने के पथ पर मुद्रास्फीति की आशंकाओं को देखते हुए भी शांति का संचार करते हैं, जो 'निम्न' और 'पर्याप्त' को लंबे समय तक आश्चस्त करते हैं।

निःसंदेह, बाजार बनाने और कुशल परिणाम प्राप्त करने के लिए कम-से-कम दो दृष्टिकोणों की आवश्यकता होती है। हालिया अवधि में, हालांकि, जब कीमतों का निर्धारण और प्रभावशाली संसाधन आबंटन की बाजार प्रक्रियाएं महामारी से अभिभूत हो गई हैं, सहकारी समाधानों की खोज अक्सर दुतरफा मुसीबत खड़ी करती हैं। बाजार सहभागियों ने केंद्रीय बैंकों का अनुमान लगाने और आगे बढ़ने की कोशिश की, जो मानते हैं कि बाजार विशेष प्रकृति के हैं और प्रतिस्पर्धी परिणामों को लाने करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ता है। प्राप्त शिक्षाओं को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए,

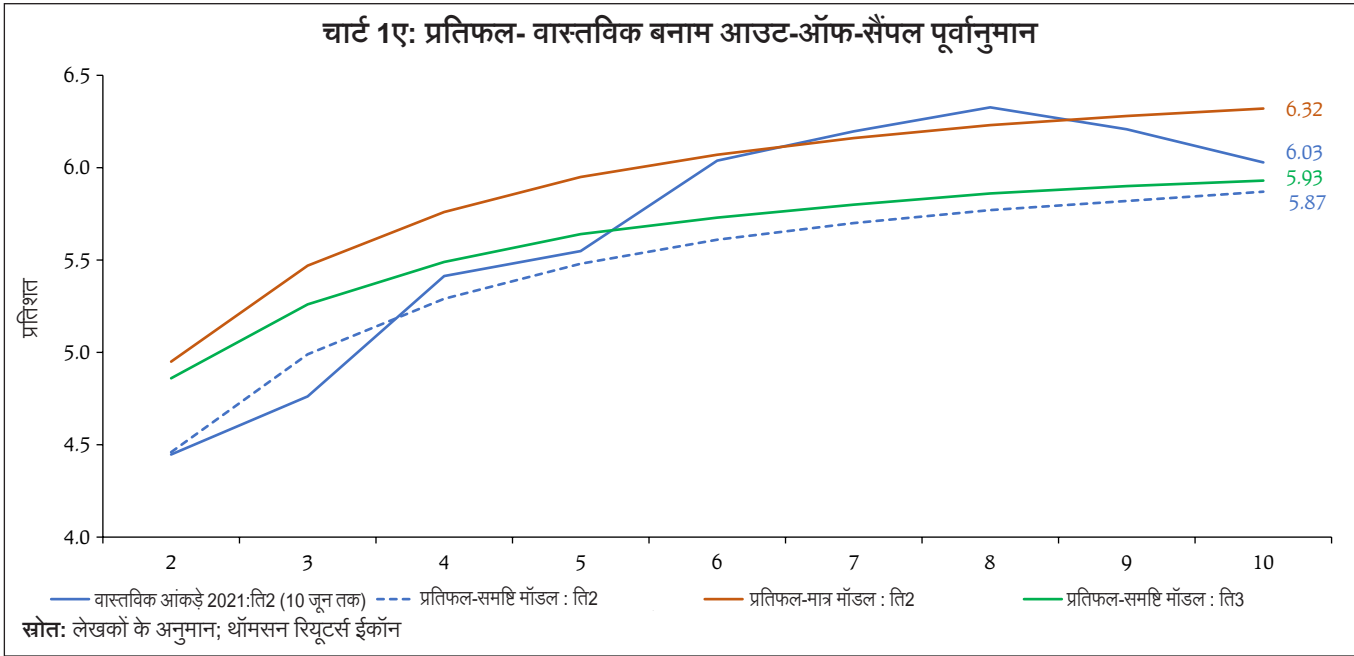
<sup>12</sup> चलनिधि में एक प्रतिशत अंक की वृद्धि बैंक की निवल मांग तथा मीयादी देयताओं (जो कि बैंकों की भारतीय रिजर्व बैंक से चलनिधि तक पहुँच का मेट्रिक है) के अनुपात के रूप में चलनिधि समायोजन सुविधा के माध्यम से चलनिधि के अन्तः क्षेपण में वृद्धि दर्शाती है। वर्तमान आधार पर यह 1.5 लाख करोड़ के समकक्ष है।

- जब जोखिम से बचने और मांग की अनुपस्थिति के कारण मौद्रिक नीति के प्रसारण के परंपरागत माध्यम काम नहीं आते हैं, तो केंद्रीय बैंकों को रिकवरी के लिए अनुकूल वित्तीय स्थिति सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसमिशन के बाजार-आधारित माध्यमों की ओर रुख करना होगा। ऐसी स्थितियों में, गिल्ट प्रतिफल, जिससे अन्य वित्तीय लिखतों की कीमत तय की जाती है, एक चर बन जाता है जो कि यह ऋण प्रबंधन की तुलना में मौद्रिक नीति के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, और इसलिए प्रतिफल वक्र के स्तर, स्लोप और कर्वेचर के किसी भी आकलन में समष्टि-आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- मौद्रिक नीति ब्याज दरों की मीयादी संरचना को प्रभावित करने के लिए एक प्रबल साधन है - नीतिगत दर में परिवर्तन से प्रतिफल वक्र का स्लोप प्रभावित होता है, जबकि चलनिधि प्रतिफल वक्र के स्तर के साथ-साथ स्लोप को प्रभावित करती है, जिससे यह प्रतिफल वक्र के प्रबंधन के लिए एक बेहतर लिखत सिद्ध होता है।
- प्रतिफल वक्र के प्रबंधन के लिए प्रभावशाली संचार सहित मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं का प्रबंधन, किसी भी कार्यनीति का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं में

परिवर्तन प्रतिफल वक्र के स्तर, स्लोप और कर्वेचर को प्रभावित करते हैं और मौद्रिक नीति के रुख को प्रभावहीन कर सकते हैं।

- इस आलेख में प्राप्त अनुभवजन्य परिणामों से संकेत मिलता है कि केवल प्रतिफल मॉडल 6-8 साल की परिपक्वता अवधि (तालिका 2: अनुबंध) को छोड़कर पूरे स्पेक्ट्रम में प्रतिफल के स्तर का अधिक पूर्वानुमान लगाता है। 2021 की दूसरी तिमाही के लिए (10 जून तक की स्थिति में), पूर्वानुमानों के साथ वास्तविक प्रतिफलों की तुलना करते हुए, प्रतिफल-समष्टि मॉडल 2-3 साल के परिपक्वता खंड में 1-23 बीपीएस और नीचे की ओर 39-56 तक यील्ड को समायोजित करने की गुंजाइश की ओर इशारा करता है। 6-9 साल के सेगमेंट में बीपीएस। यह 5 साल की उपज को काफी मूल्यवान मानता है और 10 साल की उपज Q2: 2021 में उचित मूल्य में परिवर्तित हो जाती है। तीसरी तिमाही (जुलाई सितंबर 2021) में, अनुमान बताते हैं कि मौजूदा स्तरों से 10 साल के प्रतिफल में और कमी आने की गुंजाइश है। ये उभरती उपज वक्र गतिशीलता खुले बाजार के संचालन की गुंजाइश और उपज वक्र पर उन बिंदुओं का सुझाव देती है जिन पर उन्हें लक्षित करने की आवश्यकता होती है।

अनुबंध



## संदर्भ

- Ang, A., and Piazzesi, M. (2003). A No-arbitrage Vector Autoregression of Term Structure Dynamics with Macroeconomic and Latent Variables. *Journal of Monetary Economics*, 50(4), 745-787.
- Campbell, T. S. (1980). On the Extent of Segmentation in the Municipal Securities Market. *Journal of Money, Credit and Banking*, 12(1), 71-83.
- Das, S. (2019). *Statement by Governor - Sixth Bi-monthly Monetary Policy Press Conference for 2018-19*, February, Reserve Bank of India.
- Das, S. (2020a). *Governor's Statement, December 4, 2020*, Reserve Bank of India.
- Das, S. (2020b). *Governor's Statement, August 6, 2020*, Reserve Bank of India.
- Das, S. (2020c). *Governor's Statement, October 9, 2020*, Reserve Bank of India.
- Das, S. (2021a). *Governor's Statement, February 5, 2021*, Reserve Bank of India.
- Das, S. (2021b). Edited Transcript of Reserve Bank of India's Monetary Policy Press Conference, June 04, Reserve Bank of India.
- Diebold, F. X., and Li, C. (2006). Forecasting the Term Structure of Government Bond Yields. *Journal of Econometrics*, 130(2), 337-364.
- Diebold, F. X., Rudebusch, G. D., and Aruoba, S. B. (2006). The Macroeconomy and the Yield Curve: A Dynamic Latent Factor Approach. *Journal of Econometrics*, 131(1-2), 309-338.
- Fan, L., and Johansson, A. C. (2010). China's Official Rates and Bond Yields. *Journal of Banking and Finance*, 34(5), 996-1007.
- Fisher, I. (1896). *Appreciation and Interest*. Publications of the American Economic Association, 11, 21-29.
- Froot, K. A. (1989). New Hope for the *Expectations Hypothesis* of the Term Structure of Interest Rates. *The Journal of Finance*, 44(2), 283-305.
- Gürkaynak, R. S., and Wright, J. H. (2012). Macroeconomics and the Term Structure. *Journal of Economic Literature*, 50(2), 331-67.
- Nelson, C. R., and Siegel, A. F. (1987). Parsimonious Modeling of Yield Curves. *Journal of Business*, 60(4), 473-89.
- Patra, M.D., Behera, H. and John, J. (2020). Revisiting the Determinants of the Term Premium in India. *RBI Bulletin*, Reserve Bank of India, November.
- Patra, M.D., et al. (2021). State of the Economy. *RBI Bulletin*, Reserve Bank of India, May.
- Taylor, M.P. and Masson, P.R. (1991). Modelling the Yield Curve. *IMF Working Paper*, December.
- Svensson, L. E. (1994). Estimating and Interpreting Forward Interest Rates: Sweden 1992-1994. *NBER Working Paper*, No. w4871, National Bureau of Economic Research.
- Vargas, G. A. (2005). Macroeconomic Determinants of the Movement of the Yield Curve. *MPRA Working Papers*, March.



## भारत में राजकोषीय फ्रेमवर्क और व्यय की गुणवत्ता\*

अब पहले से कहीं ज्यादा इस बात की स्वीकृति है कि सार्वजनिक व्यय के वृद्धिकारक तत्वों को संरक्षित और विकसित किया जाना है। कोविड-19 ने राजकोषीय नीति को इस तरह से फिर से परिभाषित करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया है, जो सार्वजनिक व्यय के कार्यनीतिक पुनर्प्रयोजन और पुनर्प्राथमिकता द्वारा 'कितना' के बजाय 'कैसे' पर जोर देती है। भारत में, राजकोषीय प्रबंधन और अनुशासन के भीतर गुणवत्ता संबंधी सोच को संस्थागत बनाना महत्वपूर्ण है। इस आलेख में कुछ मात्रात्मक संकेतकों का प्रस्ताव दिया गया है, अर्थात्, पूंजीगत परिव्यय की तुलना में राजस्व व्यय का अनुपात और राजस्व घाटे का सकल राजकोषीय घाटे के साथ-साथ उनके लिए प्रारंभिक स्तर जिसे एक सतत विकास प्रक्षेपवक्र के लिए राजकोषीय संरचना में उपयुक्त रूप से मिश्रित किया जा सकता है।

“मानव पूंजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे पर व्यय न केवल कल्याणकारी है, बल्कि यह उनके उच्च गुणक प्रभाव और पूंजी एवं श्रम उत्पादकता दोनों में वृद्धि के माध्यम से उच्च विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। आगे चलकर, यह अनिवार्य हो जाता है कि राजकोषीय रोड मैप्स को न केवल मात्रात्मक मापदंडों जैसे कि जीडीपी अनुपात की तुलना में राजकोषीय संतुलन या जीडीपी अनुपात की तुलना में ऋण के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है, बल्कि केंद्र और राज्यों दोनों के लिए व्यय की गुणवत्ता से संबंधित गौर करने लायक मापदंडों के संदर्भ में भी परिभाषित किया जाता है, कि .... यह सुनिश्चित करेगा कि कल्याणवाद में उल्लेखनीय उत्पादक परिणाम और गुणक प्रभाव हो”

- श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, आरबीआई, 2021

\* इस लेख को संगीता मिश्रा, समीर रंजन बेहरा, विचित्रानंद सेठ और सक्षम सूद ने तैयार किया है। हरेंद्र बेहरा के बहुमूल्य तकनीकी समर्थन और देबा प्रसाद रथ और सीतीकान्त पटनायक के उपयोगी सुझावों को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया जाता है। लेखक कई उपयोगी चर्चाओं और टिप्पणियों के लिए विनीत कुमार श्रीवास्तव के आभारी हैं जिन्होंने इस लेख को समृद्ध किया। इस लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के नहीं।

## भूमिका

कोविड -19 संकट और आर्थिक गतिविधियों में अभूतपूर्व गहरे संकुचन से उबरने के लिए जबर्दस्त राजकोषीय प्रतिक्रिया से भविष्य के लिए राजकोषीय फ्रेमवर्क पर पुनर्विचार करना जरूरी हो गया है। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण को विवेक और स्थिरता के पथ पर निर्देशित करने के लिए ऋण/घाटे/व्यय नियमों को स्थापित करने के मानक दृष्टिकोण के तहत सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। भारत में, गुणवत्ता संबंधी विचार राजकोषीय प्रबंधन और अनुशासन के केंद्र में रहते हैं और इसलिए, उन्हें संस्थागत बनाना इन पहलुओं को मजबूत करेगा।

आमतौर पर, राजकोषीय नियमों का उद्देश्य विकृत प्रोत्साहनों को दुरुस्त करना और अधिक खर्च करने के दबाव को नियंत्रित करना है ताकि राजकोषीय जिम्मेदारी और ऋण स्थिरता सुनिश्चित हो सके। हालाँकि, दूसरे देशों के अनुभव से पता चलता है कि हेडलाइन राजकोषीय संतुलन के संदर्भ में स्थापित नियम राजकोषीय नीति को प्रचक्रियता प्रदान करते हैं, राजकोषीय खर्च की गुणवत्ता को कम करते हैं, और सरकार के हाथों में व्यापार चक्रों के लिए बहिर्जात/अनिश्चित आघात पर प्रतिक्रिया देने की स्वतंत्रता को कम करते हैं (मंडन, 2014; गुर्गुइल एवं अन्य, 2017)। यह बाद वाले के संदर्भ में है कि दूसरी पीढ़ी के राजकोषीय नियमों में पलायन/सुधार उपबंध<sup>1</sup> शामिल है और/या उनके बेहतर स्थिरीकरण गुणों को देखते हुए चक्रिय रूप से समायोजित शर्तों (हेडलाइन राजकोषीय शेष के बजाय) में परिभाषित किया गया है (आईएमएफ, 2014; स्कैचटर एवं अन्य, 2012)। जहां इस तरह के उपबंध नैतिक खतरे में पड़ सकते हैं और उन्हें संचार चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, वहीं व्यय नियम पसंदीदा विकल्प बन गए हैं क्योंकि वे अच्छी तरह से समझे जाते हैं, निगरानी में आसान होते हैं और राजकोषीय नीति की चक्रियता को कम करते हैं (मानेस्कु और बोवा, 2021)<sup>2</sup>। इस विशिष्ट शैली में, दूसरे देश के अनुभव के साथ-साथ अपने स्वयं के ऐतिहासिक अतीत से भारत

<sup>1</sup> भारत के लिए बचाव और सुधार खंडों की चर्चा अनुबंध I में की गई है।

<sup>2</sup> सरकार की व्यय बाध्यता और बाध्यकारी राजकोषीय नियमों ने एक अन्य प्रकार के गैर-पारदर्शी राजकोषीय जोखिमों को जन्म दिया है, जो अनिवार्य रूप से 'गैर-जरूरी' मदों से हैं। इसके मद्देनजर, अधिक पारदर्शिता के साथ, 2018 से आईएमएफ द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के तुलन-पत्र दृष्टिकोण पर जोर दिया जा रहा है।

के लिए एक स्पष्ट सबक है कि सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता से समझौता नहीं करना है।

कोविड-19 महामारी ने प्रमुख वस्तुओं और सार्वजनिक वस्तुओं पर खर्च करने की आवश्यकता को महत्वपूर्ण बना दिया है, विशेष रूप से वे जो मानव और सामाजिक पूंजी एवं भौतिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार करते हैं (आईएमएफ, 2020)। समझदारी भी व्यय की गुणवत्ता पर ध्यान देने को सही ठहराती है। बाजार उधारियों के माध्यम से सरकारी व्यय के बड़े पैमाने पर वित्तपोषण होने से यह महत्वपूर्ण है कि उधार लिया गया धन, जो लागत और कर्ज सेवा दबाव को लागू करता है, का उपयोग दीर्घकालिक प्रतिलाभ के साथ उत्पादक साधनों के लिए किया जाता है (सुब्बाराव, 2012; भानुमूर्ति एवं अन्य, 2019)। सार्वजनिक व्यय को उच्च गुणक पूंजीगत व्यय को प्रेरित करना चाहिए और निजी निवेश के बहिर्गमन संबंधी जोखिमों को कम करना चाहिए, खासकर तब जब निजी निवेश में सुधार हो रहा हो (एलेसिना और पेरोटी, 1995; गुप्ता एवं अन्य, 2005; आरबीआई, 2019)। साथ ही, अच्छी गुणवत्ता वाला व्यय जो महत्वपूर्ण आपूर्ति बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकता है, वह गैर-मुद्रास्फीतिकारी होगा।

इस पृष्ठभूमि में, शेष आलेख को निम्नानुसार संरचित किया गया है: खंड II व्यय की गुणवत्ता और इसलिए, वृद्धि पर इसके प्रभाव के विशिष्ट दृष्टिकोण से राजकोषीय समायोजन की प्रकृति के संबंध में दूसरे देशों के अनुभव का एक सिंहावलोकन प्रदान करता है। खंड III में मौजूदा वित्तीय नियमों की गुणवत्ता विशेषताओं के बीच, व्यक्तिगत रूप से और एक समग्र सूचकांक के रूप में, सार्वजनिक व्यय मानकों की विभिन्न गुणवत्ता के संदर्भ में, केंद्र और राज्यों दोनों में भारत के वित्तीय अनुभव संबंधी शोधपरक तथ्यों पर संक्षेप में चर्चा की गयी है। खंड IV में भारत के लिए महामारी के बाद के राजकोषीय फ्रेमवर्क के महत्वपूर्ण तत्वों को विश्लेषणात्मक रूप से निर्धारित करके आगे की कार्य-योजना दी गयी है जो पारंपरिक रूप से मानदंड के साथ परिभाषित ऋण स्थिरता के मात्रात्मक आयामों को मिश्रित करता है जिससे कि श्रेष्ठ लोकहित को सुरक्षित करने के लिए व्यय की गुणवत्ता को संरक्षित और समृद्ध किया जा सके। अंतिम नीतिगत दृष्टिकोण खंड V में दिए गए हैं।

## II. व्यय की गुणवत्ता: दूसरे देशों के अनुभव

1990 के दशक के मध्य से, दुनिया भर के देशों ने व्यापक आर्थिक और वित्तीय अस्थिरता को दूर करने के लिए नीतिगत

ढांचे के एक अभिन्न तत्व के रूप में राजकोषीय समेकन का कार्य किया है, यह मानते हुए कि इन असमानताओं को दूर करने में राजकोषीय नीति की महत्वपूर्ण भूमिका है। समायोजन के मूल में अर्थव्यवस्था में राजकोषीय फुटप्रिंट में कमी है, जिसकी वजह अनेक तरह के तथाकथित 'राजकोषीय नियम' हैं, जो दोनों तरह के घाटे, या कर्ज, या व्यय, या उसके संयोजन में कमी का एक प्रक्षेपवक्र निर्धारित करना चाहते हैं। देश के अनुभव, विशेष रूप से बड़े और लगातार असंतुलन की पृष्ठभूमि के खिलाफ, यह दर्शाता है कि समायोजन का आकार अपने आप में एक स्व-पूर्ति का अंत बन जाता है, जबकि मुख्य उद्देश्य व्यापक आर्थिक स्थिरता के आधार पर निरंतर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। राजकोषीय समायोजन विकास के अनुकूल होने के लिए, यह जिस तरह से किया जाता है वह मायने रखता है, परिमाण नहीं। सरकारी व्यय के कुछ घटक दूसरों की तुलना में अधिक उत्पादक होते हैं और निजी व्यय के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय पूरक होते हैं, और कुछ कर परिवर्तन दूसरों की तुलना में संसाधन आबंटन पर उनके प्रभाव में अधिक फायदेमंद होते हैं। हाल ही में, इसलिए, साहित्य और देश के अनुभव में इस बात को लेकर आम सहमति बढ़ रही है कि यदि वे ऋण स्थिरता और भविष्य के कर बोझ के बारे में अनिश्चितता को कम करें तो राजकोषीय नियम विकास को समर्थन देने में योगदान दे सकते हैं, और इस प्रकार निवेश और खपत को बढ़ावा देते हैं (आईएमएफ, 2012)।

तदनुसार, विकास को बढ़ावा देने के मामले में अधिकतम लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से राजकोषीय समायोजन की गुणवत्ता को प्राथमिकता देने के लिए देश तेजी से अपना मुद्दा बदल रहे हैं। व्यावहारिक दृष्टिकोण से, समायोजन की मात्रा के विपरीत, राजकोषीय समायोजन की गुणवत्ता को मापना कठिन है। देश के अनुभव से पता चलता है कि एक सामान्य नियम के अनुसार, राजकोषीय दायरे के भीतर कुछ निश्चित व्यय को प्राथमिकता देना और वृद्धि को बढ़ावा देने वाली कर प्रणाली का संस्थापन वृद्धि के अनुकूल राजकोषीय समायोजन की स्पष्ट रूप से दिखने वाली विशेषताएं हैं जो कि बचत और निवेश के आबंटन के मामले में बहुत ही कम विकृत करने वाला है और कर अनुपालन के बोझ को कम करती है। वित्तीय समायोजन प्रक्रिया के भीतर संरक्षित किए जाने वाले व्यय की अच्छी श्रेणियों में शिक्षा, स्वास्थ्य और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च शामिल है, जिनकी प्रतिफल की सामाजिक



दर उच्च है और आमतौर पर निजी क्षेत्र द्वारा आपूर्ति नहीं की जाती है; उद्यमिता के लिए एक स्थिर वातावरण को बढ़ावा देने वाली प्रशासनिक और नियामक सेवाओं पर व्यय; सामाजिक सुरक्षा जाल; और प्रभावी एवं कुशल सार्वजनिक व्यय प्रबंधन बजटीय प्रक्रियाओं का सर्वोत्तम उदाहरण है जो पारदर्शी, समझने योग्य और समय पर हैं। राजकोषीय समायोजन की गुणवत्ता को बढ़ाने वाले कर प्रणाली के निम्नलिखित तत्व हैं: यदि कुछ न हो तो, कुछ छूट के साथ अन्य बातों के साथ-साथ एक समान और मध्यम कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत आयकर दर; सामान्य बिक्री कर के रूप में अधिमानतः एक दर और न्यूनतम छूट के साथ एक मूल्य वर्धित कर; जितना संभव हो उतना कम औसत दर और सीमित प्रसार वाला सीमा शुल्क टैरिफ; मुश्किल वाले कर क्षेत्रों में आयकर के लिए केवल एक प्रॉक्सी के रूप में निर्यात कर; और एक कुशल कर प्रशासन जो स्वैच्छिक अनुपालन, निगरानी को प्रोत्साहित करता है और चोरी एवं धोखाधड़ी को हतोत्साहित करता है (मैकेंजी और ओर्समंड, 1996)।

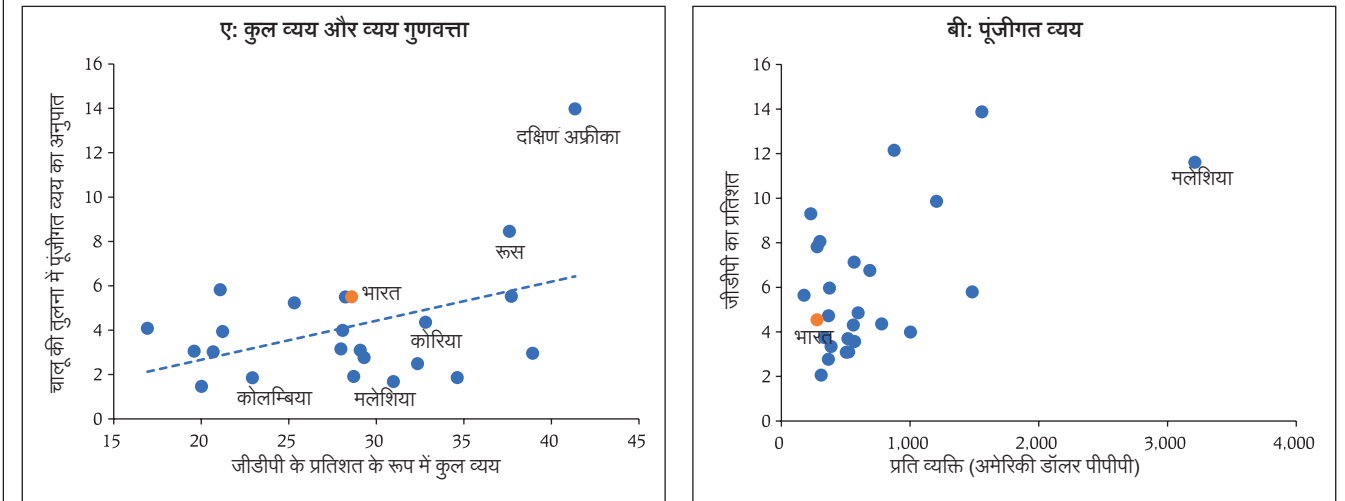
व्यवहार में, राजस्व बढ़ाने के उपायों की तुलना में टिकाऊ राजकोषीय समेकन प्राप्त करने में व्यय में कटौती अधिक प्रभावी पाई गई है (प्राइस, 2010; एलेसीना, 2010)। टिकाऊ राजकोषीय समायोजन चालू व्यय में स्थायी कटौती (डी राटो, 2004; मैकडरमोट और वेस्कॉट, 1996) से जुड़े हैं, गैर-ब्याज चालू व्यय के साथ - वेतन बिल, पेंशन, कल्याणकारी खर्च और बेरोजगारी लाभ - करेक्शन का खामियाजा भुगतते हुए: कनाडा (1994-97); फ़िनलैंड (1998); जर्मनी (2003-05); नीदरलैंड (2004-05); स्वीडन (1994-98); दक्षिण अफ्रीका (1993-2001); स्पेन (1996-97); और यूनाइटेड किंगडम (1995-98)। हालांकि, देश के साक्ष्य से पता चलता है कि राजकोषीय समेकन के माध्यम से कुल व्यय में पूंजीगत व्यय के हिस्से को बनाए रखने या बढ़ाने से इसकी सफलता की संभावना बढ़ गई है, खासकर एशिया, अफ्रीका और प्रशांत क्षेत्र के देशों में (गुप्ता एवं अन्य, 2005; काबेज़ोन एवं अन्य, 2015)। यह मुख्य रूप से उस पूरक भूमिका से जुड़ा है जो सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक व्यय निजी निवेश के अंतर्गमन में भूमिका निभाता है, ज्यादातर विकासशील देशों में (एर्डन और होल्कोम्ब, 2005)। प्रमुख चालू व्यय मदों जैसे अंतरण, सब्सिडी

और मजदूरी में कमी को सार्वजनिक निवेश सहित अन्य व्यय मदों की तुलना में राजनीतिक रूप से अधिक कठिन पाया गया है (हेगन और सैटराच, 2001)।

अन्य देशों में - संयुक्त राज्य अमेरिका (1994); फ्रांस (1996-97); चिली (1990-2000); ब्राजील (1999-2003); रूस (1999-2002); और नाइजीरिया (1994) - राजकोषीय समेकन राजस्व पक्ष उपायों द्वारा किया गया था (ओकवुओकी, 2014)। राजस्व पक्ष से समायोजन, सामान्य रूप से, अल्पकालिक रहा है, जैसा कि वर्ष 1999-2003 के दौरान ब्राजील में हुआ था (ब्लैंको और हेरेरा, 2006; एलेसीना और पेरोटी, 1995; एलेसीना और अर्दंगा, 2012)। कर-जीडीपी अनुपात 1998 में सकल घरेलू उत्पाद के 29 प्रतिशत से बढ़कर 2004 में 35 प्रतिशत हो गया। व्यय के मोर्चे पर, जबकि पूंजीगत व्यय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग आधा कर 0.5 प्रतिशत हो गया था, लेकिन सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सहायता लाभ के बढ़ते जाने, कार्मिक लागत और अंतर-सरकारी स्थानान्तरण के कारण चालू व्यय कठोर बना रहा। कर के बोझ में वृद्धि और सार्वजनिक निवेश के दबाव ने भविष्य के विकास की संभावनाओं को बाधित किया। इसके विपरीत, वर्ष 1993-2001 के दौरान दक्षिण अफ्रीका द्वारा अपनाए गए राजकोषीय समायोजन में व्यय पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसमें वेतन बिलों में कमी, सब्सिडी एवं अंतरण और पूंजीगत व्यय में वृद्धि शामिल थी। राजस्व के मोर्चे पर, संरचनात्मक सुधार हुए थे - कर आधार में वृद्धि; छूट खत्म कर देना; कम आयकर; और मूल्य वर्धित कर (वैट) में वृद्धि कुल घाटे में 6.5 प्रतिशत अंक की कमी में से, खर्च में 3.5 प्रतिशत अंक की कटौती हुई और राजस्व में 3 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई (ओकवुओकी, 2014)। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के कमजोर राजस्व आधार को देखते हुए, राजस्व समायोजन उपायों में अनिवार्य रूप से कर आधार और कम दरों का विस्तार करने के लिए संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें कुल समायोजन का केवल एक तिहाई खर्च नियंत्रण लेखांकन है (आईएमएफ, 2013)।

मध्यम आय वाले ईएमई में, सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 20-40 प्रतिशत के सामान्य सरकारी व्यय के साथ, वर्तमान और पूंजीगत व्यय का अनुपात - व्यय की गुणवत्ता का एक संकेतक -

**चार्ट 1: व्यय की गुणवत्ता: दूसरे देश से तुलना**



**टिप्पणी:** 1. चार्ट्स में दिए गए आंकड़े वर्ष 2017/2018 से संबंधित हैं।  
 2. समरूप स्रोत से दूसरे देश के पूंजीगत परिव्यय संबंधी आंकड़ों के अभाव में, पूंजीगत व्यय का उपयोग किया गया है।  
**स्रोत:** ओईसीडी यूसीएलजी डेटाबेस

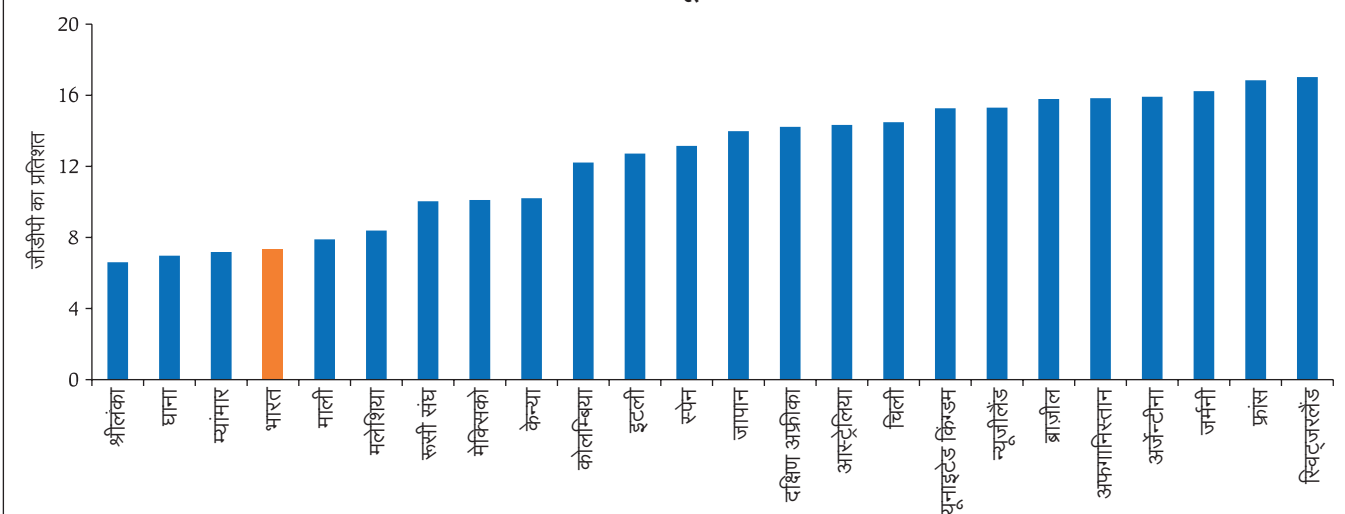
समान स्तर के व्यय के साथ अपने समकक्षों की तुलना में भारत के लिए उच्च स्तर पर है (चार्ट 1ए)। नतीजतन, सामान्य सरकारी पूंजीगत व्यय कम रहता है, खासकर प्रति व्यक्ति के संदर्भ में (चार्ट 1 बी)।

मानव पूंजी पर खर्च, ज्यादातर शिक्षा और स्वास्थ्य, सार्वजनिक व्यय के लिए पसंदीदा विकल्प के रूप में कोविड-19

के बाद उभरा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलना करें तो भारत में मानव पूंजी पर सरकारी खर्च ब्रिक्स और उन्नत देशों से काफी पीछे है (चार्ट 2)।

वित्तीय नियमों में व्यय की गुणवत्ता को संस्थागत बनाना वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद की अवधि में ईएमई अनुभव में तेजी से पाया जा रहा है, जो मौजूदा नियमों से एक नयी

**चार्ट 2: वर्ष 2017 में मानव पूंजी के ऊपर सरकारी व्यय**



**स्रोत:** विश्व बैंक

तरह का विचलन है जो आम तौर पर कुल खर्च<sup>3</sup> को लक्षित करता है। कुछ उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने कुल खर्च के बजाय खर्च के आवर्ती घटक को लक्षित करके व्यय की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया है - अर्थात् मेक्सिको; पेरू; कोलंबिया - दोहरे विचारों द्वारा निर्देशित: पहला, एक विकासात्मक परिप्रेक्ष्य, जो प्राप्त ज्ञान को दर्शाता है कि सार्वजनिक परिव्यय की संरचना वृद्धि पर इसके प्रभाव को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है (आईएमएफ, 2014; गुप्ता एवं अन्य, 2005); और दूसरा, बजट संतुलन और ऋण नियमों की तुलना में व्यय नियमों के बेहतर अनुपालन रिकॉर्ड का समर्थन करने वाले साक्ष्य के साथ एक प्रभावशीलता परिप्रेक्ष्य (कॉर्ड्स एवं अन्य, 2015)<sup>4</sup>।

### III. भारतीय अनुभव में शोधपरक तथ्य

2000 के दशक की शुरुआत में राजकोषीय सुदृढीकरण के मार्ग में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। 1990 के दशक की शुरुआत के संकट के बाद किए गए व्यापक आर्थिक समायोजन और संरचनात्मक सुधारों के एक अभिन्न तत्व के रूप में, भारत ने वर्ष 2004-05 में केंद्र के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (एफआरबीएम) अधिनियम के तहत राजकोषीय अनुशासन कानूनों को अपनाया, जिसका अनुकरण वर्ष 2003 से 2008 की अवधि में अधिकांश राज्यों द्वारा किया गया था (अनुबंध I)। आने वाले वर्षों में, मुख्य रूप से सकल राजकोषीय घाटे और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सार्वजनिक ऋण के लिए ग्लाइड पथ का पालन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। हालांकि, इस प्रक्रिया में सरकार के दोनों स्तरों पर व्यय की गुणवत्ता को नुकसान हुआ है, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

#### ए. व्यय की संरचना

मानक मैक्रोइकॉनॉमिक विश्लेषण में, व्यय की संरचना को एक आवश्यक के रूप में नियोजित किया जाता है, हालांकि व्यय की गुणवत्ता का पर्याप्त संकेतक नहीं है। संक्षेप में, यह वर्तमान उपयोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं पर सरकार के अंतिम उपभोग व्यय के वित्तपोषण पर खर्च किए गए संसाधनों का मूल्यांकन करता है,

साथ ही वस्तुओं और सेवाओं पर पूंजीगत व्यय, जिसका उद्देश्य भविष्य में लाभ उत्पन्न करने वाली आस्तियां बनाना है, अर्थात्, बुनियादी ढांचे में निवेश परिवहन (सड़क, रेल और हवाई अड्डे), स्वास्थ्य और अनुसंधान खर्च<sup>5</sup>। ऐतिहासिक रूप से, दोहरे बजट, या वर्तमान और पूंजीगत व्यय के लिए अलग-अलग बजट, जो 1930 के दशक के अंत में यूरोपीय देशों में उत्पन्न हुए थे, ने अधिक अनुत्पादक लोगों से उत्पादक या अधिक विकास के अनुकूल प्रकार के खर्च को अलग करने में सक्षम बनाया है (आईएमएफ, 1995; अफोन्सो एवं अन्य, 2005)। हाल के वर्षों में, एक "सुनहरा नियम" (जो केवल पूंजीगत व्यय के लिए उधार लेने की अनुमति देता है) का उपयोग पूंजी और वर्तमान व्यय के एक अलग उपचार के औचित्य के रूप में उभरा है (प्रेमचंद, 1989; जैकब्स, 2009)। इस संदर्भ में, पूंजीगत व्यय की तुलना में राजस्व व्यय अनुपात को साहित्य में व्यय की इष्टतम संरचना का आकलन करने, दूसरे देशों से तुलना करने और वृद्धि को समर्थन प्रदान करने के लिए राजस्व से पूंजी पर स्विच करने हेतु नीतियों की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए अपील मिली है (देवराजन एवं अन्य, 1996; फोर्ट और मैगज़ीनो, 2014; ओईसीडी 2020; भानुमूर्ति एवं अन्य, 2019)। व्यवहार में, इस सूचक ने विभिन्न प्रकार के व्यय के बीच संतुलन को उजागर करने के लिए सार्वजनिक व्यय संबंधी घरेलू नीति विश्लेषण में भी प्रवेश किया है (भारत सरकार, 2021; आरबीआई, 2019)।

पूंजीगत परिव्यय की तुलना में राजस्व व्यय (आरईसीओ) अनुपात जो 1990 के दशक के दौरान उच्च स्तर पर मंडराता था - केंद्र के लिए लगभग 11 और राज्यों के लिए 9 - व्यय की खराब गुणवत्ता को दर्शाता है, जिसमें एफआरबीएम के बाद एक महत्वपूर्ण सुधार देखा गया, जो अर्थव्यवस्था में उच्च वृद्धि से भी जुड़ा था<sup>6</sup>। ये लाभ जीएफसी के बाद की अवधि में समाप्त हो गए थे (चार्ट 3ए)। राजकोषीय समेकन के ग्लाइड पथ से बड़े विचलन के लिए सुधार में अक्सर पूंजी परिव्यय में कटौती शामिल होती है। तदनुसार, आरईसीओ अनुपात में पिछले एक

<sup>3</sup> राजकोषीय नियमावली डेटाबेस के अनुसार, 45 देशों में व्यय नियम हैं, जो या तो विशेष रूप से, या अन्य वित्तीय नियमों के साथ में हैं। व्यय नियम (ईआर) संबंधी विवरण अनुबंध II में दिया गया है।

<sup>4</sup> इसके अलावा, विशिष्ट उच्चतम सीमा के संदर्भ में परिभाषित ईआर का प्रदर्शन रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, बनिस्बत उनके जिसे कि जीडीपी, मुद्रास्फीति आदि जैसे अन्य व्यापक आर्थिक कारकों के संबंध में परिभाषित किया गया है।

<sup>5</sup> पब्लिक स्पेंडिंग कोड | ए ग्लाइड टू इवैल्यूएटिंग, प्लानिंग एंड मैनेजिंग करेंट एक्सपेंडीचर, 2012 (43555\_b026e01682a24a4fb4db411bc15c3df3.pdf)

<sup>6</sup> पूंजी परिव्यय, जो ऋणों और अग्रिमों के कुल पूंजीगत व्यय को दर्शाता है, व्यय की गुणवत्ता का एक सख्त और बेहतर संकेतक है क्योंकि सभी ऋण और अग्रिम उत्पादक आस्तियों के सृजन पर खर्च किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं।

**चार्ट 3: पूंजीगत परिव्यय की तुलना में राजस्व व्यय**



दशक में कोई विशेष सुधार नहीं दिखा है, जिसे केंद्र के लिए 7.5 और राज्यों के लिए 2019-20 में 6.2 पर रखा गया है (चार्ट 3 बी)।

**बी. घाटे की संरचना**

सकल राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे (आरडी-जीएफडी) की हिस्सेदारी निवेश के बजाय राजस्व व्यय पर समाप्त उधार

संसाधनों के अनुपात को इंगित करता है और, इस प्रकार, यह व्यय की गुणवत्ता को दर्शाता है - कम आरडी-जीएफडी सुधार की ओर इशारा करता है चूंकि राजकोषीय गुणक चालू व्यय की तुलना में पूंजीगत परिव्यय के लिए अधिक होते हैं। तदनुसार, यह केंद्रीय बजट के मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति वक्तव्य के साथ-साथ वित्त आयोग की रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए दूरदेशी विश्लेषण का हिस्सा है। एफआरबीएम समीक्षा समिति की रिपोर्ट

**चार्ट 4: सकल राजकोषीय घाटा की तुलना में राजस्व घाटा (आरडी)**



में लगभग 32 प्रतिशत की आरडी-जीएफडी की परिकल्पना की गई है, जो उधार लेने के सुनहरे नियम के अनुरूप वृद्धि को अधिकतम करने के लिए पूंजीगत खर्च में वृद्धि के लिए पर्याप्त जगह सुनिश्चित करेगी (भारत सरकार, 2017)। केंद्र के मामले में आरडी-जीएफडी 70 प्रतिशत से ऊपर हो गया है, जो एफआरबीएम समीक्षा समिति द्वारा परिकल्पित स्तर से दोगुने से अधिक है। जहां राज्यों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, वहीं आरडी-जीएफडी हाल के वर्षों में बढ़ रहा है (चार्ट 4ए एवं बी)।

सी. क्या व्यय वृद्धि अनुकूल है?

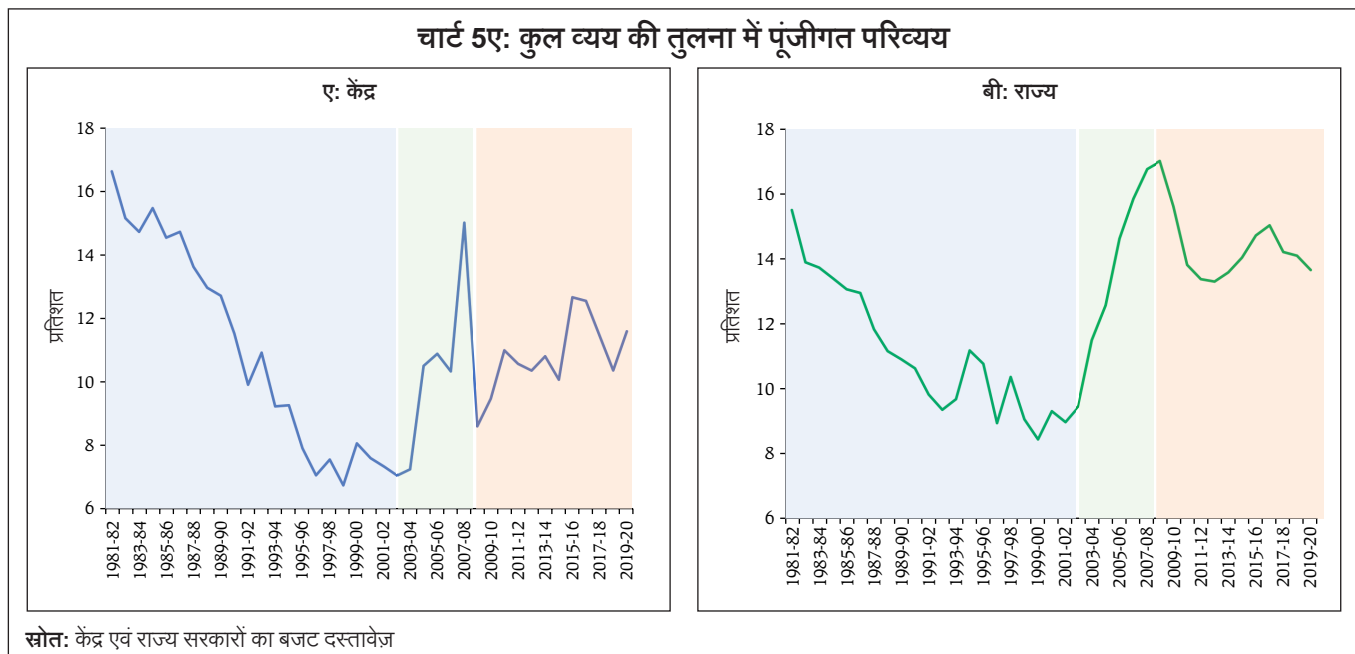
आम तौर पर, पूंजी परिव्यय अन्य श्रेणियों की तुलना में उच्च गुणक, मजबूत रोजगार सृजन क्षमता और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के साथ पिछड़े और आगे के संबंधों को देखते हुए वृद्धि देने वाली विशेषताओं से जुड़ा है (आरबीआई, 2019; बोस और भानुमूर्ति, 2013)। तदनुसार, कुल व्यय दायरे में पूंजी परिव्यय के अनुपात का उपयोग गुणवत्ता के संकेतक के रूप में किया जाता है, या तो व्यक्तिगत रूप से या अन्य शासन और दक्षता मापदंडों के साथ एक व्यापक सूचकांक के घटकों में से एक के रूप में (हेरिविबोबो एवं अन्य, 2016; आईएमएफ, 2014)। यह अनुभवजन्य रूप से देखा गया है कि यूरोपीय संघ

(ईयू) देशों के लिए सार्वजनिक निवेश का इष्टतम आकार सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10.5 प्रतिशत है, जबकि वास्तविक सार्वजनिक निवेश सकल घरेलू उत्पाद के 4-5 प्रतिशत की सीमा में रहता है (फोर्ट और मैगज़ीनो, 2014)।

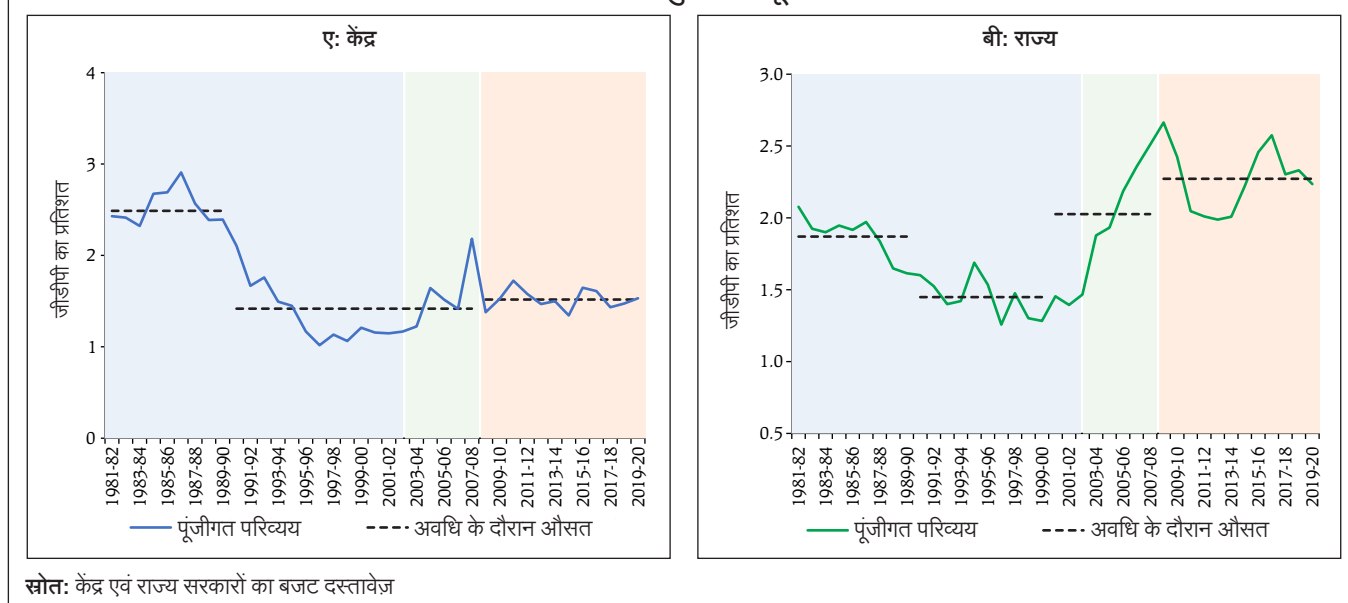
2000 के दशक की शुरुआत में केंद्र में एफआरबीएम और राज्यों के लिए राजकोषीय नियम विधान (एफआरएल) की स्थापना ने वर्ष 1980-81 के बाद से कुल व्यय में पूंजीगत परिव्यय के हिस्से में गिरावट की प्रवृत्ति को रोक दिया। वर्ष 2003-08 की उच्च वृद्धि अवधि केंद्र और राज्यों दोनों के लिए कुल व्यय में पूंजीगत परिव्यय के हिस्से में उल्लेखनीय वृद्धि से जुड़ी हुई थी (चार्ट 5ए)। जीएफसी के बाद पूंजीगत परिव्यय में केंद्र के लिए एक मॉडरेशन देखा गया, जबकि राज्यों के लिए गिरावट आई। निवेश दर के लिए, सकल घरेलू उत्पाद के पूंजीगत परिव्यय का अनुपात लगभग तीन दशकों से केंद्र के लिए लगभग 1.5 प्रतिशत पर स्थिर रहा है, जबकि राज्यों के लिए यह औसत गति से लगभग 2.3 प्रतिशत तक बढ़ा है, जो कि पोस्ट- जीएफसी अवधि, हालांकि पिछले कुछ वर्षों में गिरावट के साथ (चार्ट 5 बी)।

राजकोषीय व्यय की गुणवत्ता में सुधार सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निवेश, शिक्षा और प्रशिक्षण (सक्रिय श्रम

चार्ट 5ए: कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत परिव्यय



चार्ट 5बी: जीडीपी की तुलना में पूंजीगत परिव्यय



बाजार नीतियों के साथ), स्वास्थ्य देखभाल के साथ-साथ अनुसंधान और विकास से जुड़ा हुआ है जो उत्पादन कारकों (श्रम और पूंजी) या उनकी उत्पादकता की अर्थव्यवस्था की वृत्ति में सुधार करके वृद्धि का समर्थन करता है (यूरोपीय आयोग, 2012)। ऐसे उत्पादक खर्च के लिए सार्वजनिक व्यय का पुनर्गठन अर्थव्यवस्था में विकृतियों को पैदा किए बिना वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है जो विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है (जगलर और डर्नकर, 2003)। कुल व्यय में प्रतिबद्ध और अप्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा अक्सर गुणवत्ता के संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है (बैरो, 1990; गुप्ता एवं अन्य, 2005; ग्रिगोली, 2012)। भारतीय अनुभव में, सरकारी संसाधनों पर वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान के रूप में प्रतिबद्ध व्यय का पहला प्रभार है। केंद्र के लिए, प्रतिबद्ध व्यय उच्च और मूल्यनिरपेक्ष रहता है; राज्यों के लिए, पेंशन द्वारा संचालित हाल के वर्षों में अपट्रेंड स्पष्ट है (चार्ट 6ए और बी)। इसका परिणाम यह हुआ है कि विकासात्मक व्यय में सन्निहित सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे पर खर्च पिछले ढाई दशकों में स्थिर रहा है, खासकर केंद्र के लिए (चार्ट 6सी और डी)।

### डी. वित्तपोषण पैटर्न

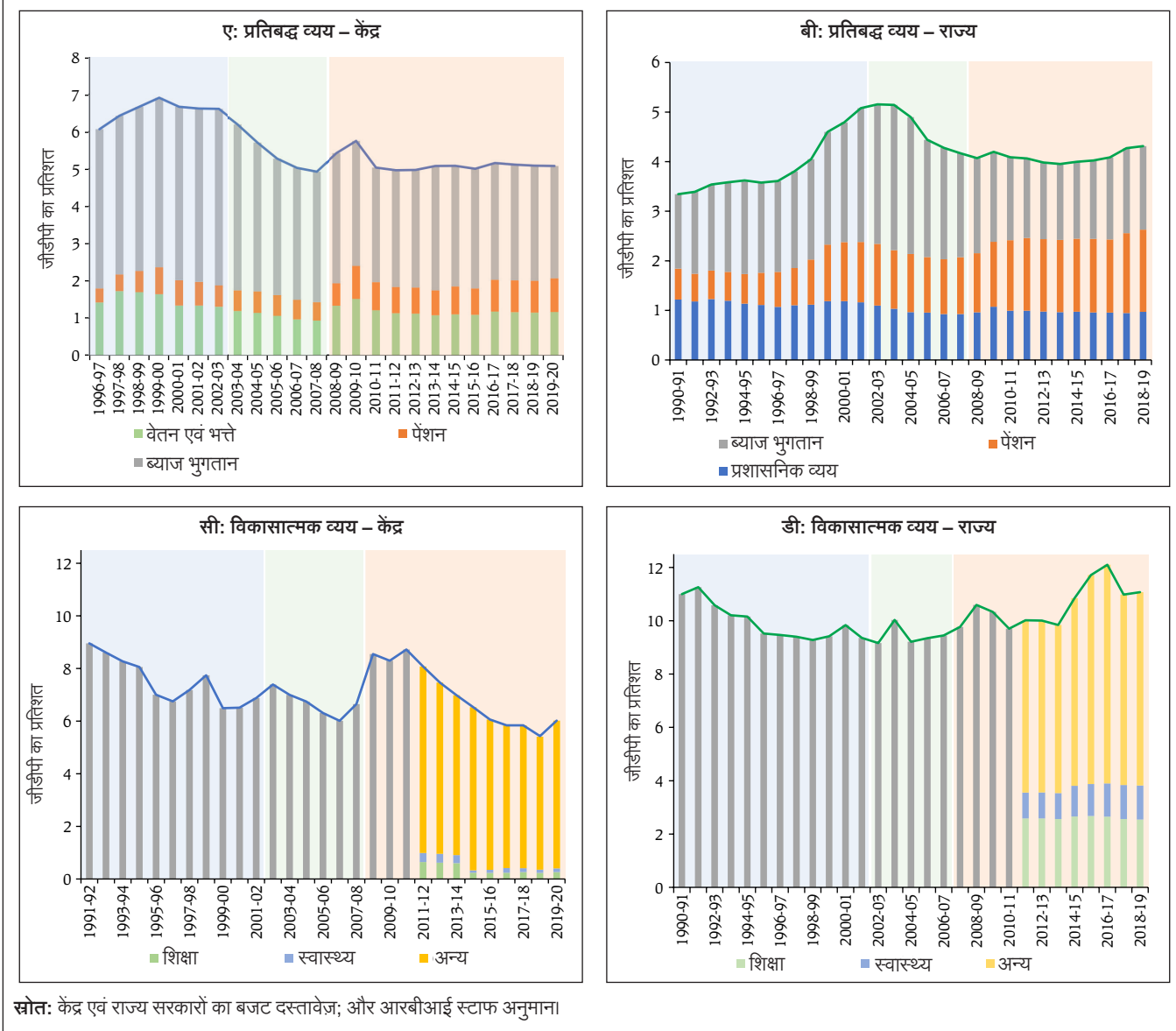
वित्त पोषण पैटर्न और व्यय की संरचना के संबंध में, व्यय के लिए उधार जो आवर्तक प्रकृति के होते हैं, और जिन्हें हर साल खर्च करने की आवश्यकता होती है, वांछनीय नहीं हो सकते हैं और राजस्व के माध्यम से वित्त पोषित किया जाना चाहिए- राजकोषीय नीति में अंतर्निहित इस विचार को कथित तौर पर 'सुनहरा नियम' होता है (जेनेलोग्लू, 2018)। कई यूरोपीय देशों ने भी औपचारिक रूप से इस सुनहरे नियम को अपने वित्तीय फ्रेमवर्क<sup>7</sup> में एकीकृत किया है। यह बजट घाटे और सार्वजनिक डेबिट (की स्थिरता की स्थिति से भी जुड़ा हुआ है (डोमर, 1944)<sup>8</sup>।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि ऊपर देखे गए व्यय की गुणवत्ता के संकेतकों में गिरावट के साथ, केंद्र और राज्यों दोनों के लिए वित्त पोषण में बाजार उधार के अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है (चार्ट 7ए और बी)। इसलिए, आगे जाकर, बाजार आधारित

<sup>7</sup> गोल्डन रूल (राजकोषीय नीति) - विकिपीडिया ; द गोल्डेन रूल ऑफ पब्लिक डेट | लार्स पी. स्यल्ल (wordpress.com); भारत सरकार, 2017 (एफआरबीएम समीक्षा समिति की रिपोर्ट)।

<sup>8</sup> डोमर के अनुसार, ऋण-वित्तपोषित घाटा स्थायी है यदि ऋण की गुणवत्ता अच्छी है, अर्थात्, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर ऋण पर भुगतान की गई ब्याज दर से अधिक है।

**चार्ट 6: केंद्र और राज्यों के प्रतिबद्ध एवं विकासात्मक व्यय**



ब्याज दरों पर उधार लिए गए संसाधन, सुनहरे नियम के अंतर्निहित सिद्धांत के खिलाफ, शून्य या कम प्रतिफल के साथ राजस्व व्यय के वित्तपोषण की ओर बढ़ गए हैं।

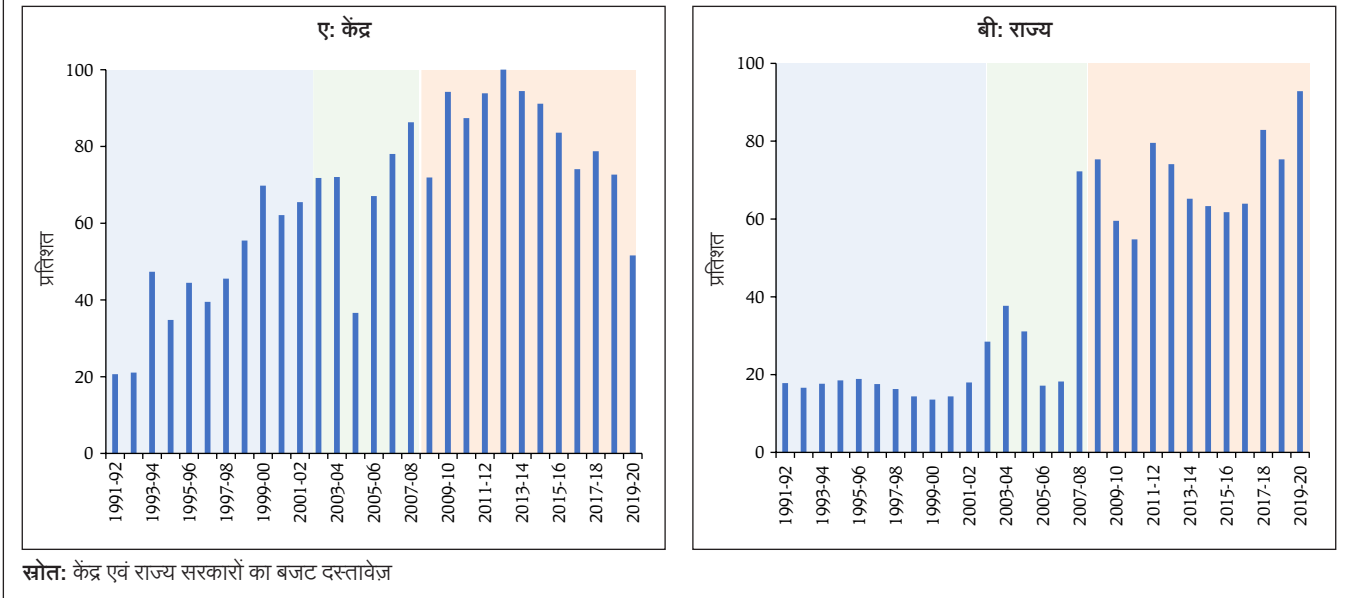
**ई. सरकारी व्यय की गुणवत्ता का सूचकांक**

ऊपर जांचे गए छह संकेतकों, अर्थात्, पूंजीगत परिव्यय अनुपात की तुलना में राजस्व व्यय; सकल राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटा; कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत परिव्यय; जीडीपी की तुलना में पूंजी परिव्यय; जीडीपी की

तुलना में विकास व्यय; और जीडीपी की तुलना में प्रतिबद्ध व्यय, का उपयोग करके केंद्र और राज्यों के लिए अलग-अलग प्रमुख घटक विश्लेषण (पीसीए) को नियोजित करते हुए व्यय की गुणवत्ता का एक समग्र संकेतक विकसित किया गया है<sup>9</sup>। सूचकांकों से पता चलता है कि एफआरबीएम के बाद के उच्च वृद्धि वर्षों के दौरान कुछ सुधारों के साथ केंद्र के खर्च की गुणवत्ता में गिरावट आई है। राज्यों के मामले में, 1990 के दशक में खर्च

<sup>9</sup> सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त पीसीए और भारों का संक्षिप्त विवरण अनुबंध III में दिया गया है।

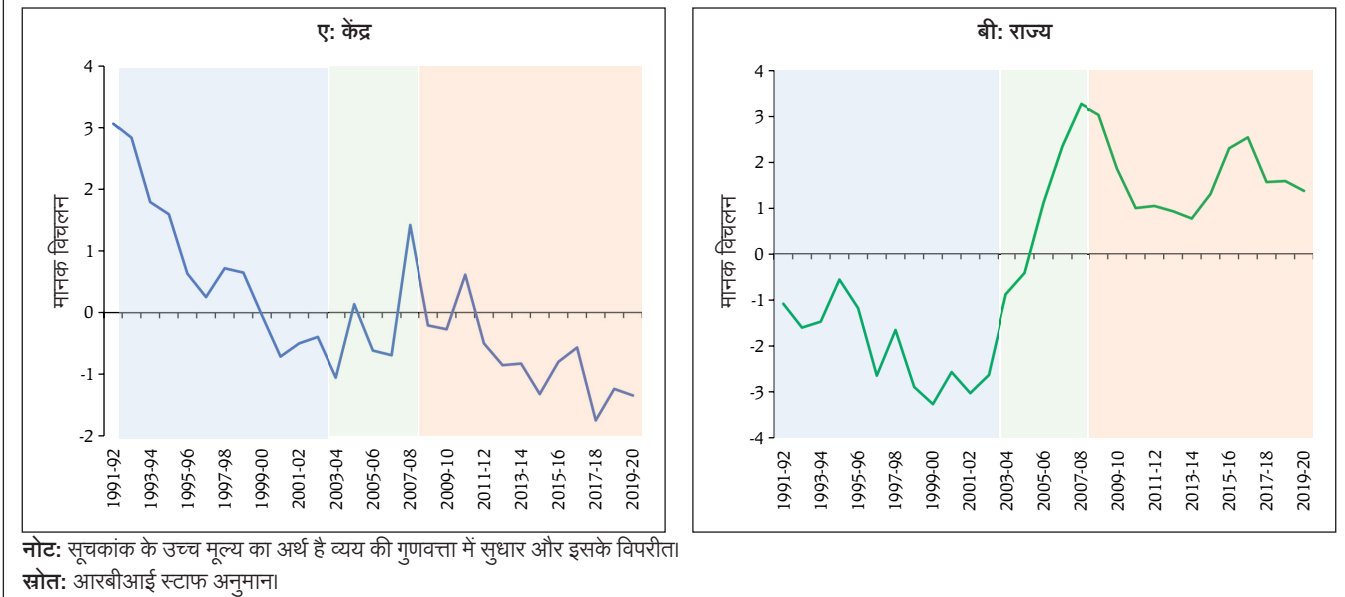
**चार्ट 7: सकल राजकोषीय घाटे में बाजार उधारी की हिस्सेदार**



की गुणवत्ता में गिरावट को न केवल रोका किया गया था, बल्कि जीएफसी से पहले उच्च वृद्धि अवधि के दौरान भी काफी सुधार हुआ था। वर्ष 2009-10 में सुधार रुक गया और जीएफसी के बाद की अवधि में सामान्य गिरावट आई है, हालांकि 1990 के दशक जैसा नहीं है (चार्ट 8)।

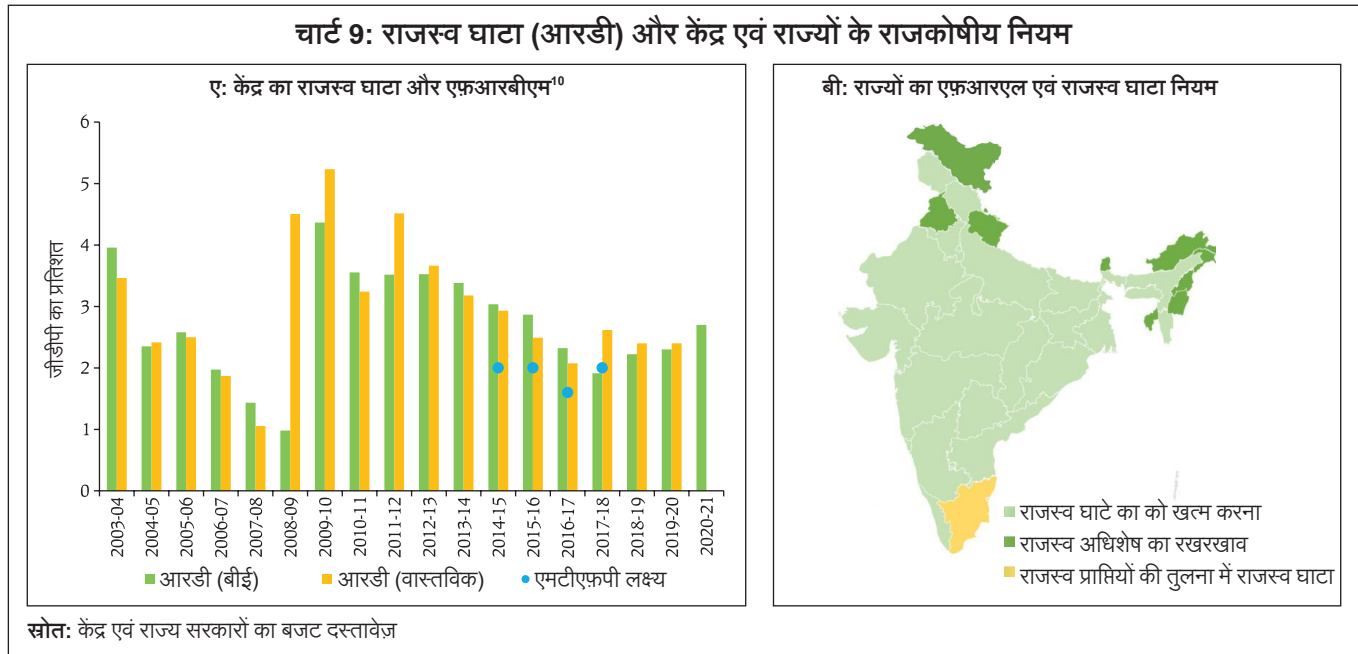
यह उल्लेखनीय है कि जब राजकोषीय नियमों की परिकल्पना की गई थी, तो उनमें व्यय की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने वाली विशेषताएं शामिल थीं - उदाहरण के लिए, एफआरबीएम अधिनियम, 2003 ने शून्य राजस्व घाटे के नुस्खे के रूप में गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया गया था। हालांकि, यह नोट किया गया है कि जीएफडी-जीडीपी लक्ष्यों की व्यापक खोज में

**चार्ट 8: सरकारी व्यय की गुणवत्ता के सूचकांक का उतार-चढ़ाव**





**चार्ट 9: राजस्व घाटा (आरडी) और केंद्र एवं राज्यों के राजकोषीय नियम**



जीएफसी के बाद की अवधि में गुणवत्ता पर जोर दिया गया था, जिसमें अभिसरण के साथ 3 प्रतिशत संख्यात्मक मानदंड को अक्सर एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य के रूप में उद्धृत किया जाता है (भारत सरकार, 2017) (चार्ट 9)<sup>11</sup>। केंद्र की तरह, राज्यों के एफआरएल राजस्व घाटे को खत्म करने, राजस्व अधिशेष (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नगालैंड, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा

और उत्तराखंड) के रखरखाव या राजस्व घाटे को राजस्व प्राप्तियों (तमिलनाडु) से जोड़कर गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया गया था जिसे जीएफसी के बाद की अवधि को छोड़कर मोटे तौर पर हासिल कर लिया गया था।

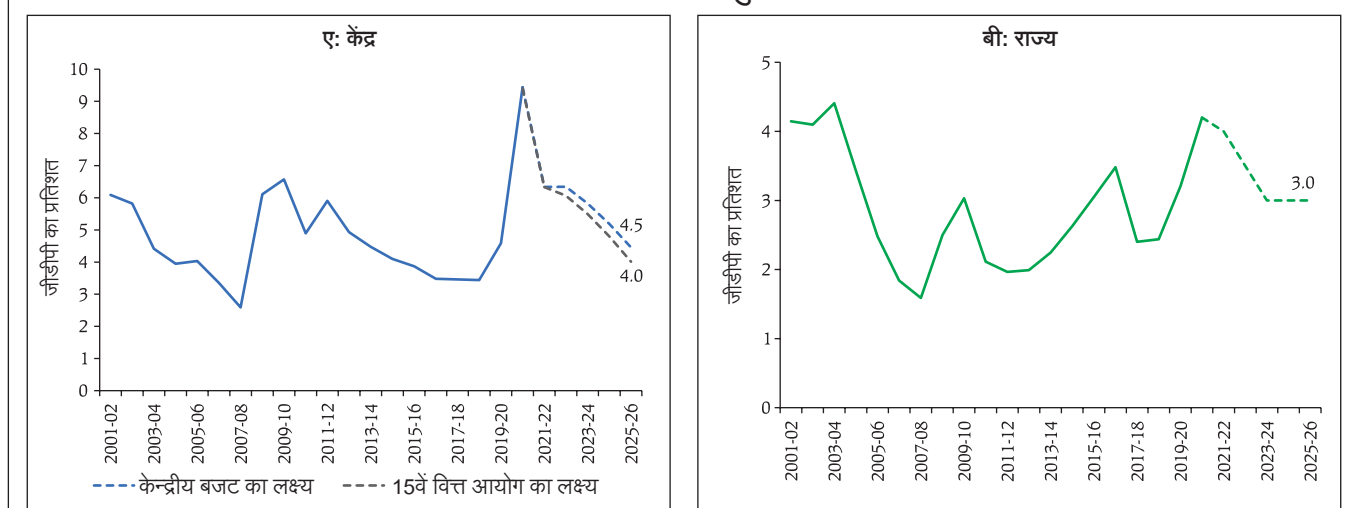
#### IV. आगे की राह

राजकोषीय नीति का हालिया रुख महामारी के विरुद्ध है, जिसमें 2020-21 में सामान्य सरकार का सकल राजकोषीय घाटा जीडीपी का करीब 13 प्रतिशत है और 2021-22 के लिए 10 प्रतिशत अनुमानित है। आगे चलकर, महामारी के दौर से वापसी के लिए एक क्रमिक मार्ग की परिकल्पना की गयी है (चार्ट 10)। अंतर्निहित आर्थिक गतिविधि में सुधार की शर्त पर ही राजकोषीय रुख का एक सफल सामान्यीकरण हो सकता है। वृहत स्तर पर महामारी उपरांत पुनर्निर्माण की अनिवार्यता यह चेतावनी देती है कि राजकोषीय सुधार व्यय की गुणवत्ता की कीमत पर हासिल नहीं किया जाना चाहिए। केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा पूंजीगत व्यय और इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर राजकोषीय नीति के रुख का जोर, व्यय की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार की निश्चित मंशा को दर्शाता है। तदनुसार, ठोस उपायों और लक्ष्यों के साथ एक मध्यम-अवधि के राजकोषीय फ्रेमवर्क को निर्धारित करना महत्वपूर्ण हो सकता है (आईएमएफ, 2021)। एक मात्रात्मक मैट्रिक्स के माध्यम से व्यय की गुणवत्ता को बढ़ाने से आवश्यक जांच और संतुलन प्रदान करने में मदद मिलेगी और इसे

<sup>10</sup> जीएफसी के बाद की अवधि में एफआरबीएम लक्ष्यों से निरंतर विचलन था। वर्ष 2012-13 के बजट भाषण में एफआरबीएम अधिनियम को फिर से लागू किया गया था और संख्यात्मक लक्ष्यों की समय सीमा 2015 तक बढ़ा दी गई थी और एक नया वित्तीय संकेतक, अर्थात् 'प्रभावी राजस्व घाटा' (पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान को छोड़कर राजस्व घाटा) पेश किया गया था। राजस्व घाटे का लक्ष्य बढ़ाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया और यह अनिवार्य किया गया कि प्रभावी राजस्व घाटा वर्ष 2014-15 तक समाप्त हो जाएगा। फरवरी 2015 के बजट भाषण में, सार्वजनिक व्यय हेतु वित्तीय गुंजाइश बनाने के लिए इन समय-सीमा को वर्ष 2015 से बढ़ा कर वर्ष 2018 कर दिया गया था। इसके अलावा, वित्त अधिनियम 2018 ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राजस्व घाटे के लक्ष्य को समाप्त कर दिया कि सभी राजस्व व्यय व्यर्थ खर्च नहीं हैं और आस्तियों के रखरखाव पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

<sup>11</sup> व्यय की गुणवत्ता के साथ-साथ, मौजूदा वित्तीय नियमों में व्यय प्रबंधन के महत्व को मान्यता देने के उदाहरण हैं। एक मध्यम अवधि व्यय ढांचा (एमटीईएफ), वार्षिक आधार पर, व्यय प्रबंधन की सुविधा के लिए व्यय संकेतकों के लिए तीन साल के रोलिंग लक्ष्य को पहली बार केंद्रीय बजट भाषण 2012-13 में पेश किया गया था (जिसमें जीएफसी के बाद एफआरबीएम को फिर से चालू करने की मांग की गई थी)। पहला एमटीईएफ अगस्त 2013 में प्रकाशित हुआ था और बाद में 2018 तक प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में (2014 को छोड़कर, जो एक चुनावी वर्ष था और इसलिए इसे दिसंबर में प्रकाशित किया गया था) प्रकाशित किया गया। एफआरबीएम समीक्षा समिति ने अन्य तीन दस्तावेज - मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति वक्तव्य; राजकोषीय नीति संबंधी कार्यनीति वक्तव्य; और मैक्रोइकॉनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट के साथ-साथ एमटीईएफ के प्रकाशन का भी समर्थन किया था।

चार्ट 10: जीएफ़डी-जीडीपी अनुपात : संभावित पथ



**टिप्पणी:** चार्ट ए 2021-22 बीई के पंद्रहवें वित्त आयोग की वृद्धि और कर उछाल धारणाओं पर आधारित है। चार्ट बी में, राज्य, संभावित पथ पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुसार, केन्द्रीय बजट 2021-22 द्वारा स्वीकृत।

**स्रोत:** केन्द्रीय बजट; पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट; आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

राजकोषीय फ्रेमवर्क में एकीकृत किया जाना चाहिए (दास, 2021)। सीधे-सीधे व्यय में कटौती के बजाय, एक सुविचारित रणनीति के तहत बनाई गयी नीतियों के मिश्रण को उच्च सीमांत सामाजिक लाभ वाले कार्यक्रमों की रक्षा करनी चाहिए, इस प्रकार यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गुणवत्ता में सुधार का इरादा वांछनीय परिणामों में फलित हो।

कहना आसान है करना मुश्किल! ऐसे मैट्रिक्स का डिजाइन क्या होना चाहिए? हालांकि सख्त गुणवत्ता मानदंड निर्धारित करना मुश्किल हो सकता है जो हर समय सरकार के सभी स्तरों पर लागू होते हैं, संकेतकों की एक सरणी अस्थायी बेंचमार्क के रूप में काम कर सकती है। सबसे पहले, एक सांकेतिक बेंचमार्क केंद्र के लिए एफ़आरबीएम समीक्षा समिति (भारत सरकार 2017) द्वारा निर्धारित स्तरों के प्रति आरडी-जीएफ़डी अनुपात में कमी हो सकती है, वर्तमान के उच्च स्तरों से, इस आधार पर कि उधार ली गई धनराशि का एक बड़ा हिस्सा पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण की दिशा में जाना चाहिए। दूसरा, पूंजी परिव्यय (आरईसीओ) की तुलना में राजस्व व्यय को 4 से 5 की सीमा में रखने का प्रयास किया जा सकता है जो कि सबसे अधिक विकास अनुकूल है<sup>12</sup>

<sup>12</sup> महामारी के पहले भारत के विकास की कथा दर्शाती है कि कोविड-19 के पहले 6-7 तिमाहियों में कुल मांग को बढ़ाने के लिए सरकारी सहायता ने अत्यधिक राजस्व व्यय के जरिये रिकवरी को बनाए रखने या मध्यम अवधि में युवा जोश को तरोताजा करने के लिए राजस्व के निम्न और अल्पकालिक गुणकों को देखते हुए पर्याप्त अधिशेष नहीं दिया (गोस्वामी, 2021)।

इन सीमाओं से संबंधित अनुभवजन्य साक्ष्य भी सामान्य सरकारी स्तर पर आरडी-जीएफ़डी और आरईसीओ इन दो संकेतकों की सीमाओं का समर्थन करते हैं (बॉक्स I)।

तीसरी सीमा पूंजी परिव्यय-जीडीपी अनुपात की सतह से या पूंजी परिव्यय में वृद्धि की एक विशेष दर को लक्षित करने के माध्यम से हो सकती है ताकि कुल व्यय में इसके हिस्से में कमी को रोका जा सके। सैद्धांतिक और अनुभवजन्य साहित्य के एक बड़े निकाय ने सार्वजनिक पूंजी व्यय और सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों में निवेश के माध्यम से संचालित विकास के बीच एक सकारात्मक संबंध पाया है। भारत में पूंजीगत व्यय गुणक को 2 से अधिक माना जाता है (आरबीआई, 2019; जैन और कुमार, 2013)। जीडीपी के अनुपात में पूंजी परिव्यय की सतह सरल, पारदर्शी और अच्छी तरह समझने योग्य होनी चाहिए<sup>13,14</sup>

इस तरह मैट्रिक्स के माध्यम से व्यय की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए 2025-26 तक घोषित 4.5 प्रतिशत के

<sup>13</sup> कुछ नीति निर्माताओं के साथ बातचीत से मिले वास्तविक साक्ष्य के अनुसार, रचनात्मक लेखांकन की गुंजाइश कम है अगर नियम पूंजीगत व्यय और जीडीपी के अनुपात में है क्योंकि पूंजीगत व्यय और जीडीपी दोनों की परिभाषा निर्विवाद है।

<sup>14</sup> राज्यों द्वारा वृद्धिशील उधारी के कुछ भाग जीएसडीपी के 3 प्रतिशत से ऊपर को पूंजीगत व्यय से जोड़ने के लिए एक छोटा सा कदम रहा है, हालांकि मध्यम अवधि के लिए एक स्पष्ट रणनीति की सरकार के सभी स्तरों पर जरूरत है।

**बॉक्स 1: व्यय की गुणवत्ता- भारत में सामान्य सरकार के लिए आकलन की अधिकतम सीमा**

राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच उचित मिश्रण क्या है जिससे अधिकतम वृद्धि प्राप्त हो सकती है?<sup>15</sup> सामान्य सरकारों के व्यय गुणवत्ता के संकेतकों और आर्थिक विकास के बीच एक कड़ी खोजने का प्रयास किया जाता है। पूंजीगत व्यय के लिए राजस्व व्यय का अनुपात अल्पकालिक और दीर्घकालिक के बीच एक दुविधा का संकेत देता है। विकास पर राजस्व व्यय का प्रभाव लगभग एक वर्ष तक रहता है, जबकि पूंजीगत व्यय का प्रभाव अधिक गहरा और लंबे समय तक रहता है, सबसे अधिक प्रभाव तो दो-तीन वर्षों बाद होता है।

वास्तविक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (पीसीजीडीपीजी) में पंच वर्षीय अग्रसर औसत वृद्धि और भारत में सामान्य सरकार (केंद्र और राज्यों)<sup>16</sup> के लिए पूंजीगत परिव्यय के लिए राजस्व व्यय के अनुपात (आरईसीओ) के बीच संबंध की एक परीक्षा आरईसीओ अनुपात (4.0 प्रतिशत से 5.5 प्रतिशत) के लिए उपयुक्त नियंत्रण<sup>17</sup> और विभिन्न सीमा

स्तरों के साथ ओएलएस प्रतिगमन फ्रेमवर्क दर्शाता है, कि सकारात्मक और महत्वपूर्ण प्रभाव विशेष रूप से 4.0 से 5.0 की सीमा पर दिखाई देता है जिसके बाद यह महत्व खो देता है। गुणवत्ता के एक अन्य महत्वपूर्ण संकेतक को आरईसीओ की जगह लाने से, जैसा कि पिछले खंड में देखा गया है, राजस्व घाटे का सकल राजकोषीय घाटे से अनुपात (आरडी-जीएफडी)<sup>18</sup> अन्य सभी विशिष्टताओं के समान होने के साथ, 30 से 40 के बीच की सीमा सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है (सारणी 1)

संक्षेप में, सभी स्तरों पर सरकारों को रचनात्मक व्यय स्विचिंग और पुनर्प्राथमिकता रणनीतियों में संलग्न होने की आवश्यकता है जो विकास की गुणवत्ता पर राजकोषीय नीति के प्रभाव को बढ़ाने के लिए वर्तमान से पूंजीगत व्यय पर जोर देते हैं। उधार का उपयोग मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय के लिए किया जाना चाहिए।

**सारणी 1: सामान्य न्यूनतम-वर्ग परिणाम**  
निर्भर चर: पंच-वर्षीय अग्रसर औसत वास्तविक प्रति-व्यक्ति जीडीपी वृद्धि

चर	समीकरण 1	समीकरण 2	समीकरण 3	समीकरण 4	समीकरण 5	समीकरण 6	समीकरण 7	समीकरण 8	समीकरण 9	समीकरण 10	समीकरण 11
पीसीजीडीपीजी (-1)	0.58***	0.57***	0.53***	0.56***	0.62***	0.46***	0.54***	0.57***	0.59***	0.58***	0.58***
टीआरडीजीडीपी	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00
आरईसीओ	0.10*										
आरईसीओ (>4.0)		0.08*									
आरईसीओ (>4.5)			0.07**								
आरईसीओ (>5.0)				0.05							
आरईसीओ (>5.5)					0.03						
आरडी-जीएफडी							0.01***				
आरडी-जीएफडी (>30.0)								0.01**			
आरडी-जीएफडी (>40.0)									0.01**		
आरडी-जीएफडी (>50.0)										0.01	
एलआर	0.06**	0.06**	0.06**	0.05**	0.05**	0.06**	0.06**	0.05**	0.05**	0.06**	0.04*
टीईजीडीपी	-0.01	-0.02	0.04	-0.02	-0.01	0.04	-0.05	-0.03	-0.01	-0.04	-0.04
अपरिवर्तनीय	-1.33	-0.81	-0.30	-0.40	-0.73	-1.19	0.08	-0.27	-0.78	-0.07	0.46
समायोजित आर <sup>2</sup>	0.82	0.82	0.84	0.84	0.81	0.85	0.84	0.83	0.83	0.82	0.80
क्रमिक सहसंबंध के लिए एलएम टेस्ट	0.83	0.82	0.68	0.69	0.83	0.88	0.81	0.66	0.40	0.74	0.26
विषमविसारिता टेस्ट: ब्रुश-पगन-गॉडफ्रे	0.93	0.94	0.89	0.71	0.90	0.99	0.89	0.95	0.99	0.91	0.70

**स्रोत:** आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

पीसीजीडीपीजी: वास्तविक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में पंच-वर्षीय आगे की ओर अग्रसर औसत वृद्धि; टीआरडीजीडीपी: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निर्यात और आयात द्वारा मापा गया अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आकार; आरईसीओ: गुणवत्ता व्यय के प्रतिनिधि के रूप में पूंजीगत परिव्यय के लिए राजस्व व्यय का अनुपात; एलआर: वयस्क साक्षरता दर; और टीईजीडीपी: सरकार के व्यय के आकार प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए जीडीपी के कुल व्यय अनुपात।

ध्यान दें: (1) हालांकि चर गैर-स्थिर हैं, उनका अवशिष्ट स्थिर है जो संयोग संबंध को दर्शाता है और इस प्रकार, ओएलएस चलाया जा सकता है। (2) आरईसीओ में सीमा की पहचान करने के लिए, हमने 4 संवादात्मक प्रतिरूपी चर का उपयोग किया है जहाँ '>' का अर्थ सीमा से अधिक मान है, अन्यथा शून्य (3) \*\*\*, \*\* और \* क्रमशः 1,5 और 10 प्रतिशत के स्तर पर महत्व दर्शाते हैं।

<sup>15</sup> इष्टतम मिश्रण महत्वपूर्ण है। कारण यह है कि पूंजीगत व्यय की वृद्धि-अनुकूल प्रकृति साहित्य से प्राप्त ज्ञान की स्थापना है, जबकि राजस्व व्यय भी अल्पकालिक-मांग प्रबंधन में एक उपयोगी भूमिका निभाता है। इसके अलावा, अक्सर राजस्व व्यय और आवर्ती प्रकृति की कई सामाजिक सेवाएं मानव पूंजी को बढ़ाने या/और कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करती हैं जो एक स्वस्थ निवेश वातावरण (डायमंड, 1989) के लिए आवश्यक शर्तें हैं।

<sup>16</sup> भारत के लिए सामान्य सरकारी पूंजी परिव्यय की अनुपस्थिति में, कर पश्चात राशि को कम मान कर केंद्र और राज्यों के पूंजी परिव्यय के साधारण योग को एक प्रतिनिधि के रूप में लिया जाता है।

<sup>17</sup> उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण चर आयात और निर्यात को मिलाकर जीडीपी के प्रतिशत के संदर्भ में भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आकार के हैं (टीआरडीजीडीपी), वयस्क साक्षरता दर (एलआर) और सकल घरेलू उत्पाद अनुपात (टीईजीडीपी) के आकार के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में कुल व्यय हैं।

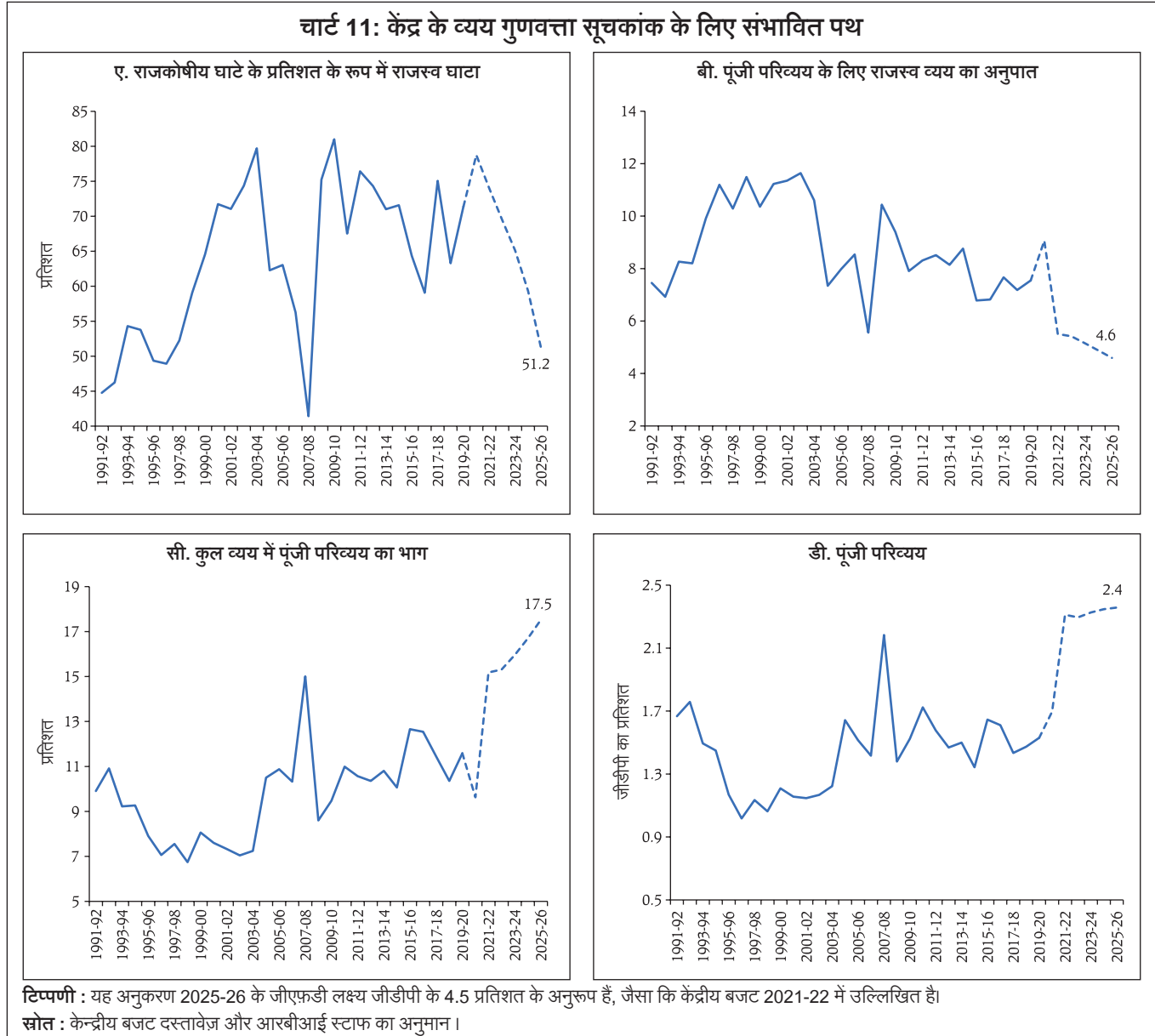
<sup>18</sup> यह संकेतक दर्शाता है कि कितना उधार लिया गया धन राजस्व खाते और पूंजी खाते की ओर जा रहा है। चूंकि लंबी अवधि की परिसंपत्तियों में निवेश उच्च प्रतिफल देता है जिसका उपयोग उधार ली गई धनराशि को चुकाने के लिए किया जा सकता है, इस अनुपात का ऋण स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण निहितार्थ है।

जीएफडी-जीडीपी लक्ष्य का अनुकरण सार्वजनिक व्यय की संरचना में सुधार करने की इच्छा पर निर्भर करेगा (चार्ट 11)। कोविड महामारी के पश्चात इन गुणवत्ता संबंधी विचारों को संस्थागत रूप देना सतत विकास के लिए सबसे अच्छी टीका बन सकता है<sup>19</sup>।

**कर्ज संबंधी विचार**

जीएफडी-जीडीपी लक्ष्य के साथ प्रस्तावित गुणवत्ता संबंधी विचारों का मेल इस भावी राजकोषीय प्रतिमान में राजकोषीय समेकन की नींव को मजबूत करेगा और सार्वजनिक कर्ज के लिए मात्रात्मक लक्ष्य भी प्राप्त कर सकता है।

**चार्ट 11: केंद्र के व्यय गुणवत्ता सूचकांक के लिए संभावित पथ**



<sup>19</sup> भारतीय राज्यों की विभिन्न विकास आवश्यकताओं और स्थिति के साथ विषम प्रकृति को देखते हुए, इस तरह के अनुकरण का प्रयास नहीं किया गया है। और इस पत्र के दायरे से बाहर है। हालांकि, व्यय की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए इस तरह के मैट्रिक्स का संचालन सार्वभौमिक है और सरकार के सभी स्तरों पर व्यवहार्य रहता है।

आज, जीडीपी के 90 प्रतिशत से भी अधिक भारत का सामान्य सरकारी ऋण ऐतिहासिक शिखर पर है। जबकि यह विश्वभर में कोविड-पश्चात जो कर्ज में वृद्धि हुई है उसके अनुरूप है, एक स्पष्ट रूप से संप्रेषित आसान पथ राजकोषीय फ्रेमवर्क की विश्वसनीयता बहाल करने में मदद करेगा। अतिरिक्त ऋण से प्रतिलाभ प्राप्त हो सकता है ताकि विकास को मजबूत करके भविष्य के ऋण को कम किया जा सके और ऋण गतिकी की स्टॉक (आर-जी) और प्रवाह (जीडीपी के लिए कम प्राथमिक घाटा) की बाधाओं को कमजोर कर सके<sup>20</sup>।

### व्यापार चक्र और मेयता विवेचन

जहां 'बचाव' और 'मोचन' उपबंध संशोधित एफ़आरबीएम के अभिन्न तत्व हैं जो वांछित और सिद्ध लचीलापन प्रदान कर सकते हैं जो राजकोषीय नीति को प्रति-चक्रीय बना सकते हैं<sup>21</sup>, वहीं मात्रात्मकता की जगह गुणवत्ता केंद्रित व्यय कार्यक्रम के साथ भारत की राजकोषीय नीति को संवृद्धि अनुकूल बनाने और हेडलाइन जीएफ़डी नियम के साथ व्यय की गुणवत्ता पर ध्यान देने से राजकोषीय नीति में प्रतिचक्रीयता के पक्ष में जो तत्व हैं उसमें और कमी आने की संभावना है<sup>22</sup>।

जैसा कि इस साल के केंद्रीय बजट से शुरुआत की गयी है, सभी ऑफ-बजट देनदारियों समेत जीएफ़डी का व्यापक मापन, अनुपालन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बनाए रखा जाना चाहिए, जिससे किसी भी राजकोषीय नियम को दरकिनार करने की कोई गुंजाइश नहीं रहे। स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियों की स्थापना लक्ष्यों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए और ऐसे राजकोषीय फ्रेमवर्क से जुड़ी संचार चुनौतियों को कम करते हुए समायोजन

<sup>20</sup> ऋण को धारणीय माना जाता है यदि (ए) वास्तविक जीडीपी वृद्धि (जी) ऋण के स्टॉक पर ब्याज लागत से अधिक है। (आर) और (बी) प्राथमिक अधिशेष है या घटता/छोटा प्राथमिक घाटा है (उच्च वृद्धि की वजह से उच्च राजस्व होने के कारण)।

<sup>21</sup> इसके अलावा, उछाल के वर्षों के दौरान मोचन अनुबंध के माध्यम से बफर बनाना गिरावट के दौरान प्रोत्साहन देने के काम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

<sup>22</sup> उल्लेखनीय है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 ने पहली बार बताया कि भारत की राजकोषीय नीति में चक्रीयता के संकेत हैं जिसमें यदि संभव हो तो, राजकोषीय नियमों में बदलाव के माध्यम से भी उलटाव की जरूरत है। चिली का उदाहरण एक बॉक्स आइटम में उद्धृत किया गया है जो संरचनात्मक राजकोषीय नियम का उपयोग करता है। तदुसार, आंतरिक मूल्यांकनों को चक्र-समायोजित अवधारणाओं के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए अन्य वृहत-मानदंडों पर इसके प्रभाव के संदर्भ में राजकोषीय स्थिति की बेहतर समझ के लिए, भले ही राजकोषीय नियम समग्र राजकोषीय संतुलन के संदर्भ में जारी रह सकता है।

की गुणवत्ता में सुधार करके राजकोषीय परिणामों में सुधार करने में मदद कर सकती है। (आयरोड और अन्य, 2018; आईएमएफ़, 2017)

### V. समापन टिप्पणियां

यहां तक कि जब कोविड-19 ने दुनिया को अपनी घातक चपेट में ले लिया, मृत्यु और विनाश का निशान छोड़ दिया, तब भी महामारी के समय और बाद के जीवन में राजकोषीय नीति की भूमिका में एक नए सिरे से रुचि पैदा हुई है। तेजी से, कथा प्रोत्साहन और समेकन की संकीर्ण सीमाओं से एक स्थायी विकास-अनुकूल राजकोषीय नीति के लिए बाहर आ रही है। राजस्व और व्यय दोनों के रणनीतिक उद्देश्य और प्राथमिकता को फिर से स्थापित करने से, राजकोषीय अधिकारियों ने दिखाया कि वे 'धन की पूरी कीमत' निकाल सकते हैं (ए) सार्वजनिक क्षेत्र विकास के अवसरों को बढ़ाने में निजी क्षेत्र से अग्रणी; (बी) सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमशीलता भागीदारी में निजी क्षेत्र के साथ; और (सी) सार्वजनिक क्षेत्र पीछे हटते हुए निजी उद्यमों को उभरते क्षेत्रों में नेतृत्व करने की अनुमति देता है, जो कि राजकोषीय खर्च की गुणवत्ता में और अंततः विकास की गुणवत्ता के समग्र सुधार में शामिल होता है। केन्द्रीय बजट 2021-22 व्यय की संरचना को बदलकर इन्फ्रास्ट्रक्चर के पक्ष में करने की दिशा में कदम उठाता है, जो कि भारत के विश्व स्तरीय भौतिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता के नज़रिये से सही है। इस लेख का प्रयास सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता को मात्रात्मक रूप में मापने का प्रस्ताव लाकर इस प्रतिमान बदलाव का पता लगाना है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल में निवेश करके सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का भी उन्नयन शामिल है। मौन क्रांति तब पूर्ण होगी, जब राजकोषीय नीति के संचालन में मात्रा से अधिक गुणवत्ता पर ज़ोर देने की प्रवृत्ति को जीवन के एक तरीके के रूप में संस्थागत किया जाएगा। संक्षेप में, यह लेख आरडी-जीएफ़डी और आरईसीओ सीलिंग को औपचारिक रूप से शामिल करने का मामला बनाता है। व्यय की संरचना के संबंध में, सामान्य सरकार (केंद्र और राज्य दोनों) के लिए आरईसीओ का अनुपात 5 से अधिक और आरडी-जीएफ़डी का अनुपात 40 प्रतिशत से अधिक नहीं है, जो स्थायी विकास प्रक्षेपवक्र के लिए उपयुक्त पाया गया है। अच्छे व्यय नियमों के मानक 'सरलता' और 'सुगमता'

को पूरा करने के अलावा, राजकोषीय समेकन पथों में गुणवत्ता लक्ष्यों के औपचारिक गठन के परिणामस्वरूप राजकोषीय नीति को मानवीय चेहरे के साथ स्थापित किया जाएगा, और यहां तक कि सार्वजनिक वस्तुओं की गुणवत्ता के प्रावधान का एक स्थिर स्तर को सुनिश्चित करके राजकोषीय नीति की प्रति-चक्रीयता पूर्वाग्रह को भी संतुलित कर सकता है। प्रोत्साहन की अवधि के बाद अनिवार्य रूप से राजकोषीय सुधार के लिए अभियान में पहले से कहीं अधिक मान्यता है, सार्वजनिक व्यय में विकास को बढ़ाने वाले जो तत्व हैं उनको संरक्षित रखना तथा विकसित करना है। जबकी कोविड-19 ने शेष विश्व की तरह भारत में भी राजकोषीय नीति फ्रेमवर्क में लचीलेपन की सीमाओं का परीक्षण किया है, इसने राजकोषीय नीति को इस तरह से फिर से परिभाषित करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया है जो 'कितना' नहीं बल्कि 'कैसे' पर ज़ोर देती है।

### संदर्भ

- Afonso, A.; Schuknecht, L. and Tanzi, V. (2005). Public Sector Efficiency: An International Comparison. *Public Choice*, 123(3), 321-347.
- Alesina, A.F. (2010). Fiscal Adjustments: Lessons from Recent History. *Ecofin Meeting Madrid*, April.
- Alesina, A.F. and Ardanga, S. (2012). The Design of Fiscal Adjustments. Working Paper No. 18423. National Bureau of Economic Research, September.
- Alesina, A.F. and Perotti, R. (1995). Fiscal Expansions and Fiscal Adjustments in OECD Countries. Working Paper No. 5214. National Bureau of Economic Research, August.
- Barro, R.J. (1990). Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth. *Journal of Political Economy* 98(S5): 103-125.
- Bhanumurthy N.R., Bose, S. and Satija, S. (2019). Fiscal Policy, Devolution and Indian Economy. National Institute of Public Finance and Policy Working Paper No. 287, December.
- Blanco, F. and Herrera, S. (2006). The Quality of Fiscal Adjustment and the Long-Run Growth Impact of Fiscal Policy in Brazil. World Bank Policy Research Working Paper 4004, September.
- Bose, S. and Bhanumurthy, N.R. (2013). Fiscal Multipliers for India, National Institute of Public Finance and Policy Working Paper No. 2013-125, September.
- Cabazon, E., Tumbarello, P., and Wu, Y. (2015). Strengthening Fiscal Frameworks and Improving the Spending Mix in Small States. Working Paper WP15/124. International Monetary Fund.
- Cordes, T.; Kinda, T. Muthoor, P. Weber, A. (2015) Expenditure Rules: Effective Tools for Sound Fiscal Policy? Working Paper WP/15/29, International Monetary Fund.
- Das, S (2021), Towards a Stable Financial System. Nani Palkhivala lecture delivered by Governor, RBI, January 21.
- de Rato, R. (2004). Benefits of Fiscal Consolidation. Remarks to the Real Academia de Doctores, Spain. November
- Devarajan, S.; Swaroop, V. and Zou, H. (1996). The Composition of Public Expenditure and Economic Growth. *Journal of Monetary Economics*, Volume 7, Issue 2, April.
- Diamond, J. (1989). Government Expenditure and Economic Growth: An Empirical Investigation. Working Paper WP/89/45. International Monetary Fund.
- Domar, E. D. (1944). The Burden of Debt and the National Income. *American Economic Review*, 34(4): 798-827.
- Erden, L. and Holcombe, R. (2005). The Effects of Public Investment on Private Investment in Developing Economies. *Public Finance Review* vol. 33, issue 5.
- Eyraud, L.; Debrun, X.; Hodge, A.; Lledo, V.; Pattillo, C. (2018). Second-Generation Fiscal Rules: Balancing Simplicity, Flexibility, and Enforceability. IMF Staff Discussion Note, April.
- European Commission (2012). The Quality of Public Expenditures in the EU. Occasional Paper, 125, December.

- Forte, F. and Magazzino, C. (2014). Optimal Size of Governments and the Optimal Ratio between Current and Capital Expenditure. Ch 15 in Handbook of Alternative Theories of Public Economics, Edward Elgar Publishing.
- GoI (2017). Responsible Growth: A Debt and Fiscal Framework for 21<sup>st</sup> century India. FRBM Review Committee Report (Chairman: Shri N.K. Singh), 1, January.
- GoI (2021) Fifteenth Finance Commission Report, Government of India.
- Grigoli, F. (2012). Public Expenditure in the Slovak Republic: Composition and Technical Efficiency. IMF Working Paper WP/12/173.
- Guerguil, M., Mandon, P., and Tapsoba, R. (2017). Flexible fiscal rules and countercyclical fiscal policy. Journal of Macroeconomics, 52, 189-220.
- Gupta, S.; Clements, B.; Baldacci, E. and Mulas-Grandos, C. (2005). Fiscal policy, expenditure composition, and growth in low-income countries. Journal of International Money and Finance. Volume 24, Issue 3, April.
- Hagen, H. V. and Satrauch, R. R. (2001). Fiscal Consolidations: Quality, Economic Conditions, and Success. Public Choice, 109 (3/4), 327-346.
- Heriwibowo D.; Juanda, B.; Hadi, S.; and Supono, S. (2016). The Measurement of Local Government Spending Quality with Indicators of Sustainable Local Development in Indonesia. Journal of Economics and Sustainable Development ISSN 2222-1700 (Paper) ISSN 2222-2855 (Online), Vol.7, No.4.
- IMF (1995); Guidelines for Fiscal Adjustment. Fiscal Affairs Department, International Monetary Fund
- IMF (2012); Fiscal Monitor, International Monetary Fund, October.
- IMF (2013; 2014; 2017, 2020; 2021). Fiscal Monitor, International Monetary Fund, April
- Jacobs, D.F. (2009). Capital Expenditures and the Budget. Public Financial Management Technical Guidance Note. International Monetary Fund.
- Jain, R. and Kumar, P. (2013). Size of Government Expenditure Multipliers in India: A Structural VAR Analysis, RBI Working Paper 07 / 2013, September.
- Lledo, V.; Yoon, S.; Fang, X.; Mbaye, S. and Kim, Y. (2017). Fiscal Rules at a Glance. International Monetary Fund.
- Mackenzie, G.A. and Orsmond, W.H. (1996). The Quality of Fiscal Adjustment and Growth. Finance & Development, Volume 0033, Issue 002, International Monetary Fund, June.
- McDermott, C.J. and Wescott, R.F. (1996). An Empirical Analysis of Fiscal Adjustments. IMF Staff Papers, Vol. 43, No. 4, December.
- Mandon, P. (2014). Evaluating Treatment Effect and Causal Effect of Fiscal Rules on Procyclicality New assessments on old debate: rules vs. discretion. Working Papers 201414, CERDI.
- Manescu, C.B. and Bova, E. (2021). Effectiveness of national expenditure rules: Evidence from EU member states. VOX, CEPR Policy Portal.
- OECD (2020). Government Support and the COVID-19 Pandemic. April
- Okwuokei, J.C. (2014). Fiscal Consolidation: Country Experiences and Lessons from the Empirical Literature. Chapter 5 in Caribbean Renewal: Tackling Fiscal and Debt Challenges / edited by Charles, Amo-Yartey and Therese Turner-Jones. International Monetary Fund.
- Premchand, A. (1989). Government Budgeting and Expenditure Controls Theory and Practice. International Monetary Fund.

Price, R. (2010). *The Political Economy of Fiscal Consolidation*. OECD Economics Department Working Papers, No. 776, OECD Publishing, Paris.

RBI (2016). *State Finances: A Study of Budgets of 2015-16*. Reserve Bank of India, April.

RBI (2019). *Monetary Policy Report*, Reserve Bank of India, April.

Schaechter, A., Kinda, T., Budina, N., and Weber, A. (2012). *Fiscal Rules in Response to the Crisis: Toward the 'Next-Generation' Rules: A New Dataset*. IMF Working Papers, 12/187.

Subbarao D (2012). "Price Stability, Financial Stability and Sovereign Debt Sustainability Policy Challenges from the New Trilemma", speech delivered at second International Research Conference, February.

Zagler, M. and Durnecker, G. (2003). *Fiscal Policy and Economic Growth*. *Journal of Economic Surveys*, Vol. 17, No. 3.

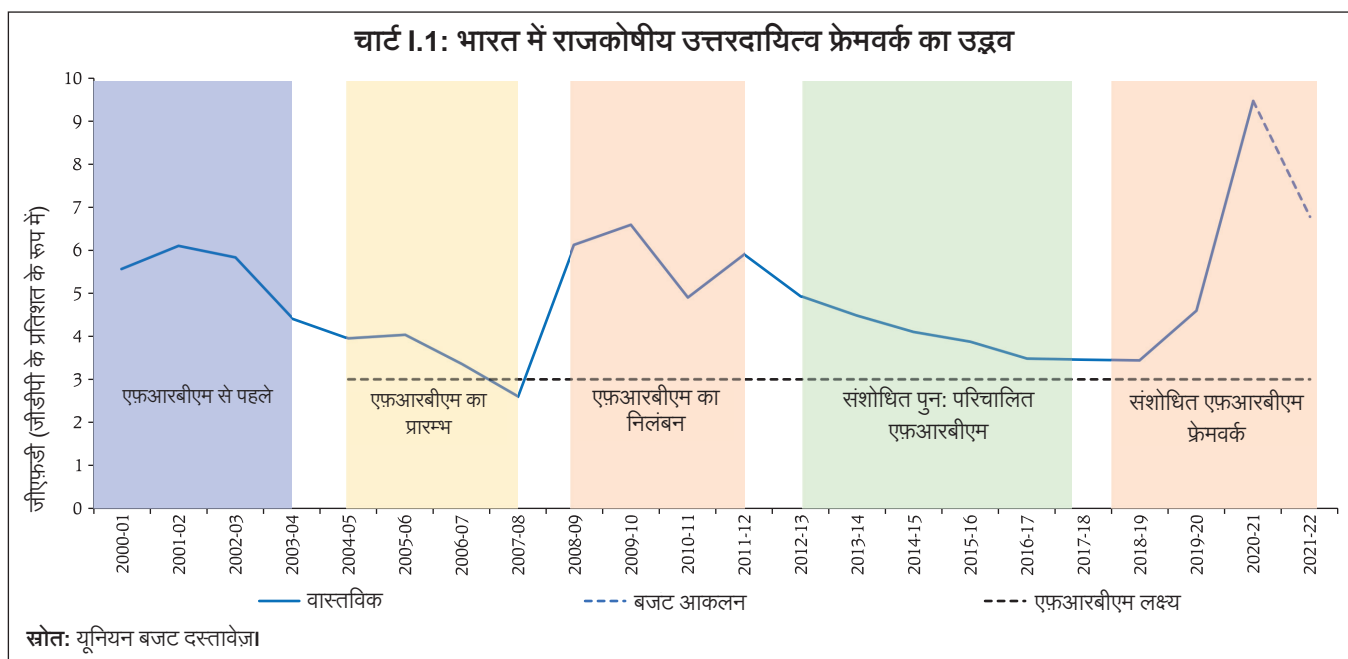
Zeyneloglu, I. (2018). *Fiscal Policy Effectiveness and the Golden Rule of Public Finance*. *Central Bank Review, Research and Monetary Policy Department*, Central Bank of the Republic of Turkey, vol. 18(3)



### अनुबंध I: भारत के राजकोषीय नियम : केंद्र और राज्य

भारत ने 1990 से पहले के अपने बड़े-पैमाने पर घाटे के वित्तपोषण के युग से 2004-05 से राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम के तहत राजकोषीय नियमों के साथ-साथ बाजार आधारित वित्तपोषण के विषय में रूढ़िवादी किया। ज्ञात राजकोषीय जोखिमों को कम करने के लिए, एक संतुलित बजट नियम पेश किया गया था, जिसमें केंद्र सरकार के लिए सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। जबकि एफआरबीएम के तत्काल बाद की अवधि में हासिल किया गया राजकोषीय अनुशासन उल्लेखनीय था, वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के कारण यह प्रक्रिया रुक गई थी, जिसके लिए सरकार की ओर से महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता थी। 2013-14 से एफआरबीएम में बार-बार संशोधन होता रहा। व्यापार चक्रों के लिए उपयुक्त रूप से लेखांकन के बाद, राजकोषीय घाटे को देखते हुए वांछित लचीलापन लाने की आवश्यकता

महसूस की गई (आरबीआई, 2012; भारत सरकार, 2017)। वांछित प्रति-चक्रियता लाने के लिए, केंद्रीय बजट 2018-19 में अपनाए गए संशोधित एफआरबीएम ने अगले संशोधन के एजेंडे में चक्रिय रूप से समायोजित बजट शेष नियम को अपनाने को ध्यान में रखते हुए 'बचाव' और 'मोचन' उपबंध<sup>23</sup> को जोड़ा। इसके अलावा, विकसित हो रही वैश्विक राजकोषीय सोच के अनुरूप, 2018-19 के संशोधन में मध्यम-अवधि के आश्रय के रूप में ऋण की सीमा स्तर को जोड़ा गया था। हालांकि ये प्रगतिशील विकास थे, लेकिन जीएसटी में संक्रमण के कारण राजस्व पर प्रभाव, 2019-20 की चक्रिय मंदी और फिर 2020 में महामारी के प्रभाव के कारण उनके प्रदर्शन को बाद के वर्षों में परिकल्पित नहीं किया जा सका। पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में उठाए गए कदमों ने भी लक्ष्य से जीएफडी अनुपात के विचलन में योगदान दिया, 2020-21 के लिए अनंतिम खातों में केंद्र के लिए लक्ष्य जीडीपी के 9.2 प्रतिशत पर रखा गया (चार्ट I.1)।



<sup>23</sup> राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार या आधारों पर, आपदा, कृषि में एकाएक गिरावट, अप्रत्याशित राजकोषीय प्रभाव के साथ संरचनात्मक सुधार, तिमाही के दौरान पिछली चार तिमाहियों के औसत से कम से कम से 3 प्रतिशत बिन्दुओं से वास्तविक उत्पादन वृद्धि में गिरावट, वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पार/अस्थगित किया जा सकता है, जिसमें राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से विचलन एक वर्ष में जीडीपी के 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए (मोचन अनुबंध)। केंद्र सरकार वास्तविक उत्पादन वृद्धि में किसी तिमाही में पिछली चार तिमाहियों के औसत से कम से कम 3 प्रतिशत बिन्दुओं से बढ़ोतरी होने पर, वर्ष के राजकोषीय घाटे में कम से कम जीडीपी के 0.25 प्रतिशत की कमी करेगी (मोचन उपबंध)। इन दोनों स्थितियों में, सरकार, संसद के दोनों सदनों के समक्ष, इसके कारणों और वार्षिक निर्धारित लक्ष्यों पर वापसी का मार्ग बताते हुए एक विवरण प्रस्तुत करेगी।

जहां तक राज्यों का संबंध है, राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों (एफआरएल) के समय और लक्ष्य दोनों के संदर्भ में व्यापक भिन्नताएं हैं। जबकि कुछ दक्षिणी राज्यों (केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक), उत्तर प्रदेश और पंजाब ने केंद्र के एफआरबीएम अधिनियम (2003) से पहले एफआरएल को अपनाया था, शेष अधिकांश राज्यों ने 2003 और 2008 के बीच अपने संबंधित एफआरएल को अपनाया था। पश्चिम बंगाल और सिक्किम केवल

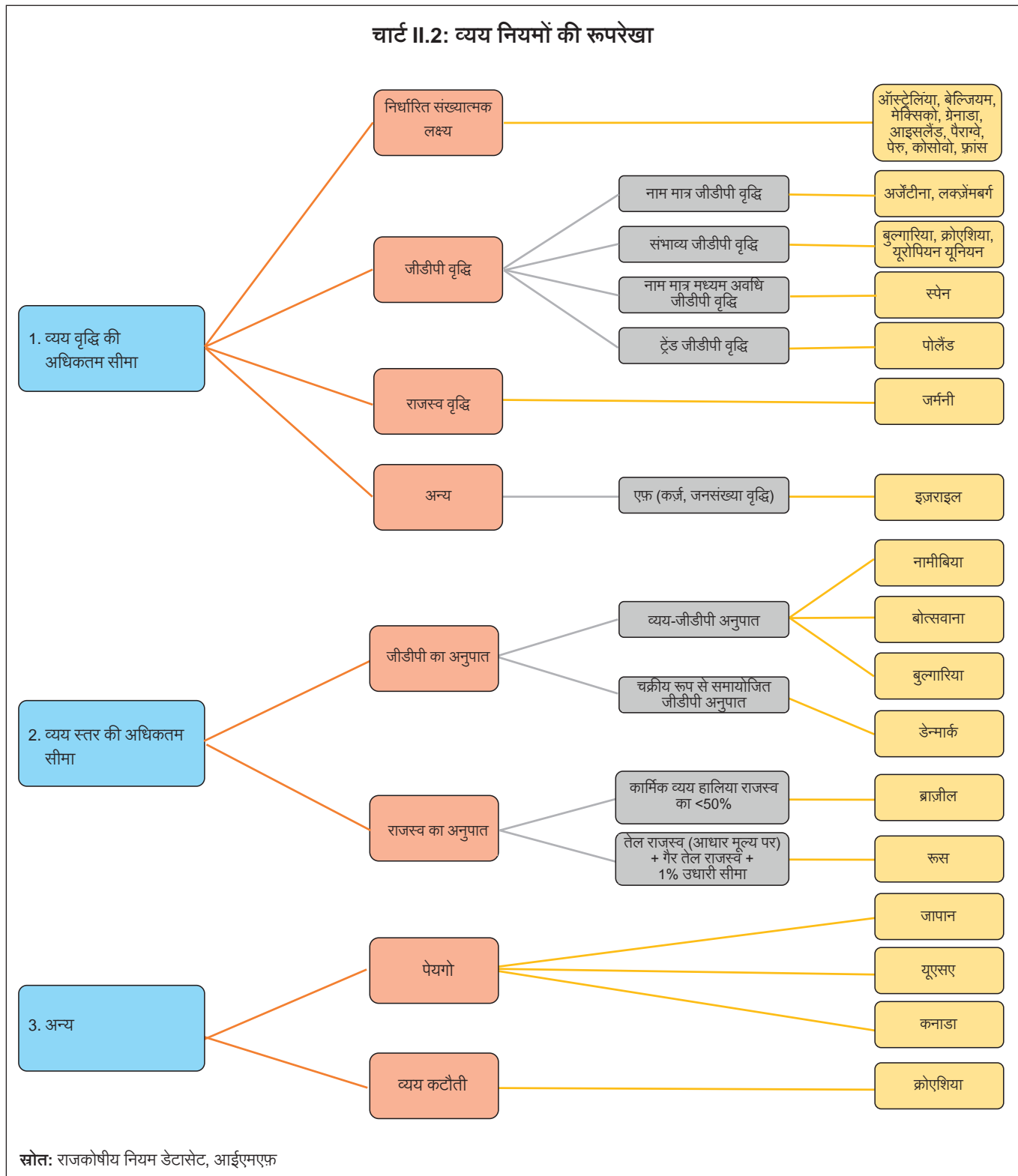
दो राज्य हैं जिसने जीएफसी के बाद एफआरएल को अपनाया। अधिकांश राज्य जीएफडी-जीडीपी अनुपात को 3 प्रतिशत के साथ ही समय सीमा के साथ लक्षित करते हैं। जबकि राज्य एफआरएल ने कई वर्षों से कोई महत्वपूर्ण संशोधन नहीं देखे हैं, यह ध्यान दिया जा सकता है कि मूल एफआरएल में भी बड़े पैमाने पर भिन्नताएं बनी हुई हैं जिनमें कुछ में ऋण नियमों के उदाहरण और मोचन अनुबंध के लिए प्रावधान हैं (चार्ट 1.2)।

**चार्ट 1.2: भारत के राज्यों के विभिन्न राजकोषीय नियम**

सकल राजकोषीय घाटा नियम	ऋण नियम	मोचन अनुबंध
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल	<p><b>ऋण (जीएसडीपी का प्रतिशत)</b> आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल</p> <p><b>ऋण+गारंटी (जीएसडीपी का प्रतिशत)</b> असम और हरियाणा</p> <p><b>ऋण (राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत)</b> झारखंड, ओडिशा, मिजोरम और राजस्थान</p> <p><b>राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान</b> गोवा</p>	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

**स्रोत:** राज्यों के एफआरएल दस्तावेज़।





यू गो) नियम शामिल हैं, जो संयुक्त राज्य, जापान और कनाडा में लागू हैं। सामान्य तौर पर, पेगो नियम के लिए आवश्यक है कि कोई भी उपाय जिसमें व्यय में वृद्धि या

राजस्व में कमी शामिल है, को व्यय में स्थायी कमी या स्थायी राजस्व जुटाने के उपायों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए।

### अनुबंध III: प्रमुख घटक विश्लेषण

प्रमुख घटक विश्लेषण (पीसीए) समानता और अंतर के स्वरूप की पहचान करके विभिन्न सहसंबद्ध चर के बीच साहचर्य के स्तर पर कार्य करता है। यह असंबद्ध सामान्य घटकों की एक श्रृंखला का वर्णन करके एक विश्लेषण में चर की संख्या को कम करने की एक परिमाणिक-कमी विधि है जिसमें चर में अधिकांश भिन्नताएं होती हैं लेकिन सूचना सामग्री को याद किए बिना।

पीसीए सबसे ज़्यादा विचरण वाले चर के रैखिक संयोजनों की पहचान करता है जिसमें पहले प्रमुख घटक में अधिकतम समग्र विचरण होता है। इसी तरह, दूसरे प्रमुख घटक में पहले प्रमुख घटक के बाद अधिकतम विचरण होता है, लेकिन इसके साथ असंबंधित होता है और इसी तरह इसके बाद भी। मूल डेटा सेट में जानकारी को इस तरह विभाजित किया जाता है कि घटक (आयतीय रूप से स्वतंत्र) हों।

विचाराधीन निरंतर प्रारंभिक चरों की सीमा को मानकीकृत करने के बाद, सहप्रसरण मैट्रिक्स की गणना चरों के सभी संभावित युग्मों के बीच सहसंबंधों का पता लगाने के लिए की जाती है। डेटा के प्रमुख घटकों को निर्धारित करने के लिए

सहसंयोजक मैट्रिक्स से आइजेनवेक्टर और आइजेनवैल्यू का अनुमान लगाया

लगाया जाता है। पीसीए में, घटकों और कारक भार को स्थिर माना जाता है। समय में भिन्नता तथा न देखे गए घटकों को एक गतिशील कारक मॉडल और बायेसियन विश्लेषण से प्राप्त किया जा सकता है।

हर एक घटक के लिए आइजेनवैल्यू सभी मर्दों/चरों के वर्गित घटकों के भार का योग है, जो प्रत्येक मर्दों में भिन्नता की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है जिसे प्रमुख घटक द्वारा समझाया जा सकता है। आइजेनवेक्टर प्रत्येक आइजेनवैल्यू के वजन का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइजेनवेक्टर बार आइजेनवैल्यू का वर्गमूल घटक भारों को देता है जिसे प्रमुख घटक के साथ प्रत्येक आइटम के सहसंबंध के रूप में समझा जा सकता है। पीसीए में आइजेनवेक्टर या चर के कारक भार का संकेत उस विशेष प्रमुख घटक के साथ इसके संबंध के बारे में बताता है।

पीसीए में, घटकों और कारक भार को स्थिर माना जाता है। अलग-अलग समय के अनदेखे घटकों को गतिकी कारक या बायेसियन विश्लेषण से प्राप्त किया जा सकता है।

#### प्रमुख घटक विश्लेषण: संबंधित सूचकांकों में चरों के भार

चर	केंद्र	राज्य
आरईसीओ	19.7	24.5
आरडीजीएफडी		19.8
सीओटीई	20.4	24.5
सीओजीडीपी	19.1	24.1
डीईजीडीपी	10.6	6.6
सीओएमजीडीपी	17.6	0.4

**टिप्पणी:** आरईसीओ पूंजीगत परिव्यय के लिए राजस्व व्यय का अनुपात है; आरडी-जीएफडी सकल राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा है; सीओटीई कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजी परिव्यय है; सीओजीडीपी जीडीपी के प्रतिशत के रूप में पूंजी परिव्यय है; डीईजीडीपी जीडीपी के प्रतिशत के रूप में विकासात्मक व्यय है; और सीओएमजीडीपी जीडीपी के प्रतिशत के रूप में समर्पित व्यय है।

**स्रोत:** आरबीआई स्टाफ का अनुमान।



# वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक  
भारतीय रिज़र्व बैंक  
मुद्रा और बैंकिंग  
मूल्य और उत्पादन  
सरकारी लेखा और खज़ाना बिल  
वित्तीय बाजार  
बाह्य क्षेत्र  
भुगतान और निपटान प्रणालियाँ  
अवसरिक शृंखला





## विषय -वस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिदा आर्थिक संकेतक	93
	<b>भारतीय रिज़र्व बैंक</b>	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	94
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	95
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरीकी डॉलर का क्रय/विक्रय	96
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमरीकी डॉलर)	97
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	97
	<b>मुद्रा और बैंकिंग</b>	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	98
7	मुद्रा स्टॉक (एम <sub>3</sub> ) के स्रोत	99
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	100
9	कुल चलनिधि राशियां	100
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	101
11	आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत	101
12	वाणिज्य बैंक सर्वेक्षण	102
13	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेश	102
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	103
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन	104
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	105
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	106
	<b>मूल्य और उत्पादन</b>	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)	107
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	107
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	107
21	थोक मूल्य सूचकांक	108
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)	112
	<b>सरकारी खाते और खज़ाना बिल</b>	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	112
24	खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	113
25	खज़ाना बिलों की नीलामी	113
	<b>वित्तीय बाजार</b>	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	114
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	115
28	वाणिज्यिक पत्र	115
29	चुनिदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	115
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	116

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	<b>बाह्य क्षेत्र</b>	
31	विदेशी व्यापार	117
32	विदेशी मुद्रा भंडार	117
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां	117
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	118
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत जावक विप्रेषण	118
36	भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) सूचकांक	119
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)- पंजीकरण	119
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमरीकी डॉलर)	120
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (करोड़ ₹)	121
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमरीकी डॉलर)	122
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (करोड़ ₹)	123
42	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	124
	<b>भुगतान और निपटान प्रणालियाँ</b>	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	125
	<b>अवसरिक श्रृंखला</b>	
44	लघु बचत	127
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	128
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	129
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	130
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	131
49	राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां	132

टिप्पणियां : .. = उपलब्ध नहीं।

— = शून्य/नगण्य

प्रा/अ= प्रारंभिक/अनंतिम      आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

## सं. 1 : चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2020-21	2019-20		2020-21	
		ति3	ति4	ति3	ति4
	1	2	3	4	5
<b>1 वास्तविक क्षेत्र (% परिवर्तन)</b>					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	-6.2	3.4	3.7	1.0	3.7
1.1.1 कृषि	3.6	3.4	6.8	4.5	3.1
1.1.2 उद्योग	-6.4	-3.0	-3.2	1.6	5.5
1.1.3 सेवाएं	-8.4	5.8	5.6	-0.2	3.2
1.1क अंतिम खपत व्यय	-7.3	6.8	3.3	-2.6	6.4
1.1ख सकल नियत पूंजी निर्माण	-10.8	2.4	2.5	2.6	10.9
	2020-21	2020		2021	
	1	मार्च	अप्रै.	मार्च	अप्रै.
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	-8.6	-18.7	-57.3	22.4	-
<b>2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)</b>					
2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंक					
2.1.1 जमाराशियां	11.4	7.9	9.9	11.4	11.2
2.1.2 ऋण	5.6	6.1	6.8	5.6	6.2
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	5.5	6.1	6.7	5.5	6.0
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	19.3	10.6	14.9	19.3	14.1
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	18.8	9.4	9.1	18.8	18.7
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	11.7	8.9	10.8	11.7	10.6
<b>3 अनुपात (%)</b>					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	3.50	3.00	3.00	3.50	3.50
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.25	18.00	18.00	18.00
3.3 नकदी-जमा अनुपात	4.2	4.6	3.7	4.2	4.4
3.4 ऋण-जमा अनुपात	72.4	76.4	74.9	72.4	71.5
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात	37.4	60.3	-62.6	37.4	-24.4
3.6 निवेश-जमा अनुपात	29.5	27.6	28.9	29.5	29.7
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	46.8	36.2	147.5	46.8	44.6
<b>4 व्याज दरें (%)</b>					
4.1 नीति रिपो दर	4.00	4.40	4.40	4.00	4.00
4.2 रिवर्स रिपो दर	3.35	4.00	3.75	3.35	3.35
4.3 सीमांत स्थायी सुविधा दर	4.25	4.65	4.65	4.25	4.25
4.4 बैंक दर	4.25	4.65	4.65	4.25	4.25
4.5 आधार दर	7.40/8.80	8.15/9.40	8.15/9.40	7.40/8.80	7.40/8.80
4.6 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	6.55/7.05	7.40/7.90	7.10/7.75	6.55/7.05	6.55/7.05
4.7 एक वर्ष से अधिक की मीयादी जमा दर	4.90/5.50	5.90/6.40	5.70/6.00	4.90/5.50	4.90/5.50
4.8 बचत जमा दर	2.70/3.00	3.00/3.50	2.75/3.50	2.70/3.00	2.70/3.00
4.9 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	3.25	5.05	4.09	3.25	3.21
4.10 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	3.32	4.36	3.64	3.32	3.32
4.11 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	3.47	4.97	3.66	3.47	3.45
4.12 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	3.83	4.94	3.70	3.83	3.72
4.13 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय (एफबीआईएल)	6.34	6.71	6.55	6.34	6.26
<b>5 आरबीआई संदर्भ दर और फारवर्ड प्रीमिया</b>					
5.1 भा.रु.-अमरीकी डॉलर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	72.40	74.84	76.42	72.40	74.02
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	85.31	82.64	82.21	85.31	89.69
5.3 फारवर्ड प्रीमिया अमरीकी डॉलर					
1-माह (%)	6.80	8.98	3.93	6.80	6.00
3-माह (%)	5.64	5.93	3.85	5.64	5.38
6-माह (%)	5.47	5.05	3.93	5.47	5.17
<b>6 मुद्रास्फीति (%)</b>					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	6.18	5.8	7.2	5.5	4.3
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.03	5.5	5.4	5.7	5.1
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	1.25	0.4	-1.6	7.4	10.5
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	1.64	2.2	-1.1	6.4	10.2
6.3.2 ईंधन और पावर	-7.95	-2.9	-12.6	10.3	20.9
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	2.71	0.3	0.2	7.3	9.0
<b>7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)</b>					
7.1 आयात	-17.09	-28.0	-59.6	53.8	167.1
7.2 निर्यात	-7.20	-34.3	-60.2	60.3	195.7

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) भारतीय रिजर्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार जी सेक बेचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रसारण शुरू किया है।

## भारतीय रिज़र्व बैंक

## सं. 2 : भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां\*

(करोड़ ₹)

मद	अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति						
	2020-21	2020	2021				
		मई	अप्रै. 30	मई 7	मई 14	मई 21	मई 28
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1 निर्गम विभाग</b>							
<b>1.1 देयताएं</b>							
1.1.1 संचलन में नोट	2831727	2590153	2887884	2913024	2930881	2937217	2936065
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	11	16	14	14	14	14	15
<b>1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां</b>	<b>2831738</b>	<b>2590169</b>	<b>2887898</b>	<b>2913039</b>	<b>2930895</b>	<b>2937231</b>	<b>2936080</b>
<b>1.2 आस्तियां</b>							
1.2.1 सोने के सिक्के और बुलियन	106555	109837	110440	112734	112937	115721	115898
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	2724437	2479521	2776759	2799612	2817269	2820826	2819499
1.2.3 रुपया सिक्का	746	811	699	692	689	685	683
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-
<b>2 बैंकिंग विभाग</b>							
<b>2.1 देयताएं</b>							
2.1.1 जमाराशियां	1504697	1170867	1507507	1470797	1452851	1570638	1618155
2.1.1.1 केंद्र सरकार	100	101	100	101	100	101	101
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना							
2.1.1.3 राज्य सरकारें	42	42	42	43	42	42	42
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	542693	435222	579344	557032	578084	603344	645726
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	6529	5619	6487	6309	6495	6858	7191
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	3204	2575	3311	3342	3516	3745	3717
2.1.1.7 अन्य बैंक	31820	25557	32482	32565	31754	35770	36088
2.1.1.8 अन्य	895440	694192	885731	871396	831613	919531	924064
2.1.1.9 भारत के बाहर वित्तीय संस्थान	24868	7559	8	8	1246	1248	1225
2.1.2 अन्य देयताएं	1343670	1468659	1458976	1438064	1432634	1330062	1300816
<b>2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां</b>	<b>2848367</b>	<b>2639526</b>	<b>2966482</b>	<b>2908860</b>	<b>2885485</b>	<b>2900700</b>	<b>2918971</b>
<b>2.2 आस्तियां</b>							
2.2.1 नोट और सिक्के	11	16	14	14	14	14	15
2.2.2 विदेश में रखे शेष	1204135	990118	1296637	1245745	1218902	1202518	1218300
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.2 राज्य सरकारें	1674	7187	4506	7619	10402	2656	6473
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	90275	291023	89934	89592	89592	90486	90093
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.6 नाबार्ड	26422	22000	17077	1664	1664	1679	1679
2.2.3.7 एक्विजिशन बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.8 अन्य	6678	5402	6729	4013	4013	-	-
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	24858	-	8	8	1246	1244	1225
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.2 सरकारी खजाना बिल	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 निवेश	1331671	1174491	1397597	1402946	1402161	1440302	1438893
2.2.6 अन्य आस्तियां	162643	149289	153979	157258	157490	161801	162293
2.2.6.1 सोना	146572	137294	152269	155432	155711	159919	160164

\*: डेटा अनंतिम है।

## सं. 3 : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(करोड़ ₹)

दिनांक	रिपो	रिवर्स रिपो	परिवर्तन-शील रिपो दर	परिवर्तन-शील रिवर्स रिपो दर	एमएसएफ	स्थायी चलनिधि सुविधाएं	बाज़ार स्थिरीकरण योजना	विक्रय	क्रय	दीर्घावधि रिपो परिचालन	लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन&	म्यूचुअल फंड के लिए विशेष चलनिधि सुविधा	एनबीफसी/एचएफसीएस के लिए विशेष चलनिधि योजना **	निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+6+9+10+11+12+13-2-4-7-8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
अप्रै. 1, 2021	-	246294	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-246286
अप्रै. 2, 2021	-	32480	-	-	920	-	-	-	-	-	-	-	-	-31560
अप्रै. 3, 2021	-	83315	-	-	468	-	-	-	-	-	-	-	-	-82847
अप्रै. 4, 2021	-	8611	-	-	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-8474
अप्रै. 5, 2021	-	720562	-	-	13	-	-	-	1575	-	-	-	-	-718974
अप्रै. 6, 2021	-	728884	-	-	0	-197	-	-	-	-	-	-	-	-729081
अप्रै. 7, 2021	-	720001	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-719990
अप्रै. 8, 2021	-	692763	-	-	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-692626
अप्रै. 9, 2021	-	531695	-	200017	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-731703
अप्रै. 10, 2021	-	2633	-	-	465	-	-	-	-	-	-	-	-	-2168
अप्रै. 11, 2021	-	5022	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-4938
अप्रै. 12, 2021	-	447338	-	-	180	-2000	-	-	-	-	-	-	-	-449158
अप्रै. 13, 2021	-	18839	-	-	1299	-	-	-	-	-	-	-	-	-17540
अप्रै. 14, 2021	-	35651	-	-	1804	-	-	-	-	-	-	-	-	-33847
अप्रै. 15, 2021	-	499304	-	-	108	2000	-	-	-	-	-	-	-	-497196
अप्रै. 16, 2021	-	464632	-	-	210	-4000	-	-	25000	-	-	-	-	-443422
अप्रै. 17, 2021	-	30080	-	-	759	-	-	-	-	-	-	-	-	-29321
अप्रै. 18, 2021	-	3600	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-3528
अप्रै. 19, 2021	-	489904	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-489904
अप्रै. 20, 2021	-	378478	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-378478
अप्रै. 21, 2021	-	48336	-	-	5974	-	-	-	-	-	-	-	-	-42362
अप्रै. 22, 2021	-	421947	-	-	0	-	-	-	15000	-	-	-	-	-406947
अप्रै. 23, 2021	-	390042	-	200017	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-589910
अप्रै. 24, 2021	-	5969	-	-	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-5839
अप्रै. 25, 2021	-	6644	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-6562
अप्रै. 26, 2021	-	418620	-	-	121	80	-	-	-	-	-	-	-	-418419
अप्रै. 27, 2021	-	422887	-	-	12	-	-	-	85	-	-	-	-	-422790
अप्रै. 28, 2021	-	419112	-	-	154	-3000	-	-	150	-	-	-	-	-421808
अप्रै. 29, 2021	-	430126	-	-	4	-1500	-	-	15240	-	-	-	-	-416382
अप्रै. 30, 2021	-	419013	-	-	342	-	-	-	170	-	-	-	-	-418501

नोट: # लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ ) और लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0 ) शामिल है। ऋणात्मक (-) चिन्ह बैंकों द्वारा किए गए पुनर्भुगतान को दर्शाता है।

\*\* 01 जुलाई 2020 के आरबीआई अधिसूचना संख्या 2020-21/01 के अनुसार

ऋणात्मक (-) चिन्ह विशेष चलनिधि योजना में आरबीआई के निवेश के लिए प्राप्त परिपक्वता आय को दर्शाता है।  
& ऋणात्मक(-) चिन्ह बैंकों द्वारा किए गए पुनर्भुगतान को दर्शाता है।

## सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरीकी डॉलर का क्रय-विक्रय

## i) ओटीसी सेगमेंट में ऑनशॉर / ऑफशॉर में परिचालन

मद	2020-21	2020	2021	
		अप्रै.	मार्च	अप्रै.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरीकी डॉलर) (1.1-1.2)	68315	-1142	-5699	4212
1.1 क्रय (+)	162479	2450	20250	8182
1.2 विक्रय (-)	94164	3592	25949	3970
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (करोड़ ₹)	510516	-8589	-41123	31779
3 संचयी (मार्च के अंत से) (मिलियन अमरीकी डॉलर)	68315	-1142	68315	4212
(करोड़ ₹)	510516	-8589	510516	31779
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरीकी डॉलर)	72751	-1739	72751	64944

## ii) मुद्रा फ्यूचर्स सेगमेंट में परिचालन

मद	2020-21	2020	2021	
		अप्रै.	मार्च	अप्रै.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरीकी डॉलर) (1.1-1.2)	0	0	0	0
1.1 क्रय (+)	12118	500	830	690
1.2 विक्रय (-)	12118	500	830	690
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरीकी डॉलर)	690	0	690	0

सं. 4ए भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार)  
परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	30 अप्रैल 2021 की स्थिति		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	6492	400	6092
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	15027	0	15027
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	53845	10020	43825
4. 1 वर्ष से अधिक	0	0	0
<b>कुल (1+2+3+4)</b>	<b>75364</b>	<b>10420</b>	<b>64944</b>

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	2020-21	2020		2021				
		मई 22	दिसं. 18	जन. 29	फर. 26	मार्च 26	अप्रै. 23	मई 21
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	182	1400	1	0	58	182	149	494
2 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त								
2.1 सीमा	-	-	-	-	-	0	-	-
2.2 बकाया	-	-	-	-	-	0	-	-
3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा								
3.1 सीमा	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900
3.2 बकाया	-	1372	0	0	0	0	0	0
4. अन्य								
4.1 सीमा	75000	50000	75000	75000	75000	75000	75000	60000
4.2 बकाया	32387	21369	34760	32205	32842	32387	27122	1662
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	32569	24141	34761	32205	32900	32569	27271	2156

टिप्पणी: 1. अन्य को विशेष पुनर्वित्त सुविधा अर्थात एक्जिम बैंक को 22 मई 2020 से पुनः शुरू कर दिया।

2. अन्य के लिए पुनर्वित्त सुविधा, अर्थात भारिबैंक अधिनियम 1934 के नाबार्ड/ सिडबी/एनएचबी यू/एस 17 (4 एच), 17 अप्रैल 2020 से।

## मुद्रा और बैंकिंग

## सं. 6: मुद्रा भंडार की मात्रा

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2020-21 *	2020	2021		
		अप्रै. 24	मार्च 26	अप्रै. 9	अप्रै. 23
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	2757847	2424665	2757847	2788070	2803941
1.1 संचलन में नोट	2831727	2496611	2831727	2857645	2880247
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	26170	25616	26170	26170	26170
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	743	743	743	743	743
1.4 बैंकों के पास नकदी	100793	98305	100793	96488	103218
2 जनता की जमाराशियां	2031608	1621593	2031608	1913256	1896488
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियां	1984261	1582022	1984261	1866964	1850979
2.2 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियां	47347	39570	47347	46292	45509
<b>3 एम<sub>1</sub> (1 + 2)</b>	<b>4789456</b>	<b>4046258</b>	<b>4789456</b>	<b>4701326</b>	<b>4700429</b>
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियां	150963	150963	150963	150963	150963
<b>5 एम<sub>2</sub> (3 + 4)</b>	<b>4940419</b>	<b>4197221</b>	<b>4940419</b>	<b>4852289</b>	<b>4851392</b>
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियां	13983686	12987875	13983686	14202754	14139871
<b>7 एम<sub>3</sub> (3 + 6)</b>	<b>18773142</b>	<b>17034133</b>	<b>18773142</b>	<b>18904080</b>	<b>18840300</b>
8 कुल डाकघर जमाराशियां	433441	433441	433441	433441	433441
<b>9 एम<sub>4</sub> (7 + 8)</b>	<b>19206583</b>	<b>17467574</b>	<b>19206583</b>	<b>19337521</b>	<b>19273741</b>



सं. 7: मुद्रा भंडार (एम<sub>3</sub>) का स्रोत

(करोड़ ₹)

स्रोत	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2020-21*	2020	2021		
			अप्रै. 24	मार्च 26	अप्रै. 9
	1	2	3	4	5
<b>1 सरकार को निवल बैंक ऋण</b>	<b>5692569</b>	<b>5415971</b>	<b>5692569</b>	<b>6045792</b>	<b>5871943</b>
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	982063	1214517	982063	1246043	1144052
1.1.1 सरकार पर दावे	1332127	1214660	1332127	1343003	1381547
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	1330453	1213597	1330453	1340648	1379184
1.1.1.2 राज्य सरकारें	1674	1063	1674	2355	2363
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमाशियां	350065	143	350065	96961	237496
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	350022	100	350022	96918	237453
1.1.2.2 राज्य सरकारें	42	43	42	42	42
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	4710506	4201454	4710506	4799749	4727891
<b>2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण</b>	<b>11610050</b>	<b>10923206</b>	<b>11610050</b>	<b>11551354</b>	<b>11522203</b>
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	8524	6126	8524	8672	8672
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	11601526	10917080	11601526	11542682	11513531
2.2.1 वाणिज्य बैंकों द्वारा बैंक ऋण	10949512	10273416	10949512	10888464	10860396
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	643045	633810	643045	645062	643950
2.2.3 वाणिज्य और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	8969	9854	8969	9157	9184
<b>3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)</b>	<b>4511386</b>	<b>3872236</b>	<b>4511386</b>	<b>4648873</b>	<b>4691323</b>
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	4181453	3661602	4181453	4318939	4361389
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	4181689	3661836	4181689	4319175	4361626
3.1.2 विदेशी देयताएं	237	234	237	237	237
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	329934	210634	329934	329934	329934
<b>4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं</b>	<b>26913</b>	<b>26359</b>	<b>26913</b>	<b>26913</b>	<b>26913</b>
<b>5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं</b>	<b>3067777</b>	<b>3203639</b>	<b>3067777</b>	<b>3368851</b>	<b>3272081</b>
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	1331957	1456364	1331957	1475837	1514082
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	1735819	1747275	1735819	1893014	1757999
<b>एम<sub>3</sub> (1+2+3+4-5)</b>	<b>18773142</b>	<b>17034133</b>	<b>18773142</b>	<b>18904080</b>	<b>18840300</b>

\* :डेटा 26 मार्च, 2021 से संबंधित है

## सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2020-21*	2020	2021		
		अप्रै. 24	मार्च 26	अप्रै. 9	अप्रै. 23
	1	2	3	4	5
<b>मौद्रिक समुच्चय</b>					
एन एम1 (1.1 + 1.2.1+1.3)	4789456	4046258	4789456	4701326	4700429
एन एम2 (एन एम1 + 1.2.2.1)	11013466	9809730	11013466	11023399	10994116
एन एम3 (एन एम2 + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4- 2.5)	18864615	17155433	18864615	18993375	18922870
<b>1 घटक</b>					
1.1 जनता के पास मुद्रा	2757847	2424665	2757847	2788070	2803941
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियां	15815395	14389739	15815395	15916016	15836950
1.2.1 मांग जमाराशियां	1984261	1582022	1984261	1866964	1850979
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	13831134	12807716	13831134	14049052	13985970
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	6224010	5763472	6224010	6322073	6293687
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	78702	163845	78702	89606	86436
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	7607124	7044244	7607124	7726979	7692284
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	47347	39570	47347	46292	45509
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग /सावधि निधीयन	244025	301459	244025	242997	236470
<b>2 स्रोत</b>					
2.1 देशी ऋण	18294061	17253140	18294061	18608145	18385461
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	5692569	5415971	5692569	6045792	5871943
2.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	982063	1214517	982063	1246043	1144052
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	4710506	4201454	4710506	4799749	4727891
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	12601492	11837169	12601492	12562353	12513519
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैंक ऋण	34946	6126	34946	34097	30097
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	12566546	11831043	12566546	12528256	12483422
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	951313	902293	951313	974490	956266
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26913	26359	26913	26913	26913
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4420255	3668867	4420255	4602126	4690547
2.3.1 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4181453	3661602	4181453	4318939	4361389
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	238802	7264	238802	283187	329158
2.4 पूंजी खाता	2790207	2789555	2790207	2867898	2937753
2.5 अन्य मदें (निवल)	1086406	1003377	1086406	1375910	1242297

## सं. 9: चलनिधि समुच्चय

(करोड़ ₹)

समुच्चय	2020-21*	2020	2021		
	1	अप्रै.	फर.	मार्च	अप्रै.
		2	3	4	5
<b>1 एन एम<sub>3</sub></b>	<b>18864615</b>	<b>17155433</b>	<b>18643535</b>	<b>18864615</b>	<b>18922870</b>
2 डाकघर जमाराशियां	433441	433441	433441	433441	433441
<b>3 एल<sub>1</sub> (1 + 2)</b>	<b>19298056</b>	<b>17588874</b>	<b>19076976</b>	<b>19298056</b>	<b>19356311</b>
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	34673	56424	34795	34673	31426
4.1 सावधि मुद्रा उधार	2645	9928	2645	2645	3563
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	27050	43199	28865	27050	22775
4.3 सावधि जमाराशियां	4978	3297	3285	4978	5088
<b>5 एल<sub>2</sub> (3 + 4)</b>	<b>19332729</b>	<b>17645298</b>	<b>19111771</b>	<b>19332729</b>	<b>19387737</b>
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियां	31905	..	..	31905	..
<b>7 एल<sub>3</sub> (5 + 6)</b>	<b>19364634</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>19364634</b>	<b>..</b>

टिप्पणी : 1. संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

\*: डेटा 26 मार्च, 2021 से संबंधित है।

## सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2020-21*	2020		2021	
		अप्रै. 24	मार्च 26	अप्रै. 9	अप्रै. 23
	1	2	3	4	5
<b>1 घटक</b>					
1.1 संचलन में मुद्रा	2858640	2522970	2858640	2884558	2907160
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां	584246	457178	584246	577242	595372
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	542693	423731	542693	535652	552893
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	47347	39570	47347	46292	45509
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	3490233	3019718	3490233	3508092	3548040
<b>2 स्रोत</b>					
2.1 भा.रि.बैं.के देशी ऋण	613825	788121	613825	638078	673821
2.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण	982063	1214517	982063	1246043	1144052
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	980431	1213497	980431	1243730	1141731
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	-	111985	-	-	-
2.1.1.1.2 खजाना बिलों में निवेश	-	-	-	-	-
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1329707	1100775	1329707	1339923	1378479
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	1329707	1100775	1329707	1339923	1378479
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	746	837	746	725	705
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियां	350022	100	350022	96918	237453
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैं. ऋण	1632	1020	1632	2313	2321
2.1.2 बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावे	-403183	-432522	-403183	-642062	-500328
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को ऋण और अग्रिम	-376761	-432522	-376761	-616636	-478902
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैं. के ऋण	34946	6126	34946	34097	30097
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	1	4162	1	1	1
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	26422	-	26422	25426	21426
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26913	26359	26913	26913	26913
2.3 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4181453	3661602	4181453	4318939	4361389
2.3.1 सोना	253128	251551	253128	263965	269822
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	3928343	3410069	3928343	4054991	4091584
2.4 पूंजी खाता	1187995	1239451	1187995	1270080	1307634
2.5 अन्य मदें (निवल)	143962	216913	143962	205757	206448

## सं. 11: रिज़र्व बैंक - घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	2020-21	मार्च 31 /माह के अंतिम शुक्रवारों/शुक्रवारों की स्थिति के अनुसार बकाया						
		2020		2021				
		मई 1	मार्च 26	अप्रै. 2	अप्रै. 9	अप्रै. 16	अप्रै. 23	अप्रै. 30
	1	2	3	4	5	6	7	8
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	3599981	3066239	3490233	3514970	3508092	3547430	3548040	3585500
<b>1 घटक</b>								
1.1 संचलन में मुद्रा	2853763	2535178	2858640	2854904	2884558	2899808	2907160	2914857
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां	698867	486339	584246	611065	577242	601865	595372	621624
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	47351	44722	47347	49002	46292	45757	45509	49019
<b>2 स्रोत</b>								
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	1099686	1314023	982063	1123015	1246043	1214865	1144052	1187599
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	-378066	-471497	-376761	-486564	-616636	-553372	-478902	-512012
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	8709	6474	8524	8709	8672	8672	8672	8686
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4199400	3605611	4181453	4198577	4318939	4309948	4361389	4335869
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26913	26359	26913	26913	26913	26913	26913	26973
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	1356660	1414731	1331957	1355679	1475837	1459595	1514082	1461615

## सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवारों/ माह के रिपोर्टिंग शुक्रवारों की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2020-21	2020	2021		
		अप्रै. 24	मार्च 26	अप्रै. 9	अप्रै. 23
	1	2	3	4	5
<b>1 घटक</b>					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियां	14960977	13543024	14960977	15057751	14980407
1.1.1 मांग जमाराशियां	1861209	1461382	1861209	1742864	1727332
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	13099768	12081642	13099768	13314887	13253075
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	5894896	5436739	5894896	5991699	5963884
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	78702	163845	78702	89606	86436
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	7204873	6644903	7204873	7323188	7289191
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधायन	244025	301459	244025	242997	236470
<b>2 स्रोत</b>					
2.1 देशी ऋण	16368358	15148325	16368358	16414649	16300562
2.1.1 सरकार को ऋण	4461632	3968353	4461632	4548174	4477794
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	11906727	11179973	11906727	11866475	11822767
2.1.2.1 बैंक ऋण	10949512	10273416	10949512	10888464	10860396
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	10888258	10220772	10888258	10838765	10802061
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	13970	11933	13970	11347	13887
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	894	1293	894	1136	1180
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	942351	893331	942351	965528	947304
2.2 वाणिज्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	238802	7264	238802	283187	329158
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	454866	294196	454866	493050	534987
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियां	152552	180159	152552	153702	153900
2.2.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार	63512	106773	63512	56161	51930
2.3 निवल बैंक रिजर्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	1010202	944027	1010202	1238831	1124923
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	542693	423731	542693	535652	552893
2.3.2 उपलब्ध नकदी	90748	87774	90748	86543	93128
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	-376761	-432522	-376761	-616636	-478902
2.4 पूंजी खाता	1578041	1525934	1578041	1573648	1605948
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	834319	729201	834319	1062271	931817
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	593102	414847	593102	511317	505242
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	70853	68082	70853	67346	66934

## सं. 13: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(करोड़ ₹)

मद	26 मार्च 2021 की स्थिति	2020	2021		
		अप्रै. 24	मार्च 26	अप्रै. 9	अप्रै. 23
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	4462526	3969646	4462526	4549310	4478975
2 वाणिज्यिक पत्र	82584	110876	82584	80593	78327
3 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
3.1 सरकारी उद्यम	9840	13561	9840	9789	9753
3.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	64035	70543	64035	65019	64979
3.3 अन्य	5210	5250	5210	5155	5145
4 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
4.1 सरकारी उद्यम	121008	128735	121008	120533	121112
4.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	308904	254767	308904	321922	313810
4.3 अन्य	149325	154872	149325	158579	155243
5 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
5.1 म्यूचुअल फंड	31142	45325	31142	37745	33616
5.2 वित्तीय संस्थाएं	167130	109411	167130	166192	165317

## सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(करोड़ ₹)

मद	अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार (मार्च के संबंध में) / अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			
	2020-21	2020	2021		2020-21	2020	2021	
		अप्रै.	मार्च	अप्रै.		अप्रै.	मार्च	अप्रै.
1	2	3	4	5	6	7	8	
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	209	210	209	209	133	134	133	133
<b>1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं</b>	<b>259530</b>	<b>329371</b>	<b>259530</b>	<b>267694</b>	<b>254589</b>	<b>323746</b>	<b>254589</b>	<b>262751</b>
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	200585	248986	200585	186226	195866	243507	195866	181561
1.2 बैंकों से उधार राशि	40886	64521	40886	61927	40880	64521	40880	61920
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	18059	15863	18059	19541	17843	15717	17843	19270
<b>2 अन्य के प्रति देयताएं</b>	<b>16457782</b>	<b>14977356</b>	<b>16457782</b>	<b>16523279</b>	<b>16014145</b>	<b>14546260</b>	<b>16014145</b>	<b>16076879</b>
2.1 कुल जमाराशियां	15540152	14138077	15540152	15688937	15113512	13723182	15113512	15260104
2.1.1 मांग	1899343	1491632	1899343	1797356	1861193	1455445	1861193	1758653
2.1.2 मीयादी	13640809	12646445	13640809	13891581	13252320	12267737	13252320	13501450
2.2 उधार	248271	305582	248271	243137	244025	301459	244025	238212
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	669359	533697	669359	591205	656607	521620	656607	578564
<b>3 रिजर्व बैंक से उधार</b>	<b>90275</b>	<b>288194</b>	<b>90275</b>	<b>89934</b>	<b>90275</b>	<b>288194</b>	<b>90275</b>	<b>89934</b>
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 अन्य	90275	288194	90275	89934	90275	288194	90275	89934
<b>4 उपलब्ध नकदी और रिजर्व बैंक के पास शेष</b>	<b>650745</b>	<b>526661</b>	<b>650745</b>	<b>690113</b>	<b>633440</b>	<b>511505</b>	<b>633440</b>	<b>672600</b>
4.1 उपलब्ध नकदी	92793	90292	92793	95307	90748	87774	90748	93256
4.2 रिजर्व बैंक के पास शेष	557951	436369	557951	594806	542693	423731	542693	579344
<b>5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां</b>	<b>265729</b>	<b>334246</b>	<b>265729</b>	<b>271479</b>	<b>197541</b>	<b>267597</b>	<b>197541</b>	<b>211287</b>
5.1 अन्य बैंकों के पास शेष	179430	195372	179430	196800	143294	161923	143294	163203
5.1.1 चालू खाते में	16796	20294	16796	38182	14226	17946	14226	36075
5.1.2 अन्य खातों में	162634	175077	162634	158618	129068	143977	129068	127128
5.2 मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	36716	44751	36716	29388	10654	19699	10654	8100
5.3 बैंकों को अग्रिम	19908	26669	19908	17378	16764	25331	16764	14912
5.4 अन्य आस्तियां	29675	67453	29675	27914	26829	60643	26829	25072
<b>6 निवेश</b>	<b>4598924</b>	<b>4090423</b>	<b>4598924</b>	<b>4664059</b>	<b>4462526</b>	<b>3969646</b>	<b>4462526</b>	<b>4528292</b>
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	4591896	4082461	4591896	4656742	4461632	3968352	4461632	4527038
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	7029	7962	7029	7317	894	1293	894	1253
<b>7 बैंक ऋण</b>	<b>11297014</b>	<b>10604139</b>	<b>11297014</b>	<b>11260599</b>	<b>10949509</b>	<b>10273416</b>	<b>10949509</b>	<b>10913799</b>
7क खाद्यान्न ऋण	91653	83051	91653	115321	61254	52643	61254	79502
7.1 ऋण नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	11081668	10404439	11081668	11052336	10736491	10076434	10736491	10707813
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	30896	22932	30896	29877	30531	22511	30531	29860
7.3 देशी बिल - भुनाए गए	128831	135788	128831	125919	127883	134450	127883	124517
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	20762	15344	20762	19416	20394	14956	20394	19133
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	34857	25637	34857	33051	34210	25065	34210	32476

## सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

क्षेत्र	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 26, 2021	2020	2021		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
			अप्रै. 24	मार्च 26		
	1	2	3	4	%	%
<b>I. सकल बैंक ऋण (II+III)</b>	<b>10951561</b>	<b>10273416</b>	<b>10951561</b>	<b>10860425</b>	<b>-0.8</b>	<b>5.7</b>
<b>II. खाद्यान्न ऋण</b>	<b>61254</b>	<b>52643</b>	<b>61254</b>	<b>58335</b>	<b>-4.8</b>	<b>10.8</b>
<b>III. गैर-खाद्यान्न ऋण</b>	<b>10890307</b>	<b>10220772</b>	<b>10890307</b>	<b>10802090</b>	<b>-0.8</b>	<b>5.7</b>
<b>1. कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां</b>	<b>1299914</b>	<b>1159999</b>	<b>1299914</b>	<b>1291299</b>	<b>-0.7</b>	<b>11.3</b>
<b>2. उद्योग</b>	<b>2918028</b>	<b>2884372</b>	<b>2918028</b>	<b>2895875</b>	<b>-0.8</b>	<b>0.4</b>
2.1 सूक्ष्म और लघु <sup>1</sup>	383854	358340	383854	372063	-3.1	3.8
2.2 मझौले	136054	99457	136054	143052	5.1	43.8
2.3 बड़े	2398121	2426575	2398121	2380760	-0.7	-1.9
<b>3. सेवाएं</b>	<b>2630566</b>	<b>2560489</b>	<b>2630566</b>	<b>2592346</b>	<b>-1.5</b>	<b>1.2</b>
3.1 परिवहन परिचालक	145195	144464	145195	143969	-0.8	-0.3
3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	21043	20157	21043	20957	-0.4	4.0
3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	49590	47101	49590	50395	1.6	7.0
3.4 शिपिंग	7172	5411	7172	5409	-24.6	0.0
3.5 नौवहन	25624	24315	25624	26309	2.7	8.2
3.6 पेशेवर सेवाएं	119488	117921	119488	114327	-4.3	-3.0
3.7 व्यापार	617627	551419	617627	609247	-1.4	10.5
3.7.1 थोक व्यापार	319197	260027	319197	316896	-0.7	21.9
3.7.2 खुदरा व्यापार	298430	291392	298430	292350	-2.0	0.3
3.8 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	235547	229926	235547	234890	-0.3	2.2
3.9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) <sup>2</sup> जिसमें से	945061	893733	945061	923756	-2.3	3.4
3.9.1 आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफसी)	187324	163513	187324	183748	-1.9	12.4
3.9.2 सरकारी वित्तीय संस्थाएं (पीएफआई)	78441	36399	78441	75200	-4.1	106.6
3.10 अन्य सेवाएं <sup>3</sup>	464219	526042	464219	463088	-0.2	-12.0
<b>4. व्यक्तिगत ऋण</b>	<b>2813713</b>	<b>2495788</b>	<b>2813713</b>	<b>2810419</b>	<b>-0.1</b>	<b>12.6</b>
4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	7307	8908	7307	7273	-0.5	-18.4
4.2 आवास	1459066	1334647	1459066	1461491	0.2	9.5
4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	71544	67905	71544	70693	-1.2	4.1
4.4 शेयरों और बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	4570	4818	4570	4474	-2.1	-7.1
4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	116537	96978	116537	113566	-2.5	17.1
4.6 शिक्षा	63805	65246	63805	62909	-1.4	-3.6
4.7 वाहन ऋण	241657	216968	241657	242443	0.3	11.7
4.8 सोने के आभूषण पर ऋण	60726	33476	60726	62238	2.5	85.9
4.9 अन्य व्यक्तिगत ऋण	788503	666843	788503	785334	-0.4	17.8
<b>5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (मेमो)</b>						
5.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां <sup>4</sup>	1264151	1144415	1264151	1266715	0.2	10.7
5.2 सूक्ष्म और लघु उद्यम <sup>5</sup>	1107236	1084062	1107236	1060534	-4.2	-2.2
5.3 मध्यम उद्यम <sup>6</sup>	206122	110691	206122	189012	-8.3	70.8
5.4 आवास	469863	459699	469863	473957	0.9	3.1
5.5 शिक्षा ऋण	48201	52003	48201	47510	-1.4	-8.6
5.6 नवीकरणीय ऊर्जा	1171	679	1171	1157	-1.2	70.3
5.7 सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर	2352	818	2352	2327	-1.0	184.5
5.8 निर्यात ऋण <sup>7</sup>	19028	16723	19028	19058	0.2	14.0
5.9 अन्य	18818	13290	18818	20638	9.7	55.3
5.10 नेट पीएसएलसी- एसएफ/एमएफ सहित कमजोर वर्ग	813263	772260	813263	809618	-0.4	4.8

टिप्पणी : 1. डाटा अनतिम हैं। सकल बैंक ऋण और गैर-खाद्य ऋण का डाटा धारा -42 रिटर्न पर आधारित है, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को (एससीबी) शामिल किया गया है, जब कि क्षेत्रवार गैर-खाद्य ऋण डाटा क्षेत्र-वार पर और उद्योग-वार बैंक ऋण(एसआईबीसी) रिटर्न, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा कुल गैर खाद्य ऋण के लगभग 90 प्रतिशत के चुनिंदा बैंकों को समाविष्ट किया गया है। टिप्पणी 2: जनवरी 2021 से, क्षेत्रीय ऋण डेटा संशोधित प्रारूप पर आधारित हैं, जिसके कारण पहले प्रकाशित कुछ मौजूदा घटकों के मान और विकास दर में कुछ बदलाव हुए हैं।

1. सूक्ष्म और लघु में विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्योगों को ऋण शामिल है।
2. एनबीएफसी के अंतर्गत एचएफसी, पीएफआई, माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं (एमएफआई), स्वर्ण ऋण से जुड़ी एनबीएफसी और अन्य शामिल हैं।
3. अन्य सेवाओं के अंतर्गत म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी और एमएफ के अलावा बैंकिंग व वित्त तथा अन्य सेवाएं जो सेवाओं के अंतर्गत अन्यत्र नहीं दर्शाए गए हैं।
4. कृषि और उससे सम्बद्ध कार्यकलापों के अंतर्गत प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) भी शामिल है।
5. सूक्ष्म और लघु उद्यमों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण और पीएसएलसी भी शामिल हैं।
6. मध्यम उद्यमों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत मध्यम उद्यमों को ऋण शामिल हैं।
7. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत निर्यात ऋण विदेशी बैंकों से संबंधित हैं।

## सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 26, 2021	2020	2021		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		अप्रै. 24	मार्च 26	अप्रै. 23		
	1	2	3	4	%	%
<b>1 उद्योग (2.1 से 2.19)</b>	<b>2918028</b>	<b>2884372</b>	<b>2918028</b>	<b>2895875</b>	<b>-0.8</b>	<b>0.4</b>
<b>1.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)</b>	<b>46094</b>	<b>43509</b>	<b>46094</b>	<b>44408</b>	<b>-3.7</b>	<b>2.1</b>
<b>1.2 खाद्य प्रसंस्करण</b>	<b>165669</b>	<b>152325</b>	<b>165669</b>	<b>166085</b>	<b>0.3</b>	<b>9.0</b>
1.2.1 चीनी	25552	27362	25552	25233	-1.2	-7.8
1.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	20547	18044	20547	20206	-1.7	12.0
1.2.3 चाय	5512	5192	5512	5451	-1.1	5.0
1.2.4 अन्य	114058	101728	114058	115195	1.0	13.2
<b>1.3 पेय पदार्थ और तंबाकू</b>	<b>15663</b>	<b>16457</b>	<b>15663</b>	<b>15567</b>	<b>-0.6</b>	<b>-5.4</b>
<b>1.4 वस्त्र</b>	<b>201250</b>	<b>190040</b>	<b>201250</b>	<b>204700</b>	<b>1.7</b>	<b>7.7</b>
1.4.1 सूती वस्त्र	91567	87254	91567	90769	-0.9	4.0
1.4.2 जूट से बने वस्त्र	2713	1994	2713	2806	3.4	40.7
1.4.3 मानव-निर्मित वस्त्र	30674	26094	30674	31252	1.9	19.8
1.4.4 अन्य वस्त्र	76295	74698	76295	79873	4.7	6.9
<b>1.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद</b>	<b>11299</b>	<b>10831</b>	<b>11299</b>	<b>11420</b>	<b>1.1</b>	<b>5.4</b>
<b>1.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद</b>	<b>13296</b>	<b>12343</b>	<b>13296</b>	<b>13382</b>	<b>0.6</b>	<b>8.4</b>
<b>1.7 कागज और कागज से बने उत्पाद</b>	<b>35540</b>	<b>31275</b>	<b>35540</b>	<b>35542</b>	<b>0.0</b>	<b>13.6</b>
<b>1.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आणविक इंधन</b>	<b>72323</b>	<b>81636</b>	<b>72323</b>	<b>66085</b>	<b>-8.6</b>	<b>-19.0</b>
<b>1.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद</b>	<b>186911</b>	<b>193202</b>	<b>186911</b>	<b>188929</b>	<b>1.1</b>	<b>-2.2</b>
1.9.1 उर्वरक	32212	35981	32212	33244	3.2	-7.6
1.9.2 औषधि और दवाइयाँ	51138	53199	51138	51905	1.5	-2.4
1.9.3 पेट्रो केमिकल्स	45767	47383	45767	46104	0.7	-2.7
1.9.4 अन्य	57794	56639	57794	57676	-0.2	1.8
<b>1.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद</b>	<b>53494</b>	<b>49763</b>	<b>53494</b>	<b>54312</b>	<b>1.5</b>	<b>9.1</b>
<b>1.11 कांच और कांच के सामान</b>	<b>9124</b>	<b>8412</b>	<b>9124</b>	<b>8741</b>	<b>-4.2</b>	<b>3.9</b>
<b>1.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद</b>	<b>52196</b>	<b>58916</b>	<b>52196</b>	<b>50275</b>	<b>-3.7</b>	<b>-14.7</b>
<b>1.13 मूल धातु और धातु उत्पाद</b>	<b>328663</b>	<b>354085</b>	<b>328663</b>	<b>311702</b>	<b>-5.2</b>	<b>-12.0</b>
1.13.1 लोहा और स्टील	232849	268125	232849	216918	-6.8	-19.1
1.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	95814	85961	95814	94785	-1.1	10.3
<b>1.14 सभी अभियांत्रिकी</b>	<b>147312</b>	<b>154251</b>	<b>147312</b>	<b>147546</b>	<b>0.2</b>	<b>-4.3</b>
1.14.1 इलेक्ट्रानिक्स	32433	29968	32433	33066	2.0	10.3
1.14.2 अन्य	114879	124283	114879	114480	-0.3	-7.9
<b>1.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर</b>	<b>83559</b>	<b>82565</b>	<b>83559</b>	<b>83512</b>	<b>-0.1</b>	<b>1.1</b>
<b>1.16 रत्न और आभूषण</b>	<b>62714</b>	<b>58879</b>	<b>62714</b>	<b>59311</b>	<b>-5.4</b>	<b>0.7</b>
<b>1.17 निर्माण</b>	<b>95511</b>	<b>98980</b>	<b>95511</b>	<b>97414</b>	<b>2.0</b>	<b>-1.6</b>
<b>1.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर</b>	<b>1091624</b>	<b>1055203</b>	<b>1091624</b>	<b>1091207</b>	<b>0.0</b>	<b>3.4</b>
1.18.1 पावर	566455	566556	566455	566660	0.0	0.0
1.18.2 दूरसंचार	113080	139040	113080	114553	1.3	-17.6
1.18.3 सड़क	236947	176536	236947	239136	0.9	35.5
1.18.4 हवाई अड्डा	7327	4507	7327	7392	0.9	64.0
1.18.5 बंदरगाह	7363	11083	7363	7293	-0.9	-34.2
1.18.6 रेलवे	11021	10956	11021	11075	0.5	1.1
1.18.7 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	149432	146526	149432	145098	-2.9	-1.0
<b>1.19 अन्य उद्योग</b>	<b>245786</b>	<b>231699</b>	<b>245786</b>	<b>245736</b>	<b>0.0</b>	<b>6.1</b>

टिप्पणी : जनवरी 2021 से, क्षेत्रीय ऋण डेटा संशोधित प्रारूप पर आधारित हैं, जिसके कारण पहले प्रकाशित कुछ मौजूदा घटकों के मान और विकास दर में कुछ बदलाव हुए हैं।

## सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति								
	2019-20	2020	2021						
		मार्च 27	जन. 01	जन. 15	जन. 29	फर. 12	फर. 29	मार्च 12	मार्च 26
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	32	32	32	32	32	31	32	32	32
<b>1 कुल जमा राशियां (2.1.1.2+2.2.1.2)</b>	<b>124101.8</b>	<b>124101.8</b>	<b>129799.1</b>	<b>127765.4</b>	<b>126732.3</b>	<b>123854.2</b>	<b>124513.6</b>	<b>124623.9</b>	<b>125859.6</b>
2 मांग और मीयादी देयताएं									
<b>2.1 मांग देयताएं</b>	<b>26213.8</b>	<b>26213.8</b>	<b>23521.4</b>	<b>22039.6</b>	<b>21955.8</b>	<b>22090.4</b>	<b>21473.4</b>	<b>23476.0</b>	<b>23736.9</b>
2.1.1 जमा राशियां									
2.1.1.1 अंतर-बैंक	5295.0	5295.0	4029.7	4267.1	3939.0	3845.8	3526.9	4149.0	4896.9
2.1.1.2 अन्य	14,523.6	14523.6	14236.5	13447.2	13869.6	12868.6	13379.6	13534.2	13899.4
2.1.2 बैंकों से उधार	100.0	100.0	0.0	0.0	342.5	199.9	353.0	305.0	0.0
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	6295.2	6295.2	5255.2	4325.3	3804.7	5176.0	4214.0	5487.8	4940.6
<b>2.2 मीयादी देयताएं</b>	<b>167684.5</b>	<b>167684.5</b>	<b>176086.7</b>	<b>176871.2</b>	<b>175205.9</b>	<b>172658.6</b>	<b>173903.3</b>	<b>173607.0</b>	<b>179957.5</b>
2.2.1 जमा राशियां									
2.2.1.1 अंतर-बैंक	56564.0	56564.0	58778.8	59552.0	59535.3	59971.1	59862.2	60817.7	65333.7
2.2.1.2 अन्य	109578.2	109578.2	115562.6	114318.2	112862.8	110985.6	111134.0	111089.7	111960.2
2.2.2 बैंकों से उधार	630.2	630.2	629.9	629.9	629.9	629.9	629.9	630.0	630.0
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	912.1	912.1	1115.4	2371.1	2177.8	1072.0	2277.1	1069.7	2033.7
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	35.0	0.0	0.0
4 अधिसूचित बैंक/राज्य सरकार से उधार	52772.2	52772.2	59754.7	59935.9	57881.3	61288.4	60792.5	61034.1	63559.8
4.1 मांग	13764.4	13764.4	13117.3	13543.8	13137.7	14160.3	14579.3	14357.8	15691.8
4.2 मीयादी	39007.8	39007.8	46637.4	46392.1	44743.5	47128.1	46213.1	46676.3	47868.0
<b>5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष</b>	<b>9428.2</b>	<b>9428.2</b>	<b>7579.7</b>	<b>7371.9</b>	<b>8310.8</b>	<b>6961.7</b>	<b>6871.4</b>	<b>6860.3</b>	<b>8151.1</b>
5.1 उपलब्ध नकदी	750.5	750.5	619.1	615.5	591.6	620.0	572.5	576.7	570.3
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	8677.8	8677.8	6960.6	6756.4	7719.2	6341.7	6298.9	6283.6	7580.8
<b>6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेष</b>	<b>1521.7</b>	<b>1521.7</b>	<b>933.4</b>	<b>881.9</b>	<b>871.6</b>	<b>795.0</b>	<b>834.6</b>	<b>958.3</b>	<b>1148.1</b>
<b>7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश</b>	<b>50626.9</b>	<b>50626.9</b>	<b>61168.7</b>	<b>61387.5</b>	<b>60775.8</b>	<b>60358.3</b>	<b>61913.1</b>	<b>61655.6</b>	<b>64455.2</b>
<b>8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा</b>	<b>25283.9</b>	<b>25283.9</b>	<b>27501.0</b>	<b>27428.4</b>	<b>25277.1</b>	<b>25868.3</b>	<b>26344.9</b>	<b>25950.4</b>	<b>28835.7</b>
<b>9 बैंक ऋण (10.1+11)</b>	<b>110905.5</b>	<b>110905.5</b>	<b>110706.8</b>	<b>112016.2</b>	<b>112134.6</b>	<b>113201.7</b>	<b>114409.0</b>	<b>113732.4</b>	<b>114631.6</b>
10 अग्रिम									
<b>10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट</b>	<b>110901.5</b>	<b>110901.5</b>	<b>110687.5</b>	<b>111996.9</b>	<b>112115.1</b>	<b>113182.1</b>	<b>114389.5</b>	<b>113712.9</b>	<b>114612.1</b>
10.2 बैंकों से प्राप्य राशि	81300.1	81300.1	88502.4	88603.4	88670.2	90417.9	91887.8	86925.5	89429.1
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	4.0	4.0	19.3	19.4	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5



# मूल्य और उत्पादन

## सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)

समूह/उप समूह	2020-21			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	अप्रै. '20	मार्च'21	अप्रै.'21(अ)	अप्रै.'20	मार्च'21	अप्रै.'21(अ)	अप्रै.'20	मार्च'21	अप्रै.'21(अ)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1 खाद्य और पेय पदार्थ</b>	<b>156.7</b>	<b>161.1</b>	<b>158.3</b>	<b>152.8*</b>	<b>154.5</b>	<b>155.8</b>	<b>156.1*</b>	<b>160.4</b>	<b>162.0</b>	<b>154.0*</b>	<b>156.7</b>	<b>158.1</b>
1.1 अनाज और उत्पाद	145.4	149.9	146.8	147.2	142.5	142.8	151.8	147.5	147.6	148.7	144.1	144.3
1.2 मांस और मछली	185.2	192.4	187.7	168.9*	189.4	195.5	171.3*	197.5	202.5	169.7*	192.2	198.0
1.3 अंडा	160.3	164.8	162.0	146.9	163.2	163.3	151.9	164.7	166.5	148.8	163.8	164.5
1.4 दूध और उत्पाद	154.1	154.4	154.2	155.6	154.5	155.0	155.5	155.6	156.0	155.6	154.9	155.4
1.5 तेल और चर्बी	148.2	139.9	145.2	137.1	168.2	175.2	131.6	156.4	161.4	135.1	163.9	170.1
1.6 फल	146.9	153.4	149.9	147.3	150.5	160.9	152.9	157.3	168.8	149.9	153.7	164.6
1.7 सब्जी	174.2	196.2	181.7	162.7	141.0	135.9	180.0	166.1	161.8	168.6	149.5	144.7
1.8 दाल और उत्पाद	154.4	156.0	154.9	150.2	159.2	161.1	150.8	161.1	162.9	150.4	159.8	161.7
1.9 चीनी और उत्पाद	114.4	117.0	115.3	119.8	111.7	112.3	121.2	114.3	114.8	120.3	112.6	113.1
1.10 मसाले	161.9	160.4	161.4	158.7	164.0	164.4	154.0	162.6	162.8	157.1	163.5	163.9
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	149.8	141.3	146.3	139.2	160.6	161.9	133.5	150.7	151.5	136.8	156.5	157.6
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	163.2	165.5	164.3	162.1*	166.4	166.8	162.7*	170.3	171.4	162.4*	168.2	168.9
<b>2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ</b>	<b>181.8</b>	<b>188.7</b>	<b>183.6</b>	<b>171.1*</b>	<b>186.1</b>	<b>186.9</b>	<b>179.1*</b>	<b>193.5</b>	<b>194.0</b>	<b>173.2*</b>	<b>188.1</b>	<b>188.8</b>
<b>3 कपड़ा और जूते</b>	<b>155.6</b>	<b>149.7</b>	<b>153.3</b>	<b>153.1*</b>	<b>158.9</b>	<b>159.9</b>	<b>150.4*</b>	<b>152.6</b>	<b>153.4</b>	<b>152.0*</b>	<b>156.4</b>	<b>157.3</b>
3.1 कपड़ा	156.4	152.0	154.7	153.9*	159.6	160.7	152.6*	155.1	155.9	153.4*	157.8	158.8
3.2 जूते	151.1	137.2	145.3	148.1*	154.4	155.1	138.3*	138.7	139.4	144.0*	147.9	148.6
<b>4 आवास</b>	--	<b>157.2</b>	<b>157.2</b>	--	--	--	<b>155.6</b>	<b>159.9</b>	<b>161.4</b>	<b>155.6</b>	<b>159.9</b>	<b>161.4</b>
<b>5 ईंधन और लाइट</b>	<b>149.1</b>	<b>140.9</b>	<b>146.0</b>	<b>148.4*</b>	<b>156.0</b>	<b>156.0</b>	<b>137.1</b>	<b>154.8</b>	<b>154.7</b>	<b>144.1</b>	<b>155.5</b>	<b>155.5</b>
<b>6 विविध</b>	<b>153.9</b>	<b>146.1</b>	<b>150.2</b>	<b>148.4*</b>	<b>157.3</b>	<b>158.1</b>	<b>142.5*</b>	<b>150.0</b>	<b>150.7</b>	<b>145.5*</b>	<b>153.8</b>	<b>154.5</b>
6.1 घरेलू सामान और सेवा	152.9	145.2	149.3	152.0*	154.8	155.6	145.5*	147.2	147.8	148.9*	151.2	151.9
6.2 स्वास्थ्य	160.3	151.3	156.9	154.3*	164.6	165.4	144.8	156.9	157.6	150.7	161.7	162.4
6.3 परिवहन और संचार	144.9	135.0	139.7	136.3*	151.3	151.8	128.7*	141.7	142.4	132.3*	146.2	146.9
6.4 मनोरंजन	154.0	144.3	148.5	151.7*	157.8	158.5	142.5*	148.6	149.2	146.5*	152.6	153.3
6.5 शिक्षा	162.5	156.2	158.9	161.7*	163.8	164.1	157.6*	157.6	158.3	159.3*	160.2	160.7
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव	153.7	155.8	154.5	145.6*	153.1	154.6	150.1*	154.9	156.6	147.5*	153.8	155.4
<b>सामान्य सूचकांक (सभी समूह)</b>	<b>156.1</b>	<b>154.4</b>	<b>155.3</b>	<b>151.9*</b>	<b>156.7</b>	<b>157.7</b>	<b>150.9*</b>	<b>156.9</b>	<b>158.1</b>	<b>151.4*</b>	<b>156.8</b>	<b>157.9</b>

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

अ: अनंतिम

## सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2020-21	2020		2021	
				अप्रै.	मार्च	अप्रै.	मार्च
	1	2	3	4	5	6	7
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2016	2.88	--	--	119.6	120.1	
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	1034	1014	1035	1041	
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	--	1040	1019	1043	1049	

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

## सं. 20: मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2020-21	2020		2021	
		अप्रै.	मार्च	अप्रै.	मार्च
	1	2	3	4	
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	48723	45504	44648	46517	
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	59283	42058	65981	67528	

स्रोत: मुंबई में सोने और चांदी के मूल्य के लिए भारत बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि., मुंबई।

**सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक**  
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2020-21	2020	2021		
				अप्रै.	फर.	मार्च (अ)
	1	2	3	4	5	6
<b>1 सभी पण्य</b>	<b>100.000</b>	<b>123.3</b>	<b>119.2</b>	<b>128.1</b>	<b>129.3</b>	<b>131.7</b>
<b>1.1 प्राथमिक वस्तुएं</b>	<b>22.618</b>	<b>145.6</b>	<b>137.8</b>	<b>147.1</b>	<b>146.2</b>	<b>151.8</b>
<b>1.1.1 खाद्य वस्तुएं</b>	<b>15.256</b>	<b>160.7</b>	<b>154.5</b>	<b>157.5</b>	<b>156.1</b>	<b>162.1</b>
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+ दाल)	3.462	159.3	161.8	157.4	158.1	160.6
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	179.2	161.4	160.5	154.7	172.8
1.1.1.3 दूध	4.440	153.4	151.6	154.9	155.2	154.7
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	151.1	146.2	154.7	154.7	162.1
1.1.1.5 मसाले	0.529	149.5	147.1	151.5	151.9	150.7
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	161.7	141.8	169.3	164.2	169.7
<b>1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं</b>	<b>4.119</b>	<b>130.4</b>	<b>123.9</b>	<b>137.0</b>	<b>139.5</b>	<b>143.2</b>
1.1.2.1 फाइबर	0.839	119.8	121.4	130.6	132.5	133.2
1.1.2.2 तिलहन	1.115	161.7	150.6	175.3	185.0	195.7
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	109.0	105.0	113.9	115.2	115.5
1.1.2.4 फूल	0.204	210.0	169.9	176.7	154.2	163.0
<b>1.1.3 खनिज</b>	<b>0.833</b>	<b>163.6</b>	<b>154.1</b>	<b>184.3</b>	<b>172.8</b>	<b>184.3</b>
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	158.1	145.1	183.7	168.3	183.8
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	183.0	185.7	186.2	188.5	186.2
<b>1.1.4 कच्चा तेल और नैसर्गिक गैस</b>	<b>2.410</b>	<b>70.1</b>	<b>49.9</b>	<b>85.6</b>	<b>85.5</b>	<b>89.6</b>
<b>1.2 ईंधन और बिजली</b>	<b>13.152</b>	<b>94.0</b>	<b>89.8</b>	<b>105.7</b>	<b>109.7</b>	<b>108.6</b>
<b>1.2.1 कोल</b>	<b>2.138</b>	<b>126.6</b>	<b>126.5</b>	<b>126.9</b>	<b>126.9</b>	<b>127.3</b>
1.2.1.1 कुकिंग कोल	0.647	141.8	141.9	141.9	141.9	141.9
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोल	1.401	119.3	119.0	119.8	119.8	119.8
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	130.9	131.1	129.9	129.9	138.1
<b>1.2.2 खनिज तेल</b>	<b>7.950</b>	<b>79.1</b>	<b>70.6</b>	<b>95.3</b>	<b>102.3</b>	<b>102.6</b>
<b>1.2.3 बिजली</b>	<b>3.064</b>	<b>110.1</b>	<b>113.9</b>	<b>117.6</b>	<b>116.9</b>	<b>111.1</b>
<b>1.3 विनिर्मित उत्पाद</b>	<b>64.231</b>	<b>121.5</b>	<b>118.7</b>	<b>126.0</b>	<b>127.3</b>	<b>129.4</b>
<b>1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण</b>	<b>9.122</b>	<b>141.3</b>	<b>136.3</b>	<b>146.6</b>	<b>148.8</b>	<b>153.5</b>
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	137.0	136.2	137.8	138.8	141.6
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियस, मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	139.0	132.0	144.5	145.2	143.5
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	120.2	116.2	121.7	121.6	121.5
1.3.1.4 सब्जियाँ और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	143.3	126.4	164.4	170.8	181.1
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	146.8	151.1	146.4	147.0	149.5
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	143.5	146.4	141.8	141.6	142.1
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	115.8	127.0	118.0	119.4	120.7
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	138.1	136.6	139.3	139.4	140.2
1.3.1.9 चीनी, गुड़ और शहद	1.163	118.4	118.4	116.7	117.0	118.5
1.3.1.10 कोक, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	127.8	127.8	127.6	126.3	126.4
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	132.3	126.3	132.2	135.6	131.5
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	165.9	138.1	152.1	156.2	170.9
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	147.1	144.0	150.5	150.3	153.1
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	132.0	133.1	134.8	134.8	136.5
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	142.8	151.3	139.3	137.5	141.7
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	170.4	166.1	175.4	178.4	186.3
<b>1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण</b>	<b>0.909</b>	<b>124.5</b>	<b>125.0</b>	<b>124.6</b>	<b>125.3</b>	<b>125.5</b>
1.3.2.1 शराब और स्पिरीट	0.408	120.2	119.8	120.1	121.2	121.2
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	126.4	127.6	125.8	127.1	128.9
1.3.2.3 शीतल पेय, मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी के अन्य उत्पाद	0.275	129.4	130.7	130.4	129.8	129.0
<b>1.3.3 विनिर्मित तंबाकू उत्पाद</b>	<b>0.514</b>	<b>157.2</b>	<b>156.4</b>	<b>159.0</b>	<b>157.8</b>	<b>160.3</b>
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	157.2	156.4	159.0	157.8	160.3

**सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)**  
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2020-21	2020	2021		
			अप्रै.	फर.	मार्च (अ)	अप्रै. (अ)
<b>1.3.4 वस्त्र विनिर्माण</b>	<b>4.881</b>	<b>117.6</b>	<b>117.0</b>	<b>124.9</b>	<b>127.1</b>	<b>128.4</b>
1.3.4.1 धागों की कताई और वस्त्र तैयार करना	2.582	106.5	105.7	117.0	119.6	120.8
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	131.7	131.5	136.2	138.7	140.0
1.3.4.3 बुने हुए और क्रॉचिडेट फेब्रिक्स	0.193	115.0	113.1	116.4	117.6	121.5
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	132.3	133.0	132.9	133.5	134.2
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	155.6	147.3	165.1	167.1	169.2
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	116.3	117.3	117.6	116.8	118.0
<b>1.3.5 विनिर्मित तैयार वस्त्र</b>	<b>0.814</b>	<b>138.5</b>	<b>138.9</b>	<b>139.6</b>	<b>139.4</b>	<b>139.7</b>
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर वुलन के तैयार वस्त्र	0.593	138.1	139.0	138.5	138.3	138.3
1.3.5.2 बुने हुए क्रॉचिडेट वस्त्र	0.221	139.8	138.6	142.8	142.4	143.5
<b>1.3.6 चमड़ा और उससे बने हुए उत्पाद का विनिर्माण</b>	<b>0.535</b>	<b>117.9</b>	<b>117.7</b>	<b>116.7</b>	<b>116.7</b>	<b>118.3</b>
1.3.6.1 चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगायी	0.142	100.9	104.1	94.6	94.7	97.7
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और दोहन	0.075	138.6	138.3	139.3	139.8	140.2
1.3.6.3 जूते-चप्पल	0.318	120.5	119.0	121.2	121.0	122.3
<b>1.3.7 लकड़ी के विनिर्माण और लकड़ी और कॉर्क के उत्पाद</b>	<b>0.772</b>	<b>134.6</b>	<b>132.6</b>	<b>136.2</b>	<b>137.4</b>	<b>138.2</b>
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	120.7	119.8	121.3	123.4	123.0
1.3.7.2 विनियर शीट, प्लायवुड का विनिर्माण, लॅमिन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और अन्य पॅनल और बोर्ड	0.493	136.6	134.8	138.1	139.4	140.3
1.3.7.3 बिल्डरों की बढ़ईगीरी	0.036	185.8	177.3	190.4	191.3	191.3
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	125.5	123.4	127.8	127.6	129.3
<b>1.3.8 कागज और कागज के उत्पाद का विनिर्माण</b>	<b>1.113</b>	<b>121.5</b>	<b>120.6</b>	<b>125.7</b>	<b>128.2</b>	<b>133.5</b>
1.3.8.1 लुगदी, कागज और कागज बोर्ड	0.493	124.0	123.5	128.8	133.9	138.1
1.3.8.2 लहरदार कागज और पेपर बोर्ड और कागज के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	121.8	116.6	128.9	126.3	134.1
1.3.8.3 कागज की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	117.3	120.0	117.5	121.1	125.5
<b>1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन</b>	<b>0.676</b>	<b>153.8</b>	<b>150.8</b>	<b>155.1</b>	<b>153.2</b>	<b>153.0</b>
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	153.8	150.8	155.1	153.2	153.0
<b>1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण</b>	<b>6.465</b>	<b>118.2</b>	<b>115.2</b>	<b>123.1</b>	<b>125.0</b>	<b>127.0</b>
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	118.5	115.4	127.2	128.3	131.5
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	123.5	123.4	124.0	124.4	125.3
1.3.10.3 प्लास्टिक और सिंथेटिक रबड़ प्राथमिक रूप में	1.001	116.6	106.2	128.7	135.0	138.9
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रोकैमिकल उत्पाद	0.454	124.4	120.3	125.2	125.6	128.3
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	115.0	113.2	118.0	120.0	120.4
1.3.10.6 साबुन और डिटर्जेंट, सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	120.6	118.0	122.4	122.3	123.3
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	115.1	114.6	118.1	120.0	121.7
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	93.6	95.4	99.1	102.7	102.2
<b>1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण</b>	<b>1.993</b>	<b>130.9</b>	<b>130.3</b>	<b>132.8</b>	<b>132.9</b>	<b>134.3</b>
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	130.9	130.3	132.8	132.9	134.3
<b>1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद का विनिर्माण</b>	<b>2.299</b>	<b>111.2</b>	<b>107.3</b>	<b>116.3</b>	<b>119.0</b>	<b>121.4</b>
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब, रबड़ टायर की रीट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	98.3	98.1	98.9	100.0	102.3
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	93.3	92.8	95.4	97.0	98.2
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	120.2	114.1	127.8	131.3	134.0
<b>1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण</b>	<b>3.202</b>	<b>117.6</b>	<b>117.8</b>	<b>117.9</b>	<b>119.5</b>	<b>120.8</b>
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	127.2	122.4	129.6	130.4	132.1
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	109.3	107.3	111.1	111.8	113.8
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	109.3	107.7	111.2	112.2	114.1
1.3.13.4 चीनी मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी	0.222	109.5	111.8	111.3	112.0	114.4
1.3.13.5 सीमेन्ट, चूना और प्लास्टर	1.645	120.8	122.6	119.8	122.5	123.9

**सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)**  
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2020-21	2020	2021		
			अप्रै.	फर.	मार्च (अ)	अप्रै. (अ)
1.3.13.6 कंक्रीट,सीमेन्ट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	125.3	123.0	126.7	126.4	127.1
1.3.13.7 पत्थरों को काटना,आकार देना और संवारना	0.234	121.1	121.5	123.2	123.5	123.0
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	78.9	77.6	79.9	79.6	79.6
<b>1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण</b>	<b>9.646</b>	<b>111.4</b>	<b>107.0</b>	<b>121.1</b>	<b>123.6</b>	<b>127.6</b>
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	109.1	113.1	121.2	124.7	133.1
1.3.14.2 मेटेलिक आयसन	0.653	113.3	111.1	124.6	129.1	135.5
1.3.14.3 नरम इस्पात-अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	99.7	96.3	105.6	109.7	112.4
1.3.14.4 नरम इस्पात- लंबे उत्पाद	1.081	112.0	106.2	124.7	124.6	127.1
1.3.14.5 नरम इस्पात- चपटे उत्पाद	1.144	117.2	105.1	134.4	133.2	143.6
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	108.2	101.6	119.1	121.6	125.0
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील अर्ध निर्मित	0.924	108.6	102.0	118.0	124.8	125.1
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	127.9	125.3	137.5	141.6	139.6
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	112.3	104.9	120.8	123.6	125.2
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	109.0	106.9	111.8	112.2	112.9
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	145.7	145.2	146.1	148.3	150.1
<b>1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण</b>	<b>3.155</b>	<b>115.9</b>	<b>114.8</b>	<b>120.7</b>	<b>120.9</b>	<b>122.3</b>
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	114.0	112.9	118.6	118.5	119.9
1.3.15.2 धातु से बने टैंक,जलाशय और डिब्बे	0.660	127.7	124.5	138.8	138.6	139.1
1.3.15.3 बाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलरर्स को छोड़कर	0.145	98.9	107.7	97.2	97.2	96.8
1.3.15.4 धातु की फोर्जिंग, दबाना, स्टैपिंग और रोल फॉर्मिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	96.6	98.9	97.5	97.8	102.0
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	102.9	100.8	104.2	106.5	106.7
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	124.9	122.6	128.8	129.3	130.6
<b>1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण</b>	<b>2.009</b>	<b>109.8</b>	<b>109.9</b>	<b>111.1</b>	<b>111.4</b>	<b>111.9</b>
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	99.1	98.2	100.5	101.0	102.6
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	134.8	135.0	134.4	134.5	134.5
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	114.9	115.1	115.0	116.4	116.3
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	0.641	98.6	98.0	102.4	102.4	102.4
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	107.7	111.0	106.1	106.1	107.2
1.3.16.6 हाथ घड़ी और दीवार घड़ी	0.076	141.8	141.1	141.6	141.9	141.8
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	102.7	104.3	102.7	101.5	102.2
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	102.6	112.2	94.9	95.5	95.9
<b>1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण</b>	<b>2.930</b>	<b>113.4</b>	<b>110.3</b>	<b>116.9</b>	<b>116.7</b>	<b>118.2</b>
1.3.17.1 विद्युतमोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण	1.298	112.8	108.7	116.6	114.9	116.4
1.3.17.2 बैटरी और एक्युमुलेटर	0.236	117.1	117.0	117.3	116.3	117.5
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	98.1	99.4	99.9	100.1	102.2
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के वायर और केबल	0.428	115.8	108.3	124.4	127.9	130.1
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	111.1	111.1	111.8	111.8	112.4
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	119.7	118.1	122.9	123.5	125.5
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	109.4	109.4	109.5	110.4	110.2
<b>1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण</b>	<b>4.789</b>	<b>114.0</b>	<b>113.0</b>	<b>115.4</b>	<b>116.3</b>	<b>116.6</b>
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन, एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	106.3	104.7	110.2	110.7	112.3
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	119.3	119.9	119.5	119.8	120.3
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	111.6	111.9	112.2	113.6	114.4
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गैयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	111.8	113.6	112.9	112.5	114.0
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर	0.008	81.1	81.0	71.4	81.9	72.1
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने-उतारने वाले उपकरण	0.285	113.4	111.2	115.2	115.6	116.4

**सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (समाप्त)**  
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2020-21	2020	2021		
				अप्रै.	फर.	मार्च (अ)
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	128.7	128.4	128.1	130.8	131.1
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	121.6	121.6	122.4	122.7	122.7
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	108.4	109.6	107.3	108.7	109.5
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	75.8	75.0	76.6	76.8	76.8
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	127.9	119.3	128.2	130.2	128.1
1.3.18.13 कपड़ा, परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	122.3	119.2	125.9	124.9	125.4
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	128.8	125.7	131.5	133.9	132.9
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	65.2	64.3	66.2	66.3	66.4
<b>1.3.19 मोटर वाहन, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण</b>	<b>4.969</b>	<b>117.8</b>	<b>115.0</b>	<b>119.6</b>	<b>120.0</b>	<b>120.1</b>
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	119.4	115.4	121.5	121.6	121.4
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	116.1	114.5	117.4	118.2	118.5
<b>1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण</b>	<b>1.648</b>	<b>126.2</b>	<b>120.5</b>	<b>128.8</b>	<b>128.7</b>	<b>128.9</b>
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली -वस्तुओं का निर्माण	0.117	158.8	158.8	158.9	158.9	158.8
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टॉक	0.110	105.0	105.2	104.6	104.0	104.0
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	124.7	117.6	127.7	127.5	127.7
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाड़ी	0.117	130.3	128.2	134.5	134.5	135.2
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	128.5	127.4	131.2	132.6	132.7
<b>1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण</b>	<b>0.727</b>	<b>133.0</b>	<b>132.3</b>	<b>138.1</b>	<b>139.7</b>	<b>141.9</b>
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	133.0	132.3	138.1	139.7	141.9
<b>1.3.22 अन्य विनिर्माण</b>	<b>1.064</b>	<b>132.4</b>	<b>120.0</b>	<b>137.4</b>	<b>134.5</b>	<b>133.7</b>
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	130.6	117.6	135.8	132.7	131.8
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	173.7	174.5	189.7	192.3	192.3
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	132.0	130.8	134.2	134.2	135.9
1.3.22.4 खेल और खिलौने	0.005	142.2	137.0	144.1	144.2	146.9
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और सामग्री	0.049	167.4	163.2	168.8	168.8	169.8
<b>2 खाद्य सूचकांक</b>	<b>24.378</b>	<b>153.4</b>	<b>147.7</b>	<b>153.4</b>	<b>153.4</b>	<b>158.9</b>

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

## सं. 22: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)

उद्योग	भारत	2019-20	2020-21	अप्रैल- मार्च		मार्च	
				2019-20	2020-21	2020	2021
				1	2	3	4
सामान्य सूचकांक	100.00	129.0	117.9	129.0	117.9	117.2	143.4
<b>1 क्षेत्रवार वर्गीकरण</b>							
1.1 खनन	14.37	109.6	101.0	109.6	101.0	131.0	139.0
1.2 विनिर्माण	77.63	129.6	116.9	129.6	116.9	111.6	140.4
1.3 बिजली	7.99	158.4	157.6	158.4	157.6	146.9	180.0
<b>2 उपयोग आधारित वर्गीकरण</b>							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	127.0	118.1	127.0	118.1	134.4	144.8
2.2 पूंजीगत माल	8.22	93.3	75.4	93.3	75.4	72.6	103.0
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	137.7	124.4	137.7	124.4	125.7	152.3
2.4 बुनियादी/निर्माण वस्तुएं	12.34	136.6	124.2	136.6	124.2	117.6	154.3
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	119.0	100.9	119.0	100.9	83.2	128.9
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	145.3	141.9	145.3	141.9	121.7	155.2

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

## सरकारी लेखा और खज़ाना बिल

## सं. 23: केन्द्र सरकार का लेखा - एक नज़र में

(करोड़ ₹)

मद	2021-22			2020-21		
	बजट आकलन	अप्रैल 2021		अंतिम लेखा	संशोधित आकलन	अंतिम लेखा संशोधित आकलनों का प्रतिशत
		वास्तविक	बजट आकलनों का प्रतिशत			
	1	2	3	4	5	6
<b>1 राजस्व प्राप्ति</b>	<b>1788424</b>	<b>147619</b>	<b>8.3</b>	<b>1632094</b>	<b>1555153</b>	<b>104.9</b>
1.1 कर राजस्व (निवल)	1545396	130811	8.5	1424035	1344501	105.9
1.2 करेतर राजस्व	243028	16808	6.9	208059	210652	98.8
<b>2 गैरेतर ऋण पूंजीगत प्राप्ति</b>	<b>188000</b>	<b>372</b>	<b>0.2</b>	<b>57626</b>	<b>46497</b>	<b>123.9</b>
2.1 ऋण की वसूली	13000	372	2.9	19729	14497	136.1
2.2 अन्य प्राप्ति	175000	0	0.0	37897	32000	118.4
<b>3 कुल प्राप्ति (उधारियों को छोड़कर) (1+2)</b>	<b>1976424</b>	<b>147991</b>	<b>7.5</b>	<b>1689720</b>	<b>1601650</b>	<b>105.5</b>
<b>4 राजस्व व्यय</b>	<b>2929000</b>	<b>179564</b>	<b>6.1</b>	<b>3086360</b>	<b>3011142</b>	<b>102.5</b>
जिसमें से						
4.1 ब्याज भुगतान	809701	29671	3.7	682079	692900	98.4
5 पूंजी व्यय	554236	47126	8.5	424821	439163	96.7
<b>6 कुल व्यय (4+5)</b>	<b>3483236</b>	<b>226690</b>	<b>6.5</b>	<b>3511181</b>	<b>3450305</b>	<b>101.8</b>
<b>7 राजस्व घाटा (4-1)</b>	<b>1140576</b>	<b>31945</b>	<b>2.8</b>	<b>1454266</b>	<b>1455989</b>	<b>99.9</b>
<b>8 राजकोषीय घाटा (6-3)</b>	<b>1506812</b>	<b>78699</b>	<b>5.2</b>	<b>1821461</b>	<b>1848655</b>	<b>98.5</b>
<b>9 सकल प्राथमिक घाटा (8-4.1)</b>	<b>697111</b>	<b>49028</b>	<b>7.0</b>	<b>1139382</b>	<b>1155755</b>	<b>98.6</b>

स्रोत : महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

## सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(करोड़ ₹)

मद	2020-21	2020	2021					
		मई 1	मार्च 26	अप्रै. 2	अप्रै. 9	अप्रै. 16	अप्रै. 23	अप्रै. 30
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1 91-दिवसीय</b>								
1.1 बैंक	5676	24299	5676	3732	5468	4968	4435	4289
1.2 प्राथमिक व्यापारी	16740	25088	16740	15958	13155	15239	15659	16736
1.3 राज्य सरकारें	13347	8177	13347	13043	19838	19875	23875	22875
1.4 अन्य	52802	57937	52802	51304	64895	74282	85715	95761
<b>2 182-दिवसीय</b>								
2.1 बैंक	67473	67800	67473	74562	82491	89113	86910	87003
2.2 प्राथमिक व्यापारी	30966	43375	30966	32131	36403	36314	32470	30415
2.3 राज्य सरकारें	9436	13884	9436	9436	9440	9843	9843	9843
2.4 अन्य	31800	68631	31800	32251	33560	38616	53440	67050
<b>3 364-दिवसीय</b>								
3.1 बैंक	119024	60996	119024	117218	110113	113904	116805	121312
3.2 प्राथमिक व्यापारी	154197	68460	154197	164746	156343	156173	156321	159149
3.3 राज्य सरकारें	18510	12779	18510	18505	16990	18090	18090	18090
3.4 अन्य	174501	102375	174501	164872	180020	175394	164571	151602
<b>4 14-दिवसीय मध्यवर्ती</b>								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	220351	135529	220351	192716	151862	140648	175292	163969
4.4 अन्य	747	465	747	346	650	907	298	205
<b>कुल खज़ाना बिल</b>								
<b>(14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#</b>	694471	553801	694471	697756	728717	751812	768134	784125

# 14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं है। यह बिल स्वरूप के अनुसार मध्यवर्ती हैं क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए परिसमाप्त किए जाते हैं।

## सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(राशि करोड़ ₹ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियाँ				स्वीकृत बोलियाँ				कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या	कुल अंकित मूल्य						
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी		प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>91-दिवसीय खज़ाना बिल</b>												
<b>2020-21</b>												
मार्च 30	4000	68	22440	16	13	3984	16	4000	99.18	3.3162		
<b>2021-22</b>												
अप्रै. 7	15000	128	58843	7704	41	14996	7704	22700	99.17	3.3505		
अप्रै. 12	15000	98	53870	2000	35	15000	2000	17000	99.17	3.3496		
अप्रै. 20	15000	91	59916	6805	20	14995	6805	21800	99.17	3.3382		
अप्रै. 28	15000	104	56595	4035	29	14996	4035	19030	99.18	3.3199		
<b>182-दिवसीय खज़ाना बिल</b>												
<b>2020-21</b>												
मार्च 30	7000	75	21388		17	7000		7000	98.30	3.4683		
<b>2021-22</b>												
अप्रै. 7	15000	111	36565	12	69	14988	12	15000	98.24	3.5906		
अप्रै. 12	15000	138	44570	425	65	15000	425	15425	98.23	3.6085		
अप्रै. 20	15000	190	95960	0	14	15000	0	15000	98.27	3.5281		
अप्रै. 28	15000	166	83278	5	13	14995	5	15000	98.31	3.4507		
<b>364-दिवसीय खज़ाना बिल</b>												
<b>2020-21</b>												
मार्च 30	8000	102	24475		57	8000		8000	96.32	3.8264		
<b>2021-22</b>												
अप्रै. 7	6000	117	30450	405	9	6000	405	6405	96.41	3.7393		
अप्रै. 12	6000	93	24065	1115	24	6000	1115	7115	96.39	3.7600		
अप्रै. 20	6000	112	25295	0	28	6000	0	6000	96.40	3.7500		
अप्रै. 28	6000	129	26257	0	27	6000	0	6000	96.42	3.7200		

## वित्तीय बाजार

## सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार	दरों का दायरा		भारित औसत दरें
	उधार लेना/उधार देना		उधार लेना/उधार देना
	1	2	2
अप्रै. 3, 2021	2.60-3.35		3.15
अप्रै. 5, 2021	1.90-3.50		3.12
अप्रै. 6, 2021	2.10-3.50		3.13
अप्रै. 7, 2021	1.90-3.50		3.14
अप्रै. 8, 2021	1.90-3.50		3.13
अप्रै. 9, 2021	1.90-3.57		3.15
अप्रै. 12, 2021	1.90-3.50		3.21
अप्रै. 15, 2021	1.90-3.50		3.20
अप्रै. 16, 2021	1.90-3.50		3.23
अप्रै. 17, 2021	2.40-3.00		2.78
अप्रै. 19, 2021	1.90-3.50		3.22
अप्रै. 20, 2021	1.90-3.50		3.23
अप्रै. 22, 2021	1.90-3.50		3.24
अप्रै. 23, 2021	1.90-3.50		3.22
अप्रै. 26, 2021	1.90-3.50		3.20
अप्रै. 27, 2021	1.90-3.50		3.20
अप्रै. 28, 2021	1.90-3.50		3.21
अप्रै. 29, 2021	1.90-3.50		3.22
अप्रै. 30, 2021	1.90-3.50		3.22
मई 3, 2021	1.90-3.50		3.21
मई 4, 2021	1.90-3.50		3.19
मई 5, 2021	1.90-3.50		3.24
मई 6, 2021	1.90-3.50		3.24
मई 7, 2021	1.90-3.50		3.22
मई 10, 2021	1.90-3.50		3.24
मई 11, 2021	1.90-3.50		3.21
मई 12, 2021	1.90-3.50		3.22
मई 14, 2021	1.90-3.50		3.27
मई 15, 2021	2.60-3.50		3.06

टिप्पणी: नोटिस मुद्रा सहित



## सं. 27: जमा प्रमाण-पत्र

मद	2020	2021			
	अप्रै. 24	मार्च 12	मार्च 26	अप्रै. 9	अप्रै. 23
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	180891.00	58304.34	80621.98	88675.73	85792.41
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (करोड़ ₹)	4539.49	11372.63	25590.02	8053.75	764.84
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	4.70-7.84	3.26-5.00	3.28-5.12	3.28-4.99	3.91-4.56

## सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2020	2021			
	अप्रै. 30	मार्च 15	मार्च 31	अप्रै. 15	अप्रै. 30
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	417227.05	403442.70	364374.30	382838.15	374846.75
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (करोड़ ₹)	77889.20	127121.00	96417.25	35737.15	53838.60
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	3.78-10.45	3.16-12.52	3.32-13.37	3.17-13.09	3.21-13.02

## सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक कारोबार

(करोड़ ₹)

मद	2020-21	2020	2021					
		मई 1	मार्च 26	अप्रै. 2	अप्रै. 9	अप्रै. 16	अप्रै. 23	अप्रै. 30
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	17461	17270	25647	11866	17996	13048	18580	22573
2 नोटिस मुद्रा	2604	7628	575	10041	969	8195	813	735
3 मीयादी मुद्रा	757	1569	504	359	389	380	1105	506
4 त्रिपक्षीय रिपो	421118	384319	462956	563143	524160	680085	510435	610198
5 बाजार रिपो	337341	307946	358990	379903	385947	432278	388758	420038
6 कापॉरेट बांड में रिपो	2990	2725	9399	160	2606	11537	2883	7742
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	67793	49987	90158	102809	75647	84678	72943	73580
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	62490	75189	55985	40682	63756	53920	57594	52896
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	5080	4767	7252	7046	8492	9267	7780	7340
10 खजाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	4970	4895	5756	3946	8122	6853	5687	2484
10.2 182-दिवसीय	4870	9433	2971	1383	3756	8482	10895	8363
10.3 364-दिवसीय	4010	9440	11791	16492	10371	7182	6099	2653
10.4 नकदी प्रबंधन बिल	1490	1225						
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	82910	104950	83755	69548	94497	85704	88055	73736
11.1 भारतीय रिज़र्व बैंक	-	12485	4872	653	680	8363	3847	3143

## सं. 30: गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि करोड़ ₹ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2020-21		2019-20 (अप्रै-अप्रै.)		2020-21 (अप्रै-अप्रै.)*		अप्रै. 2020		अप्रै. 2021*	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1 इक्विटी शेयर</b>	<b>74</b>	<b>102062</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>3288</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>3288</b>
1ए प्रीमियम	73	97648	3	7	9	3202	3	7	9	3202
1.1 पब्लिक	53	38004	3	14	7	3009	3	14	7	3009
1.1.1 प्रीमियम	53	34848	3	7	7	2939	3	7	7	2939
1.2 राइट्स	21	64059	—	—	3	280	—	—	3	280
1.2.1 प्रीमियम	20	62800	—	—	2	263	—	—	2	263
<b>2 अधिमान शेयर</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.1 पब्लिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>3 बांड और डिबेंचर</b>	<b>16</b>	<b>5806</b>	<b>1</b>	<b>102</b>	<b>4</b>	<b>2316</b>	<b>1</b>	<b>102</b>	<b>4</b>	<b>2316</b>
3.1 परिवर्तनीय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.1.1 पब्लिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.1.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.2 अपरिवर्तनीय	16	5806	1	102	4	2316	1	102	4	2316
3.2.1 पब्लिक	16	5806	1	102	4	2316	1	102	4	2316
3.2.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>4 कुल (1+2+3)</b>	<b>90</b>	<b>107868</b>	<b>4</b>	<b>116</b>	<b>14</b>	<b>5604</b>	<b>4</b>	<b>116</b>	<b>14</b>	<b>5604</b>
4.1 पब्लिक	69	43809	4	116	11	5325	4	116	11	5325
4.2 राइट्स	21	64059	—	—	3	280	—	—	3	280

टिप्पणी: 1. अप्रैल 2020 से इक्विटी निर्गमों का मासिक डेटा उनकी लिस्टिंग की तारीख के आधार पर संकलित किया गया है।

2. संख्याओं के पूर्णांकन के कारण कालम के आंकड़े कुल में नहीं जुड़ सकते।

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)।

\* : आंकड़े अनंतिम हैं।

## बाह्य क्षेत्र

## सं. 31: विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2020-21	2020		2021			
			अप्रै.	दिसं.	जन.	फर.	मार्च	अप्रै.
			1	2	3	4	5	6
1 निर्यात	करोड ₹	2151771	78951	200284	201148	200288	250766	228072
	मिलियन अमरीकी डॉलर	290811	10356	27215	27513	27528	34449	30625
1.1 तेल	करोड ₹	189192	9473	17185	15579	17763	24837	26976
	मिलियन अमरीकी डॉलर	25570	1243	2335	2131	2441	3412	3622
1.2 तेल से इतर	करोड ₹	1962579	69479	183099	185569	182524	225929	201095
	मिलियन अमरीकी डॉलर	265240	9114	24880	25382	25087	31037	27003
2 आयात	करोड ₹	2909827	130525	315962	306726	295007	352260	340505
	मिलियन अमरीकी डॉलर	393596	17121	42933	41954	40547	48392	45722
2.1 तेल	करोड ₹	611353	35537	70863	68900	65710	74768	80969
	मिलियन अमरीकी डॉलर	82684	4661	9629	9424	9031	10271	10872
2.2 तेल से इतर	करोड ₹	2298474	94988	245099	237826	229297	277492	259536
	मिलियन अमरीकी डॉलर	310912	12460	33304	32530	31516	38121	34850
3 व्यापार शेष	करोड ₹	-758057	-51574	-115678	-105578	-94719	-101494	-112433
	मिलियन अमरीकी डॉलर	-102785	-6765	-15718	-14441	-13019	-13943	-15097
3.1 तेल	करोड ₹	-422162	-26065	-53678	-53321	-47946	-49931	-53992
	मिलियन अमरीकी डॉलर	-57114	-3419	-7294	-7293	-6590	-6859	-7250
3.2 तेल से इतर	करोड ₹	-335895	-25509	-62000	-52257	-46773	-51563	-58441
	मिलियन अमरीकी डॉलर	-45671	-3346	-8425	-7148	-6429	-7083	-7847

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

## सं. 32: विदेशी मुद्रा भंडार

मद	इकाई	2020		2021				
		मई 29	अप्रै. 23	अप्रै. 30	मई 7	मई 14	मई 21	मई 28
		1	2	3	4	5	6	7
1 कुल भंडार	करोड ₹	3731592	4381700	4355951	4333343	4324574	4318817	4333464
	मिलियन अमरीकी डॉलर	493480	584107	588020	589465	590028	592894	598165
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	करोड ₹	3442185	4063227	4045137	4017335	4008211	3995492	4010076
	मिलियन अमरीकी डॉलर	455208	541647	546059	546493	546870	548519	553529
1.2 स्वर्ण	करोड ₹	247132	269822	262709	268166	268648	275640	276061
	मिलियन अमरीकी डॉलर	32682	35969	35464	36480	36654	37841	38106
	मात्रा (मैट्रिक टन)	657.68	695.31	695.31	695.31	695.31	696.25	696.25
1.3 एसडीआर	एसडीआरएस मिलियन	1048	1049	1049	1049	1049	1049	1049
	करोड ₹	10826	11288	11168	11052	11036	11020	10975
	मिलियन अमरीकी डॉलर	1432	1505	1508	1503	1506	1513	1515
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	करोड ₹	31449	37363	36936	36791	36680	36665	36352
	मिलियन अमरीकी डॉलर	4158	4987	4990	4989	4999	5021	5016

\* अंतर यदि कोई हो, तो पूर्णांकन के वजह से हैं।

## सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2020-21	2020	2021		2020-21	2021-22
		अप्रै.	मार्च	अप्रै.	अप्रै.	अप्रै.
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियां	141895	129339	141895	142043	953	2784
1.1 एफसीएनआर (बी)	20473	23112	20473	20049	-1132	-424
1.2 एनआर (ई) आरए	102579	90482	102579	103190	1980	2837
1.3 एनआरओ	18842	15745	18842	18804	104	372

## सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	2020-21	2020-21	2021-22	2020	2021	
		अप्रै.	अप्रै.	अप्रै.	मार्च	अप्रै.
	1	2	3	4	5	6
<b>1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)</b>	<b>43187</b>	<b>206</b>	<b>2837</b>	<b>206</b>	<b>1805</b>	<b>2837</b>
<b>1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1.1.2)</b>	<b>54665</b>	<b>1287</b>	<b>4683</b>	<b>1287</b>	<b>2731</b>	<b>4683</b>
<b>1.1.1.1 सकल अंतर्वाह/सकल निवेश</b>	<b>81722</b>	<b>4532</b>	<b>6235</b>	<b>4532</b>	<b>4592</b>	<b>6235</b>
1.1.1.1.1 इक्विटी	61423	2885	4552	2885	3110	4552
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	948	80	3	80	6	3
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक	51597	2169	4204	2169	2252	4204
1.1.1.1.1.3 शेयरों की अधिप्राप्ति	7091	524	233	524	613	233
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी	1787	113	113	113	238	113
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	16216	1305	1305	1305	1257	1305
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	4082	342	377	342	225	377
<b>1.1.1.2 प्रत्यावर्तन /विनिवेश</b>	<b>27056</b>	<b>3245</b>	<b>1552</b>	<b>3245</b>	<b>1861</b>	<b>1552</b>
1.1.1.2.1 इक्विटी	26993	3242	1536	3242	1834	1536
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	63	3	16	3	28	16
<b>1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)</b>	<b>11478</b>	<b>1082</b>	<b>1846</b>	<b>1082</b>	<b>926</b>	<b>1846</b>
1.1.2.1 इक्विटी पूंजी	5721	311	607	311	609	607
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	3232	272	272	272	263	272
1.1.2.3 अन्य पूंजी	6838	548	1142	548	1096	1142
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	4313	48	175	48	1041	175
<b>1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)</b>	<b>36843</b>	<b>-1972</b>	<b>-1978</b>	<b>-1972</b>	<b>3634</b>	<b>-1978</b>
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	-	-	-	-	-	-
1.2.2 एफआईआई	38097	-1820	-1741	-1820	3663	-1741
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	-	-	-	-	-	-
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	1254	152	238	152	30	238
<b>1 विदेशी निवेश अंतर्वाह</b>	<b>80030</b>	<b>-1766</b>	<b>858</b>	<b>-1766</b>	<b>5439</b>	<b>858</b>

## सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	2020-21	2020	2021		
		अप्रै.	फर.	मार्च	अप्रै.
	1	2	3	4	5
<b>1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण</b>	<b>12684.40</b>	<b>499.14</b>	<b>1155.61</b>	<b>1547.80</b>	<b>1188.18</b>
1.1 जमाराशियां	680.37	60.17	39.73	151.49	75.78
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	62.75	3.21	4.56	11.07	9.19
1.3 इक्विटी / डेट में निवेश	471.80	24.80	41.19	89.54	51.78
1.4 उपहार	1586.24	55.15	143.25	224.75	161.56
1.5 दान	12.59	2.68	2.06	0.65	0.72
1.6 यात्रा	3239.67	121.13	316.81	335.95	284.76
1.7 निकट संबंधियों का रखरखाव	2680.10	148.25	215.18	330.04	240.74
1.8 चिकित्सा उपचार	29.75	1.35	2.40	2.98	2.16
1.9 विदेश में शिक्षा	3836.12	78.76	383.27	390.55	353.49
1.10 अन्य	85.03	3.66	7.18	10.77	8.00

सं. 36: भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (रीर) और  
सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (नीर)

मद	2019-20	2020-21	2020	2021	
			मई	अप्रैल	मई
	1	2	3	4	5
<b>40- मुद्रा बास्केट (आधार: 2015-16=100)</b>					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	98.00	93.92	94.40	92.82	93.96
1.2 रीर	103.20	103.49	102.21	100.27	102.23
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	97.38	93.59	93.99	92.36	93.71
2.2 रीर	102.88	102.97	101.49	100.36	101.51
<b>6- मुद्रा बास्केट (व्यापार-भारित)</b>					
1 आधार : 2015-16=100					
1.1 नीर	94.92	88.47	89.91	86.52	87.22
1.2 रीर	103.60	101.78	101.14	99.68	100.41
2 आधार : 2018-19 =100					
2.1 नीर	100.78	93.93	95.45	91.86	92.60
2.2 रीर	103.30	101.49	100.86	99.40	100.12

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार - पंजीकरण

(राशि अमरीकी मिलियन डॉलर में)

मद	2020-21	2020	2021	
		अप्रै.	मार्च	अप्रै.
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	1063	50	106	111
1.2 राशि	26799	696	3883	2723
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	13	1	5	-
2.2 राशि	8456	300	5350	-
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1076	51	111	111
3.2 राशि	35255	996	9233	2723
4 भारत औसत परिपक्वता (वर्षों में)	6.03	7.00	7.35	6.25
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 6 महीने के लिबॉर पर भारत औसत मार्जिन या अस्थिर दर के ऋणों के लिए संदर्भ दर	1.93	1.70	2.19	2.10
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-13.00	0.00-10.86	0.00-10.69	0.00-9.90

## सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	अक्टू.-दिसं. 2019			अक्टू.-दिसं. 2020 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	316590	294989	21601	337696	305213	32483
1 चालू खाता (1.1+1.2)	162793	165423	-2630	157442	159188	-1746
1.1 पण्य	81245	117285	-36040	77231	111774	-34542
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	81548	48138	33410	80211	47414	32796
1.2.1 सेवाएं	55158	33280	21879	53741	30131	23610
1.2.1.1 यात्रा	8545	5569	2977	2170	2833	-664
1.2.1.2 परिवहन	5448	6411	-963	5602	5147	455
1.2.1.3 बीमा	617	549	68	575	577	-2
1.2.1.4 जीएनआईई	157	218	-62	179	260	-82
1.2.1.5 विविध	40391	20533	19859	45216	21314	23901
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	23760	2305	21455	25687	2312	23375
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	11889	12027	-138	12534	12799	-265
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	1183	550	633	1068	1192	-124
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	757	308	449	738	381	357
1.2.2 अंतरण	20827	1935	18893	20757	1498	19258
1.2.2.1 आधिकारिक	50	290	-240	62	298	-236
1.2.2.2 निजी	20777	1645	19132	20695	1200	19494
1.2.3 आय	5562	12923	-7361	5713	15785	-10072
1.2.3.1 निवेश आय	4122	12229	-8107	4179	15070	-10891
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1440	694	746	1534	715	819
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	153192	129566	23626	179536	146025	33511
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	94412	76840	17572	119992	81803	38190
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	19717	9974	9743	28387	11414	16973
2.1.1.1 भारत में	19089	5856	13233	26907	6932	19974
2.1.1.1.1 इक्विटी	11033	5747	5286	21846	6919	14926
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	3590		3590	4398		4398
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	4467	109	4358	663	13	650
2.1.1.2 विदेश में	628	4118	-3490	1480	4482	-3002
2.1.1.2.1 इक्विटी	628	2169	-1541	1480	1963	-483
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	788	-788	0	815	-815
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	1162	-1162	0	1704	-1704
2.1.2 संविभाग निवेश	74695	66866	7829	91605	70388	21217
2.1.2.1 भारत में	71761	63627	8133	91216	69514	21703
2.1.2.1.1 एफआईआई	71761	63627	8133	91216	69514	21703
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	56356	50342	6014	80566	60741	19825
2.1.2.1.1.2 ऋण	15405	13285	2119	10650	8772	1877
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0		0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	2934	3239	-304	389	875	-485
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	23041	19907	3135	19517	19354	164
2.2.1 बाह्य सहायता	2511	1243	1268	2567	1383	1184
2.2.1.1 भारत द्वारा	2	28	-26	10	21	-11
2.2.1.2 भारत को	2509	1215	1294	2557	1362	1195
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	11007	7771	3237	6497	7747	-1249
2.2.2.1 भारत द्वारा	2692	2687	5	970	484	486
2.2.2.2 भारत को	8315	5084	3231	5528	7263	-1735
2.2.3 भारत को अल्पावधि	9523	10893	-1370	10453	10224	229
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	9523	10129	-606	9538	10224	-686
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	0	764	-764	915	0	915
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	21012	23336	-2324	21093	28707	-7614
2.3.1 वाणिज्य बैंक	21012	23279	-2266	20700	28707	-8007
2.3.1.1 आस्तियां	5753	7260	-1507	5384	15872	-10489
2.3.1.2 देयताएं	15259	16019	-760	15316	12834	2481
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	14407	13579	828	14151	11183	2969
2.3.2 अन्य	0	58	-58	393	0	393
2.4 रुपया ऋण चुकौती		0	0	0	0	0
2.5 अन्य पूंजी	14726	9483	5243	18934	16162	2772
3 भूल-चूक	605		605	718		718
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	21601	-21601	0	32483	-32483
4.1 आईएमएफ						
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)		21601	-21601		32483	-32483

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

## सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(करोड़ ₹)

मद	अक्टू.-दिसं. 2019			अक्टू.-दिसं. 2020 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	2255004	2101143	153861	2490751	2251168	239583
1 चालू खाता (1.1+1.2)	1159541	1178274	-18733	1161249	1174126	-12877
1.1 पण्य	578694	835399	-256706	569637	824411	-254774
1.2 अदृश्य मर्दे (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	580847	342875	237973	591612	349715	241897
1.2.1 सेवाएं	392882	237044	155838	396378	222240	174138
1.2.1.1 यात्रा	60866	39664	21202	16002	20896	-4894
1.2.1.2 परिवहन	38806	45662	-6856	41322	37963	3359
1.2.1.3 बीमा	4395	3914	481	4238	4254	-16
1.2.1.4 जीएनआईई	1116	1555	-438	1317	1918	-601
1.2.1.5 विविध	287699	146249	141450	333498	157208	176290
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	169238	16420	152819	189459	17051	172408
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	84680	85666	-986	92447	94400	-1953
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	8427	3917	4510	7879	8793	-914
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	5390	2194	3196	5440	2809	2632
1.2.2 अंतरण	148348	13780	134568	153095	11051	142044
1.2.2.1 आधिकारिक	358	2066	-1708	457	2199	-1742
1.2.2.2 निजी	147990	11714	136276	152638	8852	143786
1.2.3 आय	39617	92050	-52433	42139	116425	-74285
1.2.3.1 निवेश आय	29362	87107	-57745	30824	111150	-80326
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	10255	4943	5312	11315	5274	6041
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	1091155	922869	168286	1324209	1077042	247167
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	672478	547315	125163	885030	603352	281678
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	140440	71043	69398	209376	84190	125186
2.1.1.1 भारत में	135969	41710	94259	198458	51132	147326
2.1.1.1.1 इक्विटी	78585	40936	37649	161128	51035	110092
2.1.1.1.2 पुननिवेशित आय	25569	0	25569	32436	0	32436
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	31815	774	31041	4894	96	4797
2.1.1.2 विदेश में	4472	29333	-24861	10918	33058	-22140
2.1.1.2.1 इक्विटी	4472	15446	-10975	10918	14479	-3561
2.1.1.2.2 पुननिवेशित आय	0	5611	-5611	0	6010	-6010
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	8276	-8276	0	12570	-12570
2.1.2 संविभाग निवेश	532037	476272	55765	675655	519162	156492
2.1.2.1 भारत में	511136	453204	57933	672784	512712	160072
2.1.2.1.1 एफआईआई	511136	453204	57933	672784	512712	160072
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	401412	358574	42838	594234	448009	146225
2.1.2.1.1.2 ऋण	109725	94630	15095	78550	64703	13847
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	20901	23068	-2168	2871	6450	-3580
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	164119	141790	22329	143955	142748	1207
2.2.1 बाह्य सहायता	17887	8856	9031	18933	10202	8731
2.2.1.1 भारत द्वारा	14	201	-187	71	153	-82
2.2.1.2 भारत को	17873	8655	9218	18862	10049	8813
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	78404	55349	23055	47922	57137	-9214
2.2.2.1 भारत द्वारा	19175	19136	39	7153	3567	3586
2.2.2.2 भारत को	59229	36212	23016	40770	53570	-12800
2.2.3 भारत को अल्पावधि	67829	77586	-9757	77100	75409	1690
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	67829	72147	-4318	70350	75409	-5059
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	0	5439	-5439	6749	0	6749
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	149666	166220	-16553	155574	211734	-56160
2.3.1 वाणिज्य बैंक	149666	165808	-16142	152674	211734	-59060
2.3.1.1 आस्तियां	40978	51709	-10731	39708	117071	-77362
2.3.1.2 देयताएं	108688	114099	-5411	112966	94663	18303
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	102621	96723	5898	104375	82480	21896
2.3.2 अन्य	0	411	-411	2900	0	2900
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	0	0	0	0	0
2.5 अन्य पूंजी	104892	67545	37347	139650	119208	20442
3 भूल-चूक	4308	0	4308	5293	0	5293
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	153861	-153861	0	239583	-239583
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	0	153861	-153861	0	239583	-239583

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

**सं. 40: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण**

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	अक्टू.-दिसं. 2019			अक्टू.-दिसं. 2020 (प्रा.)		
	जमा	नाम	निवल	जमा	नाम	निवल
	1	2	3	4	5	6
<b>1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)</b>	<b>162791</b>	<b>165395</b>	<b>-2605</b>	<b>157438</b>	<b>159161</b>	<b>-1724</b>
<b>1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)</b>	<b>136404</b>	<b>150565</b>	<b>-14161</b>	<b>130972</b>	<b>141905</b>	<b>-10933</b>
<b>1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)</b>	<b>81245</b>	<b>117285</b>	<b>-36040</b>	<b>77231</b>	<b>111774</b>	<b>-34542</b>
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	80308	110034	-29726	76317	101765	-25448
1.अ.क.2 वाणिज्य के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	938	0	938	914	0	914
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण		7252	-7252		10008	-10008
<b>1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)</b>	<b>55158</b>	<b>33280</b>	<b>21879</b>	<b>53741</b>	<b>30131</b>	<b>23610</b>
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	76	9	67	49	5	45
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	64	207	-143	38	291	-253
1.अ.ख.3 परिवहन	5448	6411	-963	5602	5147	455
1.अ.ख.4 यात्रा	8545	5569	2977	2170	2833	-664
1.अ.ख.5 निर्माण	734	570	164	619	705	-86
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	617	549	68	575	577	-2
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	1183	550	633	1068	1192	-124
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	184	2197	-2013	359	2297	-1937
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	24592	2712	21880	26498	2810	23688
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	11889	12027	-138	12534	12799	-265
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	535	757	-222	579	768	-190
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	157	218	-62	179	260	-82
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	1134	1503	-369	3471	448	3023
<b>1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)</b>	<b>5562</b>	<b>12923</b>	<b>-7361</b>	<b>5713</b>	<b>15785</b>	<b>-10072</b>
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1440	694	746	1534	715	819
1.आ.2 निवेश आय	3312	12075	-8764	3188	14720	-11533
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	1369	5760	-4391	1693	9699	-8007
1.आ.2.2 सविभाग निवेश	28	2435	-2408	67	1974	-1906
1.आ.2.3 अन्य निवेश	138	3868	-3730	130	3046	-2917
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	1777	12	1764	1298	1	1297
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	811	154	657	992	349	642
<b>1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)</b>	<b>20825</b>	<b>1907</b>	<b>18918</b>	<b>20752</b>	<b>1472</b>	<b>19281</b>
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	20777	1645	19132	20695	1200	19494
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	20062	1189	18873	19969	847	19122
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	715	455	260	725	353	373
1.इ.2 सामान्य सरकार	48	262	-214	58	272	-214
<b>2. पूंजी खाता (2.1+2.2)</b>	<b>108</b>	<b>258</b>	<b>-150</b>	<b>98</b>	<b>265</b>	<b>-167</b>
2.1 अनुत्पादित वित्तर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	19	108	-89	4	109	-105
2.2 पूंजी अंतरण	89	150	-61	94	156	-62
<b>3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)</b>	<b>153086</b>	<b>150937</b>	<b>2150</b>	<b>179442</b>	<b>178270</b>	<b>1173</b>
<b>3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)</b>	<b>19717</b>	<b>9974</b>	<b>9743</b>	<b>28387</b>	<b>11414</b>	<b>16973</b>
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	19089	5856	13233	26907	6932	19974
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	14623	5747	8875	26243	6919	19324
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	11033	5747	5286	21846	6919	14926
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	3590		3590	4398		4398
3.1.अ.2 ऋण लिखत	4467	109	4358	663	13	650
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	4467	109	4358	663	13	650
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	628	4118	-3490	1480	4482	-3002
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	628	2956	-2328	1480	2778	-1298
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	628	2169	-1541	1480	1963	-483
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश		788	-788		815	-815
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	1162	-1162	0	1704	-1704
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक		1162	-1162		1704	-1704
<b>3.2 सविभाग निवेश</b>	<b>74695</b>	<b>66866</b>	<b>7829</b>	<b>91605</b>	<b>70388</b>	<b>21217</b>
3.2अ भारत में सविभाग निवेश	71761	63627	8133	91216	69514	21703
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	56356	50342	6014	80566	60741	19825
3.2.2 ऋण प्रतिभितियां	15405	13285	2119	10650	8772	1877
3.2आ. भारत द्वारा सविभाग निवेश	2934	3239	-304	389	875	-485
<b>3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन</b>	<b>7328</b>	<b>7194</b>	<b>134</b>	<b>9304</b>	<b>12458</b>	<b>-3154</b>
<b>3.4 अन्य निवेश</b>	<b>51346</b>	<b>45302</b>	<b>6044</b>	<b>50146</b>	<b>51526</b>	<b>-1381</b>
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	14407	13637	770	14544	11183	3362
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	0	58	-58	393	0	393
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	14407	13579	828	14151	11183	2969
3.4.2.3 सामान्य सरकार						
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र						
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूंजी)	20124	18713	1411	15613	26654	-11041
3.4.3अ भारत को ऋण	17430	15998	1431	14633	26150	-11517
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	2694	2715	-21	979	504	475
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	190	660	-469	55	44	11
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	9523	10893	-1370	10453	10224	229
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	7102	1399	5703	9481	3422	6059
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार			0			0
<b>3.5 आरक्षित आस्तियां</b>	<b>0</b>	<b>21601</b>	<b>-21601</b>	<b>0</b>	<b>32483</b>	<b>-32483</b>
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण						
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए						
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए						
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	21601	-21601	0	32483	-32483
<b>4. कुल आस्तियां / देयताएं</b>	<b>153086</b>	<b>150937</b>	<b>2150</b>	<b>179442</b>	<b>178270</b>	<b>1173</b>
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	82059	70137	11922	118038	83815	34223
4.2 ऋण लिखत	63925	57799	6126	51923	58550	-6627
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	7102	23001	-15898	9481	35904	-26424
<b>5. निवल भूल-चूक</b>	<b>605</b>		<b>605</b>	<b>718</b>		<b>718</b>

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक



## सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(कोड़ ₹)

मद	अक्टू.-दिसं. 2019			अक्टू.-दिसं. 2020 (प्रा.)		
	जमा	नाम	निवल	जमा	नाम	निवल
	1	2	3	4	5	6
<b>1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)</b>	<b>1159525</b>	<b>1178077</b>	<b>-18552</b>	<b>1161217</b>	<b>1173930</b>	<b>-12713</b>
<b>1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1.अ.ख.)</b>	<b>971576</b>	<b>1072443</b>	<b>-100867</b>	<b>966014</b>	<b>1046650</b>	<b>-80636</b>
<b>1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1.अ.क.3)</b>	<b>578694</b>	<b>835399</b>	<b>-256706</b>	<b>569637</b>	<b>824411</b>	<b>-254774</b>
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	572015	783748	-211733	562893	750592	-187699
1.अ.क.2 वाणिज्य के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	6679	0	6679	6744	0	6744
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	51652	-51652	0	73819	-73819
<b>1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)</b>	<b>392882</b>	<b>237044</b>	<b>155838</b>	<b>396378</b>	<b>222240</b>	<b>174138</b>
1.अ.ख.1 अन्य के स्वाभिमूर्ति वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	543	63	480	364	34	330
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	456	1477	-1021	281	2143	-1863
1.अ.ख.3 परिवहन	38806	45662	-6856	41322	37963	3359
1.अ.ख.4 यात्रा	60866	39664	21202	16002	20896	-4894
1.अ.ख.5 निर्माण	5227	4057	1170	4565	5197	-633
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	4395	3914	481	4238	4254	-16
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	8427	3917	4510	7879	8793	-914
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	1312	15650	-14338	2651	16941	-14290
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	175162	19318	155844	195443	20727	174716
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	84680	85666	-986	92447	94400	-1953
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	3813	5395	-1582	4269	5668	-1398
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	1116	1555	-438	1317	1918	-601
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	8079	10707	-2628	25599	3305	22294
<b>1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)</b>	<b>39617</b>	<b>92050</b>	<b>-52433</b>	<b>42139</b>	<b>116425</b>	<b>-74285</b>
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	10255	4943	5312	11315	5274	6041
1.आ.2 निवेश आय	23588	86010	-62422	23511	108573	-85062
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	9753	41027	-31274	12484	71538	-59054
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	199	17347	-17148	497	14556	-14059
1.आ.2.3 अन्य निवेश	982	27548	-26566	957	22470	-21513
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	12655	88	12567	9573	9	9564
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	5774	1097	4677	7313	2577	4736
<b>1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)</b>	<b>148332</b>	<b>13584</b>	<b>134749</b>	<b>153064</b>	<b>10855</b>	<b>142209</b>
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	147990	11714	136276	152638	8852	143786
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और/अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	142897	8471	134426	147287	6249	141038
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	5093	3243	1850	5351	2603	2748
1.इ.2 सामान्य सरकार	342	1869	-1527	426	2003	-1577
<b>2. पूँजी खाता (2.1+2.2)</b>	<b>770</b>	<b>1837</b>	<b>-1068</b>	<b>724</b>	<b>1955</b>	<b>-1232</b>
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नाम) / निस्तारण (जमा)	132	768	-636	32	803	-772
2.2 पूँजी अंतरण	637	1069	-432	692	1152	-460
<b>3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)</b>	<b>1090402</b>	<b>1075090</b>	<b>15312</b>	<b>1323517</b>	<b>1314866</b>	<b>8651</b>
<b>3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1.अ+3.1.आ)</b>	<b>140440</b>	<b>71043</b>	<b>69398</b>	<b>209376</b>	<b>84190</b>	<b>125186</b>
3.1.अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	135969	41710	94259	198458	51132	147326
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	104154	40936	63218	193564	51035	142529
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	78585	40936	37649	161128	51035	110092
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	25569	0	25569	32436	0	32436
3.1.अ.2 ऋण लिखत	31815	774	31041	4894	96	4797
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	31815	774	31041	4894	96	4797
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	4472	29333	-24861	10918	33058	-22140
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	4472	21057	-16585	10918	20489	-9571
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	4472	15446	-10975	10918	14479	-3561
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	5611	-5611	0	6010	-6010
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	8276	-8276	0	12570	-12570
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	8276	-8276	0	12570	-12570
<b>3.2 संविभाग निवेश</b>	<b>532037</b>	<b>476272</b>	<b>55765</b>	<b>675655</b>	<b>519162</b>	<b>156492</b>
3.2.अ भारत में संविभाग निवेश	511136	453204	57933	672784	512712	160072
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	401412	358574	42838	594234	448009	146225
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	109725	94630	15095	78550	64703	13847
3.2.आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	20901	23068	-2168	2871	6450	-3580
<b>3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन</b>	<b>52196</b>	<b>51239</b>	<b>957</b>	<b>68626</b>	<b>91886</b>	<b>-23260</b>
<b>3.4 अन्य निवेश</b>	<b>365729</b>	<b>322675</b>	<b>43053</b>	<b>369860</b>	<b>380044</b>	<b>-10183</b>
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	102621	97135	5486	107275	82480	24796
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट, एनआरजी)	0	411	-411	2900	0	2900
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	102621	96723	5898	104375	82480	21896
3.4.2.3 सामान्य सरकार	0	0	0	0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईपीबी और बैंकिंग पूँजी)	143336	133289	10047	115154	196593	-81439
3.4.3.अ भारत को ऋण	124147	113952	10195	107930	192873	-84943
3.4.3.आ भारत द्वारा ऋण	19189	19337	-148	7224	3720	3504
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	1355	4699	-3344	404	326	78
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	67829	77586	-9757	77100	75409	1690
3.4.6 अन्य खाते प्राच्य/देय-अन्य	50588	9967	40621	69928	25237	44691
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0	0	0	0	0	0
<b>3.5 आरक्षित आस्तियां</b>	<b>0</b>	<b>153861</b>	<b>-153861</b>	<b>0</b>	<b>239583</b>	<b>-239583</b>
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	0	0	0	0	0	0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	153861	-153861	0	239583	-239583
<b>4. कुल आस्तियां / देयताएं</b>	<b>1090402</b>	<b>1075090</b>	<b>15312</b>	<b>1323517</b>	<b>1314866</b>	<b>8651</b>
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	584489	499573	84916	870616	618195	252421
4.2 ऋण लिखत	455325	411689	43636	382973	431851	-48878
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	50588	163828	-113240	69928	264820	-194892
<b>5. निवल भूल-चूक</b>	<b>4308</b>	<b>0</b>	<b>4308</b>	<b>5293</b>	<b>0</b>	<b>5293</b>

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

## सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	वित्तीय वर्ष/समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2019-20		2019		2020			
			दिसं.		सितं.		दिसं.	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	182957	418239	179734	426944	188302	455972	191304	480298
1.1 इक्विटी पूंजी और पुनर्निवेशित अर्जन	118442	395426	117163	404393	121516	430742	122814	454640
1.2 अन्य पूंजी	64515	22813	62572	22552	66786	25231	68490	25658
2 संविभाग निवेश	3847	246699	4845	266705	5041	253289	5527	274053
2.1 इक्विटी	602	134778	2619	148859	1906	149095	1732	170630
2.2 ऋण	3246	111921	2226	117846	3136	104194	3795	103423
3 अन्य निवेश	52422	427242	53415	429326	64921	431149	69530	438322
3.1 व्यापार ऋण	1460	104271	2224	105210	2917	102190	3333	102597
3.2 ऋण	6741	179577	6180	177315	9048	180599	10620	183526
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	26011	130761	27099	133331	34864	137519	37343	140683
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	18210	12634	17912	13469	18092	10841	18234	11516
4 रिज़र्व्स	477807		459863		544687		585771	
5 कुल आस्तियां/देयताएं	717033	1092180	697858	1122975	802952	1140410	852131	1192673
6 आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)		-375147		-425117		-337458		-340542

# भुगतान और निपटान प्रणाली

## सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक - भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)					
	वि. व 2020-21	2020		2021		विव 2020-21	2020		2021	
		अप्रै.	मार्च	अप्रै.	अप्रै.		मार्च	अप्रै.		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>ए. निपटान प्रणाली</b>										
<b>वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)</b>										
<b>1 सीसीआईएल प्रचलित प्रणाली (1.1 से 1.3)</b>	27.97	1.34	2.92	2.36	161943141	9808581	17383479	15138384		
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.1.1 से 1.1.3)	11.55	0.70	0.91	0.83	110634315	6644724	11182301	9963717		
1.1.1 आउटराइट	6.28	0.38	0.42	0.41	10032187	779511	678873	739674		
1.1.2 रेपो	2.84	0.17	0.26	0.21	43751173	2517435	4362390	3829853		
1.1.3 त्रि-पक्षीय रिपो	2.43	0.16	0.23	0.20	56850956	3347778	6141037	5394189		
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	16.04	0.63	1.95	1.49	48903961	3030887	5828078	4913256		
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @	0.38	0.01	0.06	0.05	2404865	132970	373100	261411		
<b>बी. भुगतान प्रणाली</b>										
<b>I वित्तीय बाजार आधार-संरचना (एफएमआई)</b>										
<b>1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)</b>	1591.92	54.35	202.35	151.52	105599849	6443653	12982215	8802868		
1.1 ग्राहक लेनदेन	1573.47	53.35	200.70	150.19	91008367	5612493	11427958	7555042		
1.2 इंटरबैंक लेनदेन	18.45	1.00	1.65	1.33	14591482	831161	1554257	1247825		
<b>II खुदरा</b>										
<b>2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.6)</b>	317851.82	17950.56	37208.47	34506.22	33522150	1687713	4053692	2946342		
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @	11.32	0.69	1.16	0.94	623	29	72	61		
2.2 एपीबीएस \$	14372.99	2312.36	1128.83	972.73	112747	18996	11086	5383		
2.3 आईएमपीएस	32783.47	1224.75	3631.44	3229.68	2941500	121141	327236	299542		
2.4 एनएसीएच जमा \$	16449.51	2657.23	1648.80	1029.55	1232714	89999	164083	101457		
2.5 एनईएफटी	30927.89	1759.79	3481.39	2862.71	25130910	1306406	3046329	2046235		
2.6 यूपीआई @	223306.64	9995.74	27316.85	26410.61	4103658	151141	504886	493664		
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	10.45	0.70	0.94	0.96	172	11	15	15		
<b>3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.3)</b>	10440.40	691.42	1023.06	1001.32	872399	56029	86351	82983		
3.1 भीम आधार पे @	160.84	20.66	12.92	13.88	2580	217	346	377		
3.2 एनएसीएच नामे \$	9629.61	667.06	904.64	894.08	868906	55805	85851	82467		
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	649.96	3.70	105.50	93.36	913	7	154	139		
<b>4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)</b>	57841.30	2822.19	5681.24	4833.00	1293080	44015	139715	115572		
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	17641.06	768.53	1887.27	1575.32	630414	20765	72319	59049		
4.1.1 पीओएस आधारित \$	8688.81	283.26	1012.86	782.31	280769	8052	33286	26314		
4.1.2 अन्य \$	8952.25	485.27	874.41	793.00	349645	12713	39033	32735		
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)	40200.24	2053.66	3793.97	3257.68	662667	23250	67396	56523		
4.2.1 पीओएस आधारित \$	20805.24	676.32	2240.07	1822.82	378044	9005	42816	35861		
4.2.2 अन्य \$	19395.00	1377.34	1553.89	1434.86	284623	14245	24580	20662		
<b>5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)</b>	49392.26	2086.01	5154.57	4762.03	197696	9648	21372	22148		
5.1 वॉलेट	39987.01	1841.26	4182.92	3963.08	152065	8693	14856	14421		
<b>5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)</b>	9405.25	244.75	971.65	798.95	45631	956	6516	7727		
5.2.1 पीओएस आधारित \$	437.31	38.21	42.20	36.85	11639	313	1579	1642		
5.2.2 अन्य \$	8967.94	206.54	929.45	762.11	33992	642	4937	6085		
<b>6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)</b>	6703.70	176.82	806.59	557.79	5627189	163685	722031	553322		
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	6702.53	176.57	806.59	557.79	5625941	163487	722031	553322		
6.2 अन्य	1.17	0.25	0.00	0.00	1249	197	-	-		
<b>कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>	442229.48	23727.00	49873.93	45660.36	41512514	1961090	5023161	3720367		
<b>कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>	443821.40	23781.35	50076.28	45811.88	147112363	8404743	18005376	12523235		
<b>कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	437117.70	23604.53	49269.69	45254.09	141485173	8241058	17283345	11969913		

## भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि. व. 2020-21	2020	2021		वि. व. 2020-21	2020	2021	
		अप्रै.	मार्च	अप्रै.		अप्रै.	मार्च	अप्रै.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ए. अन्य भुगतान चैनल</b>								
<b>1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)</b>	252364.97	11276.04	32971.49	31282.44	9089832	364031	1246220	982360
1.1 इंटर-बैंक \$	25130.99	1064.77	4852.88	2563.43	1865484	73418	270764	190500
1.2 इंटर-बैंक \$	227233.98	10211.27	28118.60	28719.01	7224348	290613	975456	791860
<b>2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)</b>	32483.42	1597.63	3390.80	2682.48	41534334	2246209	4976087	3180133
2.1 इंटर-बैंक @	6886.15	390.07	707.26	567.04	20601554	1204254	2355028	1352169
2.2 इंटर-बैंक @	25597.27	1207.57	2683.55	2115.44	20932780	1041955	2621059	1827964
<b>बी. एटीएम</b>								
<b>3 एटीएम से नकद निकासी (3.1 से 3.3)</b>	60905.81	2953.18	6040.02	5256.36	2889826	129098	285268	255527
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना \$	51.41	3.68	5.92	5.09	2560	159	307	258
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	60602.23	2938.54	6007.92	5226.23	2878025	128560	283955	254397
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	252.17	10.97	26.18	25.03	9240	379	1007	871
<b>4 पीओएस पर नकद निकासी \$ (4.1 से 4.2)</b>	394.60	40.87	22.38	22.06	1532	111	119	133
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	353.33	35.67	19.49	18.85	1483	105	114	111
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	41.27	5.21	2.90	3.20	49	5	5	22
<b>5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @</b>	9460.43	875.54	763.86	725.35	225420	14462	22276	21701
5.1 एईपीएस @	9460.43	875.54	763.86	725.35	225420	14462	22276	21701

## भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	मार्च 2021	2020	2021	
	तक	अप्रै.	मार्च	अप्रै.
	1	2	3	4
<b>भुगतान प्रणाली अवसंरचना</b>				
<b>1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)</b>	9602.51	8868.07	9602.51	9630.55
1.1 क्रेडिट कार्ड	620.49	573.60	620.49	622.60
1.2 डेबिट कार्ड	8982.02	8294.47	8982.02	9007.95
<b>2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)</b>	21951.37	18342.76	21951.37	22216.97
2.1 वॉलेट @	20052.10	17150.44	20052.10	20249.78
2.2 कार्ड @	1899.27	1192.32	1899.27	1967.19
<b>3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)</b>	2.39	2.34	2.39	2.40
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम \$	2.14	2.10	2.14	2.14
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम \$	0.25	0.24	0.25	0.25
<b>4 माइक्रो एटीएम की संख्या @</b>	4.04	2.76	4.04	4.14
<b>5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या</b>	47.20	43.91	47.20	45.25
<b>6 भारत क्यूआर @</b>	35.70	20.19	35.70	35.95
<b>7 यूपीआई क्यूआर *</b>	925.22	-	925.22	978.19

@: नवंबर 2019 से नया समावेश

\$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा।

\* सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड शामिल है।

नोट: 1. डेटा अनंतिम है।

2. 31 जनवरी 2020 से ईसीस (डेबिट और क्रेडिट) एनएसीएच के साथ मिल दिया गया है।

3. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा के परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रेन्युलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।

4. केवल घरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन लिया जाता है; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सपायर्ड कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।

# अवसरिक श्रृंखला

## सं. 44: लघु बचत

(करोड़ ₹)

योजना		2018-19	2019		2020	
			फर.	दिसं.	जन.	फर.
		1	2	3	4	5
<b>1. लघु बचत</b>	<b>प्राप्तियां</b>	<b>115714</b>	<b>9839</b>	<b>15814</b>	<b>15184</b>	<b>16911</b>
	<b>बकाया</b>	<b>918459</b>	<b>899191</b>	<b>1015010</b>	<b>1030037</b>	<b>1046766</b>
<b>1.1 कुल जमाराशियां</b>	<b>प्राप्तियां</b>	<b>91108</b>	<b>7130</b>	<b>12117</b>	<b>11091</b>	<b>11460</b>
	<b>बकाया</b>	<b>618418</b>	<b>606920</b>	<b>693812</b>	<b>704903</b>	<b>716363</b>
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	31037	2360	3455	3106	2690
	बकाया	140247	134863	150462	153568	156258
1.1.2 एमजीएनआरईजी	प्राप्तियां					
	बकाया					
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	-31	-19	-31	-25	-20
	बकाया	3107	2877	2984	2959	2939
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	53	0	-827	-2	-3
	बकाया	10	-8	-18	-20	-23
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	10967	928	1753	1712	1887
	बकाया	192658	191653	203460	205172	207059
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	13990	1184	2070	2133	2131
	बकाया	55708	54446	69464	71597	73728
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	25000	2451	4296	3999	4494
	बकाया	124292	121687	152622	156621	161115
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	71534	70179	86344	88247	90327
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	5910	5824	6749	6854	6970
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	6901	6910	7328	7397	7464
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	39947	38774	52201	54123	56354
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	10081	215	1401	168	281
	बकाया	102401	101407	114842	115010	115291
1.1.9 डाक घर सावधि मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	11	11	0	0	0
	बकाया	-26	-26	-25	-25	-25
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	21	21	21	21	21
<b>1.2 बचत प्रमाणपत्र</b>	<b>प्राप्तियां</b>	<b>16067</b>	<b>1732</b>	<b>3326</b>	<b>3524</b>	<b>3937</b>
	<b>बकाया</b>	<b>221517</b>	<b>219257</b>	<b>240900</b>	<b>244267</b>	<b>248022</b>
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	11318	1262	2272	2458	2619
	बकाया	98492	94795	110050	112508	115127
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	334	3	0	0	1
	बकाया	263	300	-289	-289	-288
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	-18678	-1609	-971	-1713	-1120
	बकाया	19303	21232	6782	5069	3949
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	23018	2065	2025	2782	2452
	बकाया	93630	91314	113273	116055	118507
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	93	12	0	-1	0
	बकाया	2	-47	-179	-180	-180
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	-18	-1	0	-2	-15
	बकाया	-80	-82	-82	-84	-99
1.2.7 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	9907	11745	11345	11188	11006
<b>1.3 लोक भविष्य निधि</b>	<b>प्राप्तियां</b>	<b>8539</b>	<b>977</b>	<b>371</b>	<b>569</b>	<b>1514</b>
	<b>बकाया</b>	<b>78524</b>	<b>73014</b>	<b>80298</b>	<b>80867</b>	<b>82381</b>

स्रोत : महालेखाकार, पोस्ट और टेलीग्राफ।

टिप्पणी : अप्रैल 2017 से प्राप्तियों का डाटा निवल प्राप्तियों हैं अर्थात् सकल प्राप्तियों माइनस सकल भुगतान

## सं. 45: केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2020				2021
	मार्च	जून	सितं	दिसं.	मार्च
	1	2	3	4	5
<b>(क) कुल (₹ करोड़ में)</b>	<b>6486585</b>	<b>6704983</b>	<b>7137069</b>	<b>7357111</b>	<b>7635902</b>
1. वाणिज्य बैंक	40.41	38.98	38.55	37.81	37.77
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.39	0.36	0.34	0.25	0.27
3. बीमाकृत कंपनियां	25.09	26.24	25.33	25.64	25.30
4. म्यूच्युअल फंड	1.43	2.02	2.42	2.62	2.94
5. सहकारी बैंक	1.90	1.86	1.86	1.83	1.82
6. वित्तीय संस्थाएं	0.53	1.19	1.42	1.00	1.00
7. कॉरपोरेट	0.81	0.78	0.94	1.05	1.06
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	2.44	1.79	2.05	2.10	1.87
9. भविष्य निधियां	4.72	4.96	4.77	4.61	4.44
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	15.13	14.70	15.00	15.71	16.20
11. अन्य	7.17	7.11	7.32	7.37	7.33
11.1 राज्य सरकार	2.05	1.99	1.86	1.76	1.69

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2020				2021
	मार्च	जून	सितं	दिसं.	मार्च
	1	2	3	4	5
<b>(ख) कुल (₹ करोड़ में)</b>	<b>3265990</b>	<b>3393099</b>	<b>3564979</b>	<b>3721573</b>	<b>3879982</b>
1. वाणिज्य बैंक	34.99	33.54	34.60	34.19	33.69
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.76	0.74	0.54	0.36	0.48
3. बीमाकृत कंपनियां	31.63	30.85	30.26	30.25	30.04
4. म्यूच्युअल फंड	1.14	1.74	1.96	1.92	1.82
5. सहकारी बैंक	4.12	4.38	4.19	4.11	4.05
6. वित्तीय संस्थाएं	0.11	1.96	1.92	1.88	1.86
7. कॉरपोरेट	0.30	0.31	0.39	0.45	0.49
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
9. भविष्य निधियां	22.22	21.70	21.31	21.20	22.00
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.81	0.77
11. अन्य	4.71	4.78	4.80	4.82	4.77
11.1 राज्य सरकार	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18

खजाना बिल					
श्रेणी	2020				2021
	मार्च	जून	सितं	दिसं.	मार्च
	1	2	3	4	5
<b>(ग) कुल (₹ करोड़ में)</b>	<b>538409</b>	<b>881362</b>	<b>982286</b>	<b>839729</b>	<b>690646</b>
1. वाणिज्य बैंक	61.06	46.11	53.50	54.75	55.54
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	2.26	1.48	2.16	1.65	2.82
3. बीमाकृत कंपनियां	7.45	4.64	4.06	4.50	5.61
4. म्यूच्युअल फंड	13.24	23.45	19.90	18.98	17.80
5. सहकारी बैंक	2.55	1.95	1.63	1.61	2.43
6. वित्तीय संस्थाएं	0.58	1.67	1.34	1.11	1.24
7. कॉरपोरेट	1.89	1.43	1.63	2.01	3.16
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. भविष्य निधियां	0.02	0.05	0.00	0.09	0.22
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	11.27	4.80	0.68	0.49
11. अन्य	10.95	7.95	10.99	14.63	10.70
11.1 राज्य सरकार	6.22	4.35	7.76	13.27	5.98

## सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(करोड़ ₹)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (सं.अ.)	2020-21 (ब.अ.)
	1	2	3	4	5	6
<b>1. कुल वितरण</b>	<b>3760611</b>	<b>4265969</b>	<b>4515946</b>	<b>5040747</b>	<b>5875914</b>	<b>6470254</b>
1.1 गतिविधियां	2201287	2537905	2635110	2882758	3486519	3818358
1.1.1 राजस्व	1668250	1878417	2029044	2224367	2708218	2920507
1.1.2 पूंजी	412069	501213	519356	596774	694262	794599
1.1.3 ऋण	120968	158275	86710	61617	84038	103252
1.2 गैर गतिविधियां	1510810	1672646	1812455	2078276	2295105	2556504
1.2.1 राजस्व	1379727	1555239	1741432	1965907	2171963	2421566
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	648091	724448	814757	894520	969344	1091617
1.2.2 पूंजी	127306	115775	69370	111029	121159	132961
1.2.3 ऋण	3777	1632	1654	1340	1984	1977
1.3 अन्य	48514	55417	68381	79713	94290	95393
<b>2. कुल प्राप्तियां</b>	<b>3778049</b>	<b>4288432</b>	<b>4528422</b>	<b>5023352</b>	<b>5779396</b>	<b>6524526</b>
2.1 राजस्व प्राप्तियां	2748374	3132201	3376416	3797731	4338225	4828088
2.1.1 कर प्राप्तियां	2297101	2622145	2978134	3278947	3547958	3951657
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	1440952	1652377	1853859	2030050	2157126	2436871
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	852271	965622	1121189	1246083	1386652	1510287
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	3878	4146	3086	2814	4180	4500
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	451272	510056	398282	518783	790267	876430
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	35779	33220	34224	36273	33272	30911
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	59827	69063	142433	140287	129507	232172
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	16561	20942	42213	44667	62499	18302
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	43266	48122	100219	95621	67008	213870
<b>3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]</b>	<b>952410</b>	<b>1064704</b>	<b>997097</b>	<b>1102729</b>	<b>1408183</b>	<b>1409995</b>
<b>3 क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार</b>						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	939662	1046708	989167	1097210	1403250	1405373
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	231090	617123	144792	387091	518093	-----
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	60472	195816	-144847	325987	190241	-----
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	708572	429585	844375	710119	885156	-----
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	12748	17997	7931	5519	4933	4622
<b>3ख. वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार</b>						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	939662	1046708	989167	1097210	1403250	1405373
3ख.1.1 बाजार उधार (निवल)	673298	689821	794856	795845	962386	1105573
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	80015	35038	71222	88961	213430	213430
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	35261	45688	42351	51004	42900	42529
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	-3322	-6436	18423	-18298	-241	2978
3ख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	13470	17792	25138	66289	32949	35987
3ख.1.6 नकद शेष	-17438	-22463	-12476	17395	96518	-54272
3ख.1.7 अन्य	158378	287268	49653	96014	55309	59147
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	12748	17997	7931	5519	4933	4622
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल वितरण	27.3	27.7	26.4	26.6	28.9	28.8
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल प्राप्तियां	27.4	27.9	26.5	26.5	28.4	29.0
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर राजस्व प्राप्तियां	20.0	20.3	19.7	20.0	21.3	21.5
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कर प्राप्तियां	16.7	17.0	17.4	17.3	17.4	17.6
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर सकल वित्तीय घाटा	6.9	6.9	5.8	5.8	6.9	6.3

...: उपलब्ध नहीं। सं.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान

स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज

## सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अप्रैल 2021 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	
1	आंध्र प्रदेश	657	25	1327	17	1230	2
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	-	-	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	-	-	-	-	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	-	-	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	1116	30	1068	10
11	झारखंड	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	155	2	267	2	-	-
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-
16	मणिपुर	-	-	239	29	150	8
17	मेघालय	29	3	-	-	-	-
18	मिजोरम	-	-	102	4	-	-
19	नगालैंड	111	30	252	19	146	10
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	-	-	-	-	-	-
23	राजस्थान	-	-	-	-	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	652	12	726	8	-	-
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-
28	उत्तरप्रदेश	-	-	-	-	-	-
29	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।



## सं.48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	अप्रैल 2021 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	8667	853	--	-
2	अरुणाचल प्रदेश	1706	3	--	-
3	असम	3983	57	--	-
4	बिहार	5834	--	--	-
5	छत्तीसगढ़	4892	--	1	4608
6	गोवा	622	314	--	-
7	गुजरात	5090	501	--	-
8	हरियाणा	806	1262	--	-
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	800
10	जम्मू और कश्मीर	--	--	--	-
11	झारखंड	288	--	--	-
12	कर्नाटक	6046	--	--	13000
13	केरल	2245	--	--	-
14	मध्य प्रदेश	--	959	--	-
15	महाराष्ट्र	43977	661	--	4000
16	मणिपुर	162	105	--	-
17	मेघालय	755	43	9	-
18	मिज़ोरम	367	47	--	-
19	नगालैंड	1720	35	--	-
20	उड़ीसा	11688	1522	88	13180
21	पुदुचेरी	321	--	--	807
22	पंजाब	1152	--	8	-
23	राजस्थान	--	--	129	2000
24	तमिलनाडु	6937	--	40	12414
25	तेलंगाना	5919	1293	--	-
26	त्रिपुरा	389	9	--	-
27	उत्तराखंड	973	--	180	-
28	उत्तरप्रदेश	3406	134	--	-
29	पश्चिम बंगाल	9297	608	214	-
	<b>कुल</b>	<b>127244</b>	<b>8405</b>	<b>668</b>	<b>50808</b>

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं

## सं. 49: राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां

(करोड़ ₹)

क्र. सं.	राज्य	2019-20		2020-21		2021-22						2020-21 में अब तक कुल राशि उठाई गई है	
		सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	फरवरी		मार्च		अप्रैल		सकल	निवल
						सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	आंध्र प्रदेश	42415	33444	50896	41915	3646	1926	-	-1137	2000	1300	2000	1300
2	अरुणाचल प्रदेश	1366	1287	767	767	-	-	286	286	400	400	400	400
3	असम	12906	10996	15030	14230	3500	3500	2130	1330	-	-	-	-
4	बिहार	25601	22601	27285	24685	1993	1993	1292	692	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	11680	10980	13000	10500	1000	1000	2000	2000	-	-	-	-
6	गोवा	2600	2000	3354	3054	300	300	500	500	-	-	-	-
7	गुजरात	38900	28600	44780	33280	1500	500	12000	10458	-	-	-	-
8	हरियाणा	24677	20677	30000	25550	3500	2300	2000	1350	-	-1800	-	-1800
9	हिमाचल प्रदेश	6580	4460	6000	3755	1000	820	-	-965	-	-	-	-
10	जम्मू और कश्मीर	7869	6760	9328	6020	700	-50	818	239	500	500	500	500
11	झारखंड	7500	5656	9400	8900	1400	1400	3000	3000	-	-	-	-
12	कर्नाटक	48500	42500	69000	61900	3000	3000	9000	9000	-	-	-	-
13	केरल	18073	12617	28566	23066	2000	-	7000	6000	-	-	-	-
14	मध्य प्रदेश	22371	16550	45573	38773	11000	11000	10573	6773	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	48498	32998	69000	50022	1000	-1471	3000	567	-	-	-	-
16	मणिपुर	1757	1254	1302	1044	152	152	120	12	200	200	200	200
17	मेघालय	1344	1070	1777	1587	-	-	256	256	200	200	200	200
18	मिज़ोरम	900	745	944	677	50	50	30	-97	-	-150	-	-150
19	नगालैंड	1000	423	1721	1366	437	437	-	-155	350	350	350	350
20	उड़ीसा	7500	6500	3000	500	-	-1000	-	-500	-	-500	-	-500
21	पुदुचेरी	970	470	1390	790	150	-100	340	190	-	-	-	-
22	पंजाब	27355	18470	32995	23467	1500	972	7772	7772	-	-1600	-	-1600
23	राजस्थान	39092	24686	57359	44273	8500	6646	5948	1798	4000	4000	4000	4000
24	सिक्किम	809	481	1292	1292	100	100	61	61	-	-	-	-
25	तमिलनाडु	62425	49826	87977	76796	10000	9700	8477	8477	-	-	-	-
26	तेलंगाना	37109	30697	43784	37365	2000	770	2250	1437	1500	1000	1500	1000
27	त्रिपुरा	2928	2578	1916	1631	142	142	61	-124	-	-	-	-
28	उत्तराखंड	69703	52744	75500	59185	14000	14000	16000	13972	-	-	-	-
29	उत्तरप्रदेश	5100	4500	6200	5208	-	-	2000	2000	-	-500	-	-500
30	पश्चिम बंगाल	56992	40882	59680	50180	7000	7000	10680	10680	-	-3173	-	-3173
	<b>कुल</b>	<b>634521</b>	<b>487454</b>	<b>798816</b>	<b>651777</b>	<b>79570</b>	<b>65087</b>	<b>107594</b>	<b>85872</b>	<b>9150</b>	<b>227</b>	<b>9150</b>	<b>227</b>

- : शून्य

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

## वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

### सारणी सं. 1

- 1.2 और 6: वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।
- 3.5 और 3.7: वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।
- 4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।
- 4.5, 4.6 और 4.7 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।
- 4.10 से 4.12 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम निलामी दिन से संबंधित है।
- 4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।
- 7.1 और 7.2: विदेशी व्यापार यूएस डॉलर से संबंधित है।

### सारणी सं. 2

- 2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।
- 2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियों और अल्पावधि प्रतिभूतियों/बांडों सहित जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी।

### सारणी सं. 4

<http://nsdp.rbi.org.in> के 'रिज़र्व टेम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्बर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

### सारणी सं. 5

अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा, अर्थात् एक्जिम बैंक को 31 मार्च 2013 से बंद है।

### सारणी सं. 6

- अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकड़े सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।
- 2.2 : आईएमएफ खाता सं.1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

### सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांड शामिल हैं।

### सारणी सं. 8

- एनएम<sub>2</sub> और एनएम<sub>3</sub> में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।
- 2.4: चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।
- 2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

### सारणी सं. 9

वित्तीय सस्थाओं में एक्जिम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।  
एल<sub>1</sub> और एल<sub>2</sub> मासिक आधार पर और एल<sub>3</sub> तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।  
जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

### सारणी सं. 13

कालम सं. (1) (2) और (3) में दर्शाए गए आंकड़ें अंतिम (आरआरबीसहित) और कालम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़ें अनंतिम (आरआरबी को छोड़कर) हैं।

#### सारणी सं. 14

कालम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकड़ें अनंतिम हैं।

#### सारणी सं. 17

2.1.1: राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।

2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।

4. : आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

#### सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

#### सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।

1: बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।

2: संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

#### सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांडों में निवेश तथा सार्क स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा और भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक को अंतरित एसडीआर शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिज़र्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यहास को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रूपी-अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों में परिवर्तित किया गया है।

#### सारणी सं. 34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.4 : अनुमान

1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान

‘अन्य पूंजी’ एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी सस्थांओ/शाखाओ के बीच के ऋण संबंधी लेनदेन से संबंधित है।

हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय-अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान-संतुलन के आंकड़ों से मेल न खाएं।

#### सारणी सं. 35

1.10 : जर्नलों के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

#### सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि या मूल्यहास का सकेंतक। 6-मुद्राओवाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2018-19 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। इससे संबंधित कार्यपद्धति का विवरण बुलेटिन के दिसंबर 2005, अप्रैल 2014 और जनवरी 2021 के अंक में दिया गया है।

#### सारणी सं. 37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

**सारणी सं. 38, 39, 40 और 41**

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

**सारणी सं. 43**

भाग I- ए. भुगतान प्रणाली

1.1.3: प्रतिभूति खंड के अंतर्गत त्रिपक्षीय रेपो का परिचालन 05 नवंबर, 2018 से किया गया है।

भाग I-बी भुगतान प्रणाली

4.1.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

4.2.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड अंतरण और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध है।

5.1: माल और सेवाओं की खरीद और वॉलेट के माध्यम से निधि अंतरण शामिल है।

5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।

6.1: तीन ग्रिडों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।

6.2: अन्य 'में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल है जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन केंद्र से संबंधित है।

भाग II- ए अन्य भुगतान चैनल

1: मोबाइल भुगतान -

o बैंकों और यूपीआई ऐप के मोबाइल ऐप के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल हैं।

o जुलाई 2017 के डेटा में केवल व्यक्तिगत भुगतान और मोबाइल के माध्यम से पहल किए गए, संसाधित और अधिकृत किए गए कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल के माध्यम से शुरू नहीं किए गए हैं, संसाधित और अधिकृत नहीं हैं, को शामिल नहीं किया गया है।

2: इंटरनेट भुगतान --नेटबैंकिंग 'के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट से किया गया वित्तीय लेनदेन शामिल है।

भाग II-बी एटीएम

3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई से किए गए लेनदेन से संबंधित है।

भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना

3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) के एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलएओ को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।

**सारणी सं. 45**

(-): नगण्य को दर्शाता है।

जून 2016 से टेबल फार्मेट संशोधित किया है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों सहित राज्य सरकारों की स्वामित्ववाली प्रतिभूतियाँ और खजाना बिलों सहित शामिल है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्वल डिस्कॉ म एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बान्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इसका हिस्सा बहुत कम है।

"अन्य" श्रेणी में राज्य सरकारों, पेंशन निधियां न्यास, संस्थाएं, हिंदू अविभक्त परिवार / वैयक्तिक आदि. शामिल है।

#### सारणी सं. 46

वर्ष 2011-12 के आधार पर जीडीपी डेटा है। वर्ष 2019-20 का जीडीपी डेटा केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा 29 मई 2020 को जारी राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान से संबंधित है। वर्ष 2020-21 का जीडीपी डेटा केंद्रीय बजट 2020-21 से लिया गया है। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि व्यय को छोड़कर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय।

1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुनःचुकोती सहित) और राज्य सरकार के निवल चुकोती से संबंधित है।

1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।

2: यह डाटा केंद्र और राज्य सरकारों को दिये गये उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते है।

3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार है।

3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधारियां शामिल हैं।

3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में किये गये निवल निवेश को दर्शाते है।

यह डेटा नए डेटा की उपलब्धता के साथ घटकों में समायोजन के कारण पिछले प्रकाशनों से भिन्न हो सकता है।

3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।

3बी.1.7: वित्तीय संस्थानों, बीमा और पेंशन निधि, प्रेषण, नकदी शेष निवेश लेखा से लिये गये ऋण, खज़ाना बिलों सहित।

#### सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपादिक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू एमए) दिया जाता है।

राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

:- नगण्य

#### सारणी सं. 48

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।

नीलामी खज़ाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारों में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों की खज़ाना बिल शामिल हैं।

--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (<https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=17618>) में उपलब्ध हैं।

‘वर्तमान सांख्यिकी’ का टाइम सीरिज डाटा <https://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध है।

विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों (जैसे **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक**) में उपलब्ध हैं।

## भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2021	₹300 एक प्रति (काउंटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित) ₹4,200 (डाक प्रभार सहित एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,150 (एक वर्ष रियायती दर*) ₹3,360 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क - डाक प्रभार सहित@) ₹2,520 (एक वर्ष रियायती दर@)	15 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (डाक प्रभार सहित) 180 अमरीकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकीय हैंडबुक 2019-20	₹550 (सामान्य) ₹600 (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक 2019-20	₹600 (सामान्य) ₹650 (डाक प्रभार सहित) ₹450 (रियायती) ₹500 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त: 2020-21 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (काउंटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी ऑन फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी (तारापोर समिति की रिपोर्ट II)	₹140 एक प्रति (काउंटर पर) ₹170 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	25 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. बैंकिंग शब्दावली (2012)	₹80 एक प्रति (काउंटर पर) ₹120 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
7. अनुवाद के विविध आयाम (हिंदी)	₹165 एक प्रति (काउंटर पर) ₹205 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
8. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन: दशा और दिशा (हिंदी)	₹150 एक प्रति (काउंटर पर) ₹200 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
9. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 40, सं. 1, 2019	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
10. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 40, सं. 2, 2019	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
11. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 41, सं. 1, 2020	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
12. पर्सपेक्टिव्स ऑन सेंट्रल बैंकिंग गवर्नर्स; स्पीक (1935-2010) प्लैटिनम जुबिली	₹1400 एक प्रति (काउंटर पर)	50 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)

## टिप्पणियां:

- उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट ([www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)) पर उपलब्ध हैं।
  - टाइम सीरीज डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (<http://dbie.rbi.org.in>)।
  - भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-1997 (4 खंड), वित्तीय संकट के संदर्भ में केन्द्रीय बैंकिंग की चुनौतियां और भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि और वित्त भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।
- \* भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- @ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा देने हेतु, घरेलू ग्राहक जो एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, उन्हें 20 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

**सामान्य अनुदेश:**

1. बिक्री हुई प्रतियां वापस नहीं ली जाएंगी।
2. प्रकाशन कन्साइनमेंट वीपीपी आधार पर नहीं भेजा जाएगा।
3. जहां कहीं रियायती मूल्य का उल्लेख नहीं है, वहां भारत में छात्रों, अध्यापकों/व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी, बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रकाशन के पिछले अंक उपलब्ध नहीं हैं।
4. प्रकाशनों की बिक्री तथा वितरण (सोमवार से शुक्रवार) तक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, आरबीआई, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001 में किया जाएगा। बिक्री अनुभाग का संपर्क नं. 022-2260 3000, विस्तार 4002, ई-मेल: spsdepr@rbi.org.in है।
5. सदस्यता शुल्क मुख्यतः एनईएफटी द्वारा किया जाना चाहिए और अग्रपत्र, जिसके साथ एनईएफटी विवरण संलग्न हो, निदेशक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, आरबीआई, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001। एनईएफटी फार्म में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित है :

लाभार्थी का नाम	आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारिबैंक
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
शाखा तथा पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBIS0MBPA04
खाते का प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8024129-19
प्रेषक से प्राप्तकर्ता की जानकारी	अभिदाता का नाम..... अभिदाता सं.....

6. प्रकाशनों को शीघ्रताशीघ्र भेजने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तथापि मांग अधिक होने पर 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर प्रकाशनों की आपूर्ति की जाएगी। औपचारिकताएं पूरा करने और उसके बाद उपलब्ध प्रकाशनों को भेजने में न्यूनतम एक महीने का समय लगेगा। 'प्रकाशन प्राप्त न होने की शिकायत' 2 महीने के अंदर भेजी जाए।
7. कृपया अपनी अंशदान संख्या, नाम, पता तथा ई-मेल आईडी spsdepr@rbi.org.in पर मेल करें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें।